राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 231

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, मंगलवार, 28 जनवरी 2020

www.jagran.com

पृष्ठ 16

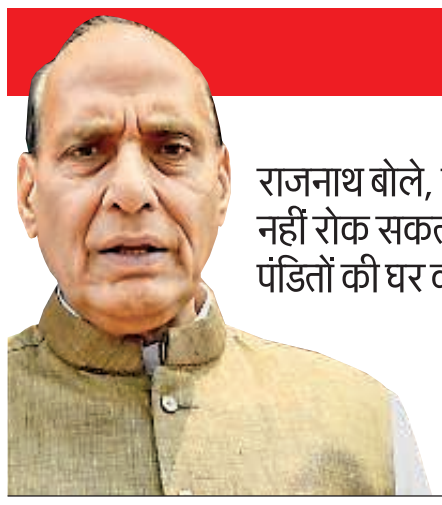

राजनाथ बोले, कोई ताकत नहीं रोक सकती कश्मीरी पंडितों की घर वापसी

>>3

सरोकार

कोर्ट की शर्त, पेड़ सूखे तो फिर जाओगे जेल

मुरैना : मप्र के मुरैना जिले में एक ऐसा जंगल है, जहां लगे पेड़ों को देखने पुलिस नियमित पहुंचती है। यह पुलिस की पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाई गई कोई मुहिम नहीं है, बल्कि जमानत के इन पेड़ों की रिपोर्ट बनाना उनकी मजबूरी है। पढ़ें पूरी कहानी। (पेज-11)

जागरण विशेष

दुनिया को ब्लैक होल का राज बताएगा भारत

कानपुर : ब्लैक होल के राज अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश में आगे बढ़ चुका भारत जल्द ही दुनिया को यह भी बताएगा कि ब्लैक होल कितनी तेजी से ब्रह्मांड को निगल रहा है। एस्ट्रोसेट सेटेलाइट से मिल रहे आंकड़ों का अध्ययन करने में आइआइटी कानपुर के वैज्ञानिक जुटे हुए हैं। (पेज-11)

सीएए के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शनों के पीछे पीएफआइ

सनसनीखेज ▶ प्रवर्तन निदेशालय ने गृह मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट, कपिल सिब्बल और इंदिरा जयसिंह को किया गया बड़ा भुगतान

इन बैंक खातों से प्रदर्शनों के दिन या एक दिन पहले बड़ी मात्रा में निकाले गए पैसे

नीलू रंजन, नई दिल्ली

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शनों के पीछे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआइ) की साजिश के सबूत मिलने लगे हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सीएए के विरोध प्रदर्शनों के दौरान पीएफआइ और उसके सहयोगी संगठनों के बैंक खातों में लेन-देन का विस्तृत ब्योरा गृहमंत्रालय को सौंपा है। इससे साफ पता चलता है कि इस दौरान पीएफआइ के खातों में बड़ी मात्रा में रकम जमा की गई और पैसे निकाले गए, जो पहले के पैटर्न से बिल्कुल अलग है। ध्यान देने की बात है कि दैनिक जागरण ने दो जनवरी को खबर दी थी कि ईडी पीएफआइ के खातों को खंगालने में जुटी है।

उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, ईडी ने दो भागों में अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी है। एक भाग चार दिसंबर, 2019, जिस दिन नागरिकता संशोधन विधेयक संसद में पेश हुआ था, से लेकर छह जनवरी, 2020 के बीच पीएफआइ व उसके सहयोगी संगठनों के खातों में हुए लेन-देन को लेकर है। वहीं दूसरे भाग में पिछले कई सालों के दौरान पीएफआइ व उसके सहयोगी संगठनों व व्यक्तियों के खातों में हुए लेन-देन का ब्योरा है। पीएफआइ के खाते से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल को 77 लाख, इंदिरा जयसिंह को चार लाख और दुष्यंत दवे को 11 लाख रुपये दिये जाने के साथ-साथ एनआइए द्वारा आरोपित अब्दुल समद को 3.10 लाख रुपये व न्यू जोशी ग्रुप को एक करोड़ 17 लाख रुपये दिये जाने का जिक्र है। इसमें पीएफआइ कश्मीर को भी एक करोड़ 65 लाख रुपये दिए जाने का जिक्र है।

सिब्बल और इंदिरा जयसिंह की सफाई : पीएफआइ और कपिल सिब्बल दोनों ने साफ कर दिया है कि ये पैसे हदिया केस के सिलसिले में फीस के रूप में दिए गए थे और इसका सीएए के खिलाफ ताजा विरोध प्रदर्शनों से कोई लेना-देना नहीं है। वहीं इंदिरा जयसिंह ने पीएफआइ से किसी तरह से धन लेने से साफ इन्कार किया है। पीएफआइ ने भी ईडी के आरोपों को गलत बताया है। यह भी कहा है कि पीएफआइ कश्मीर नाम की उसकी कोई इकाई नहीं है।

पीएफआइ के खिलाफ मनी लांड्रिंग की चल रही जांच : एनआइए के केस के बाद ईडी ने पीएफआइ के खिलाफ मनी लांड्रिंग की जांच शुरू की थी। उसके व सहयोगी संगठनों के 73 बैंक खातों में 120 करोड़ रुपये जमा कराये गए थे और एक-दो दिन के भीतर ही उससे अधिकांश रकम को निकाल भी लिया गया।

पीएफआइ के खिलाफ सक्रिय हुई जांच एजेंसियां, लगाया जा सकता है प्रतिबंध

नीलू रंजन, नई दिल्ली

नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के पीछे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआइ) के हाथ होने के सबूत मिलने के बाद केंद्रीय एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीएफआइ के खिलाफ पहले ही चार सौ बैंक खातों की जांच शुरू कर दी है, जो आरोप हैं कि जांच के दायरे में आ गए हैं। इसके बाद ईडी ने पीएफआइ को मिलने वाली फंडिंग की जांच शुरू कर दी थी। हिंसक विरोध प्रदर्शनों में पीएफआइ का हाथ सामने आने के बाद ईडी ने जांच तेज कर दी है। उसने सभी बैंकों से पीएफआइ के खातों की विस्तृत जानकारी देने को कहा है।

एजेंसियों का अनुमान है कि पीएफआइ और उसके अनुषंगिक संगठनों से जुड़े खातों में 100 करोड़ रुपये से अधिक जमा हो सकते हैं। बताया जाता है कि अकेले पीएफआइ के दायरे में लगभग तीन दर्जन बैंक खाते हैं। यह भी बताया जा रहा है कि इन बैंकों में 20 हजार से लेकर एक लाख तक की नकदी वाले पैसे पर जमा कराई गई है। इसके साथ ही विदेश से भी पैसा आने का शक है। अधिकारी अब उन व्यक्तियों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं जो जांच शुरू की थी। हिंसक विरोध प्रदर्शनों में पीएफआइ का हाथ सामने आने के बाद ईडी ने जांच तेज कर दी है। उसने सभी बैंकों से पीएफआइ के खातों की विस्तृत जानकारी देने को कहा है।

दो जनवरी को दैनिक जागरण में प्रकाशित खबर

एक बैंक खाते से एक दिन में कई बार हुई निकासी

एक बैंक एकाउंट से एक दिन में कई-कई बार पैसे निकाले गए। उदाहरण के तौर पर 12 दिसंबर को एक खाते से कुल 90 बार निकासी की गई थी। निकासी के पैटर्न से साफ है कि हिंसक विरोध प्रदर्शन के दिन या उससे एक दिन पहले बड़ी मात्रा में निकासी की गई है। ईडी के अनुसार इसमें कोई संदेह नहीं है कि छह जनवरी तक सीएए के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों के लिए पीएफआइ ने धन की व्यवस्था की थी। छह जनवरी के बाद की जांच अभी जारी है।

दिल्ली-पश्चिमी उप्र के खातों में आई मोटी रकम

ईडी के मुताबिक, पीएफआइ के नेहरू प्लेस(दिल्ली) स्थित खाते के साथ ही पश्चिम उत्तर प्रदेश के बहराइच, बिजनौर, हापुड़, शामली, डासना जैसी जगहों के खातों में भारी मात्रा में बार-बार नकदी जमा की गई। इसकी पड़ताल हो रही है। तमिलनाडु में पंजीकृत जोशी ग्रुप और पीएफआइ के बीच हुए लेन-देने की जांच की जा रही है। यह ग्रुप प्लास्टिक बैग के क्षेत्र में काम करता है। इसी तरह रिहैब इंडिया फाउंडेशन के खाते में दुबई की पीएमए इंटरनेशनल से आए 20 लाख रुपये की भी जांच की रही है कि आखिर ये पैसे किस लिए दिए गए थे।

थानल फाउंडेशन करता है मदद

खुफिया रिपोर्टों में बताया गया है कि पीएफआइ को थानल फाउंडेशन से सक्रिय सहयोग मिलता है। थानल फाउंडेशन पीएफआइ के एक नेता द्वारा चलाया जा रहा एक धार्मिक व धर्मार्थ ट्रस्ट है। जाहिर है थानल फाउंडेशन के वित्तीय स्रोतों की जांच भी शुरू हो गई है।

पहचान छिपाने को जमा कराई छोटी रकम

सूत्रों के अनुसार, ईडी ने चार दिसंबर से छह जनवरी के बीच 15 खातों में हुए लेन-देन की जांच की, जिसमें 10 खाते पीएफआइ और पांच उसके सहयोगी संगठन रिहैब इंडिया फाउंडेशन के थे। इन 15 खातों में 1.04 करोड़ रुपये जमा कराये गए थे। जमाकर्ता की पहचान छिपाने के लिए पांच हजार से 49 हजार रुपये के बीच जमा कराए गए। 50 हजार से कम की नकदी जमा करने पर पहचान बताने की जरूरत नहीं पड़ती। ये जमा या तो नकद किए गए या मोबाइल के माध्यम से आइएमपीएस के जरिए ट्रांसफर किए गए। सभी खातों में जिस तरह से पैसे जमा कराए गए थे उसी तरह से नकद या मोबाइल से एनईएफटी और आइएमपीएस के माध्यम से निकाले भी गए। ईडी की रिपोर्ट के अनुसार, इस दौरान एक करोड़ 34 लाख रुपये निकाले गए। मजेदार बात यह है कि अधिकांश निकासी दो हजार रुपये से पांच हजार रुपये तक की गई।

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

मुसलमानों को उनके समाज के लोग ही डरा रहे : भागवत

गोरखपुर : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का मानना है कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर मुसलमानों को उनके समाज के लोग ही डरा रहे हैं। कानून के प्रारूप पर भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। इस डर और भ्रम को दूर करने के लिए मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध लोगों को ही आगे आना होगा।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 5

यूरोपीय संसद में सीएए प्रस्ताव पर भारत ने जताया एतराज

नई दिल्ली : यूरोपीय संसद में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पर भारत ने एतराज जताया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यूरोपीय संसद के अध्यक्ष डेविड मारिया सासोली को लिखे पत्र में कहा है कि एक विधान मंडल का दूसरे विधान मंडल पर फैसला देना अनुचित है।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 12

अर्बन को-ऑपरेटिव बैंकों में पांच वर्षों में 220 करोड़ का खेल

नई दिल्ली : अर्बन को-ऑपरेटिव बैंकों (यूसीबी) में गत पांच वर्षों में 220 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी हुई। सूचना के अधिकार कानून के तहत पूछे गए सवाल में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने यह जानकारी दी है। वर्तमान में देशभर में 1,544 अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक हैं।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 13

वुहान में फंसे भारतीयों को निकालने की तैयारी

नई दिल्ली : चीन में कोरोना वायरस की चपेट में आकर मरने वालों की संख्या 81 हो गई है। सरकार ने वायरस के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए लूनर ईयर की छुट्टियां दो फरवरी तक बढ़ा दी हैं। वहीं, भारत सरकार ने चीन के हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान में फंसे भारतीयों को निकालने की तैयारी कर ली है। इसके लिए एयर इंडिया का विमान तैयार रखा गया है।

एयर इंडिया का कॉकपिट छोड़ने को सरकार राजी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ 100 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के लिए सरकार ने 17 मार्च तक मंगाए ईओआइ

▶ एयर इंडिया एक्सप्रेस व एआइसैट्स की हिस्सेदारियां भी बेची जाएंगी

सरकार ने चालू वित्त वर्ष में विमानन कंपनी एयर इंडिया के विनिवेश होने या नहीं होने संबंधी सभी कयासों को खत्म कर दिया है। कंपनी के रणनीतिक विनिवेश के लिए इच्छुक खरीदारों से सरकार ने 17 मार्च तक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआइ) निविदाएं मांगी हैं। चालू वित्त वर्ष के अंत यानी 31 मार्च तक योग्य कंपनियों का चयन कर लिया जाएगा।

कंपनी के विनिवेश की पिछली विफलता से सबक लेते हुए सरकार ने इस बार 100 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने और प्रबंधन की कमान पूरी तरह संभावित खरीदार के हाथों सौंपने की घोषणा की है। इतना ही नहीं, एयर इंडिया की पूरी तरह लाभ में चल रही बजट एयरलाइंस एयर इंडिया एक्सप्रेस में भी सरकार 100 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी। इसके साथ ही सरकार ने संभावित खरीदारों के लिए पात्रता संबंधी शर्तों में भी पिछली बार के मुकाबले कई तरह की ढील दी है।

नागरिक विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि रणनीतिक विनिवेश के तहत एयर इंडिया अपनी लो कॉस्ट सब्सिडियरी एयर इंडिया एक्सप्रेस की शत-प्रतिशत तथा एआइसैट्स में अपनी 50 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी। एआइसैट्स एयर इंडिया और सिंगापुर एयरलाइंस की संयुक्त उद्यम कंपनी है। एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज, एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, एयर इंडिया अलाइड सर्विसेज तथा होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में भी एयर इंडिया की हिस्सेदारी है। इन सभी इकाइयों को स्पेशल परपस व्हीकल (एसपीवी) एयर इंडिया असेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआइएएचएल) में हस्तांतरित किया जाएगा।

प्रतीकात्मक फोटो

दो वर्ष के भीतर यह दूसरा मौका है जब सरकार ने एयर इंडिया की बिक्री की कोशिश शुरू की है। एयर इंडिया के सीएमडी अश्वनी लोहानी ने कहा कि एयर इंडिया की बिक्री में कर्मचारियों का कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। क्योंकि अब एयर इंडिया में कोई अतिरिक्त कर्मचारी नहीं है। सभी कर्मचारी प्रशिक्षित और अनुभवी हैं। इन्हें पेंशन देने की भी कोई झंझट नहीं है। केवल सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ देने का मसला बचा है। लेकिन उसे भी शीघ्र ही हल किया जाएगा। इस समय एयर इंडिया में 16,077 कर्मचारी हैं।

टीके पांडेय बोले, कर्मचारियों को ईसॉप के तहत मिलेंगे शेयर पेज>>12

कर्मचारियों का बकाया भुगतान पहले किया जाएगा : हरदीपुरी पेज>>12

पाक में शादी के मंडप से अगवा की गई हिंदू दुल्हन

▶ जबरन धर्मांतरण के बाद मुस्लिम युवक से कराई गई शादी

कराची, एएनआइ : पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू युवतियों के अपहरण और जबरन धर्मांतरण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। इस बार एक हिंदू दुल्हन को शादी के मंडप से अगवा कर लिया गया। इसके बाद उसे जबरन इस्लाम धर्म कुबूल कराया गया और एक मुस्लिम पुरुष से उसकी शादी करा दी गई।

मीडिया में आई खबरों के अनुसार, यह घटना सिंध प्रांत के मटियारी जिले के हाला शहर की है। बीते शनिवार को भारती बाई नामक हिंदू युवती को कुछ लोग उस समय घर से अगवा कर ले गए, जब उसकी शादी की रस्में निभाई जा रही थीं। अपहरण के बाद शाहरुख गुल नामक मुस्लिम व्यक्ति से भारती की शादी करा दी गई। पुलिस ने शिकायत के बावजूद अपहर्ताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उलटे उन लोगों की मदद की, जो हिंदू दुल्हन को अगवा कर ले गए थे।

हिंदुओं पर बढ़ता जा रहा अत्याचार : पाकिस्तान में हाल के महीनों में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार के कई मामले सामने आए हैं। 15 जनवरी को नाबालिग महक कुमारी (15) को अगवा कर लिया गया था। जबरन धर्मांतरण के बाद महक की शादी एक मुस्लिम से करा दी गई थी। इसी तरह अगस्त में जगजीत कौर (19) की भी एक मुस्लिम पुरुष से शादी कराई गई थी। बंदूक के बल पर जगजीत का धर्मांतरण कराया गया था।

हर साल करीब 1000 हिंदू लड़कियां की जाती हैं अगवा

अमेरिका स्थित सिंधी फाउंडेशन के अनुसार, पाकिस्तान में हर साल 12 से 28 साल की उम्र की करीब एक हजार सिंधी हिंदू लड़कियों को अगवा कर लिया जाता है। इसके बाद जबरन धर्मांतरण कर उनका मुस्लिमों से निकाह करा दिया जाता है। मुल्क में मुख्य रूप से हिंदू, सिख और ईसाई जैसे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जाता है।

पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मंदिर पर हमला, तोड़फोड़ भी की पेज>>13

अमेरिकी विमान दुर्घटनाग्रस्त तालिबान ने कहा, हमने मारा

काबुल, एजेंसियां : अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वतों की तलहटी में बसे तालिबान के कब्जे वाले गजनी प्रांत में एक अमेरिकी सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। तालिबान का दावा है कि उसने ही विमान को मार गिराया है। प्रांतीय गवर्नर के प्रवक्ता आरिफ नूरी ने बताया कि दे यक जिले में दोपहर 1.10 बजे एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सोशल मीडिया में आई मलबे की तस्वीरों और वीडियो से इसके बॉम्बार्डियर ई-11 विमान होने का पता चला। अमेरिकी अफसरों ने कहा, उसका छोटा सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है जिसमें 10 से भी कम लोग सवार थे। वहीं, तालिबानी प्रवक्ता ने कहा, विमान खुफिया मिशन पर था, जिसे मार गिराया गया। अमेरिका व अफगान अधिकारियों ने इस बात का खंडन किया है।

अखंड रहेगा असम, पांच दशक पुराने बोडोलैंड विवाद का अंत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

असम की पांच दशक पुरानी बोडो समस्या का अंत हो गया है। बोडो के चार अलगाववादी गुटों समेत नौ संगठनों ने असम और केंद्र सरकार के साथ समझौता कर अलग राज्य की मांग छोड़ दी है। इससे असम की अखंडता बरकरार रहेगी। समझौते पर हस्ताक्षर के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, इससे असम में शांति के स्वर्णिम युग की शुरुआत होगी। यह पीएम नरेंद्र मोदी के पूर्वोत्तर में स्थायी शांति बहाल करने के प्रयासों की एक कड़ी है।

त्रिपक्षीय समझौते पर दस्तखत के बाद सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे असम में शांति, सद्भाव और एकजुटता की नई सुबह होगी। भारत के लिए आज का दिन बहुत खास है।

1972 में अलग राज्य की मांग को लेकर शुरू हुए हिंसक आंदोलन को समाप्त करने की कोशिशें पहले भी हुई थीं। 1993 और 2003 में समझौते किए गए थे। इस समझौते को अलग बताते हुए शाह ने कहा, पहले कभी सभी गुट समझौते की मेज पर साथ नहीं आए थे, लेकिन इस बार सभी पक्ष समझौते में शामिल हैं। अलगाववादी गुटों के सभी कैडर 30 जनवरी को आत्मसमर्पण कर देंगे। उनके पुनर्वास की जिम्मेदारी सरकार लेगी। बोडो की सांस्कृतिक पहचान बचाए रखने को बोडो भाषा को असम की दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा मिलेगा।

अमित शाह की उपस्थिति में समझौते पर एनडीएफबी, एबीएसयू और यूबीपीओ धड़े के चार वरिष्ठ अलगाववादियों, गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव सत्येंद्र गर्ग और असम के मुख्य सचिव कुमार संजय कृष्णा ने दस्तखत किए। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी बतौर गवाह दस्तखत किए।

नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह (बीच में) सोमवार को भारत सरकार-असम व बोडो प्रतिनिधियों के बीच ऐतिहासिक समझौते के बाद। शाह के दाएं हैं असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल व प्रदेश के वित्त मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा। प्रेट्र

केंद्र व राज्य 1500 करोड़ खर्च करेंगे पेज>>3

जेवर में भू-अधिग्रहण करने पहुंची टीम पर किसानों का हमला

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

▶ पथराव में एसडीएम समेत छह लोग घायल, भीड़ ने कई वाहनों को भी किया क्षतिग्रस्त

जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जमीन का अधिग्रहण करने सोमवार को रोही गांव पहुंची जिला प्रशासन और यमुना प्राधिकरण की टीम पर किसानों ने पथराव कर दिया, जिसमें एसडीएम जेवर समेत छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। किसानों ने कई वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। हंगामे के बावजूद प्रशासन ने जमीन कब्जे में लेकर प्राधिकरण को सौंप दी।

जिला प्रशासन और यमुना प्राधिकरण की टीम सोमवार सुबह 11 बजे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शेष जमीन का कब्जा लेने रोही गांव पहुंची। जेवर एयरपोर्ट किसान संघर्ष समिति के बैनर तले कुछ किसान अधिग्रहण का विरोध कर रहे थे। इसके मद्देनजर एसडीएम गुंजा सिंह पुलिस बल के साथ पहुंची थीं। उन्होंने किसानों से बातचीत की और उन्हें धरना खत्म करने को कहा, लेकिन किसानों ने शोषण का आरोप लगाते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। मौके पर मौजूद कुछ लोग काले झंडे लहराने लगे।

सहायक पुलिस आयुक्त शरद चंद शर्मा के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों ने हंगामा कर रहे लोगों को हिरासत में ले लिया और निजी बस में बैठाना शुरू कर दिया। इससे भड़के लोगों ने पथराव कर दिया, जिसमें एसडीएम गुंजा सिंह, उपनिरीक्षक सीपी शर्मा, कांस्टेबल अर्जुन सिंह,राशिद समेत छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, उन्हें जेवर के कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुंजा सिंह के दाएं हाथ में फ्रैक्चर हुआ है जबकि अर्जुन आइसीयू में भर्ती हैं। बाद में जिलाधिकारी अतिरिक्त फोर्स के साथ गांव पहुंचे और प्राधिकरण के अधिकारियों को कब्जा दिलाया।

दुखद

हेलीकॉप्टर हादसे में अमेरिकी दिग्गज बास्केटबॉल खिलाड़ी कोबे ब्रायंट सहित नौ की मौत, ब्रायंट पांच बार एनबीए चैंपियन और 18 बार ऑल स्टार चुने गए थे, 2008 व 2012 में ब्रायंट की अगुआई में ही अमेरिकी टीम ने जीता था ओलंपिक स्वर्ण

शानदार विरासत छोड़ गए एनबीए लीजेंड कोबे

लास एंजिलिस, एएफपी : बास्केटबॉल कोर्ट पर जिनके एक-एक कदम से दुनिया हिलती थी। जब वह बास्केट में गेंद डालने के लिए उछलते थे तो लोगों की सांसें थम जाती थीं। भले ही वह भारत नहीं आए लेकिन यहां भी उनके लाखों प्रशंसक थे। रविवार सुबह (अमेरिकी समयानुसार) जब बास्केटबॉल के अमेरिकी लीजेंड कोबे ब्रायंट के हेलीकॉप्टर के कैलीफोर्निया के कैलाबसास में दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर आई तो डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा, सचिन तेंदुलकर व क्रिस्टियानो रोनाल्डो तक गमगीन हो गए।

अमेरिका की नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन (एनबीए) लीग के 41 वर्षीय दिग्गज ब्रायंट और उनकी 13 वर्षीय बेटी गियाना समेत नौ लोग सिकोर्सकी एस-76 चॉपर में सवार थे। लास एंजिलिस अथॉरिटी के अनुसार, ब्रायंट के निजी हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोगों का निधन हो गया। वह थाउसंड ऑक शहर जा रहे थे जहां उन्हें बेटी की टीम को कोचिंग देनी थी। रविवार को धुंध बहुत थी और यह हादसे की बड़ी वजह हो सकती है। जांच चल रही है।

23 साल की उम्र में उपलब्धि : कोबे बीन ब्रायंट पूर्व एनबीए खिलाड़ी जो 'जेलीबीन' ब्रायंट के बेटे थे। 23 अगस्त 1978 को फिलाडेल्फिया में जन्मे ब्रायंट ने शाकिल ओ नील के साथ मिलकर एनबीए टीम लास एंजिलिस लेकर्स को 2000, 2001 और 2002 में एनबीए खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। वह 23 साल की उम्र में तीन खिताब जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने। ओ नील ने ब्रायंट से झगड़े के कारण लेकर्स को छोड़ दिया। इससे ब्रायंट का खेल भी प्रभावित हुआ और स्पेन के पाउ गैसोल के लेकर्स में आने तक उनकी टीम कोई खिताब नहीं जीत पाई। ब्रायंट की अगुआई में लेकर्स ने 2009 और 2010 में भी खिताब जीते।

नहीं भुलाया जा सकता प्रदर्शन : 22 जनवरी 2006 को टोरंटो रैप्टर्स के खिलाफ उनके प्रदर्शन को कोई नहीं भुला सकता, जब उन्होंने 81 अंक बनाए। उनसे अधिक अंक एक मैच में विल्ट चैंबरलेन (100 अंक) ने 1962 में बनाए थे। 20 साल तक लेकर्स के लिए खेलने वाले ब्रायंट ने 2016 में एनबीए के अपने अंतिम मैच में उताह के खिलाफ भी 60 अंक बनाए थे। ब्रायंट को 2008 में एनबीए का सबसे उपयोगी खिलाड़ी चुना गया था। उन्होंने बच्चों के लिए किताबें लिखीं। 'डियर बॉस्केटबॉल' फिल्म की स्क्रिप्ट भी उन्होंने ही लिखी थी जिसे ऑस्कर मिला था।

बेटी गियाना के साथ कोबे ब्रायंट। फाइल फोटो

ब्रायंट हमेशा बास्केटबॉल के एक दिग्गज खिलाड़ी रहेंगे। वह अपने परिवार से बहुत प्यार करते थे। उनके परिवार ने ब्रायंट के साथ बेटी गियाना को भी खो दिया। यह पल बहुत डरावना है।

– डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति, अमेरिका

कोबे ब्रायंट, उनकी बेटी गियाना और हेलीकॉप्टर में सवार अन्य लोगों की मौत से दुखी हूं। उनके परिवार, मित्रों और दुनियाभर के प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं।

– सचिन तेंदुलकर, क्रिकेटर, भारत

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION
ऑनलाइन कक्षाएं भी उपलब्ध

फाउंडेशन कोर्स
सामान्य अध्ययन 2021
DELHI 18 Feb | 5 PM

इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम के घटक
- प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
- मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
- निबंध लेखन - शैली, PT 365, Mains 365, सीसैट कक्षाएं
- मुख्य परीक्षा, निबंध, PT, सीसैट टेस्ट सीरीज

ऑल इंडिया GS प्रारंभिक
ओपन मॉक टेस्ट-2 (ऑफलाइन)
Also available in English
9 Feb | 11 cities
Ahmedabad | Bengaluru | Bhopal | Chandigarh | Delhi
Guwahati | Hyderabad | Jaipur | Jodhpur | Lucknow | Pune
पंजीकरण करें
www.visionias.in/opentest

व्यक्तित्व परीक्षण कार्यक्रम
- Vision IAS के वरिष्ठ संकाय सदस्यों के साथ DAF विश्लेषण सेशन
- पूर्व-प्रशासनिक अधिकारियों/शिक्षाविदों के साथ मॉक इंटरव्यू सेशन
- विगत वर्षों के टॉपर्स तथा वर्तमान प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संवाद

DELHI
• 635, Opp. Signature View Apartments, Banda Bahadur Marg, Mukherjee Nagar
• 2nd Floor, Apsara Arcade, Near Metro Gate 6,1/8 B, Pusa Road, Karol Bagh
• Contact : 8468022022, 9019066066

JAIPUR 9001949244 | PUNE 8007500096 | HYDERABAD 9000104133 | AHMEDABAD 9909447040 | LUCKNOW 8468022022 | CHANDIGARH 8468022022

55 नए मामले दर्ज किए गए हैं चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के। अब तक 402 मामले दर्ज हुए हैं। ये मामले चुनाव प्रचार के लिए बैनर-पोस्टर लगाकर संपत्तियों को बदरंग करने के आरोप में दर्ज हुए हैं।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
मंगलवार 28 जनवरी 2020

तीखा प्रहार ▸ केंद्रीय गृह मंत्री ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर केजरीवाल पर साधा निशाना

'मुख्यमंत्री बताएं शाहीन बाग के साथ हैं या खिलाफ'

शाह बोले, देश के टुकड़े की बात जो भी करेगा जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा

जागरण टीम, नई दिल्ली

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल बताएं कि वह शाहीन बाग के साथ हैं या खिलाफ। उन्होंने सीएम पर हमला बोलते हुए कहा कि केजरीवाल कहते हैं कि भाजपा के कहने पर वहां रास्ता नहीं खोला जा रहा है, जबकि उन्होंने पहले ही कहा था कि वह सीएए का समर्थन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें शहीन बाग जाना चाहिए और प्रदर्शन कर रहे लोगों को रास्ता खोलने के लिए कहना चाहिए।

शाह ने कहा कि टुकड़े-टुकड़े गैंग के खिलाफ कार्रवाई की जब भी बात आती है तो मुख्यमंत्री इसे बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार बताते हैं। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि अगर मुझसे किसी को परेशानी है तो वह मेरे बारे में बोले। अगर इससे भी पेट नहीं भरा तो मेरी पार्टी के बारे में बोले, लेकिन भारत माता के टुकड़े की बात जो भी करेगा उसे जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। गृहमंत्री सोमवार को बाहरी दिल्ली के रिठाला और पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी क्षेत्र में प्रत्याशियों के समर्थन में सभाओं को संबोधित कर रहे थे।

जनकपुरी में गृह मंत्री ने कहा कि पिछले दिनों शरजील नाम के एक व्यक्ति का वीडियो वायरल हुआ है। वह असम को अलग करने की बात करता है। उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। केजरीवाल से मैं पूछना चाहता हूं कि वह कब भारत के टुकड़े करने के नारे लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति देंगे। पिछले काफी समय से इसका इंतजार किया जा रहा है। लेकिन, अभी तक उनकी ओर से कोई पहल नहीं हुई हैं। मनीष सिसोदिया कहते हैं कि वह शाहीन बाग के साथ हैं। 1947 में जो हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, इसाई भाई हमारे देश में आए, उन्हें केजरीवाल पाकिस्तानी कहते हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि भाजपा की सरकार पाकिस्तानियों की चिंता करती है। मैं केजरीवाल को साफ बताना चाहता हूं कि वे पाकिस्तानी नहीं हैं। वे हमारे भाई हैं और इन्हें केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने नागरिकता देने का कार्य किया है। उनको नागरिकता देना हमारा फर्ज है।

गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा वोट बैंक की राजनीति नहीं करती है। लोकसभा व राज्यसभा में भाजपा बहुमत में आई तो वर्षों से चल रहे मसले को हल किया गया। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 35ए व 370 हटाया गया। जम्मू-कश्मीर अब भारत का अभिन्न अंग बना है। राम मंदिर पर पांच जजों की पीठ ने फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में चार माह के अंदर आसमान को छूने वाला भव्य मंदिर बनाया जाएगा। जनसभा के दौरान जनकपुरी से भाजपा के प्रत्याशी आशीष सूद, सांसद प्रवेश वर्मा, जबकि रिठाला में पार्टी प्रत्याशी मनीष चौधरी मौजूद रहे।

रिठाला में आयोजित जनसभा को संबोधित करते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। साथ में खड़े हैं रिठाला विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी मनीष चौधरी। आकाश दत्त शर्मा

विश्व में सबसे अच्छी राजधानी बनाएंगे दिल्ली को : गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से कहा कि इस बार आप लोग भाजपा की सरकार बनाइए। अगले पांच वर्षों में दिल्ली को विश्व में सबसे अच्छी राजधानी बना देंगे।

दस वर्ष पीछे चली गई राजधानी : अमित शाह ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार के कारण राजधानी विकास कार्यों में दस वर्ष पीछे चली गई। न तो नए स्कूल का निर्माण हुआ और न ही नए कॉलेज बनाए गए। उन्होंने कहा कि सांसद प्रवेश वर्मा ने कई स्कूलों का दौरा किया। मटियाला में एक स्कूल के भवन को खतरनाक घोषित कर दिया गया है। उसके बाद भी बच्चे में उसमें पढ़ रहे हैं। यह कैसी व्यवस्था है।

अब मोदी दिल्ली को बदलने का काम करेंगे : शाह ने कहा कि मोदी देश में सीएए लेकर आए तो ाहुल बाबा एंड कंपनी इसका विरोध कर रही है। इन्हीं लोगों ने दिल्ली में दंगे करवाए, लोगों को गुमराह किया। बसें जला दीं। वहीं जब जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी हुई इस पर भाजपा सरकार ने आरोपितों पर कार्रवाई की तो केजरीवाल और राहुल बाबा एंड कंपनी ने कहा कि भाजपा बोलने के अधिकारों को हनन कर रही है। शरजील का वीडियो सभी ने देखा होगा, राहुल और केजरीवाल बताएं कि इसके लिए उन्होंने क्या किया। भाजपा ने मुकदमा दर्ज करा दिया। राहुल और केजरीवाल बताएं कि उन्होंने देश तोड़ने वालों के खिलाफ क्या किया।

भाजपा से अपील, शाहीन बाग में लोगों से बात करे : केजरीवाल

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर शाहीन बाग मसले पर गंदी राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने पार्टी दफ्तर में हुई प्रेसवार्ता में कहा कि मेरी भाजपा के सभी बड़े नेताओं से अपील है कि वे शाहीन बाग जाकर प्रदर्शन करने वालों से बात करें और रास्ता खुलवाएं। रास्ता बंद होने से लोगों को परेशानी हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मैं जानता हूं कि भाजपा 8 फरवरी के बाद ही रास्ता खुलवाएगी। भाजपा हर चीज पर राजनीति करती है।

केजरीवाल ने कहा कि मुझे बेहद दुख है कि शाहीन बाग मुद्दे पर भाजपा गंदी राजनीति कर रही है। वहां कई दिनों से रास्ता बंद है। इसकी वजह से स्कूली बच्चों को परेशानी हो रही है। एंबुलेंस को परेशानी हो रही है। 40 मिनट का रास्ता लोग ढाई-तीन घंटे में तय कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में संविधान के तहत हर व्यक्ति को विरोध-प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन इससे आम जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। शाहीन बाग में लोगों को कई दिनों से तकलीफ हो रही है। केंद्र में भाजपा की सरकार है, जिसके अंतर्गत दिल्ली की कानून व्यवस्था आती है। वह इस समस्या का समाधान क्यों नहीं कर रही है? भाजपा नेता रोज सिर्फ प्रेसवार्ता कर रहे हैं।

आरोप-प्रत्यारोप

केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह से अपील की कि आप देश के गृहमंत्री हैं। देश में कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखना आपकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। आपको शाहीन बाग जाकर लोगों से बात करनी चाहिए और उनको समझाकर रास्ता खुलवाना चाहिए। इस समय वे लोग जिद पर अड़े हुए हैं और किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की कानून व्यवस्था प्रेसवार्ता करने से नहीं सुधरेगी, काम करने से सुधरेगी। भाजपा हमसे सीखे, कैसे काम करते हैं। उनको केवल प्रेसवार्ता और गंदी राजनीति करनी आती है। केजरीवाल ने कहा कि मैं मीडिया के माध्यम से भाजपा के सभी बड़े नेताओं गृह मंत्री अमित शाह, पीयूष गोयल, रविशंकर प्रसाद से अपील करता हूं, वे शाहीन बाग जाएं। लोगों से बात करें और एक घंटे में रास्ता खुलवा दें।

साथ ही केजरीवाल ने ट्वीट किया कि शरजील ने असम को देश से अलग करने की बात कही है। यह बेहद गंभीर है। अमित शाह, आप देश के गृह मंत्री हैं। आपका धर्म है कि आप उसे तुरंत गिरफ्तार करें। उसे ऐसा कहे हुए दो दिन हो गए हैं। आप उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे। क्या मजबूरी है आपकी या अभी भी गंदी राजनीति करनी है।

चुनावी हलचल

केजरीवाल के इरादों पर झाड़ू फेरेगी दिल्ली : जदयू

पटना : दिल्ली के जदयू प्रभारी और बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने सोमवार को कहा कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव में वहां की जनता अरविंद केजरीवाल के इरादों पर झाड़ू फेर देगी। दिल्ली के 1.46 करोड़ मतदाताओं में 33.5 प्रतिशत पूर्वांचल के लोग हैं। उन्हें यह कहने में कोई संकोच नहीं कि केजरीवाल ने इस समुदाय के लोगों को बुरी तरह से ठगा है। झा ने कहा कि दिल्ली में आज भी उन इलाकों में आधारभूत संरचना की घोर कमी है जहां पूर्वांचल के लोगों की संख्या अधिक है। कहा कि उनके दल का भाजपा के साथ गठबंधन है। उनके गठबंधन ने अनधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत किया। उनकी पार्टी का मुख्य उद्देश्य इस चुनाव में एक सकारात्मक एजेंडा प्राप्त करना है। केजरीवाल की आज स्थिति यह है कि आज वह दागियों से घिरे हैं। उनके विधायकों पर पत्नी को पीटने व दुष्कर्म तक के आरोप हैं। दिल्ली के कई इलाकों का पानी पीने लायक नहीं। (जासं)

नामांकन से वंचित 11 लोगों की याचिका सुनेगा हाई कोर्ट

नई दिल्ली : नई दिल्ली विधानसभा सीट से नामांकन करने से वंचित रहे 11 लोगों की याचिका पर हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने सोमवार को कहा कि इस याचिका को मंगलवार को न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा सुनेंगे। 11 लोगों ने टोकन होने के बावजूद आवेदन नहीं लेने का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि सभी याचिकाकर्ता 20 जनवरी को सुबह ही जामनगर हाउस पहुंच गए थे। वे आवेदन फार्म और उससे संबंधित दस्तावेज लेकर गए थे, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। इसके चलते सभी को टोकन दिए गए, लेकिन शाम तक भी उनका नंबर नहीं आया। इसके बाद रिटर्निंग अफसर ने कहा कि कल आना और उनके टोकन सबसे पहले मंजूर किए जाएंगे। जब अगले दिन आवेदन करने गए तो टोकन के बजाय उनका नाम सूचीबद्ध किया गया था। इसके बाद वहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आवेदन करने आ गए। देर शाम होने के बाद रिटर्निंग अफसर ने उनका आवेदन नहीं लिया। इसके चलते वह लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा नहीं ले सके। (जासं)

प्रत्याशी के साथ नहीं, पार्षद वार्ड में संभालेंगे मोर्चा

निहाल सिंह, नई दिल्ली

दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने पार्षदों का सदुपयोग करने के लिए नई चुनावी रणनीति तैयार की है। इसके तहत भाजपा पार्षद अपना वार्ड नहीं छोड़ सकेंगे। इतना ही नहीं, प्रत्याशी के आगे-पीछे घूमने की बजाय उन्हें अपने ही क्षेत्र में प्रत्याशी का प्रचार करना होगा। वार्ड के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उन्हें डोर टू डोर कैंपेन चलाना होगा। साथ ही निगम की उपलब्धियां बताते हुए क्षेत्र में भाजपा के पक्ष में माहौल तैयार करना होगा।

दरअसल, देखने में आ रहा था कि कुछ पार्षद अपने क्षेत्र के अलावा दूसरे क्षेत्रों में जाकर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के साथ दूसरे वार्ड में प्रचार कर रहे थे। इससे दूसरे पार्षदों को और संगठन को दिक्कत हो रही थी। इसे देखते हुए भाजपा ने सभी पार्षदों से कहा है कि उन्हें अपने-अपने क्षेत्र में ही ज्यादा से ज्यादा समय देना है। अगर प्रत्याशी को प्रचार में उनके वार्ड से कोई मदद चाहिए तो वह मदद भी उपलब्ध करानी है बाकि पूरे समय प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करना है। हालांकि संगठनात्मक बैठकों में अगर पार्षद आपेक्षित हैं तो तब ही क्षेत्र से बाहर जाने की अनुमति होगी। उल्लेखनीय है कि भाजपा यह भी संदेश देना चाहती है कि दिल्ली में अगर ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो इसका फायदा दिल्ली को ही होगा क्योंकि निगम के साथ दिल्ली और केंद्र सरकार से एक साथ वे सारे कार्य हो सकेंगे, जिनसे जनता को लाभ मिले। इस चुनाव में भाजपा केंद्र सरकार की योजनाओं को दिल्ली की केजरीवाल सरकार द्वारा लागू न करने का भी मुद्दा बना रही है। पार्षदों को भी इसी मुद्दे को लेकर लोगों के साथ संवाद करने के निर्देश दिए गए हैं।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष व भाजपा के पार्षद भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि सभी पार्षद अपने-अपने वार्ड में अच्छा कार्य चुनाव प्रचार में करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच पाएंगे। इसके तहत हम सभी पार्षद अपने-अपने क्षेत्र में प्रचार में जुटे हुए हैं।

पार्टियों की रणनीति

▸ घर-घर जाकर निगम और केंद्र सरकार के काम गिनाने का मिला आदेश

नड्डा बोले, भाजपा के लिए देश पहले

जासं, नई दिल्ली : मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र स्थित रमेश नगर में आयोजित जनसभा में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस व आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस व आम आदमी पार्टी को देश से पहले अपने वोट बैंक की चिंता रहती है, लेकिन भाजपा के लिए देश प्राथमिकता में है। वे मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुभाष सचदेवा के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। नड्डा ने कहा कि मोतीनगर से उनका गहरा लगाव है। चुनाव के समय में कई लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लुभावने वादे किए जाते हैं। लोग इन लुभावने वादों से भ्रमित भी हो जाते हैं। कई मौकों पर लोग मुझसे भी यह पूछते हैं कि किस आधार पर हम तय करें कि कौन सा वादा भविष्य में पूरा होगा। मैं उन्हें साफ साफ समझाता हूं कि वादा करने वाले व्यक्ति द्वारा अतीत में किए गए कार्यों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके वादे कितने हकीकत में तब्दील होंगे।

केजरीवाल आएंगे 'आपके द्वार', करिए मोबाइल से मिस्ड कॉल

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ मुख्यमंत्री ने सोमवार को 'केजरीवाल आप के द्वार' कार्यक्रम को किया लांच

नमस्कार! मैं अरविंद केजरीवाल, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आप बिजी तो नहीं हैं? थैंकयू, आपने अपने घर बुलाकर बात करने का मौका दिया। कुछ इसी अंदाज में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मोबाइल पर संवाद करके जनता के सवालों के जवाब देंगे। मुख्यमंत्री ने सोमवार को 'केजरीवाल आप के द्वार' कार्यक्रम को लांच किया है। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से 7690944444 पर मिस्ड कॉल करके केजरीवाल से बात की जा सकेगी।

पार्टी कार्यालय में इस कार्यक्रम को शुरू करते हुए केजरीवाल ने कहा कि वह दिल्ली के 50 लाख परिवारों के घर जाकर सीधी बात करना चाहते थे ताकि उन्हें रिपोर्ट कार्ड देकर पांच साल की सरकार के कार्यों को बता सकें। यह फिजिकली संभव नहीं था। इसलिए टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ा है। राजधानी के दो करोड़ लोगों ने जो प्यार दिया है, उसके लिए खुद को भाग्यशाली मानते हैं। वह भी जनता से उतना ही प्यार करते हैं इसलिए सीधी बात करना चाहते थे। अब इस तकनीक की मदद से खुद फोन के जरिये एक-एक घर ही नहीं, बल्कि एक-एक व्यक्ति तक पहुंच कर बात करूंगा।

बात करने के लिए ये करना होगा : 7690944444 नंबर पर मिस्ड कॉल करते ही मोबाइल पर एक मैसेज मिलेगा, जिसमें दिए गए लिंक पर क्लिक करते ही एक कॉल आएगी। इसमें केजरीवाल दरवाजे की डोर बेल बजा रहे होंगे। इसके बाद आपके घर में आकर बात करेंगे। मोबाइल स्क्रीन पर बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, महिला सुरक्षा व कच्ची कॉलोनी का विकल्प आएगा। दिल्लीवासी किसी भी विकल्प को चुन कर मुख्यमंत्री से सीधे बात कर सकेंगे और अपना फीडबैक दे सकेंगे।

ट्विटर वार

"भाजपा की एमसीडी ने पिछले 15 वर्षों से दिल्ली के स्कूलों, अस्पतालों, गलियों का सत्यानाश कर रखा है। केजरीवाल सरकार ने सिर्फ पांच वर्षों में दिल्ली की दिशा-दशा बदल दी।
-गोपाल राय, आप

"भाई मनीष सिसोदिया, मैं फिजिक्स की वह किताब ढूंढ रहा हूं, जिसमें लिखा है कि अगर 11 बजे मोटर चलाओगे तो गंदा एवं मिट्टी वाला पानी खींचेगी और आठ बजे चलाओगे तो साफ पानी आएगा। जरा ऐसा ज्ञान कहां लिखा है, हमें भी बता दो अरविंद केजरीवाल जी?
-हरीश खुराना, भाजपा

"अब पराली नहीं जल रही है, फिर दिल्ली में प्रदूषण के यह हाल क्यों? केजरीवाल जी प्रचार में लोगों को मीठी-मीठी गोलियां देने से पहले प्रदूषण के इस हालात से निपटने के आपके पास क्या उपाय हैं? ये बताएं।
-राधिका खेरा, कांग्रेस

"कांग्रेस इस बार पूरी तैयारी और मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। आप और भाजपा ने दिल्ली के साथ जो छल किया है उसे जनता के सामने रख रही है। क्योंकि यहां विकास कार्य ठप है। जो भी विकास के काम हुए वह कांग्रेस के काल में ही हुए।
-जेपी अग्रवाल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस

नुक्कड़ नाटक से बता रहे आप सरकार की उपलब्धियां

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

प्रचार प्रपंच

दिल्ली विधानसभा चुनाव में लोगों को आकर्षित और प्रभावित करने के लिए राजनीतिक दल और प्रत्याशी विभिन्न प्रचार माध्यमों का सहारा ले रहे हैं। भीड़ जुटाने और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए नुक्कड़ नाटकों का भी आयोजन किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की योजना नुक्कड़ नाटकों के जरिये अधिक से अधिक लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की है। इसके लिए पार्टी ने 50 टीमें चुनावी रण में उतार दी हैं। ये टीमें मुख्य रूप से 'अच्छे बीते पांच साल, लगे रहो केजरीवाल' का संदेश देने वाला नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर रही हैं। इसमें आप सरकार की पांच साल की उपलब्धियों के बारे में पांच मिनट में बताया जाता है। इसे आप के कार्यकर्ता भास्कर शर्मा और उनकी बहन ने तैयार किया है। भास्कर बताते हैं कि इसमें नृत्य के माध्यम लोगों तक संदेश पहुंचाया जाता है। बाजार या अन्य भीड़-भाड़ वाले इलाके में 10 लोगों की टीम जाती है और नृत्य के माध्यम से प्रस्तुति देती है।

उन्होंने बताया कि नुक्कड़ नाटक वाली टीम का हिस्सा बनने के लिए लोग आगे आ रहे हैं। पार्टी की ओर से सोशल मीडिया पर मोबाइल नंबर पोस्ट किया गया है। इसके माध्यम से नए लोग जुड़ते हैं। उन्हें एक दिन प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्होंने बताया कि इसी तरह राजस्थान से कलाकारों की टीम आई है, जिसमें 40 लोग शामिल हैं। ये लोग राजस्थानी अंदाज में नुक्कड़ नाटक कर प्रस्तुति देते हैं। एक महिला गायक ने आप के लिए गाना लिखकर गाया भी है। इसमें पांच साल के विकास कार्यों पर प्रकाश डाला गया है। इसके बोल हैं 'झांसे में न आएंगे झाड़ू पर बटन दबाएंगे'। सोशल मीडिया पर इस गीत का वीडियो रविवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जारी किया।

बता दें कि प्रत्याशियों ने विधानसभा क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटक कराने के लिए कुछ कलाकारों को भी बुलाया है। ये कलाकार सार्वजनिक स्थानों या प्रमुख चौराहों पर जाकर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रत्याशी के हक में वोट डालने की अपील करते हैं। वे विधायक और सरकार द्वारा अब तक कराए गए विकास कार्यों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। साथ ही प्रत्याशी का जहां दौरा होता है, वहां पर ये टोलियां नुक्कड़ नाटक कर ईमानदार व कर्मठ प्रत्याशी को विजयी बनाने के लिए कहती हैं।

भाजपा और आप लुभावने वादों पर मांग रहीं वोट : चोपड़ा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने कहा कि भाजपा पिछले 13 वर्षों से दिल्ली नगर निगम में सत्तारूढ़ है और केजरीवाल पांच साल से मुख्यमंत्री हैं। इसके बावजूद दोनों पार्टियां पूर्व में किए गए कामों की बजाय भविष्य के लोक लुभावन वादे कर सत्ता पाना चाह रही हैं। दिल्ली में सातों सांसद भाजपा के हैं। फिर भी केंद्र सरकार के स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ रही हैं। नगर निगमों की कारगुजारियों का ही प्रमाण है कि आज एक केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव में गृह मंत्री को गली-गली घूमना पड़ रहा है।

चोपड़ा आंबेडकर नगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी यदुराज सिंह चौधरी, देवली विधानसभा से पार्टी उम्मीदवार अरविंदर सिंह लवली और गोकलपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार एसपी सिंह के चुनाव कार्यालयों के उद्घाटन के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। चोपड़ा ने तंज कसते हुए कहा कि इन दोनों पार्टियों के नेता एक-दूसरे की पोल खोल कर कांग्रेस की प्रासंगिकता का ही उल्लेख कर रहे है। चोपड़ा ने कहा कि सीएए के मुद्दे पर आज जिस प्रकार यूरोपीय संसद और यूएन में आलोचना हो रही है, उसने मोदी की अदूरदर्शी पूर्ण विदेश नीति की पोल खोल दी है। आज देश और दिल्ली की जनता भी इस तथ्य पर सहमत है कि सरकार कांग्रेस ही चलाना जानती है।

नेशनल कैपिटल

एयरपोर्ट पर लगाए जाएंगे 69 फुल बॉडी स्कैनर

संतोष शर्मा, नई दिल्ली

▸ मिलीमीटर वेव तकनीक पर करता है काम, मशीन का एयरपोर्ट पर चल रहा है ट्रायल

▸ एड़ी के नीचे की छवि नहीं ले पाने के कारण जांच के लिए यात्रियों को उतारने होंगे जूते

आइजीआइ एयरपोर्ट पर यात्रियों की पुख्ता सुरक्षा जांच के लिए फुल बॉडी स्कैनर का अंतिम ट्रायल चल रहा है। जर्मनी निर्मित यह स्कैनर पहले वाले से काफी संवेदनशील और बेहतर है। यह प्रतिबंधित और मादक पदार्थ की बेहतर तरीके से पहचान कर सकता है। संभावना है कि अंतिम तौर पर एयरपोर्ट पर यह मशीन स्थापित कर दी जाएगी। आइजीआइ एयरपोर्ट पर चरणबद्ध तरीके से कुल 69 फुल बॉडी स्कैनर लगाए जाएंगे। यह मिलीमीटर वेब तकनीक पर काम करता है। हालांकि यह एड़ी के नीचे की छवि लेने में सक्षम नहीं है। लिहाजा यात्रियों को जूते उतारने होंगे।

दरअसल, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (बीसीएएस) ने देश के एयरपोर्ट पर अनिवार्य रूप से बॉडी स्कैनर लगाए जाने का निर्देश जारी किया है। आइजीआइ सहित संयुक्त उद्यम वाले छह एयरपोर्ट पर बॉडी स्कैनर लगाने की समय सीमा अप्रैल 2020 तय की गई है। अन्य पर अप्रैल 2021 तक बॉडी स्कैनर लगाया जाना है। माना जा रहा है कि आइजीआइ पर इस वर्ष के पहले छमाही में बॉडी स्कैनर लगा दिया जाएगा। फिलहाल वहां एक स्कैनर का ट्रायल जारी है।

आइजीआइ एयरपोर्ट पर ट्रायल के लिए लगाया गया फुल बॉडी स्कैनर। सौजन्य : एयरपोर्ट

इससे पहले वर्ष 2017 में फुल बॉडी स्कैनर का परीक्षण एयरपोर्ट पर किया गया था। यह टेलीफोन बूथ की तरह था। इसमें यात्री को अंदर जाना होता है। बाद में सुरक्षा जांच के लिए उन्हें करीब 10 सेकंड तक स्कैन किया जाता है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में जिस बॉडी स्कैनर का ट्रायल चल रहा है, वह एक खुली संरचना वाला है। इसमें आगे और पीछे सिर्फ दो दीवारें हैं। इसमें यात्री को खुले क्षेत्र में एक विशेष आकृति में खड़ा होना होता है। इसके बाद करीब आठ सेकंड के भीतर सफलतापूर्वक जांच की प्रक्रिया पूरी हो जाती है।

उन्होंने बताया कि बंद स्कैनर में कुछ यात्रियों ने घुटन (क्लस्ट्रोफोबिक) महसूस होने की भी शिकायत की थी, लेकिन नए स्कैनर में यह समस्या नहीं है। नए स्कैनर में टोपी अथवा सिर पर पहनी गई कोई भी चीज हटानी नहीं होगी। वहीं, इसमें झूठा अलार्म भी कम बजता है।

अधिकारी ने बताया कि बॉडी स्कैनर स्थापित कर दिए जाने के बावजूद एयरपोर्ट पर लगे डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर को नहीं हटाया जाएगा। उनका उपयोग दिव्यांग यात्रियों सहित कुछ विशेष रोग से ग्रसित मरीजों के लिए किया जाएगा। सीआइएसएफ के प्रवक्ता हेमेंद्र सिंह ने कहा कि आइजीआइ पर बॉडी स्कैनर का ट्रायल प्रगति पर है।

जेएनयू के दो छात्र छात्रावास से निष्कासित

जासं, नई दिल्ली : जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के माही-मांडवी छात्रावास से दो छात्रों को निष्कासित कर दिया गया है। इन छात्रों पर 14 दिसंबर 2019 को जेएनयू के कुलपति प्रो. एम. जगदीश कुमार का घेराव करने का आरोप है। सोमवार को माही-मांडवी छात्रावास के वरिष्ठ वॉर्डन प्रो. सौम्यजीत रे ने गौतम शर्मा और मनीकांत पटेल को पत्र जारी करते हुए छात्रावास को खाली कर अपना सामान ले जाने के लिए कहा है। उन्होंने पत्र में कहा है कि दोनों ने कुलपति का घेराव किया था। इनके खिलाफ जेएनयू के चीफ प्रॉक्टर द्वारा प्रॉक्टोरियल जांच बैठाई गई है। इस जांच के परिणाम लंबित हैं, तब तक इन्हें छात्रावास से निष्कासित किया गया है। गौतम पीएचडी के स्कूल ऑफ सोशल साइंस के छात्र हैं। मनिकांत सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ रिजनल डेवलपमेंट के छात्र हैं। गौतम ने प्रशासन पर पलटवार करते हुए कहा कि वह घेराव में शामिल नहीं थे। मैंने 24 जनवरी को प्रशासन को पत्र लिखकर कहा था कि मेरा दिल्ली में कोई घर नहीं है।

यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रा. लि. के हाथ होगी जेवर एयरपोर्ट की बागडोर

अरविंद मिश्रा, ग्रेटर नोएडा

जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण एवं संचालन के लिए ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी ने स्पेशल परपज व्हीकल (एसपीवी) कंपनी का गठन कर दिया है। इसे यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड का नाम दिया गया है। ज्यूरिख एयरपोर्ट कंपनी ने सिक्योरिटी क्लीयरेंस के लिए आवेदन कर दिया है। एसपीवी कंपनी को 31 जनवरी तक सिक्योरिटी क्लीयरेंस से लिए आवेदन करना है। सिक्योरिटी क्लीयरेंस के बाद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी (नियाल) व एसपीवी कंपनी के बीच कंशेसन एग्रीमेंट होगा।

जेवर एयरपोर्ट के लिए 29 नवंबर को ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी का विकासकर्ता कंपनी के तौर पर चयन किया गया था। लेकिन एयरपोर्ट का निर्माण वह तभी शुरू कर सकती है, जब भारत में कंपनी के रूप में पंजीकृत होगी। इसे देखते हुए ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी ने जेवर एयरपोर्ट के लिए एसपीवी कंपनी बनाने का फैसला किया था।

उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही जेवर एयरपोर्ट के लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी (नियाल) का गठन कर चुकी है। ज्यूरिख एयरपोर्ट कंपनी ने 22 जनवरी को यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड नाम से एसपीवी का गठन कर दिया है। कंपनी बोर्ड में प्रदेश सरकार पहले ही नागरिक उड्डयन निदेशालय के निदेशक व नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी के सीईओ को निदेशक नियुक्त कर चुकी है।

ज्यूरिख एयरपोर्ट कंपनी ने सिक्योरिटी क्लीयरेंस के लिए आवेदन भी कर दिया है। हालांकि यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को भी सिक्योरिटी क्लीयरेंस लेना होगा। इसके लिए कंपनी को 31 जनवरी तक आवेदन करना है।

सूरमाओं का समर

नजफगढ़ विस सीट पर आप प्रत्याशी को पांच साल के विकास कार्यों और भाजपा को अनुच्छेद 370, सीएए जैसे मुद्दों का भरोसा है तो कांग्रेस प्रत्याशी मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं

हुक्के की गुड़गुड़ाहट के बीच तय होगी शह-मात

भगवान झा, नई दिल्ली

सियासत की चौसर पर शह-मात का खेल शुरू हो चुका है। पश्चिमी दिल्ली की नजफगढ़ विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पांच साल के काम और विकास को हथियार बनाकर उतरे हैं। भाजपा अनुच्छेद 370, सीएए और अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण को मोहरा बनाकर मैदान मारने की कोशिश में जुट गई है। ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाकर रोमांचक बनाने में जुटे हुए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अब जो प्रत्याशी हुक्के की गुड़गुड़ाहट के बीच चर्चा में खुद को शामिल करने में सफल होगा, वही शह-मात के इस खेल का सिकंदर बनेगा।

सियासी समर में नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र के योद्धाओं की बात करें तो पहली बार विधायक बनकर मंत्री पद तक का सफर तय करने वाले कैलाश गहलोत राजनीति की बारीकी से अवगत हैं। उन्होंने अपनी रणनीति बना ली है। बिजली-पानी के मुद्दे पर मतदाताओं को साधने की कोशिश में जुटे कैलाश गहलोत को भाजपा प्रत्याशी अजीत खड़खड़ी से कड़ी चुनौती मिल रही है। दोनों ही प्रत्याशी ग्रामीण इलाकों से हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले करीब बीस गांव के मतदाताओं का रुख किस तरफ होता है। वहीं, कांग्रेस प्रत्याशी साहब सिंह मैदान में उतरकर चुनाव को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं।

कैलाश गहलोत।

अजीत खड़खड़ी।

साहब सिंह। सभी फाइल

वर्ष 2015 के चुनाव

88 साल बाद महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को यातायात और ट्रैफिक नियंत्रित करने के लिए माउंटेड पुलिस यूनिट यानी घुड़सवारी दस्ता मिलेगा। 1932 में बढ़ते वाहनों के कारण इसे बंद कर दिया गया था।

न्यूज गैलरी

नौसेना को जल्द मिलेगा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत कवरत्ती

कोलकाता : नौसेना को पनडुब्बी रोधी युद्धपोत 'आइएनएस कवरत्ती' जल्द मिल सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम गार्डेनरीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसइ) के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक रीयर एडमिरल वीके सक्सेना ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रडार की पकड़ में नहीं आने वाले इस युद्धपोत से नौसेना की ताकत में इजाफा होगा। 'कवरत्ती' उन चार पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों की श्रेणी में से अंतिम है, जिनका निर्माण जीआरएसइ ने परियोजना 'पी28' के तहत भारतीय नौसेना के लिए किया है। इस पोत के सभी परीक्षण सफल रहे हैं और पूरे हो चुके हैं। हमारी इसे इस महीने के अंत तक सौंपने की योजना है। कवरत्ती जीआरएसइ द्वारा निर्मित 104वां पोत होगा। रक्षा सूत्रों ने बताया कि यह युद्धपोत परमाणु, रासायनिक तथा जैविक युद्ध की स्थिति में भी काम करेगा। बाकी तीन रडार रोधी और पनडुब्बी रोधी पोतों के नाम हैं-आइएनएस कमोर्ता, आइएनएस कदमत और आइएनएस किलतान। ये नाम लक्षद्वीप द्वीपसमूह के द्वीपों के नाम पर रखे गए हैं। (जासं)

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर कानून पर केंद्र से मांगा जवाब

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर (किन्नर) संरक्षण कानून 2019 की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि यह कानून ट्रांसजेंडर के स्वयं की पहचान के अधिकार को सीमित करता है। यह याचिका ट्रांसजेंडरों के हितों के लिए काम करने वाली स्वाती बिधान बरुआ ने दाखिल की है। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने सोमवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 के प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। कहा गया है कि इस कानून में ट्रांसजेंडर के स्वयं की पहचान के अधिकार का हनन होता है। यह कानून ट्रांसजेंडर को स्टेट से प्रमाणपत्र लेने की बात कहता है जो कि गलत है। किसी ट्रांसजेंडर को प्रमाणपत्र देने की प्रक्रिया में किसी गैर ट्रांसजेंडर को कैसे शामिल किया जा सकता है? इस कानून से ट्रांसजेंडर के निजता के अधिकार का भी हनन होता है। याचिका में कई अन्य सवाल भी उठाए गए हैं। (जाब्यू)

केंद्र व राज्य 1500 करोड़ रुपये खर्च करेंगे

प्रथम पृष्ठ से आगे

समझौते में सरकार ने बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद (बीटीसी) को बदलकर बोडोलैंड क्षेत्रीय एरिया नाम दिया जाएगा और उसकी शक्तियां बढ़ाई जाएंगी। यहां की सीटों का विस्तार 40 से बढ़ाकर 60 कर दिया जाएगा। असम सरकार और बोडो क्षेत्रीय एरिया के प्रशासक की अधिकारों की सूची के स्पष्ट बंटवारे का भी प्रावधान है। बोडो क्षेत्र के विकास के लिए तीन सालों में केंद्र और राज्य सरकार 1500 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसके साथ ही सरकार ने समझौते में उस इलाके में केंद्रीय विश्वविद्यालय समेत कई शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थान खोलने का वादा किया है।

50 बोडो अलगाववादी कैडर ने म्यांमार में अंतिम शिविर छोड़ा

अमित शाह ने कहा कि 1972 में शुरू हुए इस आंदोलन में चार हजार से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। अब इस ऐतिहासिक समझौते के साथ असम में स्थायी शांति स्थापित हो सकेगी। इस महीने के शुरू में लगभग 50 बोडो अलगाववादी कैडर ने म्यांमार में अंतिम शिविर को छोड़कर भारत में आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बाद पिछले हफ्ते 644 बोडो कैडर ने आत्मसमर्पण किया था। 2014 में बोडो अलगाववादियों के हाथों 71 आदिवासियों की हत्या के पांच साल बाद हुए शांति समझौते को काफी अहम माना जा रहा है।

विपक्ष को पीएम मोदी को भला-बुरा कहने वाले मुस्लिम पसंद : भाजपा

अदनान सामी : पद्मश्री मामला ▸ कांग्रेस-राकांपा ने सामी के पिता का हवाला दे फैसले पर उठाए सवाल

भाजपा ने कहा- सोनिया गांधी के पिता तो मुसोलिनी-हिटलर से जुड़े थे, फिर उन्हें क्यों दी गई नागरिकता

नई दिल्ली, एजेंसियां : पाकिस्तानी मूल के हिंदुस्तानी गायक अदनान सामी को पद्म श्री देने पर सियासी घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने जहां सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं। भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा है कि विपक्ष को वे मुस्लिम ही पसंद हैं जो प्रधानमंत्री मोदी, भारतीय सेना, सुप्रीम कोर्ट और देश के लोकतंत्र को भला-बुरा कहते हैं।

अदनान सामी को पद्म श्री पुरस्कार के लिए एकदम योग्य बताते हुए भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा, 'वे देशद्रोहियों को स्वीकार करते हैं और अच्छे मुस्लिमों को छोड़ देते हैं।' अदनान सामी को 2016 में भारत की नागरिकता दी गई थी। प्रेस कांफ्रेंस में पात्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया

संबित पात्रा फाइल फोटो

गांधी के पिता इटली के तानाशाह मुसोलिनी और जर्मनी के तानाशाह हिटलर के शासन से जुड़े थे, फिर उन्हें क्यों भारत की नागरिकता दी गई। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि अदनान सामी के पिता पाकिस्तानी वायुसेना में पायलट थे और भारत के खिलाफ 1965 की लड़ाई में हिस्सा लिया था।

पात्रा ने कहा कि तथाकथित उदारवादी और तौहीनबाग वाले (भाजपा शाहीन बाग को तौहीन बाग कह रही है) सोनिया गांधी का जिक्र आने पर उन्हें उनके पिता से अलग करते हैं। संसद पर आतंकी हमले के दोषी अफजल गुरु से उसके बेटे को अलग करते हैं, लेकिन अदनान सामी को उनके पिता से जोड़ रहे हैं। ये इनका दोहरापन है।

पात्रा ने अदनान सामी की मां नौरीन खान की पृष्ठभूमि का भी जिक्र किया, जो जम्मू की रहने वाली थीं। पात्रा ने कांग्रेस से पूछा कि क्या वह जम्मू की मुस्लिम महिलाओं की इज्जत नहीं करती है।

सामी के समर्थन में पासवान : लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख और केंद्र सरकार में मंत्री रामविलास पासवान ने भी अदनान सामी को पद्म श्री देने का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि सामी ने देश का मान बढ़ाया है।

राकांपा बोली, सामी को सम्मान, भारतीयों का अपमान : राकांपा प्रवक्ता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने कहा है कि अदनान सामी को पद्म श्री देना 130 करोड़ भारतीयों का अपमान है। मोदी सरकार सीएए से हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए उन्हें यह सम्मान दिया है। मलिक ने कहा कि अगर कोई भी पाकिस्तानी 'जय मोदी' का नारा लगाएगा तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी।

अदनाम पर बंटी कांग्रेस : कांग्रेस ने भी सामी को पद्म पुरस्कार देने का विरोध किया है। लेकिन पार्टी के अंदर इस मसले पर मतभेद भी नजर आ रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने जहां सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं, वहीं दिग्विजय सिंह ने सामी को बधाई दी है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि उन्होंने अदनान सामी को भारत की नागरिकता देने की सिफारिश की थी।

कांग्रेस ने सनाउल्ला का दिया हवाला : शेरगिल ने कहा कि कारगिल में भारत की तरफ से लड़ने वाले असम के मोहम्मद सनाउल्ला को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) में विदेशी घोषित कर दिया गया है, जबकि भारत पर बम गिराने वाले पाकिस्तानी वायुसेना के अधिकारी के बेटे को भारत की नागरिकता देने के साथ ही सम्मान भी दिया जा रहा है।

अदनान का शेरगिल को जवाब : सामी ने ट्विटर के जरिए जयवीर शेरगिल को जवाब दिया है। उन्होंने लिखा है, 'हे बच्चा, क्या तुमने 'क्लीयरेंस सेल' से अपना दिमाग पाया है या किसी सेकेंड हैंड नॉवेल्टी स्टोर से? क्या बर्कले में उन्होंने तुम्हे यही पढ़ाया है कि एक पुत्र अपने पिता के कार्यों के लिए जिम्मेदार और दोषी होता है।'

मुसलमानों को उनके समाज के लोग ही डरा रहे : भागवत

▸ संघ प्रमुख ने जाति और वर्ग विभेद को बताया अभिशाप

जागरण संवाददाता, गोरखपुर : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का मानना है कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर मुसलमानों को उनके समाज के लोग ही डरा रहे हैं। कानून के प्रारूप पर भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। इस डर और भ्रम को दूर करने के लिए मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध लोगों को ही आगे आना होगा।

संघ प्रमुख ने यह विचार रविवार देर शाम गोरखपुर में लोगों से बातचीत के दौरान साझा किया। हालांकि, सीएए को लेकर लोगों की ओर से रखे गए कई सवालों को यह कहकर टाल गए कि यह राजनीतिक मसला है, इस पर उन्हें कुछ नहीं कहना। एक सवाल के जवाब में उन्होंने जाति व वर्ग विभेद को समाज के लिए अभिशाप बताया। इस विभेद के चलते ही दलितों की लंबे समय तक उपेक्षा हुई है। विभेद का कोई यथोचित तर्क नहीं है, इसे तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज के विकास में सभी वर्गों के लोगों को अपना स्थान सुनिश्चित करना चाहिए। आमदनी का एक हिस्सा समाज पर खर्च करना चाहिए।

उत्तर प्रदेश पूर्वी क्षेत्र के चार दिवसीय कार्यकर्ता बैठक के आखिरी दिन सोमवार को मोहन भागवत ने कार्यकर्ताओं को संघ के कार्य विस्तार की जानकारी दी। कहा कि किसी भी कार्य के विस्तार को लेकर जितना जरूरी चिंतन, मनन, निर्णय व योजना है, उतना ही जरूरी उसे परिश्रम के साथ पूरा करना भी है। छोटे-छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से संघ संस्कार देता है। इस संस्कार के साथ जो कार्यकर्ता निर्माण की दिशा में आगे बढ़ता है।

मोहन भागवत। फाइल

मोहन भागवत से मिले योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोहन भागवत से मुलाकात कर उन्हें कुंभ से संबंधित पुस्तक और सीएए से जुड़ी बुकलेट भेंट की। संघ प्रमुख ने गणतंत्र दिवस पर सरस्वती शिशु मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सुभाष नगर में झंडारोहण भी किया।

राज्यों में लागू होने वाली उच्च शिक्षा योजना में धांधली

▸ मंत्रालय ने केंद्रीय योजना में अनियमितताओं का संज्ञान लिया

▸ टिस ने अपने आंतरिक ऑडिट में पाई अनियमितताएं

नई दिल्ली, प्रेट्र : मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने संभवतः राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे का संज्ञान लिया है। रूसा राज्यों के लिए केंद्रीय उच्च शिक्षा योजना है। इस योजना पर अमल करने वाली एजेंसी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टिस) ने अपने आंतरिक ऑडिट में अनियमितताएं पाईं हैं। इस पर अब केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भी संज्ञान लिया है।

सूत्रों के अनुसार इस संबंध में केंद्रीय मंत्रालय ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना में अनियमितताओं को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से भी संपर्क किया है। इस मामले में एक पूर्व संयुक्त सचिव और टिस के एक प्रोफेसर के धांधली करने का आरोप है।

सूत्रों के अनुसार राज्यों के लिए संचालित केंद्र की इस उच्च शिक्षा योजना में टिस के ऑडिट में दो करोड़ रुपये से अधिक के खर्च में गंभीर अनियमितताओं का पता चला है। जहां देश-विदेश में सम्मेलन और संगोष्ठियां आयोजित करने समेत

टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। फाइल

अनेक मकसद से समय-समय पर अग्रिम राशि निकाली गई है। एक सूत्र के अनुसार ऑडिट में पता चला कि निकाली गई अग्रिम राशि और मंत्रालय को जमा किए गए बिल एक-दूसरे से मेल नहीं खाते। इससे कथित साठगांठ की ओर इशारा होता है। मंत्रालय को इसकी जानकारी दे दी गई जिसने इसका संज्ञान लिया है। केंद्र सरकार की ओर से अक्टूबर 2013 में शुरू की गई रूसा योजना का उद्देश्य राज्यों में उच्च शिक्षा को सुधारना है। टिस इस योजना को लागू करने वाला निजी संस्थान है।

माल्या की लक्जरी याट को बेचने का आदेश

लंदन, प्रेट्र : लक्जरी लाइफ स्टाइल के लिए ख्यात भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को ब्रिटिश कोर्ट ने सोमवार को झटका दिया। कोर्ट ने कहा कि फोर्स इंडिया के स्वामित्व वाली लक्जरी याट को बेचा जाए और उससे प्राप्त धनराशि से कतर नेशनल बैंक का कर्ज चुकाया जाए। याट बैंक के पास बंधक (मॉरगेज) है लेकिन उसका परोक्ष स्वामी विजय माल्या का बेटा सिद्धार्थ माल्या है। लंदन की हाई कोर्ट में बैंक ने बताया कि उसका करीब 47 करोड़ रुपये का कर्ज विजय माल्या की संबद्धता वाली कंपनी पर है। इस कर्ज को लेने के लिए विजय माल्या ने बैंक को अपनी पर्सनल गारंटी दी थी। इस लिहाज से कर्ज न चुकाए जाने पर वह सीधे जिम्मेदार बनते हैं।

हाई कोर्ट के जज नीजेल टेयर ने बैंक के इस दावे को स्वीकार किया। कहा कि इससे कर्ज लेने वाले से उनके नजदीकी रिश्ते का भी पता चलता है। इसलिए बैंक उनकी संपत्ति से कर्ज की धनराशि, उस पर ब्याज और वसूली में खर्च होने वाला धन वसूलने का हकदार है। यह धनराशि करीब छह मिलियन यूरो बनती है। आदेश में लिखा गया है कि याट की स्वामी फोर्स इंडिया कंपनी सुनवाई के दौरान नहीं आई।

रक्षा मंत्री ने कहा-कोई ताकत नहीं रोक सकती कश्मीरी पंडितों की घर वापसी

▸ राजनाथ ने किया जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन का बचाव

▸ कहा-हमें कोई परेशान करता है, तो हम उसे शांति से रहने नहीं देंगे

मंगलुरु, प्रेट्र : जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन और अनुच्छेद 370 समाप्त करने के फैसले का जोरदार बचाव करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अब कोई ताकत कश्मीरी पंडितों की घर वापसी नहीं रोक सकती। सोमवार को कर्नाटक के मंगलुरु में एक रैली को संबोधित करते हुए राजनाथ ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि यदि भारत को नुकसान पहुंचाया गया, तो वह भी ऐसा करने वाले को शांति से रहने नहीं देगा। उन्होंने कहा, 'हम किसी को छुएंगे नहीं, लेकिन यदि हमें कोई परेशान करता है, तो हम उसे शांति से रहने भी नहीं देंगे।'

संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के संबंध में उन्होंने कहा कि यह किसी भी धर्म की भावनाएं आहत करने का कानून नहीं है, बल्कि यह धार्मिक उत्पीड़न के शिकार लोगों को राहत प्रदान करने के लिए है।

रक्षा मंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से हिंदुओं, सिखों के भारत आने पर उन्हें नागरिकता देने को कहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र

कर्नाटक के मंगलुरु में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (मध्य में) का सोमवार को सीएए के समर्थन में एक रैली के दौरान अभिनंदन किया गया। प्रेट्र

मोदी ने उसी सोच को पूरा किया। कई गैर भाजपा शासित राज्यों द्वारा सीएए को लागू करने से इन्कार करने के संबंध में राजनाथ ने कहा कि यह एक केंद्रीय कानून है और सभी को इसका पालन करना चाहिए। कांग्रेस पर इस मुद्दे पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि उसे राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य बस इसलिए नहीं भूल जाना चाहिए कि वह विपक्ष में है।

पंचनामे की विश्वसनीयता बढ़ाए पुलिस : केंद्र

नई दिल्ली, आइएएनएस : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के पुलिस प्रमुखों को निर्देश दिया है कि वे आपराधिक मामलों की न्याय व्यवस्था की खामियों को दूर करने को आवश्यक कदम उठाएं। मंत्रालय ने कहा है कि इसके लिए पंचनामे में दर्ज गवाहों के बयानों को महत्व दिया जाए। साथ ही यह भी ध्यान रखा जाए कि पंचनामे में कुछ ही लोगों के बार-बार बयान दर्ज न किए जाएं। वही लोग एक से ज्यादा अपराध के चश्मदीद न बनाए जाएं।

गृह मंत्रालय ने कहा है कि पंचनामे में जिस भी गवाह का बयान दर्ज किया जाए, उसका आधार नंबर में साथ में लिखा जाए। इससे उसकी पहचान ज्यादा स्पष्ट हो सकेगी। इससे गवाह की विश्वसनीयता बढ़ जाएगी और व्यवस्था में व्याप्त खामी को खत्म करने में सहायता मिलेगी। इन कदमों से असली गवाह सामने आएंगे और फर्जी गवाह व्यवस्था से दूर जाएंगे। इस तरीके से न्याय व्यवस्था में व्याप्त बहुत बड़ी खामी दूर हो सकेगी। गृह मंत्रालय के परिपत्र में कहा गया है कि शासन व्यवस्था के नियम के अनुसार गवाह इलाके के सम्मानित लोग होने चाहिए जिनकी निष्पक्षता पर आमजन को भरोसा हो।

निकाह हलाला, बहुविवाह को चुनौती देने का विरोध

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की अर्जी

▸ मामले में उसे भी पक्षकार बनाने का किया आग्रह

▸ मौलिक अधिकारों का हनन करती हैं दोनों प्रथाएं

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआइएमपीएलबी) ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर मुसलमानों में प्रचलित निकाह हलाला और बहुविवाह के प्रचलन को चुनौती देने वाली याचिका का विरोध करते हुए उसे भी पक्षकार बनाए जाने की मांग की है।

मुसलमानों में प्रचलित निकाह हलाला के तहत अगर किसी महिला को उसी पति से दोबारा शादी करनी हो, जिसने उसे तलाक दे दिया हो, तो उसको पहले किसी दूसरे पुरुष से शादी करनी पड़ती है। शादी अमल में आने के बाद वह दूसरा पुरुष महिला को तलाक देता है, जिसके बाद वह महिला अपने पूर्व पति से दोबारा शादी कर सकती है। इसके अलावा मुस्लिम पुरुष एक साथ चार पत्नियां रख सकता है। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सी याचिकाएं लंबित हैं, जिनमें इन दोनों प्रथाओं को मुस्लिम महिलाओं के मौलिक अधिकारों का हनन बताते हुए चुनौती दी गई है।

इनमें एक याचिका भाजपा नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की भी है। सुप्रीम कोर्ट ने 26 मार्च, 2018 को

सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो

याचिकाओं पर नोटिस जारी करते हुए मामले को विचार के लिए पांच जजों की संविधान पीठ को भेज दिया था।

बोर्ड ने अर्जी में कहा है कि वह मुस्लिम मूल्यों और इस्लामिक संस्कृति को बनाए रखने की दिशा में काम करता है। इसलिए कोर्ट को इस मामले में उसका पक्ष भी सुनना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ मुस्लिम संस्कृति का हिस्सा है। इसीलिए यह संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 29 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता में आता है। बोर्ड ने कहा है कि इस याचिका में जो मुद्दा उठाया गया है, उस पर सुप्रीम कोर्ट 1997 में अहमदाबाद वुमन एक्शन ग्रुप बनाम भारत सरकार मामले में विचार कर चुका है।

उस केस में कोर्ट के सामने दो मुद्दे थे- पहला यह कि क्या बहुविवाह की इजाजत देने वाला मुस्लिम पर्सनल लॉ शून्य है और वह संविधान के अनुच्छेद 14 व 15 के तहत मिले समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है? दूसरा कि क्या मुस्लिम पति का एक से अधिक पत्नियां रखना क्रूरता माना जाएगा? उस समय कोर्ट ने इस पर विचार करने से मना कर दिया था और कहा था कि यह राज्य नीति का मामला है, जिसे विधायिका को देखना चाहिए।

बोर्ड ने कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ कुरान और हदीस पर आधारित है। उसकी वैधानिकता को मौलिक अधिकारों के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की बात कही गई है। लेकिन, यूसीसी लागू करने की बात करने वाला अनुच्छेद 44 संविधान में नीति निदेशक तत्वों का हिस्सा है। इसे लागू नहीं कराया जा सकता। इसमें यूसीसी लागू होने तक सभी धर्मों को उनके पर्सनल लॉ के मुताबिक चलने की इजाजत है।

बोर्ड ने कहा है कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकार पहले से ही मुस्लिम वुमन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स) एक्ट 1986 में संरक्षित हैं और इस कानून को कोर्ट पहले ही वैध ठहरा चुका है।

बोर्ड ने यह भी कहा है कि सामान्य तौर पर दूसरे धर्म के व्यक्ति को किसी दूसरे धर्म और उसकी मान्यताओं पर सवाल उठाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। उस धर्म के व्यक्ति को भी सिर्फ जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के संरक्षण तक ही धार्मिक आस्था का मसला उठाने की इजाजत होनी चाहिए। यह मामला मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़ा है। इसलिए बोर्ड को पक्षकार बनाया जाए।

मिर्ची मनी लांड्रिंग मामले में डीएचएफएल प्रमोटर गिरफ्तार

मुंबई, प्रेट्र : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गैंगस्टर इकबाल मिर्ची से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) के सीएमडी कपिल वधावन (46) को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद बल्लार्ड एस्टेट स्थित ईडी के दफ्तर में वधावन से पूछताछ की गई। वधावन से पहले भी पूछताछ हो चुकी है। पीएमएलए की विशेष अदालत ने वधावन को 29 जनवरी तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया।

अधिकारियों ने बताया कि वधावन को प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया गया है। वधावन पर मामले की जांच में सहयोग नहीं करने, सौदे तथा एजेंसी को दिए गए बयान में अविश्वसनीयता के आरोप हैं। मामला मिर्ची की मुंबई में स्थित संपत्तियों से संबंधित है। ईडी का आरोप है कि इन संपत्तियों की खरीद मिर्ची ने अपराध से अर्जित धन के जरिये की थी। इस प्रकार की तीन संपत्तियां सनब्लिंक रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को बेची गई थीं। सनब्लिंक का संबंध वधावन बंधु कपिल और धीरज से है। आरोप है कि कपिल ने डीएचएफएल के धन को मुखौटा कंपनियों के खाते में हस्तांतरित किया। इसके बाद कंपनियों का सनब्लिंक के साथ विलय करा दिया गया। ईडी ने मिर्ची, उसके परिवार के सदस्यों और अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

इंतजार खत्म

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इलाहाबाद, जम्मू व हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विवि में नियुक्ति की शुरू की प्रक्रिया

केंद्रीय विवि को मिलेंगे अब स्थायी कुलपति

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

केंद्रीय विश्वविद्यालयों को स्थायी कुलपति के लिए अब लंबा इंतजार नहीं करना होगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अस्थायी कुलपति के भरोसे चल रहे देश भर के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्थायी कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर काम शुरू कर दिया है। फिलहाल इलाहाबाद, जम्मू और हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालयों को लेकर विज्ञापन जारी किए गए हैं। योग्य उम्मीदवारों से एक महीने के भीतर आवेदन करने के लिए कहा गया है। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में हाल ही में इस्तीफे के बाद कुलपति का पद खाली हुआ है।

इस बीच मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश के ऐसे सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों का भी ब्योरा तलब किया है, जहां लंबे समय से स्थायी कुलपति नहीं हैं। फिलहाल इनमें त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, केरल जैसे केंद्रीय विवि के नाम सामने आए हैं। देश में मौजूदा समय में 51 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों की मानें तो केंद्रीय विवि की शैक्षणिक गुणवत्ता और प्रशासनिक क्षमता को बेहतर बनाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है।

मंत्रालय ने यह कवायद उस समय शुरू की है, जब केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के खाली पड़े 70 फीसद से ज्यादा पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इनकी नियुक्ति के आदेश जारी करने का काम चल रहा है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि स्थायी कुलपति मिलने से सभी विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियां तेज होंगी जो विश्वस्तरीय रैंकिंग की प्रतिस्पर्धा में जगह बनाने में मदद करेंगी। केंद्रीय विवि में शिक्षकों के करीब आठ हजार पद खाली थे। हालांकि इनमें अभी भी इलाहाबाद विवि जैसे कई विवि में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया अटकी हुई है। माना जा रहा है कि स्थायी कुलपति की नियुक्ति के बाद शिक्षकों की कमी भी खत्म हो जाएगी।

स्थायी कुलपति के लिए जो विज्ञापन जारी किया गया है, उनमें कुलपति का वेतन प्रतिमाह 2.10 लाख रुपए तय किया गया है। इसके साथ ही उन्हें विवि नियमों के मुताबिक, मानदेय दिए जाएंगे।

स्मार्ट सिटी पर जून में रिपोर्ट कार्ड जारी करेगी केंद्र सरकार

विशाखापत्तनम, प्रेट्र : केंद्र सरकार जून में 100 चुने हुए स्मार्ट शहरों की तीन श्रेणियों में सूची जारी करेगी। जीवन की सुगमता, नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक और जलवायु श्रेणियों पर सूची जारी होगी। स्मार्ट सिटीज मिशन के पांच वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के मुताबिक, यह शहरों को बेहतर योजना बनाने और डाटा-ड्राइवन शासन की ओर ले जाने में मदद करेगा जो अंततः उनकी जीविका में सुधार करेगा। स्मार्ट सिटी मिशन के निदेशक कुणाल कुमार ने कहा कि जून में मंत्रालय रैंकिंग के साथ सामने आएगा। उन्होंने कहा, 'जीवन बदलने के लिए हम डाटा का इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार शहरों की अर्थव्यवस्था, स्थिरता एवं अन्य पर रैंकिंग कर रही है। हमने नागरिकों की आकांक्षाओं को परिणाम में बदल दिया है।' कुमार ने कहा कि जलवायु श्रेणी में शहरों की रैंकिंग पर्यावरण से संबंधित मामलों को प्रोत्साहन में उनके काम पर आधारित रहेगी। नरेंद्र मोदी सरकार का प्रमुख कार्यक्रम स्मार्ट सिटी मिशन जून 2015 में लांच किया गया था।

REUNION IAS
IAS V.K.TRIPATHI PCS
NEW BATCHES
राजनीति विज्ञान
भारतीय विचारक (Optional)
से कक्षा प्रारम्भ... 4 FEB 2020 | 3:00 PM 5:30 PM
GS (प्रारम्भिक परीक्षा) POLITY (PT)
राजव्यवस्था
सरकार से कक्षा प्रारम्भ... 4 FEB 2020 | 6:15 PM 8:15 PM
OFFLINE / ONLINE CLASSES
B-11, 1st FLOOR, IN FRONT OF MEERUT SWEETS, MUKHERJEE NAGAR DELHI-9
9999421659-58

1320 किलोमीटर लंबी दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे परियोजना तीन साल में बनकर तैयार हो जाएगी। यह दावा केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। इस योजना की लागत 3.10 लाख करोड़ बताई जा रही है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
मंगलवार 28 जनवरी 2020

'पहले कांवड़ यात्रा थी मुश्किल, अब निकल रही गंगा यात्रा'

बिजनौर में सोमवार को गंगा यात्रा के शुभारंभ अवसर पर गंगा आरती करते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (दाएं से तीसरे) और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह (दाएं से दूसरे)। जागरण

जय प्रकाश पांडेय, बिजनौर

कोहरे और ठंड के बीच सोमवार को उप्र के बिजनौर बैराज पर गंगा आरती करने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा यात्रा का भव्य शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने गंगा तीरे स्थित ग्रामों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का पिटारा खोल दिया। बिजनौर और मुजफ्फरनगर जिले की सीमा पर स्थित रामराज में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने जहां गंगा की महिमा का बखान किया वहीं बिना नाम लिए पिछली सरकारों को भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के समय लोगों को कांवड़ यात्रा निकालने में भी तरह-तरह की परेशानी होती थी। अब गंगा यात्रा भी निकल रही है। खराब मौसम के कारण उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत नहीं आ सके।

सोमवार को एक साथ दो स्थानों पर गंगा यात्रा का आयोजन हुआ। इसमें, एक आयोजन बलिया जिले में हुआ, जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शामिल हुईं। दूसरी यात्रा का आयोजन बिजनौर में हुआ, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। यहां जनसभा में योगी ने कहा कि गंगा देश की बहुत बड़ी आबादी के लिए अर्थ की व्यवस्था का माध्यम हैं, गंगा हमारी आस्था भी हैं। हमें अर्थव्यवस्था के साथ आस्था को जोड़कर गंगाजल को निर्मल बनाना है। योगी ने आम आदमी पार्टी को घेरते हुए कहा, अगर केजरीवाल सरकार चाहती तो गंगा की तरह यमुना भी साफ हो गई होतीं। गंगा किनारे बसे ग्रामों के लिए योगी ने कई घोषणाएं कीं। कहा, गंगा तीरे के ग्रामों में गंगा पार्क व गंगा मैदान बनाए जाएंगे। इन गंगा ग्रामों में अधिकारियों की चौपालें भी लगेंगी।

गंगा यात्रा

- सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर में गंगा की आरती के साथ ही किया गंगा यात्रा का शुभारंभ
- गंगा किनारे बसे ग्रामों के लिए खोला योजनाओं का पिटारा

मखदूमपुर घाट पर गंगा आरती

बिजनौर व रामराज में जनसभा को संबोधित कर योगी लखनऊ लौट गए, जबकि रथ को लेकर कई मंत्री हस्तिनापुर पहुंचे। हस्तिनापुर के मखदूमपुर घाट पर गंगा आरती भी की गई। मंगलवार को उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा यहीं से यात्रा आगे बढ़ाएंगे। गंगा यात्रा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह, केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह भी मौजूद थे।

हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल का आज होगा विस्तार

राज्य ब्यूरो, रांची

- झामुमो व कांग्रेस कोटे से मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे विधायक

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को अपने मंत्रिमंडल में नए मंत्रियों को शामिल करेंगे। राजभवन के बिरसा मंडप में नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह शाम चार बजे आरंभ होगा। जानकारी के मुताबिक झारखंड मुक्ति मोर्चा से पांच और कांग्रेस से दो विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। कांग्रेस से पूर्व में ही दो विधायकों को शपथ दिलाई जा चुकी है। राजद के एकमात्र विधायक सत्यानंद भोक्ता भी मंत्री पद की शपथ बीते 29 दिसंबर को ले चुके हैं।

गौरतलब है कि मकर संक्रांति के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार करने की संभावनाएं थीं, लेकिन कांग्रेस द्वारा मंत्रियों की सूची में आनाकानी से देरी हुई। सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यपाल को 23 जनवरी को मंत्रिमंडल विस्तार की सूचना दी थी। हालांकि बाद में चाईबासा में हत्याकांड की घटना का हवाला देकर मंत्रिमंडल का विस्तार टाला गया। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस ने मंत्रियों की सूची ही नहीं सौंपी थी। इसी वजह से मंत्रिमंडल विस्तार को टालना पड़ा।

हेमंत सोरेन फाइल

कांग्रेस कोटे के संभावित मंत्री : बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख, राजेंद्र प्रसाद सिंह, दीपिका पांडेय सिंह।

झामुमो कोटे के संभावित मंत्री : प्रो. स्टीफन मरांडी, चंपई सोरेन, जोबा मांझी, हाजी हुसैन अंसारी, मिथिलेश ठाकुर।

इसकी भी संभावना : मुख्यमंत्री समेत अधिकतम 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं। संभव है कि एक पद छोड़कर रखा जाए ताकि विपरीत परिस्थितियों के अनुसार उलटफेर में सहूलियत हो सके। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में मंत्रिमंडल का एक पद खाली रहा।

मरांडी की भाजपा में होगी दमदार वापसी

राज्य ब्यूरो, रांची : झाविमो (झारखंड विकास मोर्चा) प्रमुख बाबूलाल मरांडी की भाजपा में वापसी का दमदार प्लॉट तैयार किया जा रहा है। भाजपा की कोशिश होगी कि मरांडी और उनकी पार्टी के विलय को ऐतिहासिक समारोह में तब्दील कर एक माहौल बनाया जाए। बताया जा रहा है कि फरवरी के पहले सप्ताह में धुर्वा के प्रभात तारा मैदान में भव्य कार्यक्रम में झाविमो का भाजपा में विलय होगा। इस खास मौके पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी की बात भी कही जा रही है। हालांकि, इससे पूर्व मरांडी दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर विलय की औपचारिकता पूरी कर सकते हैं।

झाविमो प्रमुख मरांडी ने अपनी पार्टी के आंतरिक गतिरोध तकरीबन दूर कर लिए हैं। उनके सहयोगी रहे विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की ने भी अपनी राह तलाश ली है। ऐसे में उनकी पार्टी के भाजपा में विलय को लेकर अब कोई अड़चन नहीं है। अब भाजपा को तय करना है कि वह बाबूलाल के पूरे कुनबे को कब कमल क्लब में शामिल कराती है। पार्टी सूत्रों की मानें तो प्रभात तारा मैदान में भव्य कार्यक्रम में दोनों दलों के एक लाख के करीब कार्यकर्ताओं को जुटाने की कोशिश की जाएगी।

न्यूज गैलरी

कार्ति के खिलाफ कर चोरी मामले की सुनवाई पर अंतरिम रोक बढ़ी

चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम व उनकी पत्नी के खिलाफ आयकर चोरी के मामले की कार्यवाही पर अंतरिम रोक की सीमा 12 फरवरी तक बढ़ा दी। यह मामला चेन्नई की एक विशेष अदालत में लंबित है। जस्टिस एम सुंदर ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति और उनकी पत्नी श्रीनिधि की अर्जी पर यह आदेश दिया। दोनों ने अपने खिलाफ सांसदों और विधायकों से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए गठित विशेष अदालत में कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी। वरिष्ठ वकील केटीएस तुलसी की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश ने यह आदेश दिया। याची की ओर से पेश तुलसी ने दलील दी कि आयकर की धारा 153 (ए) के तहत फिर से आकलन प्रतिबंधित है। (प्रेट्र)

जोगी की याचिका पर जस्टिस अग्रवाल का सुनवाई से इन्कार

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जस्टिस संजय के. अग्रवाल ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी और उनके पुत्र व जनता कांग्रेस छत्तीसगढ (जकांछ) पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अमित जोगी की याचिका पर व्यक्तिगत कारणों के चलते सुनवाई से इन्कार कर दिया है। इसके साथ ही याचिका को किसी अन्य बेंच में रखने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि जोगी के बंगला मरवाही सदन में कार्यरत कर्मचारी संतोष कौशिक उर्फ मनवा ने बंगले के भीतर फांसी लगा ली थी। परिजनों ने जोगी पिता-पुत्र पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। (नईदुनिया)

आंध्र प्रदेश विधान परिषद को खत्म करने का प्रस्ताव विधानसभा से पास

बदलाव ▶ तीन राजधानियों वाले विधेयकों को पास कराने में विफल वाईएसआर कांग्रेस सरकार ने रखा था प्रस्ताव

अमरावती, प्रेट्र : आंध्र प्रदेश की तीन राजधानियों वाले दो विधेयकों को पास कराने में विफल रही वाईएसआर कांग्रेस सरकार ने विधान परिषद को ही खत्म करने का फैसला किया है। सरकार की तरफ से विधान परिषद को खत्म करने के लिए विधानसभा में पेश किया गया वैधानिक प्रस्ताव सोमवार की देर शाम पास हो गया। अब इस मुद्दे पर केंद्र सरकार विचार करेगी। इससे पहले दिन में मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य विधान परिषद को खत्म करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई।

विधानसभा में जब सरकार की तरफ से प्रस्ताव रखा गया, तब सदन के कुल 175 में से 133 सदस्य मौजूद थे। शाम छह बजे हुए मत विभाजन के दौरान सदन में मौजूद सभी सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। इस प्रकार अनुच्छेद 169 (1) के तहत प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हो गया। विधानसभा अध्यक्ष टी. सीताराम ने इसकी घोषणा की। विपक्षी तेलुगु देसम पार्टी (तेदेपा) ने सरकार के प्रस्ताव का विरोध करते हुए सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया। इससे पहले मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने एक लाइन का प्रस्ताव रखते हुए कहा, 'विधान परिषद को खत्म करने का निर्णय लेते हुए मुझे गर्व हो रहा है, क्योंकि यह पूरी तरह जनहित में लिया गया है। देश के 28 में से सिर्फ छह राज्यों में ही विधान परिषद है।' मार्टिन लूथर किंग के कथन का उल्लेख करते हुए जगनमोहन रेड्डी ने कहा, 'सही काम को करने के लिए हर समय सही होता है।' उधर, तेदेपा प्रमुख व पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने कहा, 'हालांकि, वर्ष 2004 में मैं विधान परिषद को बहाल किए जाने के खिलाफ था, लेकिन जनहित में अपना फैसला बदल लिया था।' जनसेना पार्टी के एकमात्र सदस्य आरवी राव ने सरकार का समर्थन किया। तेदेपा के दो बागी सदस्यों में से एक सदन में मौजूद रहे। सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस के अनुपस्थित 18 सदस्यों में सरकार के व्हिप सीबी रेड्डी भी शामिल रहे। सदन में सरकार की तरफ से एक वीडियो क्लिप का भी प्रदर्शन किया गया, जिसमें वर्ष 2004 में चंद्रबाबू नायडू विधान परिषद के पुनर्गठन का विरोध कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले सप्ताह जगनमोहन रेड्डी सरकार ने राज्य की तीन राजधानियों से संबंधित दो विधेयकों को विधानसभा से पारित कराने के बाद विधान परिषद में रखा था। इनमें आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण और सभी क्षेत्रों का समावेशी विकास विधेयक-2020 तथा आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण कानून-2014 को खत्म करने वाला विधेयक शामिल था। इसके तहत राज्य की कार्यकारी राजधानी विशाखापत्तनम, विधायी राजधानी अमरावती और न्यायिक राजधानी कुर्नूल को बनाने का प्रस्ताव था, लेकिन तेदेपा के विरोध के कारण दोनों विधेयक पास नहीं हो पाए थे। आंध्र प्रदेश विधान परिषद के सभापति एमए शरीफ ने 22 जनवरी को दोनों विधेयकों को गहन परीक्षण के लिए प्रवर समिति को भेज दिया था। इसके बाद मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने विधानसभा के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया था। इससे पहले वाईएसआर कांग्रेस ने 17 दिसंबर को भी विधान परिषद को भंग करने की चेतावनी दी थी।

वाईएस जगनमोहन रेड्डी फाइल

अपने पिता के फैसले को ही पलटना चाहते हैं जगनमोहन

मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी विधान परिषद को खत्म करने की कोशिश में अपने पिता वाईएस राजशेखर रेड्डी के फैसले को ही पलटना चाहते हैं। राजशेखर रेड्डी ने वर्ष 2007 में संयुक्त आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए उच्च सदन को फिर से बहाल किया था। वर्ष 1985 में पहली बार विधानपरिषद को भंग किया गया था।

अफवाह साबित हुई दो मंत्रियों के इस्तीफे की अटकलें

उपमुख्यमंत्री (राजस्व) पिल्ली सुभाषचंद्र बोस और मत्स्य मंत्री एमवी रमण के इस्तीफे की अटकलें अफवाह साबित हुईं। दोनों विधान परिषद सदस्य हैं। चर्चा थी कि विधान परिषद खत्म करने संबंधी सरकार के फैसले के क्रम में दोनों नैतिक तौर पर पद से इस्तीफा दे देंगे।

विधान परिषद में वाईएसआर कांग्रेस के हैं सिर्फ नौ सदस्य

58 सदस्यीय राज्य विधान परिषद में वाईएसआर कांग्रेस के सिर्फ नौ सदस्य हैं। उच्च सदन में विपक्षी तेलुगु देसम पार्टी (तेदेपा) के सदस्यों की संख्या 28 है। सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस को इस सदन में वर्ष 2021 में ही बहुमत मिल सकता है, जब छह वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद सदस्य सेवानिवृत्त होंगे।

रिम्स में राबड़ी से मिल भावुक हुए लालू यादव

- दोनों ने ढाई घंटे संग बिताए, बेटी मीसा भी रहीं साथ
- पहली बार पति से मिलने रिम्स पहुंचीं राबड़ी देवी

बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव से मिलने उनकी पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी सोमवार को रांची स्थित रिम्स पहुंचीं। लालू चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे हैं और बीमार होने के कारण अस्पताल में भर्ती हैं। जागरण

जागरण संवाददाता, रांची

चारा घोटाले में सजा होने के बाद जेल में बंद अपने पति राजद (राष्ट्रीय जनता दल) सुप्रीमो लालू प्रसाद से मिलने राबड़ी देवी राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) के पेइंग वार्ड में पहली बार सोमवार को पहुंचीं। बड़ी बेटी मीसा भारती भी उनके साथ थीं। लालू प्रसाद से मिलते ही बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बेहद भावुक नजर आईं। लालू भी काफी भावुक दिखे।

पेइंग वार्ड के कॉरिडोर में बैठ कर दोनों ने काफी देर घर-परिवार से लेकर पार्टी-पॉलिटिक्स आदि पर बातें कीं। दोनों की एक साथ झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में राजद के कार्यकर्ता भी पहुंचे। करीब ढाई घंटे की मुलाकात के बाद राबड़ी देवी और मीसा भारती यहां से निकल गईं। दोनों ने मीडिया कर्मियों से किसी तरह की कोई बातचीत नहीं की। वहीं, रिम्स से मिली जानकारी के अनुसार लालू ने राबड़ी से परिवार को लेकर लंबी बातचीत की। तेजप्रताप व ऐश्वर्या को लेकर खासी चर्चा हुई।

दिल्ली से आंख का ऑपरेशन करा रांची पहुंचीं थीं राबड़ी

लालू करीब दो साल से होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद हैं। उनके स्वास्थ्य को देखते हुए जेल प्रशासन की ओर से उन्हें रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती किया गया है। यहां भी वह करीब डेढ़ साल से इलाजरत हैं। इस दौरान सोमवार को पहली बार राबड़ी देवी पति लालू प्रसाद का हाल चाल जानने रिम्स पहुंचीं। राबड़ी दिल्ली से अपनी आंख का ऑपरेशन कराकर लौट रहीं थीं। उन्होंने आंखों पर काला चश्मा लगा रखा था।

अब उप्र में सुबह चार बजे तक बिकेगी शराब

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : उप्र के बड़े शहरों में आने वाले पर्यटकों की सुविधा को देखते हुए सरकार ने शराब बिक्री की नई व्यवस्था का निर्णय किया है। अब सितारा होटलों में सुबह चार बजे तक शराब-बीयर उपलब्ध रहेगी, जबकि बाहर भी बार रात दो बजे तक खोले जा सकेंगे। यह व्यवस्था एक अप्रैल से लागू हो जाएगी।

आबकारी विभाग ने हाल ही में नई नीति लागू की है। प्रमुख सचिव आबकारी संजय आर. भूसरेड्डी ने बताया कि अभी फाइव स्टार, फोर स्टार और थ्री स्टार होटलों में रात दो बजे तक, जबकि बड़े शहरों के बार में रात एक बजे तक शराब की बिक्री की व्यवस्था थी। ऐसे में पर्यटन उद्यमियों की लगातार मांग थी कि रात में आने वाले पर्यटकों, खास तौर पर विदेशी मेहमानों की जरूरत को वह पूरा नहीं कर पाते। बड़े शहरों के 'नाइट कल्चर' के लिहाज से भी समय बढ़ाने की जरूरत बताई जा रही थी। इसे देखते हुए निर्णय किया गया है कि होटलों में सुबह चार बजे तक, जबकि बाहर के बार रात दो बजे तक खोले जा सकेंगे।

सोनिया ने उद्धव से लिखित में मांगा था कि संविधान के तहत काम करेंगे

- पीडब्ल्यूडी मंत्री अशोक चव्हाण ने नांदेड़ में एक बैठक में दी जानकारी
- फड़नवीस ने सरकार बनने से पहले किए गए सौदों के बारे में बताने को कहा

औरंगाबाद, प्रेट्र : कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से लिखित वचन मांगा था कि महाराष्ट्र में नई सरकार संविधान के दायरे में रहकर काम करेगी। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और उद्धव सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री अशोक चव्हाण ने नांदेड़ में एक बैठक में कहा, 'सोनिया गांधी ने स्पष्ट दिशा-निर्देश दिया था कि राज्य सरकार को संविधान के दायरे में काम करना चाहिए। उन्होंने हमें बताया कि पहले हमें शिवसेना से लिखित में लेना चाहिए कि सरकार संविधान का उल्लंघन नहीं करेगी। हमें उद्धव ठाकरे को यह बताने के लिए कहा गया था।'

उल्लेखनीय है कि उद्धव ठाकरे ने पिछले साल नवंबर में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने कांग्रेस और राकांपा के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई है। 21 अक्टूबर के विधानसभा चुनाव के परिणाम में किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। चव्हाण ने कहा कि सोनिया ने राज्य कांग्रेस को भी बताया था यदि सरकार उम्मीदों के मुताबिक कार्य नहीं करती है, तो पार्टी को इससे बाहर आ जाना चाहिए। हमने उद्धव को भी यही संदेश दिया। वह सहमत हो गए और हमने सरकार बनाई।

चव्हाण की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने कहा कि शिवसेना को महा विकास अघाड़ी सरकार बनने से पहले किए गए सौदों के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यदि गठबंधन दलों को (शिवसेना में) विश्वास नहीं है, तो पार्टी सरकार में क्यों है?

उद्धव ठाकरे फाइल

सोनिया गांधी फाइल

बच्चों ने पढ़ी संविधान की प्रस्तावना...

महाराष्ट्र में सभी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभा में संविधान की प्रस्तावना को अनिवार्य कर दिया दिया गया है। सोमवार को मुंबई के एक प्राइमरी स्कूल में प्रस्तावना का पाठ करते बच्चे। प्रेट्र

बदलती तस्वीर

कांग्रेसी हुए शत्रुघ्न सिन्हा पहुंचे सपा मुख्यालय, लखनऊ दौरे में अपनी पार्टी से बनाए रहे दूरी

अपने ही न जान पाए, 'छेनू आया था...'

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

शत्रुघ्न सिन्हा के स्टारडम से जुड़ी फिल्म 'मेरे अपने' का सुपरहिट डायलॉग 'श्याम आए तो कह देना, छेनू आया था...' सोमवार को लखनऊ में सियासी मजाक का हिस्सा बन गया। कांग्रेस नेता सिन्हा लखनऊ आए और उनकी अपनी पार्टी वाले ही न जान पाए कि 'छेनू आया था।' वह सिर्फ सपा मुख्यालय पहुंचे व अखिलेश यादव के साथ मंच साझा किया। कांग्रेस में उनके 'डबल रोल' के विरोध के साथ कयास भी शुरू हो गए हैं।

नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ गांधी शांति यात्रा लेकर लखनऊ पहुंचे पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा भी थे। दोनों ने सपा कार्यालय पहुंचकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ मंच साझा किया। शत्रुघ्न ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। अभिनेता से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा की 'पॉलिटिकल स्टोरी' का 'फ्लैशबैक' सबको याद होगा। भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री रहते हुए अपनी पार्टी से वह बगावत करते रहे। आखिरकार कांग्रेस का हाथ थाम लिया। वह पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में हैं। इसके बावजूद 2019 का लोकसभा चुनाव उन्होंने लखनऊ से सपा के टिकट पर अपनी पत्नी पूनम सिन्हा को लड़ाया। इससे उनके और सपा के रिश्तों का अंदाजा तो लगाया जा सकता है, लेकिन लखनऊ आगमन पर अपनी पार्टी के मुख्यालय न जाना, किसी नेता से संपर्क तक न करना कयासों को जन्म दे रहा है कि जल्द ही शत्रुघ्न सिन्हा सपा की साइकिल पर सवार हो सकते हैं।

लखनऊ में सोमवार को सपा प्रदेश मुख्यालय में गांधी शांति यात्रा के तहत आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित (बाएं से) सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा व शत्रुघन सिन्हा। जागरण

'शॉटगन' पर वार के साथ निकला कांग्रेसियों का दर्द

बॉलीवुड में शॉटगन कहे जाने वाले शत्रुघ्न के लखनऊ दौरे से पार्टी में उनका विरोध भी शुरू हो गया है। उनकी पत्नी के खिलाफ कांग्रेस से लोकसभा का चुनाव लड़े आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट किया- 'शत्रुघ्न सिन्हा स्टार प्रचारक हैं कांग्रेस के, लेकिन प्रचार करते हैं सपा का और कच्छा पहनते हैं आरएसएस का।' इसी पर पूर्व प्रदेश प्रवक्ता जीशान हैदर ने लिखा- यह तो वाकई सोचने वाला विषय है। ऐसे लोगों को तुरंत बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए, जो खाते यहां की हैं और बजाते कहीं और की हैं। आचार्य प्रमोद ने इसके बाद जो ट्वीट किया, उससे उनकी पार्टी और फैसलों के प्रति नाराजगी भी झलकी। उन्होंने लिखा, 'इन्हें कौन निकालेगा। ये कोई सिराज मेंहदी और संतोष सिंह थोड़ी हैं।' उल्लेखनीय है कि पूर्व एमएलसी सिराज मेंहदी और पूर्व सांसद संतोष सिंह समेत दस वरिष्ठ कांग्रेसी अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी से निकाल दिए गए हैं।

जयाप्रदा पर टिप्पणी सहित दो मामलों में आजम खां के खिलाफ वारंट जारी

जागरण संवाददाता, रामपुर

पूर्व सांसद जयाप्रदा को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी के दो मामलों में अदालत (एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट) ने सांसद आजम खां के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए हैं। दोनों मामले लोकसभा चुनाव के दौरान रामपुर के शाहबाद कोतवाली में दर्ज हुए थे।

शाहबाद में हुई चुनावी जनसभा में आजम ने भाजपा प्रत्याशी एवं फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जनसभा में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी मौजूद थे। पुलिस ने सांसद के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया था और जांच के बाद उनके खिलाफ अदालत में चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी। अदालत ने सुनवाई करते हुए उन्हें तलब करने के लिए कई बार समन भेजे। सांसद न तो कोर्ट में हाजिर हुए और न जमानत कराई। सोमवार को इस मामले में सुनवाई हुई। इस सुनवाई पर भी सांसद कोर्ट नहीं पहुंचे। इस पर अदालत ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किए हैं। दूसरा मामला शाहबाद के सैफनी क्षेत्र का है। नौ अप्रैल को शाहबाद कोतवाली में सांसद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मुकदमे में उन पर एक जनसभा में संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों और अधिकारियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। इस मामले में भी उनके खिलाफ चार्जशीट लगी थी और अदालत में सुनवाई चल रही है। सोमवार को हुई सुनवाई पर हाजिर न होने पर कोर्ट ने इस मामले में भी जमानती वारंट जारी किए हैं। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राम औतार सिंह सैनी ने बताया कि दोनों मामलों में अदालत अब 11 फरवरी को सुनवाई करेगी। वहीं, सेना पर विवादित बयान देने के मुकदमे में हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

90 करोड़ मतदाता हैं भारत में 2019 लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के मुताबिक। फर्जी मतदाताओं पर लगाम लगाने के लिए सरकार वोटर आइडी को आधार से लिंक करने को अनिवार्य करने जा रही है।

सीएए प्रस्ताव पर भारत ने जताया एतराज

रखा पक्ष ▶ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यूरोपीय संसद के अध्यक्ष को लिखा पत्र

फ्रांस खुल कर आया भारत के साथ, कहा-सीएए आंतरिक मामला

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ प्रस्तावों को लेकर यूरोपीय संसद के अध्यक्ष डेविड मारिया सासोली को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि एक विधान मंडल का दूसरे विधान मंडल पर फैसला देना अनुचित है। इस चलन का निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता है। पत्र में बिरला ने कहा है कि अंतर-संसदीय यूनियन का सदस्य होने के नाते हमें अन्य विधानमंडलों की संप्रभु प्रक्रियाओं का सम्मान करना चाहिए।

लोकसभा अध्यक्ष ने सीएए को समझाते हुए बताया है कि यह पड़ोसी देशों में धार्मिक प्रताड़ना के शिकार हुए लोगों को आसानी से नागरिकता देने के लिए है, न कि किसी की नागरिकता छीनने के लिए। इसे भारतीय संसद के दोनों सदनों में चर्चा के बाद पारित किया गया है। इस बीच, यूरोपीय संघ (ईयू) ने यूरोपीय संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों की तरफ से पेश नागरिक संशोधन कानून (सीएए) पर बहस और वोटिंग से अपने आपको अलग कर लिया है। यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यूरोपीय संसद में जो विचार व्यक्त किए जाते हैं या इसके सदस्य जो विचार सामने रखते हैं वह जरूरी नहीं है कि ईयू के अधिकारिक विचार हों। संघ ने 13 मार्च को ब्रसेल्स में होने वाली भारत और ईयू की 15वीं बैठक का जिक्र करते हुए कहा है कि भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना जरूरी है।

भारत के लिए यह भी काफी राहत की बात है कि यूरोपीय संघ का एक प्रमुख देश फ्रांस भी उसके साथ आता दिख रहा है। फ्रांस के नई दिल्ली स्थित दूतावास के कूटनीतिक सूत्रों के मुताबिक, 'हमने पहले भी कहा है और आज फिर दोहरा रहे हैं कि सीएए भारत का आंतरिक कानूनी मामला है। आगे हमारा जो भी कदम होगा इसी सोच के साथ होगा।' फ्रांस ईयू के संस्थापक देशों में है और उसका खुलकर साथ मिलने से भारत के लिए यूरोपीय संसद के सदस्यों के सामने अपनी बात रखने में मजबूती आएगी। यूरोपीय संघ के आधिकारिक बयान और फ्रांस के साथ आने के बावजूद यूरोपीय संसद से जो सूचनाएं अभी तक आ रही हैं, उसके मुताबिक वहां 29 जनवरी को सीएए, एनआरसी व जम्मू-कश्मीर पर चर्चा होगी। 30 जनवरी को इस पर वोटिंग भी होगी। यूरोपीय संसद के विभिन्न संसदीय दलों ने सीएए को लेकर छह प्रस्ताव सदन पटल पर रखे हैं। कमोबेश सभी प्रस्ताव भारत सरकार के सीएए को लेकर उठाए गए कदमों की निंदा करते हैं। सबसे ज्यादा निंदनीय प्रस्ताव 154 सांसदों वाली एसएंडडी समूह की तरफ से रखी गई है। इसमें कहा गया है कि सीएए की वजह से दुनिया की सबसे बड़ा नागरिकता संबंधी समस्या पैदा हो सकती है। 182 सांसदों वाली ईपीपी समूह ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि सीएए भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि को काफी नुकसान पहुंचाएगा। यूरोपीय संसद के 751 में से 600 सांसदों ने इन प्रस्तावों का समर्थन किया है। अभी तक भारत को लेकर कभी भी इतना बड़ा प्रस्ताव यूरोपीय संसद में नहीं आया है।

उधर, भारतीय विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, सीएए पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। इसे एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ाया गया है। कोई भी देश जब नागरिकता देता है, तो उसके लिए कुछ शर्त तय करता है। यूरोपीय संघ के भी कुछ सदस्य देश इस तरह के नियमों का पालन करते हैं। सूत्रों ने उम्मीद जताई कि यूरोपीय संसद में इस प्रस्ताव को लाने वाले इस बारे में भारत से विमर्श करेंगे और स्थिति की सही जानकारी लेंगे। भारत को चिंता है कि प्रस्ताव न सिर्फ उसकी छवि को नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि यूरोप में उसके रणनीतिक व आर्थिक हितों पर चोट करेगा।

बयान में दिखा भारत के कूटनीतिक प्रयास का असर

भारत ने यूरोपीय संसद के प्रस्ताव को लेकर अपना कूटनीतिक प्रयास तेज कर दिया है। इसका असर यूरोपीय संघ की तरफ से जारी बयान में दिखा, जिसने भारत की चिंताओं को दूर करने की कोशिश की। संघ के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, 'यूरोपीय संसद भारत सरकार की तरफ से तैयार एक कानून पर बहस करने पर विचार कर रही है। यह कानून दिसंबर, 2019 में बना है, जो कुछ पड़ोसी देशों से आने वाले कुछ खास धार्मिक समुदाय के लोगों को तेजी से नागरिकता देता है। सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार कर रहा है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है, जिसमें प्रस्ताव के मसौदे को जारी किया गया है। भारत ईयू का एक अहम रणनीतिक साझेदार देश है, जो वैश्विक चुनौतियों को देखते हुए और दुनिया में कानून सम्मत व्यवस्था कायम करने के लिए जरूरी है। मैं यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि यूरोपीय संसद की तरफ से व्यक्त विचार या किसी सांसद की तरफ से व्यक्त विचार यूरोपीय संघ के आधिकारिक स्थिति को प्रस्तुत नहीं करते।'

सीएए और एनपीआर पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का फिर इन्कार

- नई याचिकाओं में लोगों पर सरकारी निगरानी की आशंका जताई गई
- पिछले हफ्ते भी सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर रोक से किया था इन्कार

सुप्रीम कोर्ट। फाइल फोटो।

नई दिल्ली, एएनआइ : सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया है। सोमवार को शीर्ष अदालत ने नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को चुनौती देने वाली नई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।

सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की पीठ ने नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पर रोक को लेकर कोई आदेश पारित नहीं किया। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं को दूसरी याचिकाओं के साथ जोड़ने का आदेश दिया। गौरतलब है कि इसी तरह पिछले हफ्ते भी सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 140 याचिकाओं पर सुनवाई की थी और केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में केंद्र सरकार को चार हफ्ते में जवाब देने को कहा था। आल इंडिया यूनाइडेट डेमोक्रेटिक फ्रंट, असन जन मोर्चा और अन्य की तरफ से ये नई याचिकाएं दायर की गई हैं।

शीर्ष अदालत में दाखिल की गई एक याचिका में कहा गया है कि इस तरह के डाटा एकत्र करने से लोगों पर सरकार द्वारा गैरकानूनी तरीके से निगरानी का खतरा बढ़ जाएगा। यह भी कहा गया है कि अगर यह डाटा किसी तीसरे पक्ष द्वारा अवैध रूप से हासिल कर लिया जाता है तो उसके लिए न तो कोई प्रावधान किया गया है और न ही जिम्मेदारी तय की गई है। इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। याचिका में प्रक्रिया के तरीके पर भी सवाल उठाया गया है।

बता दें कि सीएए में 31 दिसंबर, 2014 से पहले तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध और जैन समुदाय के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है।

बंगाल विधानसभा में भी सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ सोमवार को बंगाल विधानसभा में भी प्रस्ताव पास हो गया। इससे पहले केरल, पंजाब और राजस्थान विधानसभा में सीएए विरोधी प्रस्ताव पास किया जा चुका है। प्रस्ताव का समर्थन करने के बावजूद वाममोर्चा व कांग्रेस की ओर से उसमें संशोधन की मांग की गई थी, लेकिन उस पर कोई मतविभाजन नहीं हुआ। भाजपा ने इसका विरोध किया। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री पार्थ चटर्जी ने सदन में दोपहर दो बजे सीएए के विरोध में प्रस्ताव पेश किया। इसमें केंद्र सरकार से सीएए को रद करने और एनआरसी के क्रियान्वयन एवं एनपीआर की योजनाओं को निरस्त करने की अपील भी की गई।

प्रस्ताव पर बहस के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा में कहा कि हमलोग बंगाल में सीएए, एनपीआर और एनसीआर लागू नहीं करने देंगे। हमलोग शांतिपूर्ण ढंग से इसका विरोध करेंगे। यह प्रदर्शन केवल अल्पसंख्यकों का नहीं बल्कि सभी का है। इस आंदोलन का सामने से नेतृत्व करने के लिए मैं हिंदू भाइयों का धन्यवाद करती हूं। उन्होंने सीएए के मुद्दे पर वाममोर्चा और कांग्रेस सहित अन्य दलों को एक साथ मिलकर लड़ने की बात कही। जब प्रस्ताव पेश किया जा रहा था तभी विधानसभा के उत्तरी गेट के सामने कांग्रेस छात्र परिषद के सदस्य विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।

सीएए के खिलाफ जारी रहेगी लड़ाई : ममता बनर्जी

जागरण संवाददाता, कोलकाता

- तृणमूल के छात्र संगठन को घर-घर जाकर सीएए व एनआरसी के खिलाफ लोगों को जागरूक करने का निर्देश

बंगाल की मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने सोमवार को फिर दोहराया कि सीएए के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। बाहुबल से इसे लागू नहीं होने दिया जाएगा। वह नेताजी इंडोर स्टेडियम में तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद के सम्मेलन को संबोधित कर रही थीं। छात्र संगठन को घर-घर जाकर सीएए-एनआरसी के खिलाफ लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया।

उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल में इनके नेता सक्रिय होकर लोगों को सीएए-एनआरसी के बारे में गलत जानकारी देकर बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष और प्रदेश प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय पर निशाना साधते हुए कहा-'एक को चाय की दुकान पर लोगों को सीएए-एनआरसी के बारे में बताना पड़ रहा है तो दूसरा यहां के लोगों के खानपान पर टिप्पणी कर रहा है। हम बंधुआ मजदूर नहीं हैं, बल्कि भारत के नागरिक हैं। आगे की रणनीति की जानकारी देते हुए ममता ने कहा कि 31 जनवरी से छात्र संगठन रानी रासमणि रोड में जारी विरोध-प्रदर्शन की कमान संभालेगा और एक-दो फरवरी को सीएए-एनआरसी के विरोध में राज्यभर में जुलूस निकाला जाएगा। पांच फरवरी को सीएए-एनआरसी के खिलाफ पार्टी की ओर से ब्लॉक स्तर पर मानव श्रृंखला बनाकर विरोध किया जाएगा। छह फरवरी को हाथों में सीएए-एनआरसी विरोधी तख्तियां लिए पार्टी कार्यकर्ता मौन जुलूस निकालेंगे। सात फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण के बाद बजट अधिवेशन होगा और आठ और नौ फरवरी को पार्टी प्रतिनिधि ब्लॉक स्तर पर एससी-एसटी समुदाय के लोगों के घर जाकर उनकी समस्याओं पर उनसे चर्चा करेंगे। 10-13 फरवरी तक पार्टी के नेता बूथ स्तर पर बैठक करेंगे।

'पोहा' वाले बयान को लेकर विजयवर्गीय को घेरा

ममता बनर्जी ने सोमवार 'पोहा' वाले बयान को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को घेरा। उन्होंने कहा कि भगवा पार्टी के नेताओं को खान-पान की आदतों और पहनावे पर टिप्पणी करने का अधिकार किसने दिया?

विदेश में भी सीएए को भारतवंशियों का समर्थन

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनपीआर) के समर्थन का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। विदेशों में भी भारतवंशी इस कानून के समर्थन में लगातार आ रहे हैं। यह नजारा अमेरिका स्थित ह्यूस्टन का है, जहां भारतवंशियों ने नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में बड़ी संख्या में एकत्रित होकर रैली निकाली। रायटर

उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ एनएचआरसी पहुंची कांग्रेस

- सीएए विरोधी प्रदर्शन में पुलिस की शिकायत की, शीघ्र कार्रवाई की मांग
- राहुल गांधी ने कहा-अपने ही नागरिकों के साथ युद्ध कर रही उप्र सरकार

नई दिल्ली में सोमवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष सीएए के विरोध में प्रदर्शन के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस की कथित बर्बरता की शिकायत के बाद मीडिया से मुखातिब (दाएं से) कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और अजय कुमार लल्लू। प्रेट्र

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस की कथित बर्बरता की शिकायत लेकर कांग्रेस राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पहुंच गई है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की अगुआई में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने वालों के खिलाफ सूबे में पुलिस-प्रशासन के कथित जुल्म की शिकायतों के दस्तावेज सौंपते हुए एनएचआरसी से तत्काल जांच कर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने पीड़ितों को ही आरोपित बना दिया है। राहुल ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने ही नागरिकों के खिलाफ युद्ध कर रही है और ऐसे में एनएचआरसी का एक्शन लेना जरूरी है।

सीएए-एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शनों में पुलिस के गंभीर उत्पीड़न की शिकायत एनएचआरसी में दर्ज कराने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर उत्तर प्रदेश सरकार को घेरा। राहुल ने कहा, 'कांग्रेस नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर प्रदेश के नागरिकों के खिलाफ प्रदेश सरकार के अत्याचारों का सुबूत एनएचआरसी को सौंपा। प्रदेश सरकार अपने ही लोगों के खिलाफ युद्ध कर रही है। इसीलिए एनएचआरसी को भारत की अवधारणा और उसके नागरिकों के संवैधानिक अधिकार की रक्षा के लिए निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए।' मानवाधिकार आयोग गई कांग्रेस की टीम में राहुल और प्रियंका के अलावा वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद, राजीव शुक्ला, जितिन प्रसाद और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू आदि शामिल थे।

एनएचआरसी अध्यक्ष और सदस्यों के साथ हुई बैठक के बाद राहुल-प्रियंका की मौजूदगी में अभिषेक मनु सिंघवी ने पत्रकारों से कहा कि हमने एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। इसमें प्रदेश में सीएए-एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की बर्बरता के मामलों से रूबरू कराया गया है। इसके प्रमाण में तीन खंडों में सुबूत दिए हैं। इसमें पीड़ितों के नाम, तस्वीरें और वीडियो आदि उपलब्ध हैं। सिंघवी ने कहा कि कांग्रेस ने नौ बिंदुओं पर आयोग का ध्यान आकृष्ट किया है।

इसमें दो-तीन पर पुख्ता सुबूत भी दिए हैं। कांग्रेस का कहना है कि सूबे में मानवाधिकारों के हनन का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रदर्शनों में 23 मौतें हुई हैं। मगर पुलिस कर्मियों के खिलाफ अभी तक एक भी एफआइआर दर्ज नहीं हुई। सिंघवी ने कहा कि मारे गए लोगों के साथ हुई बर्बरता के ब्योरे के अलावा हमने इलाके व अफसरों के नाम दिए हैं। पुलिस मित्र में आरएसएस-भाजपा के लोगों की भर्ती और उनके जनता के साथ दुश्मन की तरह व्यवहार करने के सुबूत भी सौंपे हैं।

सिंघवी ने कहा कि आयोग को उन सैकड़ों नोटिसों से रूबरू कराया गया है जिसमें खुलेआम उत्तर प्रदेश प्रशासन लोगों को लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध जताने के लिए बाहर आने पर धमका रहा है। विरोध करने से रोकने के लिए प्रशासन लोगों को जेल में बंद करने से लेकर संपत्ति जब्त करने की धमकी दे रहा है और यह मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मसला है।

अमेरिका में भी सीएए विरोधी प्रदर्शन में पाक समर्थकों की घुसपैठ

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिका में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के समर्थन और विरोध में हुए प्रदर्शनों के बीच भारतीय अमेरिकी समुदाय के एक नेता का कहना है कि पाकिस्तान समर्थक तत्वों ने अमेरिका में सीएए-विरोधी प्रदर्शनों में घुसपैठ कर ली है।

भारतीय अमेरिकी समुदाय के नेता अदापा प्रसाद ने बताया कि वाशिंगटन डीसी में हुए हाल के प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों के बीच पाकिस्तान समर्थकों को देखा गया है। इतना ही नहीं, नागरिकता संशोधन कानून विरोधी प्रदर्शन में मुख्य आयोजकों में कम-से-कम दो पाकिस्तानी अमेरिकी शामिल थे। प्रसाद ने बताया कि एक पाकिस्तानी अमेरिकी दरकशन राजा ने वाशिंगटन डीसी में कश्मीरी अलगाववादियों का भी प्रदर्शन आयोजित किया था।

नागरिकता संशोधन कानून विरोधी प्रदर्शन में इसके अलावा पाकिस्तानी अमेरिकी मुस्लिम कार्यकर्ता खुदाई तनवीर मुख्य संयोजकों में शामिल था। प्रसाद और उनकी टीम ने अपनी बात के समर्थन में इस प्रदर्शन के कई वीडियो और फोटो साझा किए। प्रसाद ने बताया कि नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों के पास जो भारत विरोधी पोस्टर बैनर थे, उनमें से एक पर लिखा था, 'हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़ के लेंगे हिंदुस्तान।' प्रसाद ने बताया कि इस रैली में खालिस्तान समर्थक लोग भी अपना एजेंडा चला रहे थे। इनमें से एक का नाम अर्जुन सेठी है।

दूसरी ओर, नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में 500 से अधिक भारतीय अमेरिकियों ने व्हाइट हाउस से लेकर भारतीय दूतावास के सामने स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा तक पदयात्रा की। हालांकि इसके विरोध में करीब न्यूयार्क, शिकागो, ह्यूस्टन समेत 30 अमेरिकी शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए।

बिहार में शरजील की गिरफ्तारी को छापेमारी

जेएनएन, नई दिल्ली

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर शाहीनबाग आंदोलन को बढ़ावा देने और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भड़काऊ भाषण देने के आरोपी शरजील इमाम की गिरफ्तारी के लिए रविवार की अल सुबह उसके पैतृक घर जहानाबाद जिले के काको और पटना के कई इलाकों में छापेमारी की गई। इंटेलीजेंस ब्यूरो (आइबी) ने जहानाबाद और पटना जिला पुलिस के सहयोग से आधा दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की, लेकिन शरजील का कुछ अता-पता नहीं चला। एसपी ने बताया कि शरजील पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा असम में मुकदमे दर्ज हैं।

इधर, शरजील की गिरफ्तारी के लिए भारत-नेपाल सीमा पर तैनात सुरक्षा एजेंसियों ने सोमवार को अलर्ट जारी किया है। सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि वह रक्सौल के सीमाई क्षेत्रों से भाग कर नेपाल में शरण ले सकता है। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत रक्सौल एसडीपीओ संजय कुमार झा ने बताया कि शरजील की गिरफ्तारी के लिए सीमाई क्षेत्र में पुलिस को विशेष सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं ताकि वह नेपाल न भाग सके।

शरजील इमाम। फाइल

जहानाबाद में आइबी की टीम जैसे ही स्थानीय पुलिस के साथ काको पहुंची, वहां अफरातफरी मच गई। हालांकि, शरजील नहीं मिला। इसके बाद केंद्रीय टीम ने उसके दो रिश्तेदारों और एक कार चालक को हिरासत में लिया। थाने में पूछताछ के बाद तीनों को बांड भरवाकर छोड़ दिया गया। बाद में एसपी मनीष कुमार भी पहुंचे और शरजील के स्वजनों से उसके बारे में जानकारी हासिल की। शरजील के चाचा अरशद इमाम ने एसपी को बताया कि वह जैसे ही घर आएगा उसे वह खुद पुलिस के हवाले कर देंगे।

पटना के कई इलाकों में भी छापे : पटना पुलिस के एक वरीय अधिकारी के मुताबिक, शरजील को फुलवारीशरीफ के हारून नगर में सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच 10 सेकेंड के लिए देखा गया था। उसका वीडियो फुटेज खुफिया विभाग को मिला है। जांच में पता चला है कि सब्जीबाग के अबु फकरूद्दीन प्लाजा में शरजील के पिता के नाम से एक फ्लैट है। जहां फिलहाल किराएदार रहता है।

भड़काऊ नहीं था भाषण : चाचा अरशद इमाम ने बताया कि शरजील ने अलीगढ़ में सीएए और एनआरसी के खिलाफ आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया था और जेएनयू का छात्र होने के नाते भाषण दिया था, लेकिन वह भड़काऊ नहीं था। यदि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने वालों को अपराधी माना जाता है तो वह भी अपराधी हैं।

जदयू के टिकट पर चुनाव लड़े थे शरजील के पिता : शरजील के पिता अकबर इमाम 2005 में जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र से जदयू के टिकट पर चुनाव लड़े थे। हालांकि, वह हार गए थे। कुछ साल पहले उनका निधन भी हो गया। छोटा भाई मुजम्मिल इमाम एक राजनीतिक दल से जुड़ा है। शरजील के मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड को खंगाल उसके रिश्तेदारों, दोस्तों व परिचितों के जरिये भी क्राइम ब्रांच की टीम उसे जल्द दबोचने का प्रयास कर रही है। बीती 25 जनवरी की दोपहर शरजील की लोकेशन पटना के दीघा रोड पर मिली थी। इंस्पेक्टर बीएन झा के नेतृत्व में सात पुलिस कर्मियों की टीम रविवार को ट्रेन से पटना के लिए रवाना हुई थी।

क्या है मामला : शरजील इमाम का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दिए भाषण का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वह कह रहा है कि अगर लोग संगठित हो जाएं तो हम भारत से असम को अलग कर सकते हैं।

कोलकाता नगर निगम के फेसबुक पेज पर नक्शे से पीओके गायब

जागरण संवाददाता, कोलकाता

- पोस्ट को लेकर सियासत शुरू, भाजपा ने मांगा मेयर का इस्तीफा
- हटाया गया विवादित नक्शा, मेयर ने साजिश का लगाया आरोप

गणतंत्र दिवस के मौके पर कोलकाता नगर निगम (केएमसी) के फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए भारत के नक्शे से गुलाम कश्मीर के गायब होने को लेकर विवाद शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को लेकर लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई है। विवाद को बढ़ते देख केएमसी ने फेसबुक पेज से विवादित पोस्ट को हटा लिया है। निगम के फेसबुक पेज पर डाले गए भारत के नक्शे में गुलाम कश्मीर और अकसाई चिन के नहीं होने के पीछे कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने 'गहरी साजिश' का आरोप लगाया है।

हकीम ने कहा कि कुछ लोगों ने अपने निहित स्वार्थों के लिए केएमसी की छवि खराब करने के इरादे से उसके प्रोफाइल को हैक कर यह काम किया है। गौरतलब है कि गणतंत्र दिवस पर निगम के फेसबुक पेज पर गुलाम कश्मीर और अकसाई चिन के बगैर डाले गए भारत के नक्शे को लेकर केएमसी के सामने असहज स्थिति पैदा हो गई। इस नक्शे के साथ मेयर का गणतंत्र दिवस का संदेश भी डाला गया है। नक्शे की छवि वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर मेयर को ट्रोल भी किया गया और बाद में नक्शे को केएमसी ने हटा लिया। भाजपा ने इस मामले पर हकीम को आड़े हाथों लेते हुए उनसे इस्तीफे की मांग की और इस घटना पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बयान की मांग भी की है। इस बारे में भाजपा के प्रदेश महासचिव सायंतन बसु ने सोमवार को कहा, 'हमने हकीम से तत्काल इस्तीफे की मांग की है। क्या नगर निगम कश्मीर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के दावे का समर्थन नहीं कर रहा।'

मध्य क्षेत्र की बैठक से पहले सीएए व एनआरसी पर सियासत गरम

नईदुनिया, रायपुर : छत्तीसगढ़ में मंगलवार को होने वाली मध्य क्षेत्र के चार राज्यों की बैठक से पहले सीएए और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को लेकर सियासत गरम हो गई है। सोमवार को रायपुर की धरती पर उतरते ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम लिए बगैर उनके हालिया बयानों पर जुबानी हमला बोला।

उन्होंने कहा कि सीएए का विरोध सिर्फ दिखावे का है। कांग्रेस ने उनके बयान पर पलटवार किया है। शाह की मौजूदगी में होनी वाली बैठक में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश कांग्रेसशासित राज्य हैं, जबकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड भाजपा शासित राज्य। सीएए और एनआरसी का मुद्दा गरमाने का अंदेशा पहले से ही था। रावत ने कहा कि सीएए और एनआरसी पर सवाल उठाना हास्यास्पद है। यह सिर्फ दिखावे का विरोध है, जो टिकेगा नहीं। रावत का बयान आते ही कांग्रेस ने पलटवार किया।

मप्र में भाजपा के पूर्व विधायक को सीएए पर बोलने से रोका

नईदुनिया, छिंदवाड़ा

- गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान छिंदवाड़ा में हुआ वाकया

मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिले के चौरई कस्बे में एसडीएम ने भाजपा के पूर्व विधायक रमेश दुबे को नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) पर भाषण देने से रोक दिया। इसका विरोध करते हुए दुबे ने कहा कि यह कानून केंद्र सरकार ने पारित किया है, यह विषय संविधान से जुड़ा है। इस पर बोलने से मुझे कैसे रोका जा रहा है। इस पर एसडीएम मेघा शर्मा ने कहा कि ये विवादित विषय है। इसके बाद दुबे ने भाषण समाप्त कर दिया।

यह वाकया चौरई में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में हुआ। भाजपा के पूर्व विधायक रमेश दुबे ने कार्यक्रम के समापन भाषण में सीएए पर बोलना शुरू किया तभी एसडीएम मेघा शर्मा के आदेश पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी दुबे के पास पहुंचे और भाषण समाप्त करने के लिए कहा। इसके बाद मंच से ही पूर्व विधायक दुबे ने एसडीएम से कहा-'यह अधिनियम है मैडम, इस विषय पर बोलने से आप नहीं रोक सकतीं।' जवाब में एसडीएम ने कहा, 'आप गणतंत्र दिवस को लेकर बोलें।' एसडीएम ने कार्यक्रम को जल्द खत्म करने तथा कहीं बैठक में जाने की बात कही तो पूर्व विधायक बोले-'मैंने कहां रोका है, बैठक में जाने से।' इसके बाद दुबे ने भाषण समाप्त करते हुए आरोप लगाया कि मुझे सीएए पर बोलने से रोका जा रहा है।

इस मामले में एसडीएम मेघा शर्मा की प्रतिक्रिया जानने के लिए लगातार प्रयास किए गए, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। व्हाट्स एप पर भी उनसे पूर्व विधायक दुबे के आरोप पर उनकी प्रतिक्रिया चाही तो उसका भी जवाब नहीं मिला।

लोहरदगा में पांचवें दिन कर्फ्यू में ढील, घायल नीरज की मौत

जासं, लोहरदगा : तिरंगा यात्रा के दौरान विगत 23 जनवरी को पत्थरबाजी के बाद लोहरदगा में भड़की हिंसा के बाद जारी कर्फ्यू में सोमवार को पांचवें दिन दो घंटे की छूट दी गई। जानकारी के मुताबिक कर्फ्यू में छूट देने से पहले पुलिस-प्रशासन ने मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। तय हुआ कि कर्फ्यू में ढील उस समय दी जाए, जब लोग अपनी आवश्यकता की चीजें भी खरीद सकें और विधि-व्यवस्था के नियंत्रण में कोई परेशानी भी न हो। अब प्रशासन छूट के दौरान शहर में रही स्थिति की समीक्षा करेगा। इधर, कर्फ्यू में मिली दो घंटे की छूट के दौरान किराने और दवा की दुकानों पर लोगों की खासी भीड़ उमड़ी। एहतियात के तौर पर सशस्त्र बल की टुकड़ियां भी चौकन्ना दिखी। इधर तिरंगा यात्रा के दौरान पिछले दिनों हुई पत्थरबाजी में घायल नीरज प्रजापति की रिम्स के ट्रामा सेंटर में सोमवार को मौत हो गई।

153 वेबसाइटों को सरकार ने जम्मू-कश्मीर में मंजूरी दे दी है, जो अब देखी जा सकती है। वहीं, 2 जिले उत्तर-कश्मीर के और जम्मू के सभी 10 जिलों में 2जी पोस्टपेड सेवा चल रही हैं।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
मंगलवार 28 जनवरी 2020

न्यूज गैलरी

भाजपा कार्यकर्ता की हत्या में बंगाल सरकार से मांगा जवाब

कोलकाता : सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार से भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया की ओर से दायर की गई याचिका पर जवाब देने को कहा है। इस बाबत चार सप्ताह का समय दिया गया है। भाटिया ने 2018 में बंगाल में भाजपा कार्यकर्ता की कथित तौर पर हत्या के मामले में उन्हें पक्षकार बनाए जाने को लेकर याचिका दायर की है। गौरतलब है कि 2018 में पुरुलिया जिले में भाजपा कार्यकर्ता दुलाल सरकार का शव बिजली के टावर पर संदिग्ध हालात में लटकता हुआ बरामद किया गया था। भाटिया ने जनहित याचिका दायर कर मामले की सीबीआइ जांच की मांग की है। मुख्य न्यायाधीश की अगुआई वाली खंडपीठ ने बंगाल सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। (जेएनएन)

बस विस्फोट मामले में बरी दो से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने दौसा जिले के समलेटी में एक बस में बम विस्फोट के 24 साल पुराने मामले में दो आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ राजस्थान सरकार की याचिका पर गौर करते हुए सोमवार को दोनों लोगों से जवाब मांगा। उस घटना में 14 लोगों की मौत हो गई थी। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने मामले में जावेद खान और अब्दुल गनी को बरी करने के खिलाफ राजस्थान सरकार की अपील पर गौर किया और उन्हें नोटिस जारी किए। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व किया। राजस्थान हाई कोर्ट ने पिछले साल 23 जुलाई को खान और गनी सहित छह आरोपियों को बरी कर दिया था जो निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद उम्रकैद की सजा काट रहे थे। (प्रेट्र)

जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट सेवा फिर बहाल

जम्मू : कश्मीर में कुछ घंटे मोबाइल इंटरनेट बंद रखने के बाद इसे फिर से बहाल कर दिया गया है। यह सेवाएं गणतंत्र दिवस समारोह के चलते बंद की गई थीं, लेकिन जैसे ही समारोह शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, सेवाएं रविवार शाम को फिर से बहाल हो गईं। जम्मू कश्मीर में पांच अगस्त के बाद से ही मोबाइल इंटरनेट और ब्राडबैंड पर प्रतिबंध लगा हुआ था। 25 जनवरी को सरकार ने जम्मू-कश्मीर के सभी बीस जिलों में 2जी मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल कर दी थी, लेकिन अभी कुछ घंटे बाद देर शाम को इसे बंद कर दिया गया। हालांकि, प्रशासन ने करीब चौबीस घंटे बाद प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों पर ही इंटरनेट सेवाएं शुरू कर दीं। करीब पांच महीने बाद शुरू हुई इन सेवाओं में प्रशासन ने सोशल साइट्स पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, मगर ई-बैंकिंग सहित कई अन्य साइट्स चल रही हैं। (राब्यू)

कश्मीर मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर

आतंक पर अंकुश ▶ कुलगाम के शाहिद ठोकर के रूप में हुई पहचान

दो सैन्यकर्मी घायल, दो से तीन आतंकियों की तलाश में अभियान जारी

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

दक्षिण कश्मीर के बिजबिहाड़ा में सोमवार को मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। इस दौरान दो सैन्यकर्मी भी गंभीर रूप से घायल हो गए। सुरक्षाबलों ने क्षेत्र में दो से तीन आतंकियों के छिपे होने की आशंका पर तलाशी अभियान जारी रखा है।

अनंतनाग जिले में बिजबिहाड़ा के पास अरवनी में आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर दोपहर को सुरक्षाबलों ने तलाशी अभियान चलाया। जवानों की एक टुकड़ी जब अरवनी में मकड़ मुकादमपोरा क्षेत्र के पास पहुंची तो वहां छिपे आतंकियों ने पहले ग्रेनेड फेंके और उसके बाद गोलीबारी करते हुए भागने का प्रयास किया। इसमें दो सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। अन्य जवानों ने उसी समय अपने घायल साथियों को वहां से हटाते हुए निकटवर्ती अस्पताल पहुंचाया और आतंकियों पर जवाबी फायर किया।

मुठभेड़ की सूचना मिलते ही आसपास के शिविरों से भी अतिरिक्त सुरक्षाबल मौके पर पहुंच गए। उन्होंने पूरे इलाके की चारों तरफ से घेराबंदी करते हुए आतंकियों के भागने के सभी रास्ते बंद कर दिए। इस दौरान कुछ शरारती तत्वों ने कथित तौर पर पथराव भी किया, जिन्हें पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर खदेड़ दिया। हालांकि किसी अधिकारी ने पथराव की पुष्टि नहीं हुई है।

इस बीच, सुरक्षाबलों ने रात को एक आतंकी को मार गिराया। उसकी पहचान कुलगाम के शाहिद ठोकर के रूप में हुई है। इसके बाद कोई गोली नहीं चली। मुठभेड़ तो समाप्त हो गई, लेकिन सुरक्षाबलों ने दो से तीन आतंकियों के छिपे होने की आशंका पर तलाशी अभियान जारी रखा है।

पाक सेना ने एलओसी से आइबी तक की गोलाबारी

जेएनएन, जम्मू : पाकिस्तानी सेना ने गणतंत्र दिवस समारोह में खलल डालने के लिए पुंछ जिला में नियंत्रण रेखा (एलओसी) और कठुआ जिला में अंतरराष्ट्रीय सीमा (आइबी) पर हीरानगर सेक्टर में गोलाबारी की। भारतीय जवानों ने भी गोलाबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाक सेना ने पुंछ जिला के गुलपुर सेक्टर के दिगवार और खड़ी करमाडा में रविवार शाम करीब 6:40 बजे भारतीय सेना की अग्रिम चौकियों पर छोटे हथियारों से गोलाबारी शुरू कर दी। भारतीय सेना की ओर से करारा जवाब मिलने पर कुछ देर बाद पाक सैनिकों ने मोर्टार दागने शुरू कर दिए। इससे पूर्व शनिवार देर रात भी पाक सैनिकों ने खड़ी करमाडा, दिगवार व शाहपुर में भारी गोलाबारी की थी, जो सुबह तक रुक-रुक कर जारी रही। गोलाबारी से भारतीय सेना की कुछ अग्रिम चौकियों के आसपास आग लग गई थी, जिस पर सेना के जवानों ने काबू पाया। वहीं, कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में भी पाक रेंजर्स ने शनिवार व रविवार की रात पप्पू चक, जगवाल पोस्टों से भारतीय क्षेत्र के चक चंगा व छन्नटांडा गांवों को निशाना बनाकर गोलाबारी की, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। सीमा सुरक्षाबल के जवानों ने भी गोलाबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। इससे पहले पाक रेंजर्स मनयारी, पानसर व रठुआ गांवों में गोलाबारी करते रहे थे, जिससे इन गांवों में रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा था और कुछ मवेशी भी मरे थे।

एक सप्ताह में तीसरी मुठभेड़

पिछले एक सप्ताह के दौरान दक्षिण कशमीर में यह तीसरी मुठभेड़ है। इससे पूर्व गत मंगलवार को त्राल के खिरयू में एक मुठभेड़ में पाकिस्तानी आतंकी सैफुल्ला मारा गया था। उसके बाद गत शनिवार को अवंतीपोर के पास एक अन्य मुठभेड़ में जैश के तीन आतंकी कारी यासिर, मूसा और बुराहनुदीन शेख मारे गए थे।

दोषी मुकेश की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

दिल्ली सामूहिक दुष्कर्म कांड

▶ कोर्ट से गुहार, राष्ट्रपति ने जल्दबाजी में लिया दया याचिका पर फैसला

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली सामूहिक दुष्कर्म कांड के दोषी मुकेश की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा। मुकेश ने राष्ट्रपति के दया याचिका खारिज करने के आदेश को चुनौती दी है। साथ ही एक फरवरी के डेथ वारंट पर भी रोक लगाने की मांग की है। यह और बात है कि दया याचिका पर राष्ट्रपति का फैसला अंतिम माना जाता है।

निचली अदालत ने इस मामले में चारों दोषियों मुकेश, अक्षय, विनय और पवन को फांसी दिए जाने के लिए एक फरवरी की तारीख तय की है। मुकेश की दया याचिका राष्ट्रपति गत 17 जनवरी को खारिज कर चुके हैं। हालांकि बाकी के तीन दोषियों ने अभी तक राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दाखिल नहीं की है।

सोमवार को मुकेश की वकील ने प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की पीठ के समक्ष याचिका का जिक्र करते हुए मामले पर शीघ्र सुनवाई की गुहार लगाई। शाम को जारी हुई सुप्रीम कोर्ट की 28 जनवरी की कार्यसूची में मुकेश की याचिका सुनवाई के लिए शामिल थी। मुकेश की याचिका पर जस्टिस आर. भानुमति, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ सुनवाई करेगी। मुकेश ने अपनी याचिका में कहा है कि राष्ट्रपति ने दया याचिका पर ठीक से विचार नहीं किया और जल्दबाजी में उसे खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने गत 14 जनवरी को मुकेश की क्यूरेटिव याचिका खारिज कर दी थी। साथ ही विनय की क्यूरेटिव याचिका भी खारिज कर दी गई थी। क्यूरेटिव याचिका खारिज होने के बाद मुकेश ने दया याचिका भेजी थी।

मालूम हो कि दिल्ली में 16 दिसंबर, 2012 की रात पैरामेडिकल छात्रा से चलती बस में सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। छात्रा से इस कदर दरिंदगी हुई थी कि बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी।

दोषियों की सेल से कुछ दूरी पर हुआ फांसी का ट्रायल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

निर्भया के दोषियों को फांसी की तारीख करीब आने के साथ ही जेल प्रशासन की तैयारियां तेज हो गई हैं। जेल अधिकारी किसी गड़बड़ी की गुंजाइश छोड़ना नहीं चाहते। सोमवार को जेल संख्या तीन में फांसी पर लटकाने का ट्रायल किया गया। करीब चार घंटे तक चले ट्रायल के दौरान दोषी व जल्लाद को छोड़कर जेल के वे सभी अधिकारी व कर्मी मौजूद थे, जिन्हें फांसी की प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहना चाहिए। सूत्रों का कहना है कि मंगलवार को भी ट्रायल किया जाएगा।

एएमयू में हंगामा कर रहे छात्रों को सुरक्षा गार्डों ने पीटा

जागरण संवाददाता, अलीगढ़ : अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में गणतंत्र दिवस भी शांतिपूर्वक नहीं मन सका। समारोह के बीच में ही कुछ छात्रों ने कुलपति गो बैक के नारे लगाकर हंगामा कर दिया। इस पर सुरक्षा गार्डों व अन्य छात्रों ने उनकी पिटाई कर दी। दो फायरिंग भी हुई। तीन छात्र व एक पूर्व छात्र को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। इससे और हंगामा हो गया। छात्रों को तो पुलिस ने शाम को छोड़ दिया। कोदागंज (मऊ) के वाजिदपुर निवासी पूर्व छात्र मुजतबा फराज अहमद को जेल भेज दिया गया। मुजतबा की रिहाई के लिए लोगों ने एएमयू के बगल में अनूपशहर रोड जाम कर सात घंटे प्रदर्शन किया।

एएमयू में 15 दिसंबर को हुए बवाल के बाद से ही धरना जारी है। छात्र सीएए का तो विरोध कर ही रहे हैं, कैंपस में पुलिस को घुसने की अनुमति देने पर कुलपति व रजिस्ट्रार से भी नाराज हैं। दोनों के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस पर विघ्न डालने के पीछे यही कारण माना जा रहा है। कुलपति प्रो. तारिक मंसूर ने एसएस साउथ हॉल स्थित स्ट्रेची हॉल पर ध्वजारोहण के बाद बोलना शुरू किया था, तभी 10-15 युवकों ने कुलपति गो बैक के नारे लगाने शुरू कर दिए। प्रॉक्टोरियल टीम व समारोह में मौजूद अन्य छात्रों ने नारेबाजी करने वालों को घेरकर पीट दिया। नारे लगाने वालों पर भीड़ नाराज थी। प्रॉक्टोरियल टीम इनमें से चार युवकों को बचाकर ले गई और पुलिस को सौंप दिया।

काले हिरण शिकार मामले में अब सुनवाई 30 मार्च को

राज्य ब्यूरो, जयपुर : काले हिरण शिकार मामले में सह अभियुक्तों को बरी किए जाने के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से दायर याचिका पर राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर मुख्य बेंच 30 मार्च को सुनवाई करेगी। जस्टिस मनोज कुमार गर्ग ने फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, नीलम और सोनाली बेंद्रे के वकील की ओर से समय मांगे जाने के बाद इस पर सोमवार को सुनवाई स्थगित कर दी। जोधपुर की सीजेएम कोर्ट इस मामले के पांच सह आरोपितों को संदेह के आधार पर बरी कर चुकी है।

गौरतलब है कि पांच अप्रैल 2018 को अभिनेता सलमान खान को इस मामले में पांच वर्ष कारावास की सजा दी गई थी। हालांकि, कोर्ट ने बाद में सलमान को भी जमानत पर छोड़ दिया था। सलमान खान ने दो रातें जोधपुर जेल में भी बिताई थीं। उनके साथी कलाकार सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम, तब्बू व एक अन्य स्थानीय सहयोगी व सह आरोपित दुष्यंत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए कोर्ट ने बरी कर दिया था।

पीडीपी नेता मुजफ्फर बेग बोले, भारत का अविभाज्य अंग है जम्मू-कश्मीर

राज्य ब्यूरो, जम्मू

▶ कहा-जम्मू-कश्मीर में कभी नहीं हो सकता जनमत संग्रह

▶ गणतंत्र दिवस पर पद्म भूषण से सम्मानित किए गए हैं बेग

सेल्फ रूल का नारा देने वाली पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के संस्थापकों में शामिल और पद्म भूषण से सम्मानित मुजफ्फर हुसैन बेग एक बार फिर पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की लाइन और नीतियों से हटकर मुखर नजर आए। बेग ने कहा कि केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर में कभी भी जनमत संग्रह नहीं हो सकता।

देश के 71वें गणतंत्र दिवस के मौके पर मुजफ्फर हुसैन बेग ने रविवार को जम्मू स्थित पार्टी मुख्यालय में राष्ट्र फहराया। इस मौके पर पत्रकारों के साथ संक्षिप्त बातचीत में उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का एक अविभाज्य अंग है और यह सच्चाई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी स्वीकारते करते हैं। इसलिए वह जम्मू-कश्मीर के लिए स्वायत्तता की मांग करते हैं।

बेग ने कहा कि हम भी भारत सरकार से जम्मू-कश्मीर के लिए वही मांग रहे हैं जो भारतीय संविधान इसे देता है। उन्होंने

मुजफ्फर बेग। फाइल

कहा कि केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदों को पूरा करना चाहिए। उन्होंने सभी राजनीतिक बंदियों की रिहाई का समर्थन करते हुए कहा कि इससे जम्मू-कश्मीर में हालात सामान्य बनाने और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।

हम हमेशा से भारत का हिस्सा है और रहेंगे : इस बार गणतंत्र दिवस पर पद्म भूषण से सम्मानित किए जाने पर बेग ने कहा कि यह सम्मान मुझे नहीं बल्कि जम्मू-कश्मीर लोगों को मिला है। प्रदेश की जनता ने हमेशा ही भारतीय लोकतंत्र में आस्था जताई है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में आम जनता विकास और शांति चाहती है। कश्मीर में अमन, तरक्की और खुशहाली का माहौल बनाने की जिम्मेदारी केंद्र व जम्मू कश्मीर प्रशासन की है। हम हमेशा से भारत का हिस्सा है और रहेंगे।

महबूबा की भड़काऊ बयानबाजी को बता चुके हैं जिम्मेदारी : एकीकृत जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री और वित्तमंत्री रह चुके मुजफ्फर हुसैन बेग को बीते साल महबूबा मुफ्ती ने पीडीपी में बागियों पर काबू पाने के लिए पार्टी संरक्षक बनाया था। बेग अनुच्छेद 370 व अन्य कई मुद्दों पर महबूबा द्वारा अपनाई गई नीतियों के मुखर आलोचक हैं। वह कई बार कह चुके हैं कि महबूबा मुफ्ती के भड़काऊ बयानबाजी के कारण ही केंद्र ने अनुच्छेद 370 को हटाने के साथ जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित राज्यों जम्मू-कश्मीर व लद्दाख में पुनर्गठित किया है।

सीएए के तहत आवेदन देते समय धर्म बताना पड़ेगा

31 दिसंबर, 2014 या उससे पहले भारत आने का सुबूत भी देना पड़ेगा

नई दिल्ली, प्रेट्र : पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन देते समय अपने धर्म का सुबूत पेश करना होगा। इस बात का भी सुबूत देना होगा कि वे 31 दिसंबर, 2014 या उससे पहले भारत आए थे।

एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि सीएए के तहत जो भारतीय नागरिकता चाहेगा, उसे अपनी धार्मिक मान्यता का साक्ष्य देना होगा और सीएए के तहत जारी होने वाली नियमावली में उसका उल्लेख किया जाएगा। सीएए के अनुसार, धार्मिक उत्पीड़न के कारण 31 दिसंबर, 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को अवैध प्रवासी नहीं समझा जाएगा। उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार सीएए के तहत असम में भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन भरने के इच्छुक लोगों को महज तीन महीने का समय दे सकती है। सीएए के क्रियान्वयन के लिए जारी होने वाली नियमावली में असम के लिए कुछ खास प्रावधान किए जाने की संभावना है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और वित्त मंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने सीएए के तहत आवेदन के लिए सीमित समय रखने का अनुरोध किया था। असम के लिए कुछ विशिष्ट प्रावधान भी नियमावली में शामिल करने का अनुरोध किया था।

पिछले साल संसद से इस कानून के पारित होने के बाद से असम में प्रदर्शन हो रहा है। मूल लोगों में यह डर फैलता जा रहा है कि इस कानून से उनके हितों को सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से नुकसान पहुंचेगा।

बघेल के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर हुई पुनर्विचार याचिका

नईदुनिया, बिलासपुर

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ गरीबों की जमीन हड़पने का आरोप लगाते हुए अशोक शर्मा ने हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर दी है। हाई कोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए आर्थिक अपराध अन्वेषण इकाई(ईओडब्ल्यू) व राज्य शासन को नोटिस जारी कर दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए हैं।

याचिकाकर्ता ने पुनर्विचार याचिका में कहा है कि वर्ष 1995 में भूपेश बघेल पाटन विधानसभा क्षेत्र के विधायक निर्वाचित हुए थे। उस वक्त अपने पद व राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए भिलाई अरपा साडा में अपनी पत्नी व मां के नाम जमीन आवंटन के लिए आवेदन लगाया था। अरपा साडा के इंजीनियरों ने आवेदन पर कार्रवाई करते हुए ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित दो भूखंड को चिह्नित किया और चार-चार हजार स्क्वायर फीट जमीन का आवंटन मुख्यमंत्री बघेल की मां व पत्नी के नाम पर कर दिया। यह जमीन गरीबों के लिए आरक्षित की गई

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। फाइल

थी। याचिका के अनुसार जमीन आवंटन की जानकारी के बाद ईओडब्ल्यू में अशोक शर्मा व विजय बघेल(अब भाजपा सांसद) ने शिकायत दर्ज कराई थी। जांच के बाद शिकायत को सही पाते हुए आवेदनकर्ताओं के विरुद्ध ईओडब्ल्यू ने एफआइआर दर्ज की थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस राज्य की सत्ता पर काबिज हो गई और बघेल सीएम बन गए। मुख्यमंत्री बनने के बाद ईओडब्ल्यू ने एफआइआर को रद करते हुए मामले की जांच बंद कर दी और निचली अदालत में क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी। ईओडब्ल्यू द्वारा पेश क्लोजर रिपोर्ट पर विशेष अदालत में सुनवाई हुई और रिपोर्ट पर सहमति जताते हुए क्लोजर रिपोर्ट को मान्य कर लिया।

आरएसएस विचारक गुरुमूर्ति के घर पर पेट्रोल बम से हमले की कोशिश

चेन्नई, एजेंसियां : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) विचारक व तमिल पत्रिका तुगलक के संपादक एस. गुरुमूर्ति के घर पर रविवार की सुबह एक समूह ने पेट्रोल बम से हमले की कोशिश की। हालांकि, कुत्ते के भौंकने और सुरक्षाकर्मियों की सतर्कता के कारण हमलावर अपनी मंशा में सफल नहीं हो सके। इस मामले में पुलिस ने आठ आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने सोमवार को बताया, हमले की कोशिश रविवार की सुबह तीन बजे हुई। थंथई पेरियार द्रविड़ कषगम के आठ सदस्यों ने गुरुमूर्ति के घर पर पेट्रोल बम से हमले की कोशिश की। वे चार बाइकों से आए थे। इसी दौरान गुरुमूर्ति के घर पर मौजूद कुत्ता भौंकने लगा। ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मी जब उस दिशा में भागे तो हमलावर फरार हो गए। पुलिस आयुक्त एके विश्वनाथ ने मौके का दौरा किया। उन्होंने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं।

पुलिस ने एक बयान में बताया कि आठ आरोपित गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उनकी पहचान शशिकुमार, जनार्दन, बालू, तमीष,

एस. गुरुमूर्ति। फाइल

प्रशांत, शक्ति, दीपन और वासुदेवन के रूप में हुई है। शशिकुमार पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उस पर वूडलैंड्स होटल और सत्यम थिएटर पर पेट्रोल बम फेंकने के भी आरोप हैं।

पांच वर्षों से गुरुमूर्ति के घर पर पहरा देता है दोस्त का कुत्ता : गुरुमूर्ति ने हमले के बारे में जानकारी साझा करते हुए ट्वीट किया, 'मेरे परिवार की जीवनशैली कुत्ता रखने की अनुमति नहीं देती, लेकिन मेरे पुराने दोस्त अपने एक कुत्ते को रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक मेरे घर पर पहरेदारी के लिए भेज देते हैं।

एनएसए डोभाल दे चुके हैं सुरक्षा की सलाह : गुरुमूर्ति ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल भी उन्हें सलाह दे चुके हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। खुफिया विभाग के एक अधिकारी अकसर उनके घर आते हैं और सतर्क करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें मारने की यह पहली कोशिश नहीं है, बल्कि 30 वर्षों से यही चल रहा है।

पेरियार पर रजनीकांत के बयान के बाद शुरू हुआ विवाद

14 जनवरी को अभिनेता रजनीकांत ने पत्रिका तुगलक के समारोह में कहा था कि द्रविड़ नेता पेरियार की सलेम में आयोजित रैली में प्रभु श्रीराम-सीता की आपत्तिजनक तस्वीरें लगाई गई थीं। तुगलक ने मंगलवार के अंक में उक्त रैली से संबंधित तस्वीरें और रिपोर्ट प्रकाशित की थीं।

मप्र में सीएए समर्थक व विरोधी भिड़े, कई पुलिसकर्मी घायल

नईदुनिया, जबलपुर

मध्य प्रदेश के जबलपुर में गणतंत्र दिवस के मौके पर सुदर्शन वाहिनी द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा के दौरान सीएए के समर्थकों व विरोधियों में हिंसक झड़प हो गई। जमकर पथराव और वाहनों में तोड़फोड़ की गई। पथराव में दो टीआइ समेत दर्जनभर पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने बल प्रयोग कर उपद्रवियों को खदेड़ दिया।

शहर के अधारताल में आनंद नगर बस स्टॉप के पास विवाद की शुरुआत हुई थी। इसके बाद दोनों समुदाय के लोगों ने एक-दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया। सड़क के किनारे खड़े दो पहिया व चार पहिया वाहनों में तोड़फोड़ करते हुए लोगों के घरों व प्रतिष्ठानों में पत्थर बरसाए गए। पथराव में माढ़ोताल थाना प्रभारी अनिल गुप्ता व मदन महल थाना प्रभारी संदीप अयाची समेत दर्जनभर से ज्यादा जवान घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने लाठियां फटकारते हुए उपद्रवियों को तितर-बितर कर दिया।

हिंसा को लेकर गोहलपुर व अधारताल पुलिस थानों में सैकड़ों उपद्रवियों के खिलाफ नौ आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक अमित सिंह के निर्देश पर दोनों थाना क्षेत्रों में आठ फिक्स पाइंट बनाए गए, जहां आगामी आदेश तक सशस्त्र जवानों को तैनात किया गया है।

बिहार में सीएए के समर्थन में निकली तिरंगा यात्रा

मुजफ्फरपुर : सीएए के समर्थन में सोमवार को बिहार के मधुबनी जिले के बाबूबरही और हरलाखी में भाजपा ने तिरंगा यात्रा निकाली। हरलाखी में मधुबनी के सांसद डॉ. अशोक कुमार यादव ने कहा कि सीएए से किसी भी भारतीय की नागरिकता को खतरा नहीं है। वहीं, सीतामढ़ी में नगर भाजपा की ओर से शहर के गोशाला चौक के पास हस्ताक्षर अभियान चलाया गया।

नापाक इरादे

सरहद पार आतंकी संगठनों, पाक सेना, आइएसआइ ने की बैठक, भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियां हुई चौकस

पाक अभी से कर रहा है गर्मी में घुसपैठ की साजिश

गगन कोहली, राजौरी

गणतंत्र दिवस पर बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए एलओसी पर घुसपैठ की तमाम साजिशें नाकाम होने से सरहद पार आतंकी संगठनों, पाक सेना और आइएसआइ में खलबली मची है। हाल ही में आइएसआइ ने आतंकी संगठनों के कमांडरों के साथ घुसपैठ करने के लिए नया गेम प्लान तैयार किया है। चूंकि इस समय पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हुई है। ऐसे में रास्ते बंद हैं।

इसलिए अब बर्फ पिघलने का इंतजार हो रहा है। इसके चलते अभी से गर्मी की शुरुआत में आतंकियों की बड़े पैमाने पर घुसपैठ कराने के लिए पूरा खाका तैयार कर लिया है। इसकी भनक लगते ही भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियां चौकस हो गई हैं। गौरतलब है कि नवनियुक्त सेना अध्यक्ष ने हाल ही में राजौरी-पुंछ में अग्रिम क्षेत्रों में हालात जाने थे।

सूत्रों के अनुसार सीमा पर कुछ दिनों से लगातार आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडरों के साथ पाक की खुफिया एजेंसी के अधिकारी व पाक सेना के अधिकारी लगातार बैठकें कर रहे हैं। कुछ रोज पहले रावलपिंडी में बैठक हुई थी, जिनमें लश्कर के सरगना हाफिज सईद का भतीजा और दामाद समेत कई आतंकी संगठनों के आतंकी शामिल थे। इसके अलावा आइएसआइ और पाक सेना के अधिकारी भी मौजूद थे। सूत्रों के अनुसार, बैठक में साफ कहा कि जैसे ही गर्मी शुरू होती है घुसपैठ के प्रयास तेज किए जाएं।

जहां बर्फ नहीं वहां घुसपैठ के प्रयास करें : सरहद पार पाकिस्तान में ऐसी रणनीति तैयार की गई है कि जहां इस समय बर्फ नहीं है, वहां पाक सेना बार-बार संघर्ष विराम का उल्लंघन करके अधिक से अधिक आतंकवादियों की घुसपैठ करवाने की कोशिश में जुटी है। भारतीय सेना कड़ा जवाब देते हुए घुसपैठ की सारी कोशिशें नाकाम कर रही है।

बैट को भी अधिक हमलों के निर्देश जारी

सीमा पार बार्डर एक्शन टीम (बैट) जिसमें पाक सेना के विशेष एसएसजी कमांडों के साथ आतंकी और पाक सेना के जवान शामिल हैं, को साफ निर्देश है कि भारतीय क्षेत्र में भारतीय सेना के जवानों पर अधिक से अधिक हमले किए जाएं।

तीन माह में संघर्ष विराम का उल्लंघन

पिछले तीन माह में ही 50 से अधिक बार संघर्ष विराम का उल्लंघन हो चुका है। इसी की आड़ में घुसपैठ की कोशिशें हो चुकी हैं। सेना के पोर्टर सहित पांच जवान शहीद हो चुके हैं। सबसे अधिक पाक गोलाबारी पुंछ के कृष्णा घाटी, शाहपुर किरनी, बालाकोट, राजौरी के तरकुंडी, झंगड़ और लाम में होती है।

इंदौर में कमलनाथ के भाषण से पूर्व दो कांग्रेसी नेताओं के बीच मारपीट

नईदुनिया, इंदौर : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के मुख्य आतिथ्य में इंदौर के कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन पर गणतंत्र दिवस के दिन झंडावंदन से पहले दो स्थानीय नेताओं के बीच जमकर मारपीट हो गई। दोनों नेताओं ने एक-दूसरे को तमाचे मारे। सोमवार को मामला थाने तक पहुंचा और एफआइआर दर्ज कर ली गई।

रविवार सुबह सवा आठ बजे इंदौर के प्रिंस यशवंत रोड स्थित गांधी भवन के बाहर शहर और जिला कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंच गए थे। मुख्यमंत्री कमलनाथ के आने के ठीक पहले स्थानीय कांग्रेस नेता देवेंद्रसिंह यादव और चंदू कुंजीर के बीच मंच के पास जाने को लेकर कहासुनी होने लगी। विवाद बढ़ने पर दोनों मारपीट पर उतारू हो गए। दरअसल, मुख्यमंत्री के मंच के नजदीक एक खास घेरा बनाया गया था। इस घेरे में सिर्फ चुनिंदा पदाधिकारियों को ही आने की अनुमति थी।

'पार्टी ने मुझे व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी दी थी, क्योंकि मैं सभी नेताओं को पहचानता हूं। मुझे जिम्मेदारी दी गई थी कि सुरक्षा घेरे में कोई प्रवेश न करे। हमने मांग की है कि कुंजीर को पार्टी से निकाला जाए।

-देवेंद्रसिंह यादव, कांग्रेस नेता

'हमारे समाज के कुछ लोग सीएम से तान्हाजी फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग करने गए थे। उनके पास शिवाजी महाराज का फोटो भी था। देवेंद्र यादव ने मेरे साथ गाली गलौज की, चांटा मारा और धक्का दिया। इससे फोटो फट गया। हमने इस संबंध में पुलिस को आवेदन दिया है।

- चंदू कुंजीर, कांग्रेस नेता

कुंजीर वहां पहुंचे तो घेरे के अंदर खड़े देवेंद्र यादव ने उन्हें रोका। इस पर दोनों के बीच बहस और मारपीट हो गई। पंढरीनाथ थाना में देवेंद्र सिंह यादव की शिकायत पर चंद्रकांत कुंजीर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

रामजन्मभूमि न मिली तो रामालय न्यास जाएगा कोर्ट

जागरण संवाददाता, वाराणसी : ज्योतिष एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के प्रतिनिधि शिष्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि केंद्र सरकार जब रामालय न्यास को जमीन सौंपेगी तब अयोध्या में रामलला का भव्य दिव्य मंदिर निर्माण शुरू हो सकेगा। इसमें कोई खामी हुई तो न्यास के लोग न्यायालय जा सकते हैं, इससे भी विलंब ही होगा। अतः ट्रस्ट को जल्द जमीन सौंपी जाए ताकि मंदिर निर्माण में विलंब न हो।

न्यायालय में प्रमुख पक्षकार रही श्रीराम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति के उपाध्यक्ष और अयोध्या श्रीरामजन्मभूमि रामालय न्यास के सचिव स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती सोमवार को केदारघाट स्थित श्रीविद्यामठ में पत्रकारों से म

43 फीसदी बच्चों का वजन मध्य प्रदेश में औसत से भी कम है। 2016 में जारी चौथे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार, लगभग 26 प्रतिशत बच्चे अतिगंभीर कुपोषण के शिकार थे।

प्रधानमंत्री को कोई भी अपशब्द कह देता है, और कितनी आजादी चाहिए

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल

जागरण संवाददाता, जयपुर

- फेस्टिवल के आखिरी दिन मीडिया पर दबाव को लेकर हुई गरमागरम चर्चा
- मोदी सरकार के दौरान चार नए न्यूज चैनल को लाइसेंस दिए गए

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में सोमवार को आयोजित सत्र 'चौथा स्तंभ : द फोर्थ एस्टेट' में अपनी बात रखते पांचजन्य के संपादक हितेश शंकर (बाएं), दैनिक जागरण के एसोसिएट एडिटर अनंत विजय (बीच में) और वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी (दाएं)। सौ. जेएलएफ

यह झूठ है कि वर्तमान दौर में आम जनता या मीडिया की आजादी छीनी जा रही है। आज कोई भी मुंह उठाकर सीधे प्रधानमंत्री को अपशब्द कह देता है और इसे अभिव्यक्ति की आजादी बताने लगता है। यह आजादी नहीं है तो फिर क्या है! सच तो यह है कि मीडिया हो चाहे आम जनता, जितनी आजादी इस दौर में सबको मिली हुई है, उतनी पहले कभी नहीं मिली। जिन्हें आजादी महसूस नहीं होती, वे आपातकाल का दौर याद कर लें, जब प्रेस, विपक्षी नेता, कलाकार से लेकर जनता तक को कुछ भी कह सकने की स्वतंत्रता नहीं थी। बोलते ही जेल में डाल दिया जाता था, इसलिए सबको इस आजादी का सम्मान करना सीखना होगा। यह बात जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में सोमवार को आयोजित सत्र 'चौथा स्तंभः द फोर्थ एस्टेट' में कही गई। सत्र में वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी, दैनिक जागरण के एसोसिएट एडिटर अनंत विजय, पांचजन्य के संपादक हितेश शंकर और अतुल चौरसिया ने मॉडरेटर अनु सिंह चौधरी से बातचीत की। सत्र में मीडिया के दक्षिण और वामपंथ के खेमे में बंट जाने पर गरमागरम बहस हुई। थानवी ने कहा- 'आज का मीडिया गोदी मीडिया हो गया है।' प्रत्युत्तर में हितेश शंकर और अनंत विजय ने इसका जोरदार खंडन करते हुए कहा- 'मोदी को अपशब्द कह देने से मीडिया की दुकान चलती है। इसलिए कुछ खास एजेंडे वाला मीडिया दिनभर मोदी को कोसता रहता है। सच तो यह है कि इसके बिना उनका काम ही नहीं चल पाता।'

थानवी ने दी गलत जानकारी : सत्र में थानवी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि '2014 के बाद से चैनल रिपब्लिक के अलावा किसी नए चैनल को लाइसेंस नहीं दिया गया। यह मीडिया का गला घोंटने जैसा है।' इस पर शंकर ने बताया कि मोदी सरकार के दौरान चार नए न्यूज चैनल, 16 मनोरंजन चैनल के लाइसेंस दिए गए हैं।

सोशल मीडिया सच सामने ला रहा : सोशल मीडिया व मुख्य धारा के मीडिया को लेकर चर्चा में कहा गया कि 'सोशल मीडिया अराजक हो गया है, क्योंकि इस पर गलत जानकारियां व अफवाहें चल रही हैं।' इसके जवाब में अनंत विजय और हितेश शंकर ने प्रतिकार किया कि 'कल तक मीडिया की ताकत चंद लोगों के हाथ में थी, आज हर हाथ में मोबाइल है और हर व्यक्ति रिपोर्टर या संपादक है। पहले मीडिया खास विचारधारा के समर्थन में एजेंडा चलाता था, अब संभव नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया ने हर व्यक्ति को सच बताना शुरू कर दिया है।'

पेंदे में छेद वाली बाल्टी है जिंदगी, इसे कैसे भरोगे

ईश्वर शर्मा, जयपुर

- फिल्म 'थ्री इडियट' से प्रसिद्ध हुए सोनम वांगचुक से नईदुनिया ने की खास बातचीत

'जिंदगी क्या है? इसका सटीक जवाब यह है कि 'पेंदे में छेद वाली बाल्टी है जिंदगी, इसे कितना भी भरोगे, ये खाली होती जाएगी। इसलिए इसे भरने में अपना सब कुछ खत्म कर देने के बजाय यह जो है, जैसी है, उसे मस्ती से जीना सीखिए।' यह बात फिल्म 'थ्री इडियट' से प्रसिद्ध हुए लद्दाख के वैज्ञानिक-शिक्षक सोनम वांगचुक ने कही। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के मौके पर दैनिक जागरण के सहयोगी प्रकाशन 'नईदुनिया' ने उनसे खास बातचीत की।

वांगचुक फेस्टिवल में 'क्लाइमेट इमरजेंसी' विषय पर चर्चा करने पहुंचे थे। वांगचुक ने यह स्वीकारा कि फिल्म थ्री इडियट ने उन्हें वैज्ञानिक फुंगसुक वांगडू के रूप में फेमस कर दिया और उसके बाद उनकी जिंदगी में बहुत बदलाव आया। लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग करते हुए पृथक केंद्र शासित प्रदेश बनाने का उन्होंने स्वागत किया। वे बोले- 'क्लाइटमेट में बदलाव का सबसे अधिक असर लद्दाख जैसे इलाके में भी हो रहा है। अब वहां उतनी बर्फ नहीं पड़ती। गर्मी होने लगी है। इससे वहां की जलवायु और संस्कृति खतरे में हैं।'

बाजार के मेंढक मत बनिए : वांगचुक ने सलाह दी कि खुश रहना चाहते हैं तो बाजार के इशारे पर नाचने वाले मेंढक मत बनिए। आप वही खरीदिए जो आपकी सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा, 'भारत उपभोग नहीं बल्कि 'त्येन त्यक्तेन भुंजीथाः' अर्थात त्याग की संस्कृति वाला देश रहा है। आज पश्चिम की होड़ में हम उपभोक्ता बनते जा रहे हैं। इससे हम अपनी स्वाभाविक खुशियां खो देंगे।'

बच्चे जानते हैं 20 ग्राम की जिंदगी : वांगचुक ने चिंता जताई कि आज पांच साल का बच्चा भी जानता है कि 20 ग्राम क्या होता है, क्योंकि वह कार्टून चैनल के विज्ञापनों में वही सब देखता है। दरअसल, बच्चों की जिंदगी ही हमने 20 ग्राम के आसपास समेट दी है।

फूट-फूटकर रोईं अभिनेत्री दीया मिर्जा

ग्लोबल वॉर्मिंग और धरती के बदलते वातावरण पर हुए सत्र में फिल्म अभिनेत्री दीया मिर्जा मंच पर फूट-फूटकर रोने लगीं। वे वातावरण में आ रहे बदलावों, हाल ही में हुई क्रिकेटर की मौत व दुनिया में बढ़ रहे अपराधों जैसे विषयों पर बोल रही थीं। अपनी बात कहते-कहते दीया भावुक हो गईं और यह कहकर रोने लगीं कि हम अपने बच्चों को कैसी दुनिया देकर जाएंगे।

न्यूज गैलरी

पूर्व सैनिकों ने विभिन्न मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया

अहमदाबाद : गुजरात में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों ने गांधीनगर में प्रदर्शन किया। पूर्व सैनिक सरकारी नौकरियों में कड़ाई से आरक्षण लागू करने और शहीदों के आश्रितों को मिलने वाले मुआवजा राशि में वृद्धि करने की मांग कर रहे हैं। अपनी 14 मांगों के समर्थन में पूर्व सैनिक रविवार से शाहीबाग इलाके में शहीद स्मारक पर धरना दे रहे थे। सोमवार को पूर्व सैनिकों ने सचिवालय परिसर तक कार रैली निकाली। पूर्व सैनिकों ने कहा कि गुजरात की भाजपा सरकार दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार की तरह अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए जान देने वाले जवानों के परिवार को मुआवजे के तौर पर एक करोड़ रुपये का भुगतान करे। गुजरात पूर्व सैनिक संघ के अध्यक्ष जितेंद्र निमावत ने कहा, 'दिल्ली में आप सरकार शहीदों के आश्रितों को एक करोड़ रुपये देती है, गुजरात सरकार केवल एक लाख दे रही है। हम चाहते हैं कि यहां की भाजपा सरकार भी मुआवजा बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दे।' (राब्यू)

मप्र में ध्वजारोहण के दौरान आंबेडकर का पोस्टर फाड़ा

शिवपुरी : मध्य प्रदेश में शिवपुरी जिले के ग्राम दावरअली में गणतंत्र दिवस पर शासकीय माध्यमिक विद्यालय में डॉ. भीमराव आंबेडकर का पोस्टर फाड़ने को लेकर बवाल मच गया। ग्रामीणों के समक्ष हुआ घटनाक्रम थाने तक पहुंचा। पुलिस ने दो शिक्षक और एक पंचायत सचिव पर केस दर्ज कर लिया है। ध्वजारोहण कार्यक्रम में ग्रामीणों ने महापुरुषों की प्रतिमा रखे जाने की बात कही। शिकायतकर्ता हरगोविंद ने पुलिस को बताया कि जब लोगों ने डॉ. आंबेडकर की तस्वीर भी रखने को कहा तो शिक्षक नाराज हो गए। वहां मौजूद पंचायत सचिव ने भी विरोध प्रकट करते हुए डॉ. आंबेडकर का पोस्टर फाड़ दिया। पुलिस ने शिक्षक सुरेंद्रसिंह परमार, बृजभानसिंह राजपूत व पंचायत सचिव संतोष के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। (नईदुनिया)

अनुराग ठाकुर ने लगवाए आक्रामक नारे

नई दिल्ली : केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कथित रूप से देश के गद्दारों को लेकर आक्रामक नारे लगवाए। रिठाला में आयोजित जनसभा में अनुराग ठाकुर ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर शाहीन बाग में हो रहे विरोध प्रदर्शन पर सवाल खड़े किए। इस दौरान उन्होंने करीब पांच मिनट तक भीड़ से आपत्तिजनक नारे लगवाए। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में दिल्ली की जनता कमल के फूल का बटन इतनी जोर से दबाएगी कि उसकी गूंज शाहीन बाग होते हुए पाकिस्तान तक पहुंचेगी। (जासं)

हनी ट्रैप केस के साक्ष्य सौंपने पर एसआइटी की टालमटोल

बड़ा मामला ▶ हाई कोर्ट ने आयकर विभाग को सुबूत सौंपने के दिए थे निर्देश

एसआइटी का कहना है कि आदेश मिलने के बाद तय करेंगे आगे की रणनीति

राजीव सोनी, भोपाल

मध्य प्रदेश के बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले में विशेष जांच दल (एसआइटी) द्वारा जब्त सभी साक्ष्य और दस्तावेज आयकर विभाग के हवाले करने को लेकर फिलहाल ना-नकुर की स्थिति है। आयकर इंवेस्टीगेशन विंग का मानना है कि साक्ष्य हाथ में आने के बाद ही जांच की दिशा तय होगी। मामले में रसूखदारों की संलिप्तता, लाखों-करोड़ों रुपए का लेनदेन, कांट्रेक्ट आदि की छानबीन और साक्ष्यों का सत्यापन होना है। इसके बाद कालेधन और बेनामी संपत्ति को लेकर संबंधितों की आर्थिक कुंडली खंगाली जाएगी।

प्रदेश के सियासी और प्रशासनिक हलकों में हलचल मचाने वाले इस प्रकरण में हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने 20 जनवरी को एसआइटी को निर्देश दिए थे कि आयकर विभाग को 10 दिन में प्रकरण से जुड़े साक्ष्य सौंप दिए जाएं। एसआइटी का कहना है कि उसे अभी (सोमवार अपरान्ह तक) हाई कोर्ट का आदेश नहीं मिला है। आदेश देखने के बाद ही अगली कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इधर, आयकर इंवेस्टीगेशन विंग इस इंतजार में है कि हाई कोर्ट के आदेशानुसार उसे जो साक्ष्य उपलब्ध कराए जाएंगे, उनकी पड़ताल के बाद मामले से संबद्ध अन्य लोगों को कालेधन के लेनदेन, हवाला, बेनामी प्रॉपर्टी और टैक्स के मुद्दे पर पूछताछ के लिए तलब करेंगे। प्रकरण में मुख्य आरोपित श्वेता स्वप्निल जैन, श्वेता विजय जैन और आरती दयाल से हुई पूछताछ में आयकर विभाग लेनदेन के संदर्भ में सैकड़ों सवालों के लिखित बयान ले चुका है।

आयकर विभाग पूर्व में दो बार एसआइटी को पत्र भेजकर साक्ष्यों की मांग कर चुका है, जिसमें उसने हनीट्रैप प्रकरण में काली कमाई के लेनदेन की छानबीन में मदद का प्रस्ताव दिया था। निराशा हाथ लगने के बाद ही आयकर ने हाई कोर्ट में गुहार लगाई।

> हनी ट्रैप मामले में आयकर विभाग का मुख्य फोकस आर्थिक लेनदेन की छानबीन पर ही है। बाकी मामले से हमें कोई लेना-देना नहीं। प्रकरण में संबंधित लोगों से यदि राशि का लेनदेन हुआ है तो उसकी पड़ताल होगी, पैसा कहां से आया और कहां गया उसके तथ्य जुटाए जाएंगे। इसके आधार पर टैक्स वसूली निकाली जाएगी।
> **-राजेश टुटेजा, महानिदेशक, आयकर विभाग, मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़**

आदेश देखने पर अगली कार्रवाई

एसआइटी प्रमुख एवं स्पेशल पुलिस महानिदेशक राजेंद्र कुमार ने बताया कि हाई कोर्ट का आदेश अभी हमारे पास पहुंचा नहीं है। कोर्ट के आदेश का अध्ययन और वकील से चर्चा के बाद ही अगली कार्रवाई तय करेंगे। यह पूछने पर कि क्या मामले में पुनर्विचार याचिका भी दायर करेंगे? इस पर वह बोले कि यह तो आदेश देखने के बाद ही निर्णय करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि अभी हनी ट्रैप मामले में आरोपितों से जब्त साक्ष्य व अन्य जानकारी आदि आयकर को नहीं दी गई है।

उम्रकैद मामले में गवली की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार को नोटिस

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने गैंगेस्टर से राजनेता बने अरुण गवली की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है। गौरतलब है कि शिवसेना के पार्षद कमलाकर जामशांदेकर की हत्या मामले में अरुण गवली को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। गैंगेस्टर ने उसी सजा को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

बता दें कि शिवसेना पार्षद जामशांदेकर की 2008 में दो लोगों ने हत्या कर दी थी। अरुण गवली के सहयोगी ने इस हत्या की सुपारी दी थी। उस समय गवली विधायक थे। गवली ने पिछले महीने बांबे हाई कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले को चुनौती दी थी। इसके बाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था। फिर गवली ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने अरुण गवली की अपील पर सुनवाई की सहमति व्यक्त की और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। हाई कोर्ट ने नौ दिसंबर 2019 को गवली की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी थी।

बता दें कि निचली अदालत ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के विभिन्न प्रावधानों के तहत सजा सुनाई थी। गवली को 21 मई 2008 को गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वह महाराष्ट्र की एक जेल में बंद है।

भोपाल गैस कांड में अतिरिक्त मुआवजे पर सुनवाई आज

- 2010 में दायर केंद्र की क्यूरेटिव याचिका पर सुनवाई करेगी संविधान पीठ
- केंद्र सरकार ने अमेरिकी कंपनी से की है अतिरिक्त 7,844 रुपये की मांग

नई दिल्ली, प्रेट्र : भोपाल गैस कांड में 7,844 करोड़ रुपये के अतिरिक्त मुआवजे की मांग वाली केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ मंगलवार को सुनवाई करेगी। सरकार ने अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन (यूसीसी) को खरीदने वाली डो केमिकल्स से मुआवजे की मांग की है। भोपाल गैस कांड 1984 में हुआ था।

जस्टिस अरुण मिश्र, जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस विनित शरण, जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एस. रविंद्र भट की पीठ पीड़ितों के लिए मुआवजा राशि बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से दायर क्यूरेटिव याचिका पर सुनवाई करेगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अतिरिक्त मुआवजा राशि का भुगतान करने के लिए यूनियन कार्बाइड और अन्य कंपनियों को निर्देश देने का अनुरोध किया है। यूनियन कार्बाइड ने 1989 में हुए समाधान के तहत मुआवजे के लिए 47 करोड़ डॉलर (लगभग 750 करोड़ रुपये) का भुगतान किया था।

क्या था मामला : यूसीसी की भोपाल स्थित फैक्ट्री से 2-3 दिसंबर, 1984 की दरम्यानी रात मिथाइल आइसोसाइनेट (एमआइसी) नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। इसमें तीन हजार से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और एक लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे। उचित मुआवजे और सही इलाज के लिए पीड़ितों ने लंबी लड़ाई लड़ी।

केंद्र ने 2010 में दायर की याचिका

मुआवजा राशि बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने दिसंबर, 2010 में सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दायर की थी। सात जून, 2010 को भोपाल की एक अदालत ने इस मामले में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (यूसीआइएल) के सात अधिकारियों को दो साल कैद की सुनाई थी।

वारेन एंडरसन था मुख्य आरोपित

इस मामले में यूसीसी का चेयरमैन वारेन एंडरसन मुख्य आरोपित था, लेकिन उसे कभी पकड़ा नहीं जा सका। हादसे के तुरंत बाद वह अमेरिका भाग गया था। एक फरवरी, 1992 को भोपाल की सीजेएम अदालत ने एंडरसन को भगोड़ा अपराधी घोषित किया था। भोपाल की अदालतों ने 1992 और 2009 में उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किए थे। लेकिन उसका प्रत्यर्पण नहीं हो सका। सितंबर, 2014 में एंडरसन की मौत हो गई थी।

आइआरसीटीसी की वेबसाइट में सेंध लगाने वाले तीन गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, बस्ती

आइआरसीटीसी की वेबसाइट में सेंध लगाने वाले हामिद अशरफ की कमर तोड़ने में जुटी आरपीएफ, सीआइबी व पुलिस की संयुक्त टीम ने रविवार की देर शाम उप्र के मऊ जिले के तीन स्थानों से उसके तीन गुर्गों को गिरफ्तार किया। तीनों हामिद के नेटवर्क से लंबे से जुड़े हुए थे।

बस्ती के रहने वाले हामिद की तलाश में पूरे देश में छापेमारी चल रही है। वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त अमित प्रकाश मिश्र ने बताया कि हामिद ने 2012 में आइआरसीटीसी की वेबसाइट में सेंध लगाकर स्वयं का साफ्टवेयर ब्लैक टीएस बनाया। इसके जरिये वह तत्काल कोटे का टिकट पलक झपकते ही निकाल लेता था। बाद में रेड मिर्ची साफ्टवेयर बनाकर इसने पैनल सेलर बनाना शुरू कर दिया। 2016 में सीबीआइ की गिरफ्त में आने के बाद जब छूटा तो नेपाल चला गया और वहीं से नया एएनएमएस साफ्टवेयर बनाया। बस्ती व गोंडा में दिसंबर और जनवरी में अवैध टिकट के साथ पकड़े गए आधा दर्जन लोगों के कनेक्शन भी हामिद से ही थे। भुवनेश्वर में गुलाम मुस्तफा आरपीएफ के हाथ लगा तो हामिद के आतंकी कनेक्शन सामने आए। इसी के बाद से आरपीएफ के साथ खुफिया एजेंसियां भी उस तक पहुंचने में लग गईं।

इनकी हुई गिरफ्तारी

आरपीएफ इंस्पेक्टर बस्ती नरेंद्र यादव ने बताया कि अमित गुप्ता, नंदन गुप्ता और अब्दुल रहमान उर्फ नेहाल खान को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से तीन लैपटाप, पांच मोबाइल, 261 तत्काल व सामान्य ई टिकट, काउंटर टिकट, जिनकी कीमत सात लाख रुपये से अधिक है, मिले हैं। ये टिकट हामिद के साफ्टवेयर से ही बनाए गए हैं। इनसे आइआरसीटीसी की 150 फर्जी पर्सनल आइडी भी जब्त की गई है।

गोंडा बम विस्फोट का भी आरोपित है हामिद

उप के गोंडा में गत 21 जुलाई 2019 को खोड़ारे थाना क्षेत्र के एक स्कूल में हुए बम विस्फोट में हैकर हामिद अशरफ मुख्य आरोपित है। गोंडा पुलिस इस मामले में उसका घर कुर्क करने की तैयारी में है।

कमर्शियल उड़ानें सबसे सुरक्षित

- हवाई यात्राओं में होती हैं सबसे कम मौतें : शोध
- 2008 और 2017 के बीच पिछले दशकों के मुकाबले एयरलाइन यात्रियों के हताहत होने की घटनाएं कम हुई

ट्रांसपोर्टेशन साइंस में प्रकाशित हुआ शोध। प्रतीकात्मक

बोस्टन, प्रेट्र : आम धारणा के विपरीत हवाई यात्राएं सबसे अधिक सुरक्षित हैं। ताजा शोध के मुताबिक विश्व भर में सबसे कम मौतें कमर्शियल फ्लाइट में ही होती हैं।

ट्रांसपोर्टेशन साइंस में प्रकाशित शोध के मुताबिक वर्ष 2008 और 2017 के बीच पिछले दशकों के मुकाबले एयरलाइन यात्रियों के हताहत होने की घटनाएं बहुत कम हुई हैं। अमेरिका के मैसाचुएट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआइटी) के अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार फिलहाल वैश्विक स्तर पर विमान से होने वाली कमर्शियल यात्राओं में प्रति 79 लाख यात्रियों में सिर्फ एक यात्री की मौत हुई है। जबकि वर्ष 1998-2007 तक प्रति 27 लाख यात्रियों पर एक यात्री की मौत होती थी। लिहाजा सड़क, जल मार्ग के मुकाबले हवाई यात्राएं सुरक्षित हैं। लेकिन इसमें भी प्राइवेट विमान के बजाय कमर्शियल उड़ान से यात्राएं अधिक सुरक्षित हैं। शोध में पाया गया कि वर्ष 1978-1987 के बीच कमर्शियल उड़ानों में मौत का खतरा हर 7,50,000 उड़ानों में से एक का होता था। एमआइटी के विद्वान अर्नाल्ड बार्नेट ने बताया कि हर दो दशक के बाद मौत का खतरा तेजी से घटता जा रहा है। यह बेहद रोचक तथ्य है और यह बात लोगों को अपने दिमाग में बैठा लेनी चाहिए। शोध में यह भी स्पष्ट किया गया है कि एयरलाइन की सुरक्षा साफ तौर पर क्षेत्रीय कारक भी है।

यह पाया गया है कि सबसे कम खतरे वाली एयरलाइनें अमेरिका में हैं। इसके अलावा, यूरोपीय संघ, चीन, जापान, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इजरायल की एयरलाइनें भी बेहद सुरक्षित हैं। अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार इन देशों में वर्ष 2008-2017 के दौरान हर 331 लाख यात्रियों में एक की ही मौत हुई।

इसके अलावा, कुछ अन्य देश भी हैं जहां खतरे का स्तर मध्यम रहता है। यहां वर्ष 2008-2017 के बीच 74 लाख हवाई यात्रियों में केवल एक मौत हुई है। इस श्रेणी में एशिया के अधिकांश देश, दक्षिण अमेरिका के कुछ देश और पश्चिम एशिया के देश शामिल हैं। इसी तरह तीसरी श्रेणी में सबसे खतरे वाले विकासशील देश आते हैं जिसमें कुछ एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देश शामिल हैं। वर्ष 2008-2017 के बीच 12 लाख हवाई यात्रियों में एक की मौत होती है।

वाराणसी में चूहे ने रोक दी उड़ान, रातभर मची रही अफरातफरी

जासं, वाराणसी : वाराणसी के बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से देहरादून जाने वाले एयर इंडिया के विमान में शनिवार की रात चूहा प्रवेश करने की सूचना को लेकर अफरातफरी मच गई। चूहे से खतरे को भांपते हुए उसमें बैठे यात्रियों को उतार दिया गया। काफी खोजबीन के बाद भी चूहा न मिलने पर विमान को रद कर दिया गया। यात्रियों को एयरलाइंस प्रबंधन द्वारा शहर में स्थित एक होटल में ठहराया गया। करीब 24 घंटे बाद दूसरे दिन विमान को भेजा गया।

एयर इंडिया का विमान एआइ 691 कोलकाता से शाम 3.55 बजे उड़ान भरने के बाद 5.20 बजे वाराणसी एयरपोर्ट पर उतरता है। वाराणसी से यही विमान देहरादून के लिए उड़ान भरता है। शनिवार को यह विमान रात लगभग आठ बजे वाराणसी एयरपोर्ट पर पहुंचा। यात्री विमान यहां खाली हुआ और फिर देहरादून जाने वाले यात्री उसमें बैठ गए। उसी समय विमान में बैठे एक यात्री को चूहा दिखाई पड़ा। यात्री ने क्रू मेंबर को तत्काल इसकी जानकारी दी। विमान में बैठे सभी यात्रियों को उतार दिया गया और चूहे की खोजबीन शुरू हो गई।

नक्सलियों ने दो मालगाड़ियों के गार्डों से लूटे तीन वॉकी-टॉकी

नईदुनिया, दंतेवाड़ा

नक्सलियों ने गणतंत्र दिवस के पूर्व शनिवार की रात छत्तीसगढ़ के बचेली और भांसी थाना क्षेत्र में मालगाड़ियों के गार्डों से तीन वाकी-टॉकी लूट लिए। दोनों थानों में मामले के संबंध में रेलवे की ओर से किसी ने अपराध दर्ज नहीं कराया है।

एसपी डॉ. अभिषेक पल्लव ने बताया कि शनिवार की रात नक्सलियों ने दो जगह लूट की। रात करीब साढ़े सात बजे कुछ जनमिलिशिया सदस्य बचेली स्टेशन पहुंचे और मालगाड़ी के गार्ड और चालक से दो वाकी-टॉकी लूट ले गए। लूट की दूसरी घटना कमालूर स्टेशन पर हुई। यहां भी नक्सली मालगाड़ी के गार्ड से रात करीब साढ़े दस बजे वाकी-टॉकी, टॉर्च और मोबाइल लूट ले गए।

फ्रिक्वेंसी बदलकर करते हैं उपयोग : एसपी ने बताया कि नक्सली लूटे गए वाकी-टॉकी का उपयोग फ्रिक्वेंसी बदलकर करते हैं। रेलवे का वाकी-टॉकी ज्यादा शक्तिशाली नहीं होता। उसकी रेंज डेढ़ से दो किमी तक ही होती है। एसपी के अनुसार नक्सली बड़ी वारदात को अंजाम देते समय टुकड़ियों में बंटे समूह के साथ बातचीत करने में इसका इस्तेमाल करते हैं।

छत्तीसगढ़ के बीजापुर में तीन वाहनों में लगाई आग

बीजापुर, नईदुनिया : बीजापुर जिले के मोदकपाल थाना क्षेत्र में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर नक्सलियों ने सड़क निर्माण में लगे तीन वाहनों को आग के हवाले कर दिया। एसपी दिव्यांग पटेल ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण में ये वाहन लगे थे। वाहन पुसगुडी स्कूलपारा में खड़े थे। जहां हथियारबंद नक्सलियों ने वारदात की। नक्सली इस इलाके में सड़क निर्माण का विरोध कर रहे हैं।

रज्जू भैया स्कूल में प्रवेश परीक्षा एक मार्च को

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर

- देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यह पहला सैनिक विद्यालय
- शहीद सैनिकों के बच्चों के लिए आठ सीट आरक्षित

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर स्थित शिकारपुर क्षेत्र के खंडवाया में बनाए जा रहे रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर स्कूल का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। कक्षा छह से 12 तक के इस स्कूल में प्रवेश की तैयारी भी शुरू हो गई है। कक्षा छह में प्रवेश के लिए 23 फरवरी तक पंजीकरण करा सकते हैं। एक मार्च को प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। छह अप्रैल से शैक्षिक सत्र शुरू हो जाएगा। इसके लिए विद्यालय समिति की बैठक भी हो चुकी है। विभिन्न राज्यों से अभिभावक पंजीकरण के लिए पहुंचे रहे हैं।

देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यह पहला सैनिक विद्यालय है। यहां संस्कृति और संस्कार मूल में होंगे, जो देश के भावी सैनिकों को प्रदान किए जाएंगे। आरएसएस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि शिक्षा के साथ बच्चों का नैतिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन किया जाएगा। यह केवल आवासीय विद्यालय में ही संभव है। इस विद्यालय में सीबीएसई पैटर्न पर पढ़ाई होगी। फिलहाल यहां लड़कों का प्रवेश होगा। बाद में लड़कियों के प्रवेश पर भी विचार किया जाएगा। स्कूल का संचालन आरएसएस की शिक्षा शाखा विद्या भारती करेगी। यहां छात्रों को रक्षा का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

विद्यालय प्रबंध समिति अध्यक्ष शिवकुमार के मुताबिक, कक्षा छह में प्रवेश के लिए कुल 160 सीटें हैं। युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के बच्चों के लिए आठ सीटें आरक्षित हैं। शहीदों के बच्चों को आयु में कुछ छूट दी जाएगी। इसके अलावा कोई आरक्षण नहीं होगा। स्कूल प्रबंधक डीके शर्मा के मुताबिक, स्कूल में छात्र और शिक्षक दोनों के लिए यूनिफार्म व्यवस्था रहेगी।

लिखित परीक्षा के बाद साक्षात्कार व मेडिकल होगा

स्कूल के लिए भूमि पूर्व सैनिक चौधरी राजपाल सिंह ने दान की है। समिति सदस्य जयप्रकाश गर्ग ने बताया कि विद्यालय आठ एकड़ भूमि पर बना है। प्रवेश परीक्षा में बच्चे की तर्क शक्ति, सामान्य ज्ञान, गणित की क्षमता जांची जाएगी। अंग्रेजी का ज्ञान भी परखा जाएगा। लिखित परीक्षा के बाद साक्षात्कार होगा। इसके बाद मेडिकल परीक्षा होगी।

'छपाक' के निर्माता ने कहा अधिवक्ता को दिया श्रेय

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- अपर्णा भट्ट की अवमानना याचिका पर दिया जवाब

दिल्ली हाई कोर्ट में हिंदी फिल्म 'छपाक' के निर्माता और निर्देशक पर अवमानना की कार्यवाही करने की मांग वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। फिल्म की निर्देशक मेघना गुलजार और निर्माता फॉक्स स्टार स्टूडियो की तरफ से हाई कोर्ट को बताया गया कि भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज की गई फिल्म में लक्ष्मी अग्रवाल की अधिवक्ता अपर्णा भट्ट को श्रेय दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय रिलीज में श्रेय नहीं दिया गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी।

अधिवक्ता अपर्णा भट्ट ने याचिका दायर कर कहा था कि दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक के निर्माताओं के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जाए, क्योंकि उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया। हाई कोर्ट ने फिल्म के निर्माण में अधिवक्ता अपर्णा भट्ट के योगदान को देखते हुए 11 जनवरी को आदेश दिया था कि उन्हें भी श्रेय दिया जाए।

फिल्म की निर्देशक मेघना गुलजार और निर्माता फॉक्स स्टार स्टूडियो को हाई कोर्ट ने कहा था कि क्रेडिट स्लाइड में दर्ज किया जाए कि अपर्णा भट्ट से जो इनपुट लिए गए, उन्हें स्वीकार किया गया है। कोर्ट की तरफ से कहा गया कि जिन सिनेमाघरों में फिल्म की डिजिटल कॉपी दी गई है, उनमें 15 जनवरी तक इन बिंदुओं को लागू करना होगा। इसके अलावा केबल टीवी, डीटीएच, इंटरनेट मनोरंजन और अन्य माध्यमों पर फिल्म अधिवक्ता के श्रेय के बगैर प्रसारित नहीं हो सकेगी। इन आदेशों को जब माना नहीं गया तो अपर्णा भट ने अवमानना की याचिका दायर कर दी।

दैनिक जागरण
स्वयं को जानने से बड़ा कोई और ज्ञान नहीं

एयर इंडिया की बिक्री

सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया को बेचने की एक और पहल समय की मांग है। घाटे में डूबी किसी कंपनी को इस आधार पर चलाते रहने का कोई मतलब नहीं कि वह एक सार्वजनिक उपक्रम है। यह सही है कि एयर इंडिया एक बड़ा ब्रांड है और उसे खास सरकारी कंपनी होने का तमगा भी हासिल है, लेकिन अगर ऐसी कोई कंपनी खजाने पर बोझ बन जाए तो फिर उसे चलाते रहना न तो आर्थिक दृष्टि से समझदारी है और न ही प्रशासनिक नजरिये से। सरकार का काम उद्योग-धंधे चलाना नहीं होता। उसका काम तो ऐसे नियम-कानून और साथ ही निगरानी व्यवस्था बनाना होता है जिससे हर तरह के उद्योग-धंधे सही तरह से चल सकें। इनमें एयरलाइंस भी शामिल हैं। बेहतर हो कि सरकार अपनी विनिवेश नीति को धार दे और इसके पहले कि अन्य सार्वजनिक उपक्रमों की स्थिति डांवाडोल हो, उनका विनिवेश किया जाए। उसे इससे अवगत होना चाहिए कि यदि कोई सरकारी कंपनी घाटे की चपेट में आ जाती है तो फिर उसका विनिवेश तो मुश्किल से होता ही है, अपेक्षित राजस्व भी नहीं मिल पाता। उसे इससे भी परिचित होना चाहिए कि सेवा क्षेत्र की सरकारी संस्थाएं निजी संस्थाओं का मुकाबला नहीं कर सकतीं।

किसी भी ऐसी सरकारी कंपनी का विनिवेश करना ही बेहतर है जो घाटे से उबर न पा रही हो। एयर इंडिया इसी तरह की एक कंपनी है। उसका सालाना घाटा बढ़ता जा रहा है। यदि उसके विनिवेश में और देरी हुई तो ऐसी भी नौबत आ सकती है कि उसे बंद करना पड़े। मोदी सरकार ने दो वर्ष पहले भी एयर इंडिया को बेचने की कोशिश की थी, लेकिन तब केवल 76 फीसदी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया था और साथ ही भारी-भरकम बकाया राशि चुकाने की शर्त लगाई थी। माना जाता है कि इसी कारण कोई खरीदार आगे नहीं आया। इस बार सरकार ने सौ प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का इरादा जाहिर करने के साथ ही बोली की शर्तों को आसान किया है। देखना है कि ये आसान शर्तें एयर इंडिया के विनिवेश को आसान बनाती हैं या नहीं? जो भी हो, यह हैरानी की बात है कि उदारीकरण को आगे बढ़ाने और विनिवेश नीति का श्रीगणेश करने वाली कांग्रेस एयर इंडिया की बिक्री की पहल का विरोध कर रही है। यह दिखावे की राजनीति के अलावा और कुछ नहीं। कम से कम कांग्रेस को तो इससे अच्छी तरह परिचित होना ही चाहिए कि आर्थिक मामलों में दिखावे की इसी राजनीति ने सार्वजनिक उपक्रमों की हालत खस्ता की है। सरकारी संपत्ति बेचने पर हाय-तौबा मचाना इसलिए व्यर्थ है, क्योंकि विनिवेश के जरिये हासिल राजस्व अर्थव्यवस्था को गति देने में ही इस्तेमाल होता है।

जानलेवा चाइनीज डोर

पंजाब में एक दूसरे की पतंग काटने लिए गैरकानूनी तरीके से इस्तेमाल की जा रही चाइनीज डोर जिंदगी की डोर काटने लगी है। कहीं यह डोर बिजली की अच्छी सुचालक होने का उदाहरण पेश करते हुए सांसों को झटका दे रही है तो कहीं यह कसाई की भूमिका निभाते हुए लोगों के गले काट रही है। दूसरी ओर, पुलिस और प्रशासन पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशों पर चाइनीज डोर की बिक्री और इसके चलन को रोक पाने में असफल साबित हो रहे हैं। राज्य में लगभग हर रोज लोग इस जानलेवा डोर के साथ पतंगबाजी कर रहे हैं और जख्मी भी हो रहे हैं, इसके बावजूद इस डोर से खूनी खेल खेलने वालों पर नकेल नहीं कसी जा रही रही है। यही वजह है कि गत दिनों इस डोर से जालंधर एवं बठिंडा में भी दो लोगों के गले कट गए। शुक्र है कि दोनों की जान बच गई। जालंधर में जिस व्यक्ति का गला कटा है वह अपने दोपहिया वाहन पर घर से सैलून पर काम के लिए जा रहा था। दोमोरिया पुल रेलवे ओवरब्रिज पर उसके गले में चाइनीज डोर लिपट गई। जब तक वह संभलता उसकी गर्दन पर गहरा कट लग गया। लोगों ने तुरंत खून से लथपथ व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया। इसी तरह बठिंडा में एक बुजुर्ग स्कूटर से बस स्टैंड की तरफ जा रहा था कि रास्ते में खूनी डोर ने उसे अपना शिकार बना डाला। बुजुर्ग की गर्दन बुरी तरह से कट गई। डोर से होने वाले हादसे कोई नए नहीं हैं, इससे पहले भी विगत कुछ वर्षों पर नजर डालें तो कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और कई लोग इससे अपने अंग कटवाकर इसके खतरनाक होने की गवाही दे रहे हैं। लोग फिर भी मान नहीं रहे हैं और खतरे से खेलकर खुद तो जोखिम उठा ही रहे हैं साथ ही दूसरों की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। पंजाब में गांव से लेकर शहरों तक सब जगह प्रतिबंधित चाइनीज डोर चोर दरवाजे से बिक रही है, पतंगबाजी के लिए इसका इस्तेमाल भी सरेआम हो रहा है और हर रोज लोग इससे लहूलुहान होकर अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, परंतु बड़ी हैरानी की बात है कि पुलिस और प्रशासन को न तो कहीं पर चाइनीज डोर बिकती हुई मिल रही है और न ही इससे जख्मी होने वाले लोग नजर आ रहे हैं। सरकार को चाहिए कि वह चाइनीज डोर की बिक्री और इस्तेमाल के खिलाफ सख्त कदम उठाए।

पंजाब में गांव से लेकर शहरों तक सब जगह प्रतिबंधित चाइनीज डोर चोर दरवाजे से बिक रही है, पतंगबाजी के लिए इसका इस्तेमाल भी सरेआम हो रहा है

नए सिरे से विचार हो मुक्त व्यापार पर

डॉ. भरत झुनझुनवाला

प्रत्येक देश को अपनी स्थिति एवं अपने हितों के अनुसार उन खास देशों से विदेश व्यापार को बढ़ाना चाहिए जिससे उन्हें परस्पर लाभ होता दिखे

बजट का एक प्रमुख विषय विदेशी व्यापार का होता है। बजट में सरकार तय करती है कि विदेशों से आयातित हो रहे माल पर कितना आयात कर लगाया जाए और विदेशों से आ रहे निवेश को कितनी सहूलियत दी जाए। इस विषय पर आज हमारे सामने दो विरोधाभासी विकल्प उपलब्ध हैं। यदि हम मुक्त व्यापार को अपनाते हैं तो हमें आयात कर घटाना होगा और विदेशी निवेश को सहूलियतें देनी होंगी। इसके विपरीत यदि हम मानते हैं कि घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने से लाभ होगा तो हम आयात कर बढ़ाएंगे और घरेलू पूंजी को बाहर जाने से रोकने का प्रयास करेंगे। खुले व्यापार के पक्ष में चीन का उदाहरण सामने है। 1995 में विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ की स्थापना के समय चीन इस संस्था का सदस्य नहीं था। बड़ी मशक्कत के बाद चीन उसका सदस्य बना। चीन के आर्थिक विकास में डब्ल्यूटीओ ने चार चांद लगाए। इसीलिए अर्थशास्त्रियों का एक वर्ग मानता है कि हमें मुक्त व्यापार को अपनाना चाहिए जैसा कि चीन ने किया। हालांकि विचारणीय यह भी है कि चीन के आर्थिक विकास का स्रोत मुक्त व्यापार है या घरेलू बचत? 2008 में हमारी घरेलू बचत दर 37 प्रतिशत थी और चीन की 51 प्रतिशत। घरेलू बचत उस रकम को बोलते हैं जिसकी हम खपत न करके निवेश करते हैं। वर्तमान में भारत की घरेलू बचत दर घटकर 31 प्रतिशत और चीन की घटकर 46 प्रतिशत हो गई है। चीन की तुलना में हम ज्यादा खपत और निवेश कम कर रहे हैं। मेरे खयाल से चीन के आर्थिक विकास का मुख्य स्रोत डब्ल्यूटीओ की सदस्यता न होकर यही घरेलू बचत दर है। इसके अन्य प्रमाण भी उपलब्ध हैं।

जर्मनी की बर्तल्स्मान संस्था द्वारा डब्ल्यूटीओ के 25 वर्षों के प्रभाव का आकलन किया गया। उनके अनुसार भारत और चीन, दोनों पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। चीन की जनता के जीवन स्तर में डब्ल्यूटीओ का योगदान मात्र 0.65 प्रतिशत रहा है जबकि भारत में 2.68 प्रतिशत। यह महत्वपूर्ण इसलिए है, क्योंकि चीन ने खुले व्यापार को पुरजोर तरीके से अपनाया जबकि भारत ने कम ही अपनाया है। दोनों देशों के निर्यात में वृद्धि अवश्य हुई है, लेकिन उसका असर जनता के जीवन स्तर पर भारत में अधिक पड़ा है। अतः कम विदेशी व्यापार से जीवन स्तर में अधिक सुधार हुआ। इसलिए अधिक विदेशी व्यापार को चीन की जनता के जीवन स्तर में सुधार का कारण नहीं बताया जा सकता। उसका वास्तविक कारण चीन की घरेलू बचत दर है। भारत की घरेलू बचत दर कम होने के बावजूद हमारी जनता के जीवन स्तर में सुधार अधिक हुआ है, क्योंकि हमने मुक्त व्यापार को कम अपनाया है।

चीन को मुक्त व्यापार से कम लाभ होने का दूसरा प्रमाण यह है कि इसी माह चीन ने अमेरिका के साथ एक द्विपक्षीय समझौता किया। चीन ने अमेरिका को आश्वासन दिया है कि वह अमेरिका से कुछ वस्तुओं का आयात बढ़ाएगा। इसके बदले में अमेरिका ने कहा है कि वह चीन से आयातित होने वाली वस्तुओं पर लगाए आयात कर को घटाएगा। इस बीच बड़ा सवाल यही है कि इन देशों को डब्ल्यूटीओ के दायरे से बाहर जाकर द्विपक्षीय समझौते की जरूरत क्यों पड़ी?

यदि चीन का मुक्त व्यापार मंत्र ही सही है तो चीन अपने आयात कर घटाकर संपूर्ण विश्व से आयातों को बढ़ा सकता था, लेकिन डब्ल्यूटीओ की बहुराष्ट्रीय व्यवस्था के अंतर्गत व्यापार को संचालित करने के स्थान पर इन दोनों देशों ने द्विपक्षीय समझौता किया है। यह समझौता खुले व्यापार का लाभ हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि अमेरिका और चीन के सामरिक स्वार्थों से कहीं अधिक प्रेरित है। या फिर हम कह सकते हैं कि उन्होंने खुले व्यापार को उपयुक्त नहीं माना, इसीलिए उन्होंने सभी देशों के लिए खुले व्यापार को अपनाने के बजाय आपस में खोलने तक सीमित रखा है। इसका अर्थ हुआ कि डब्ल्यूटीओ की व्यवस्था में मुक्त व्यापार लाभप्रद नहीं रह गया है। प्रत्येक देश को अपनी स्थिति एवं अपने हितों के अनुसार उन खास देशों से विदेश व्यापार को बढ़ाना चाहिए जिससे उन्हें परस्पर लाभ होता दिखे। इस तरह देखें तो मुक्त व्यापार का सिद्धांत अनुपयुक्त हो गया है।

ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की जयश्री सेनगुप्ता के अनुसार भारत के कई देशों विशेषकर आसियान देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते हो चुके हैं। यानी डब्ल्यूटीओ से बाहर आ जाने पर भारत को कोई विशेष नुकसान नहीं। इसके कई कारण हैं। पहला यह कि आसियान की तर्ज पर हम दूसरे प्रमुख देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते कर अपने व्यापार को अपेक्षित दिशा में ले जा सकते हैं। दूसरा यह कि डब्ल्यूटीओ से बाहर निकलकर हम अपने चिन्हित उद्योगों को संरक्षण दे सकेंगे। छोटे उद्योगों को इसका सबसे अधिक लाभ मिलेगा। इससे रोजगार के अवसर सृजित होंगे और अर्थव्यवस्था में जमीनी स्तर पर मांग बढ़ेगी जो वृद्धि दर को तेजी देने का काम करेगी। डब्ल्यूटीओ से बाहर निकलकर हमें मौजूदा पेटेंट एक्ट के मकड़जाल से भी मुक्ति के रूप में तीसरा फायदा मिलेगा। हम विदेशी कंपनियों के उत्पादों की नकल करके उन्हें यहां भी बना सकेंगे। इससे देसी कंपनियों के लिए अवसर बढ़ेंगे और रॉयल्टी की मद में देश से बाहर जा रही रकम बचेगी। इसका चौथा लाभ पर्यावरण के मोर्चे पर मिलेगा। असल में खुले व्यापार में उसकी जीत होती है जो अपने पर्यावरण को सर्वाधिक नष्ट करता है। जैसे चीन ने अपनी नदियों और हवा को प्रदूषित करने की पूरी छूट दे दी। चीन के सस्ते उत्पादों की एक वजह यह भी है। पर्यावरण की इस क्षति से चीन में उत्पादन लागत कम आती है और वह विश्व व्यापार में आगे है। यदि हम डब्ल्यूटीओ से बाहर आते हैं तो हम चीन के सस्ते माल पर भारी आयात कर लगाकर उसके आयात को रोक सकेंगे। तब हमें भी अपने पर्यावरण को नष्ट करके सस्ता माल बनाने की होड़ में पड़ने की जरूरत नहीं होगी।

पांचवां कारण यह है कि भविष्य में विश्व व्यापार का विस्तार मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र में होगा। यह क्षेत्र मूल रूप से डब्ल्यूटीओ से बाहर है। इसीलिए हमारी सेवाओं के निर्यात पर डब्ल्यूटीओ से बाहर आने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन फायदों को देखते हुए देश को डब्ल्यूटीओ से बाहर आकर संरक्षणवाद की नीति अपनानी चाहिए। इसी के साथ आधुनिक तकनीकों का आयात किया जाए ताकि देश तकनीकी रूप से पीछे न रह जाए और घरेलू प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया जाए। इससे हम विश्वस्तरीय उत्पाद बनाने के साथ ही घरेलू उद्योगों को संरक्षण भी दे सकेंगे।

(लेखक आर्थिक मामलों के जानकार हैं)

response@jagran.com

अवधेश राजपूत

अभिव्यक्ति की आजादी का घातक इस्तेमाल

हरेंद्र प्रताप

दिल्ली का शाहीन बाग हो या ऐसे ही अन्य धरना स्थल, उनमें सक्रिय शरजील जैसे तत्व चेहरा भर हैं

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) का कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों की ओर से विरोध प्रदर्शन जारी है। इस क्रम में वे तमाम संवैधानिक मर्यादाओं को ताक पर रखने में भी संकोच नहीं कर रहे हैं। आलम यह है कि पंजाब, केरल, बंगाल, राजस्थान आदि राज्य इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित कर केंद्र की शक्ति को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। इस तरह वे देश के मुसलमानों के मन में बेवजह का डर फैलाकर अपना वोट बैंक दुरुस्त करने की कुटिल सोच को ही जाहिर कर रहे हैं, लेकिन उनका यह कदम देशहित पर भारी पड़ता प्रतीत हो रहा है। दरअसल इसके दुष्प्रभाव दूसरे रूप में नजर आ रहे हैं। मुसलमानों के मन में उनके द्वारा बैठाए गए भय का फायदा कट्टरपंथी ताकतें उठाती नजर आ रही हैं। बिहार के जहानाबाद के रहने वाले जेएनयू के छात्र शरजील इमाम का जो वीडियो सामने आया है वह इस बात की पुष्टि कर रहा है। अपने वीडियो में वह साफ-साफ असम को शेष भारत से काटने के लिए 'चिकन नेक' कहे जाने वाले सिलीगुड़ी गलियारे को बाधित करने की बात कह रहा है। उसने जिस 'चिकन नेक' गलियारे को बंद कर असम को शेष देश से काटने की बात की है वहां से बिहार का किशनगंज जिला कुछ ही दूरी पर है और किशनगंज से बांग्लादेश की दूरी मात्र 22 किलोमीटर है।

पूर्वोत्तर के आठों राज्य-सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम इसी 'चिकन नेक' के जरिये शेष भारत से जुड़े हैं। ऐसे में इसके महत्व का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं। दरअसल सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण किशनगंज बिहार का एकमात्र मुस्लिम बहुल जिला है जिसे लालू प्रसाद यादव ने अपने शासनकाल में पूर्णिया जिला से काटकर बनाया था। आजादी के समय इस जिले का किशनगंज प्रखंड हिंदू बहुल था। 1961 में किशनगंज प्रखंड में मुस्लिमों की आबादी 46 प्रतिशत थी जो अब बढ़कर लगभग 61 प्रतिशत हो गई है। हाल में बिहार विधानसभा के लिए हुए उपचुनावों में किशनगंज विधानसभा से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का एक उम्मीदवार चुनाव जीता है। यह जगजाहिर है कि बिहार के पूर्वी और बंगाल के उत्तरी-पूर्वी जिले घुसपैठ प्रभावित हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने 'मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस' में लिखा है कि 'पाकिस्तान का भारत के साथ मतभेद केवल कश्मीर को लेकर नहीं है, बल्कि असम, बंगाल और बिहार के सीमावर्ती जिले जो बांग्लादेश (पूर्वी पाकिस्तान) से सटे हुए हैं, उन्हें लेकर भी है।' इस कथन के संदर्भ में देखें तो आजादी के बाद जिस प्रकार योजनाबद्ध ढंग से बांग्लादेशी घुसपैठिये भारत आ रहे हैं, उसके कारण भारत के लिए खतरा गहराता जा रहा है। यहां यह भी जानना महत्वपूर्ण होगा कि जिस प्रकार बिहार के किशनगंज और बंगाल के दिनाजपुर, मालदा एवं मुर्शिदाबाद मुस्लिम बहुल जिले हैं उसी प्रकार असम में बोगाईगांव, धुबरी, ग्वालपाड़ा, बारपेटा आदि भी मुस्लिम बहुल जिले हैं। इन्हीं से होकर असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में जाया जा सकता है। वर्ष 1961 का ग्वालपाड़ा जिला आज ग्वालपाड़ा, कोकराझार, बोगाईगांव तथा धुबरी जिलों के रूप में बंट गया है। किशनगंज प्रखंड की तरह ही यहां भी मुस्लिमों की जनसंख्या तेजी से बढ़ी है।

रेलवे मार्ग से पूर्वोत्तर राज्यों की ओर जाने वाले लोगों को मालूम है कि कोकराझार के बाद आने वाला प्रमुख स्टेशन बोगाईगांव है। तेल और प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध बोगाईगांव जिला 2001 तक हिंदू बहुल था, लेकिन फिर वह मुस्लिम बहुल जिला इसलिए हो गया, क्योंकि पुराने बोगाईगांव जिले के हिंदू बहुल हिस्से को काटकर एक नया जिला चिरांग बना दिया गया। मुस्लिम बहुल जिलों से गैर मुस्लिमों के पलायन का सिलसिला कायम है। बोगाईगांव में 1991-2001 के बीच हिंदुओं की आबादी मात्र 3.6 प्रतिशत की दर से बढ़ना इसका सुबूत है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन का महत्व किसी से छिपा नहीं है। भारत-चीन सीमा पर तैनात देश के जवान इसी स्टेशन पर आकर ट्रेन पकड़ते हैं। 1999 के कारगिल युद्ध के समय 22 जून को इस स्टेशन पर एक भयानक बम विस्फोट हुआ था, जिसमें 10 लोग मारे गए थे और 80 के करीब घायल हुए थे। उस दौरान किशनगंज-न्यू जलपाईगुड़ी के रेलवे ट्रैक पर भी बम रखे गए थे जिस पर समय रहते एक किसान की नजर पड़ गई और एक बड़ी दुर्घटना टल गई थी। शरजील इमाम एएमयू में इसी किशनगंज-न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे लाइन को बाधित करने की हिदायत दे रहा था।

यह दिखाता है कि नागरिकता कानून में हुए संशोधन और एनआरसी तैयार करने की चर्चा से डरे घुसपैठियों के वापस बांग्लादेश लौटने की आ रही खबरों से देश में वोटबैंक के सौदागर तिलमिला उठे हैं। यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि भारत को पुनः तोड़ने का सपना देख रहे पाकिस्तान परस्त भी अपनी खोह से निकलकर सक्रिय हो रहे हैं। दिल्ली का शाहीन बाग हो या ऐसे ही अन्य धरना स्थल, उनमें सक्रिय शरजील इमाम तो एक चेहरा भर है। पर्दे के पीछे ऐसे अनेक चेहरे छुपे हैं जो पाकिस्तानी नेता जुल्फिकार अली भुट्टो के सपने को साकार करने के लिए मौके का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि मोदी सरकार के मजबूत सुरक्षा घेरे के आगे वे अपनी बाजी हारते जा रहे हैं। नागरिकता कानून के विरोध में धरने पर बैठे जो लोग संविधान की दुहाई दे रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में 'राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने' की बात कही गई है। इसका अर्थ है कि यह संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उन्हीं को देता है, जिनका इस देश की एकता और अखंडता में विश्वास है। ऐसे में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर दिए गए शरजील इमाम के बयान को हल्के में न लिया जाए। शरजील इमाम के साथ-साथ उसके शातिर साथियों को भी बेनकाब करना समय की मांग है।

(लेखक बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

संबंधों का इंद्रजाल

परमात्मा हर जीव को जन्म देता है। उसके पोषण की व्यवस्था करता है और नियत अवधि के बाद उसका जीवन हर लेता है। सृष्टि का चक्र इन तीन बिंदुओं पर ही टिका हुआ है। इस दृष्टि से एक ही शाश्वत संबंध है जो परमात्मा और जीव के मध्य स्थापित होता है। परमात्मा न चाहे तो जीव का जन्म ही न हो। इस इच्छा के लिए परमात्मा से दिन-रात प्रार्थना करने वालों की कमी नहीं है। विडंबना यह है कि जीव जन्म लेते ही उस शाश्वत संबंध को भुला देता है और अपने बनाए संबंधों के जाल में उलझकर रह जाता है। उसे माता-पिता, भाई-बहन, पत्नी, बेटी-बेटा, मित्र आदि ही दिखाई देने लगते हैं। इन संबंधों की औपचारिकता निभाने में इतना समय निकल जाता है कि परमात्मा से संबंध निभाना तो दूर याद करने का समय नहीं बचता।

यदि हम अपने मूल संबंध के प्रति निष्ठावान नहीं हैं तो हम किसी अन्य संबंध को भी निष्ठा से निभाने योग्य नहीं हैं। परमात्मा से संबंध की चिंता न करने का ही फल है कि आज निकट से निकट संबंध में खोट दिखाई दे रहा है। सारे संबंध स्वार्थों पर टिके हैं। जब वे स्वार्थ पूरे नहीं होते तो संबंध पल भर में ध्वस्त हो जाते हैं। बाहर से सामान्य दिखने वाले सारे संबंध मन की गहराइयों में कहीं न कहीं दरके हुए हैं। जब ये दरके संबंध दबाव नहीं सह पाते तो सामाजिक विघटन दिखने लगता है। जब जड़ें सूखने लगें तो पेड़ कितने दिनों तक हरा-भरा रह सकता है। हम एक भयावह स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। इसका एक ही समाधान है अपने मूल संबंध की जड़ों को फिर से हरा-भरा करना।

परमात्मा ने जीवन दिया। जीवित रहने के लिए सांसें दे रहा है। इससे बड़ा कारण और क्या हो सकता उसके प्रति आभारी होने का। हर एक सांस के लिए उसका आभारी होना ही परमात्मा से संबंध की निष्ठा का निर्वहन करना है। इससे संसार और जीवन को देखने की दृष्टि बदल जाएगी।

डॉ. सत्येंद्र पाल सिंह

कौन खरीदेगा 'महाराजा' को

फिर से

एयर इंडिया की घरेलू बाजार में हिस्सेदारी करीब 12 फीसद है। इसके बंद होने से बहुत से लोगों पर इसका असर पड़ेगा

मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि वह सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया की 100 फीसद हिस्सेदारी बेचेगी। सरकार ने 17 मार्च तक इसके लिए बोली मंगाई है। अब मोदी सरकार एयर इंडिया को और अधिक आर्थिक सहायता नहीं देना चाहती है। अगर आधिकारिक आंकड़ों को देखें तो वित्त वर्ष 2019 में कंपनी ने 25,509 करोड़ रुपये की कमाई की और 30,194 करोड़ रुपये खर्च किए? यानी 4,685 करोड़ रुपये का नुकसान। बता दें कि एयर इंडिया के पास करीब 125 एयरक्राफ्ट हैं और दिसंबर 2019 के अनुसार इसका घरेलू मार्केट में शेयर करीब 11.9 फीसद है।

मोदी सरकार ने पहले भी 2018 में एयर इंडिया को बेचने का प्रस्ताव रखा था। उस समय सरकार 76 फीसद हिस्सेदारी बेच रही थी, लेकिन किसी ने भी इसे खरीदने में कोई रुचि नहीं दिखाई। अपने पुराने अनुभव से सरकार ने सबक लेकर इस बार एयर इंडिया की 100 फीसद हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। यह भी सुनने में आ रहा है कि सरकार ने एयर इंडिया की 60 हजार करोड़ रुपये की कर्जदारी का एक बड़ा हिस्सा माफ करने का भी ऑफर दिया है। बता दें कि यूपीए सरकार ने 2011-12 में एयर इंडिया में आने वाले 10 साल में 30,000 करोड़ रुपये लगाने को मंजूरी दी थी और दिसंबर 2019 तक सरकार की ओर से एयर इंडिया में 30,520.21 करोड़ रुपये डाले जा चुके हैं।

माना जा रहा है कि इसे खरीदने के लिए टाटा समूह, हिंदुजा, इंडिगो, स्पाइसजेट और कुछ निजी इक्विटी फर्म की तरफ से बोली आ सकती है। एविएशन इंडस्ट्री के एक सूत्र के अनुसार इंडिगो इसे खरीदने वाला सबसे बड़ा दावेदार हो सकता है। एयर इंडिया के एक अधिकारी की मानें तो अगर जून 2020 तक एयर इंडिया को कोई खरीददार नहीं मिलता है तो इसकी हालत भी जेट एयरवेज की तरह हो सकती है और कंपनी बंद करने की नौबत आ जाएगी। कंपनी ने सरकार से 2,400 करोड़ रुपये की सोवरेन गारंटी (कंपनी पर किसी थर्ड पार्टी के कर्ज का निपटारा करने का वादा) मांगी थी, लेकिन सरकार ने सिर्फ 500 करोड़ रुपये की गारंटी दी है। उनके अनुसार कंपनी के फंड्स से एयर इंडिया अधिक से अधिक जून 2020 तक चल सकती है, उसके बाद भी अगर सरकार ने पैसे नहीं दिए या कोई खरीददार नहीं मिला तो एयर इंडिया के विमान आसमान में नहीं दिखेंगे।

यूं तो एयर इंडिया की घरेलू बाजार में हिस्सेदारी करीब 12 फीसद है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 18 फीसद, लेकिन इसके बंद होने से बहुत से लोगों पर इसका असर पड़ेगा। विभिन्न धर्म के लोगों के लिए धार्मिक स्थलों तक जाने के लिए कई विमान सेवाएं शुरू की हैं। कंपनी उस इलाकों में भी सेवा देती है, जहां बाकी एयरलाइन अपने विमान नहीं भेजते हैं। ऐसे में कर्ज बढ़ना स्वाभाविक है। अब अगर यह कंपनी बंद होती है तो समझिए कि श्रद्धालुओं को मिलने वाली सब्सिडी बंद हो जाएगी।

(साभार : आइचौक.इन में अनुज मौर्या)

मेलबाक्स

विरोधाभासी तथ्य

बजट में अवसर न गंवाए सरकार शीर्षक से लिखा प्रो. राजेंद्र प्रताप गुप्ता का लेख पढ़ा। लेख कई विरोधाभासों से भरा हुआ है। एक तरफ तो वह स्वीकार कर रहे हैं कि सरकार के पास पर्याप्त नकदी है, अतः देश में 1991 जैसी भुगतान संतुलन की समस्या नहीं है। दूसरी तरफ वह आगामी बजट में सरकार को कुछ अभूतपूर्व कदम उठाने की सलाह भी दे रहे हैं, ताकि अर्थव्यवस्था से जुड़े आवश्यक मुद्दों का समाधान हो सके। हालांकि एक जगह वह स्वयं मानते हैं कि अर्थव्यवस्था की वर्तमान दिक्कतें बजट के दायरे से बाहर की चीज हैं। लेखक यह भी मानते हैं कि हमारे पास बेहतर इरादों वाले प्रधानमंत्री हैं। यदि ऐसा है तो फिर उन्हें प्रधानमंत्री द्वारा अर्थव्यवस्था में घुस आई कतिपय बुराइयों को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों पर भी भरोसा रखना चाहिए था। नोटबंदी और जीएसटी को इसलिए लाना पड़ा, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था के अंदर ही दो नंबर की समानांतर अर्थव्यवस्था, जैसे जाली नोटों की तस्करी, कर वंचना, हवाला कारोबार आदि ने अपना वर्चस्व बना लिया था। पिछले कई वर्षों से यह औपचारिक अर्थव्यवस्था को घुन की तरह खाए जा रही थी। कोई भी जिम्मेदार राष्ट्र, जो अर्थव्यवस्था की दीर्घकालीन मजबूती के लिए काम कर रहा हो, इस अव्यवस्था को अनंत काल तक चलने नहीं दे सकता। हां, इतना जरूर है कि कई सारे सुधारात्मक कदमों को करीब-करीब एक ही समय लागू किए जाने से उद्यमियों के लिए तत्कालिक तौर पर कुछ कठिनाइयां आई हैं। इस स्थिति को देखते हुए ही सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स को कम किया है तथा जीएसटी दरों को भी तर्कसंगत बनाया है। उम्मीद है कि आगामी बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार द्वारा अन्य जरूरी कदम भी उठाए जाएंगे।

चंदन कर्ण, देवघर

खुद को बनाएं संविधान सम्मत

दैनिक जागरण के 25 जनवरी के अंक में प्रकाशित गिरीश्वर मिश्र का लेख, अनुशासन मांगता है गणतंत्र, में शिक्षा से लेकर राजनीति तक गांधी जी के सिद्धांतों को अपनाने की बात कहने के साथ भारतीय गणतंत्र से बंधुता, समरसता, समानता जैसे लक्ष्यों को हासिल करने के अलावा गणतंत्र में अनुशासन की मांग उठाई गई जो कि औचित्य पूर्ण है। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि हमारा गणतंत्र भटक क्यों गया? क्या वजह रही जिनके चलते आज ये मांग उठने लगी कि गणतंत्र में अनुशासन की जरूरत है? पहले हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, श्रम, कानून, तकनीकी, रोजगार, प्रर्यावरण में निहित जल, जंगल, जमीन आदि गणतंत्र के वो विभिन्न आयाम होते हैं जो संविधान सम्मत होकर गणतंत्र के अधीन रहने वाले प्रजातंत्र को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि क्या हम और हमारी सरकारें इन आयामों पर कार्य कर रही हैं? यदि हां तो फिर ये जाति, धर्म, भाषा संप्रदाय के झगड़े आज भी क्यों होते हैं? इन सब की वजह दलगत, स्वार्थगत और संकुचित राजनीति है। ऐसा लगता है जैसे कि संविधान सरकारों को नहीं, बल्कि सरकारें संविधान को चला रही हैं। इन सरकारों को राजनीतिक दल चलाते हैं। अतः जरूरत इस बात की है कि हम अपने आपको भी संविधान सम्मत बनाकर अनुशासित कर एक बेहतर सरकार के गठन में अपनी भागीदारी निभाएं।

पवन कुमार मुरली, कादीपुर, गुरुग्राम

ऐसे बयान ठीक नहीं

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर बॉलीवुड दो खेमों में बंटा हुआ है। सरकार द्वारा बनाए गए कानून को लेकर सबकी राय अलग हो सकती है, परंतु इस पर सियासत और देश को बांटने वाली सियासत नहीं होनी चाहिए। किसी भी देश की सरकार नागरिकों के हितों को ध्यान में रखकर ही कोई कानून बनाती है। नागरिकता संशोधन कानून भी इससे अछूता नहीं है। बॉलीवुड से जुड़े अथवा अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों को कोई भी बयान देते समय देशहित को ध्यान में रखना चाहिए। कुछ लोग इस कानून को सिर्फ धर्म के चश्मे से ही देख रहे हैं। बालीवुड से जुड़े व्यक्तियों को देश में धार्मिक आधार पर जहर घोलने वाले बयानों से बचना चाहिए।

हितेंद्र डेढ़ा, चिल्ला गांव

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अ

5.7 प्रतिशत से घटाकर पांच फीसद कर दिया है संयुक्त राष्ट्र ने भारत के जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान। आइएमएफ ने भी वर्ष 2019-20 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान कम करते हुए इसे 4.8 प्रतिशत कर दिया है।

आजकल

मांग बढ़ाने से ही दूर होगी आर्थिक सुस्ती

राहुल लाल
स्वतंत्र टिप्पणीकार

भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय मांग की भारी कमी से जूझ रही है। आगामी बजट में पूरा ध्यान इस पर लगाने की आवश्यकता है कि मांग को कैसे बढ़ाया जाए। दिग्गज सर्वे कंपनी 'नील्सन' की रिपोर्ट कहती है कि रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाले सामान यानी एफएमसीजी की बिक्री की बढ़ोतरी दर भी लगातार गिरती जा रही है। यही कारण है कि अधिकांश देसी-विदेशी संस्थाएं भी भारत की धीमी रफ्तार के लिए मांग में कमी को जिम्मेदार बता रही हैं। मांग में कमी के कारण ही विनिर्माण क्षेत्र में लगातार गिरावट देखी जा रही है। कोर सेक्टर भी इससे बुरी तरह प्रभावित है। उम्मीद है कि बजट में सरकार मांग से संबंधित अर्थव्यवस्था की विभिन्न चुनौतियों का कोई न कोई कारगर तोड़ अवश्य निकालेगी

प्रतीकात्मक फोटो।

भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार लगातार धीमी हो रही है। अर्थव्यवस्था का हर क्षेत्र मांग की कमी से प्रभावित है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर फिसलते हुए 4.5 फीसद पर पहुंच चुकी है। अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष यानी आइएमएफ ने वर्ष 2019-20 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को कम कर 4.8 फीसद कर दिया है। इसके पहले आइएमएफ ने चालू वित्त वर्ष में 6.1 फीसद बढ़त का अनुमान जारी किया था। रिजर्व बैंक तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने भी इसके पूर्व विकास दर का अनुमान घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया है। इसी तरह संयुक्त राष्ट्र ने भारत का जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 5.7 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया है।

अनेक एजेंसियों ने घटाया जीडीपी बढ़ोतरी दर का अनुमान : हाल ही में आइएमएफ के बाद इंडिया रेटिंग्स एजेंसी ने भी भारतीय जीडीपी वृद्धि दर के अनुमानों को घटाया। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने इस वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 5.5 प्रतिशत लगाया है। यह आइएमएफ के 4.8 प्रतिशत तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के पांच प्रतिशत के अनुमानों से ज्यादा है। इन आंकड़ों से यह तो स्पष्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था कम खपत और कम निवेश मांग के दौर में फंस गई है। आइएमएफ के अनुसार भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल यानी एनबीएफसी में दिक्कतों और मांग में कमी के कारण आर्थिक वृद्धि में धीमापन आ रहा है। भारत सरकार लगातार आर्थिक मंदी के लिए वैश्विक कारणों को जिम्मेदार बताती रही है। आइएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने हाल ही में कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि भारत की जीडीपी में गिरावट का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। इसका आशय है कि भारत की सुस्त विकास दर की वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था की विकास की रफ्तार पर असर पड़ रहा है।

बजट से उम्मीदें : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले वर्ष जब अपना पहला बजट पेश किया था तो उस समय भी उनके लिए चुनौतियां जीडीपी दर में तीव्र गिरावट, राजकोषीय दबाव, दोहरी बैलेंस शीट की समस्याएं, एनबीएफसी, रोजगार सृजन की सुस्त रफ्तार, कृषि क्षेत्र और छोटी इकाइयों में व्याप्त तनाव और हर क्षेत्र में मांग की कमी थी। आज भी हालात जस के तस हैं और कुछ समस्याएं तो और गंभीर हो गई हैं। आज जब भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है, तो ऐसे में बजट में सरकार से यह अपेक्षा है कि वह अर्थव्यवस्था का ईमानदार आकलन पेश करने के साथ ही उसे दोबारा पटरी पर लाने की योजना भी रखे।

> अर्थव्यवस्था की वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत की जानी चाहिए ताकि आर्थिक वृद्धि के लिए सरकार कड़े फैसले ले सके

मांग में वृद्धि पर जोर दे सरकार : सरकार ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कॉरपोरेट टैक्स में कटौती की थी। इसके साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक ने कई बार रेपो रेट में कटौती कर ब्याज दरों को घटाया। लेकिन इन प्रयासों का कोई विशेष परिणाम नहीं दिख रहा है। अर्थव्यवस्था का वर्तमान संकट मूलतः मांग पक्ष से संबद्ध है। कॉरपोरेट टैक्स में कमी का लाभ मांग पक्ष से संबद्ध न होकर आपूर्ति पक्ष से संबद्ध है। उपभोक्ता क्रय क्षमता में कमी के कारण मांग में कमी आ रही है। इस कारण कंपनियों को उत्पादन में कटौती करनी पड़ रही है। इस समस्या का समाधान क्या है? कॉरपोरेट टैक्स में कमी के कारण सरकार को 1.45 लाख करोड़ रुपये का बोझ उठाना पड़ा। मांग में वृद्धि के लिए सबसे आवश्यक है कि सरकार सबसे निम्न वर्ग की क्रय क्षमता में वृद्धि करे। उदाहरण के लिए सरकार इस समय किसानों को 'प्रधानमंत्री सम्मान निधि' योजना के अंतर्गत छह हजार रुपये वार्षिक दे रही है। इस बजट में आवश्यक है कि सरकार इस योजना को प्राथमिकता में रखे। किसानों को प्रत्यक्ष नकदी अंतरण के तहत बजट में और ज्यादा राशि दी जानी चाहिए और उन्हें यह तय करने देना चाहिए कि वह इसे कहां खर्च करेंगे। यह ग्रामीण भारत के लिए आंशिक आय समर्थन योजना की तरह होगा। मांग पर इसका वृद्धिशील प्रभाव उल्लेखनीय होगा। वर्ष 2008 के आर्थिक संकट के दौरान ग्रामीण क्षेत्र की मजबूत स्थिति बनी हुई थी, लेकिन इस बार ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मांग की भारी कमी से जूझ रही है। ऐसे में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बल देना सरकार के लिए अनिवार्य है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 'मांग' उत्पन्न करने के लिए 'मनरेगा' जैसी योजनाओं के बजट में भी वृद्धि करने की आवश्यकता है। वर्ष 2019-20 में उर्वरक सब्सिडी पर 80 हजार करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इस सब्सिडी को भी और कारगर तथा लाभार्थियों के लिए बजट में लक्षित बनाए जाने के प्रयास होने चाहिए। गेहूं और धान का खरीद मूल्य भी सीधे किसानों के बैंक खाते में पहुंचाने की व्यवस्था होनी चाहिए। ओडिशा और पंजाब की राज्य सरकारें अपने राज्यों में इसी तरह की योजना लाने की कोशिश कर रही हैं। वित्त वर्ष 2020-21 के आम बजट में पूरे देश में इस तरह की योजना लाने पर विचार किया जा सकता है।

व्यक्तिगत कराधान में कटौती से मुमकिन मांग में बढ़ोतरी : मांग में वृद्धि हेतु सरकार को व्यक्तिगत कराधान में कटौती करनी चाहिए। इससे मध्यम वर्ग की क्रय क्षमता में वृद्धि होगी तथा मध्यम वर्ग बाजार में मांग वृद्धि में सक्षम होंगे। अगर सरकार कॉरपोरेट टैक्स की तुलना में व्यक्तिगत आयकर की दरों में कमी लाती, तो इसके कुछ अच्छे परिणाम अभी तक हम लोगों को दिख भी जाते।

समावेशी विकास की उम्मीद

सतीश सिंह
आर्थिक मामलों के जानकार

इस वर्ष सभी लोग करिश्माई बजट की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि राह में मुश्किलें अनेक हैं। कॉरपोरेट कर एवं दूसरी राहतें देने से सरकारी खजाने पर 1.45 लाख करोड़ रुपये का बोझ पड़ने का अनुमान है। आर्थिक सुस्ती की वजह से कॉरपोरेट कर से मिलने वाले राजस्व में लगभग दो लाख करोड़ रुपये की कमी आने की आशंका है। दिसंबर 2019 तक वस्तु एवं सेवा कर संग्रह अपेक्षित नहीं रहने से सरकार को 85,000 करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान की आशंका है। अप्रैल से नवंबर 2019 के दौरान उत्पाद शुल्क और कस्टम ड्यूटी में भी वर्ष 2018 के मुकाबले कमी आई है।

राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार खर्चों में कटौती करने के अलावा सरकारी संपत्तियों को बेचने की रणनीति अपना सकती है। सरकारी संपत्ति के निपटान का राजकोषीय स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और यह तरलता की समस्याओं का समाधान करता है। विश्व के कई देशों में ऐसा किया गया है। भारत में 212 ईकाइयों की संपत्ति जीडीपी का लगभग 15 प्रतिशत है, जो राशि में लगभग 28 लाख करोड़ रुपये है। अतः सरकार ऐसी संपत्तियों को बेचकर राजकोषीय घाटे को कम कर सकती है। सरकार विविध अदालतों में लंबित मार्च 2018 तक के कर राजस्व से जुड़ी कुल 7.8 लाख करोड़ रुपये की राशि का इस्तेमाल भी राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए कर सकती है, लेकिन इस मामले में सरकार को नीतिगत निर्णय लेना होगा।

छोटी बचतों के माध्यम से सरकार पहले ही एक लाख करोड़ रुपये पूंजी की उगाही कर चुकी है। इसलिए 1.3 लाख करोड़ रुपये के बजटीय लक्ष्य को आसानी से प्राप्त करने की उम्मीद है। इस आधार पर सरकार वित्त वर्ष 2020-2021 में बजटीय लक्ष्य को बढ़ाकर 1.5 लाख करोड़ रुपये कर सकती है। वर्तमान नीतिगत अनिश्चितता की वजह से स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं हो पा रही है। रीयल एस्टेट में भी दबाव की स्थिति बनी हुई है। राजस्व के नुकसान की भरपाई सस्ती दर पर पूंजी एकत्रित करके की जा सकती है। सरकार ने अगस्त 2014 में पीपीएफ की सीमा को सालाना पचास हजार रुपये से बढ़ाकर डेढ़ रुपये किया था जिससे वित्त वर्ष 2016 के दौरान, इसमें एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की बढ़ोतरी हुई थी। लिहाजा प्रोविडेंट फंड की सीमा को एक लाख रुपये और बढ़ाते हुए 2.5 लाख रुपये करने से दो लाख करोड़ रुपये बचत में वृद्धि हो सकती है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत 15 लाख रुपये जमा किया जा सकता है, जिस पर 8.6 प्रतिशत की दर से ब्याज देय है, लेकिन इस पर मिलने वाला ब्याज कर योग्य है। मार्च 2018 तक ऐसे खातों में 38,662 करोड़ रुपये की राशि जमा थी। अगर इस योजना को कर मुक्त कर दिया जाता है तो सरकारी खजाने पर 3,092 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा, लेकिन जमा में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

सुधारों के बावजूद किसानों की दशा में अपेक्षित सुधार नहीं हो रहा है। फिलहाल सरकार 12.5 करोड़ छोटे एवं सीमांत किसानों को सालाना छह हजार रुपये वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है। लाभार्थियों की कम संख्या हैरानी पैदा करती है, क्योंकि देश में लगभग 90 प्रतिशत भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण हो चुका है। वर्तमान समय में एनबीएफसी वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहा है। लिहाजा इस क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए सरकार को कारगर कदम उठाने होंगे, जिसे अल्पावधि एवं दीर्घावधि उपायों को अपनाकर पूरा किया जा सकता है। इसमें दो राय नहीं है कि देश की अर्थव्यवस्था सुस्ती के दौर से गुजर रही है, लेकिन बजट में कारगर प्रावधानों का समावेश करके भारतीय अर्थव्यवस्था को गुलाबी बनाया जा सकता है।

खरी-खरी

गण के मन की बात!

पीयूष पांडे

भारत एक गण प्रधान देश है। यहां इफरात में गण पाए जाते हैं। जितने गण ट्रेन में भीतर बैठते हैं, कई बार उससे भी अधिक ट्रेन के ऊपर बैठकर सफर करते देखे जा सकते हैं। परेशान गण को कुछ नहीं सूझता तो वो धरना-प्रदर्शन करने निकल पड़ता है। दरअसल गण चाहता है कि उसके मन की बात सुनी जाए। आखिर, मन गण के पास भी है, लेकिन गण-तंत्र में मन की बात करने के लिए उसके पास समुचित व्यवस्था नहीं है।

गण के पास मन की बात के लिए किसी रेडियो स्टेशन में कोई स्लॉट नहीं है। न्यूज चैनल पर तो गण का लोड लेने वाला कोई है ही नहीं। वहां हर सेकेंड की कीमत हजारों-लाखों में है। गण के पास बातें हैं, पैसा नहीं। कर्ज में डूबा किसान मन की बात कहना चाहता है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। दुष्कर्म-पीड़ित लड़की मन का दर्द सुनाना चाहती है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। मन की बात सिर्फ राजनेता अफोर्ड कर सकता है, गण नहीं। फिर, जिस गण की जेब में पैसा है वो रहे भले हिंदुस्तान में, पर व्यवहार में अमेरिकी सिटीजन टाइप हो जाता है। वो आइफोन का लेटेस्ट मॉडल खरीदते हुए सेल्फी फेसबुक पर डाल खुद को अमेरिकी घोषित करता है।

तो बेचारा आम गण अपने मन की बात कैसे करे? वो कैसे बताए कि राजनेता बेशर्मी करते हैं और अखबार में छपता है कि लोकतंत्र की हत्या हो गई? वो कैसे बताए कि चंद राजनेता बंद कमरे में कई बार करोड़ों लोगों की किस्मत का फैसला कर देते हैं और गण मारा-मारा संविधान की दुहाई दिए फिरता है? ऐसे में वह दो काम कर सकता है। ट्विटर पर सरकारों को कोसने का और धरना-प्रदर्शन का। सो वो दोनों काम करता है। लेकिन कोई सरकार नहीं चाहती कि गण खुलकर मन की बात करे। कई नेता तो मानते हैं कि मन अब एक्सक्लूसिव आइटम है। इस जमाने में हर ऐरा-गैरा मन रखना अफोर्ड नहीं कर सकता। क्योंकि मन बावला होता है। मन होगा तो मनी मांगेगा। थोड़ा मनी दे दो तो रोजगार, रोजगार दे दो तो तरक्की मांगेगा। तरक्की दो तो कार मांगेगा। आल्टो दे दो तो ऑडी मांगेगा। मन का कोई ठौर-ठिकाना तो है नहीं। और मांगते-मांगते गण का मन कब सत्ता मांगने लगे, क्या पता? और सच यह है कि राजनेता गण को सिर्फ वादों का झुनझुना पकड़ा सकते हैं, सत्ता की चाबी नहीं।

ट्वीट-ट्वीट

दिल्ली में शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों का असली चेहरा उजागर हो रहा है। उसकी एक रणनीतिकार कह रही हैं कि भारत में इस्लामिक राज कायम करने के लिए कैसे लोगों को 'समावेशन' जैसे शब्दों से बेवकूफ बनाया जा सकता है।

विवेक रंजन अग्निहोत्री@vivekagnihotri

एक भारतीय होने के नाते मेरा मानना है कि कट्टरपन किसी भी धर्म का हो, वह पूरी तरह से गलत है। कोई भी चीज एक की सही और एक की गलत नहीं हो सकती- चाहे वो नारे हों, मजहबी दिखावा हो। उनमें तुष्टीकरण किसी का ना हो, नियम कानून सबके लिए बराबर हो तभी होगा सेक्युलर भारत।

ऋचा अनिरुद्ध@richaanirudh

अब कानून मंत्री ही शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों को टुकड़े-टुकड़े गैंग बता रहे हैं। वास्तव में असली टुकड़े-टुकड़े गैंग तो सत्तारूढ़ दल ही है जो भारत को धार्मिक आधार पर विभाजित करने पर तुला है।

पी चिदंबरम@PChidambaram_IN

एक टीवी चैनल के खुलासे में कपिल सिब्बल के तार एफपीआइ से जोड़े जा रहे हैं। वैसे कांग्रेस की आधी मुश्किलों की जड़ तो कपिल सिब्बल ही हैं। आज कांग्रेस की जो हिंदू-विरोधी पार्टी की छवि बनी है उसमें सबसे बड़ी भूमिका उनकी ही है।

साध्वी खोसला@sadhavi

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या भीमा-कोरेगांव मामला एनआइए को सौंपने का फैसला उचित है?

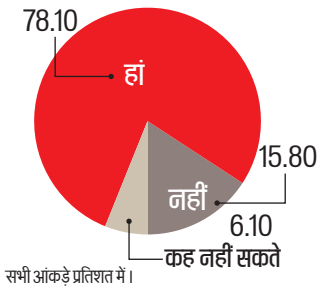

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या अदनान सामी को पद्मश्री सम्मान दिए जाने पर सवाल उठाना उचित है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

नई-नवेली आ गई नव-जिन्ना की पौध,
जो जेएनयू में करे बैठे-बैठे शोध।
बैठे-बैठे शोध बनाती रहती है मन,
कैसे रेती जाय आज मुर्गी की गर्दन!
पुन: धर्म के नाम जा रही साजिश खेली,
जो शरजील इमाम रच रहा नई-नवेली।

– ओमप्रकाश तिवारी

हरियाणा डायरी

सीएमओ, प्रधान सचिव पद पर आइपीएस क्यों

राकेश क्रांति
समाचार संपादक, हिसार

भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1991 बैच के हरियाणा कैडर के अधिकारी अशोक खेमका के निशाने पर एक बार फिर सत्ता पक्ष है। इस बार उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय के खिलाफ मोर्चा खोला है कि खेल विभाग का प्रधान सचिव एक आइपीएस क्यों? हाल में सरकार ने इस पद पर भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी ओपी सिंह की नियुक्ति की है। खेमका ने इस बाबत सीएम को पत्र लिख सवाल उठाया कि यह तो संविधान के अनुच्छेद 14, 16 का सीधा उल्लंघन है। आइएएस कैडर के पद पर आइपीएस की तैनाती नहीं की जा सकती, वह भी तब जब उस रैंक के आइएएस अधिकारी मौजूद हों। अपनी बेबाकी और भ्रष्टाचार के खिलाफ दबंग छवि के लिए मशहूर खेमका का तर्क वाजिब है कि जब प्रधान सचिव के प्रदेश में कुल 12 पद हैं और इस रैंक के 16 आइएएस उपलब्ध हैं तो फिर किसी अन्य की तैनाती किसलिए? खैर ये सीएमओ का अधिकार है कि वह किसे कहां नियुक्ति दे मगर सीएमओ से पंगा लेकर एक बार फिर खेमका चर्चा में हैं। प्रदेश में सरकार किसी की भी रही हो खेमका नियमों और व्यवस्था पर सवाल उठाते रहे हैं।

विज का क्या बस इतना सा ख्वाब था : क्राइम इन्वेस्टीगेशन डिपार्टमेंट (सीआइडी) अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल को ही नहीं, गृह मंत्री अनिल विज को भी ब्रीफिंग करेगी। यह तय होते ही विज के तेवर ठंडे हो गए। बोले- मेरे और मुख्यमंत्री के बीच कोई मतभेद नहीं है, क्योंकि हम बेस्ट फ्रेंड हैं। अब उनकी मित्रता कितनी घनिष्ठ है और मतभेद-मनभेद कितना है, यह एक पखवाड़े तक अखबारों की सुर्खियों से जाहिर हो चुका है। सीआइडी अपने काम की भनक तक नहीं लगने देती, मगर सीआइडी पर अधिकार को लेकर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की जंग चंडीगढ़ के सचिवालय से निकल कर दिल्ली

अशोक खेमका।

दरबार तक पहुंच गई। भाजपा के शीर्ष को हस्तक्षेप करना पड़ा। हरियाणा भाजपा के प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव अनिल जैन को कहना पड़ा कि मामला सुलझ चुका है। मुख्यमंत्री सरकार के प्रमुख हैं और वह जो विभाग चाहें अपने पास रख सकते हैं। विज ने भी कहा- मैंने गृह मंत्री होने के नाते सीआइडी से ब्रीफिंग मांगी थी जो शुरू हो गई है। सीआइडी किसके पास है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस विवाद के पटाक्षेप होने के बावजूद सवाल यह भी उठता है कि क्या विज की इतनी सी चाहत थी। राजनीति में बेस्ट फ्रेंड हमेशा बेस्ट फ्रेंड नहीं रहते। मित्रों के बीच छोड़िए, परिवार में मतभेद उभर आते हैं। मौजूदा भाजपा सरकार की सहयोगी पार्टी (जजपा) ताजा उदाहरण है।

कैप्टन ने किया माफ, राहत आसान नहीं : मनोहर सरकार की पहली पारी में कैप्टन अभिमन्यु दूसरे सबसे बड़े ताकतवर मंत्री थे। 19 फरवरी 2016 की शाम को कैप्टन के परिवार को तब गहरा आघात पहुंचा, जब आरक्षण आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा में उनकी रोहतक स्थित कोठी जलकर खाक हो गई। उपद्रवियों की भीड़ जब कोठी को घेरकर फूंक रही थी तो अंदर परिवार के बच्चों और महिलाओं समेत दस सदस्य मौजूद थे। उन्होंने पिछले दरवाजे से भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई थी। सूबे के कद्दावर मंत्री होने के बावजूद अपने घर को बचाने में नाकाम रहने की टीस कैप्टन को हमेशा कचोटती रही, मगर अब उनके परिवार ने सबको माफ कर दिया है। सतरोल खाप की पहल पर जींद में 108 खापों की महापंचायत में कैप्टन के बड़े भाई वीरसेन ने आरोपितों को माफी दी। कैप्टन का परिवार अब अपना केस वापस लेगा। उस महापंचायत में आरोपितों ने माफीनामा दिया था। भले ही कैप्टन के परिवार ने 54 आरोपितों को माफ कर दिया मगर केस को खत्म करना इतना आसान भी नहीं। रोहतक में हिंसा को लेकर सीबीआइ ने तीन एफआइआर दर्ज की थीं जिसमें कैप्टन की कोठी जलाने की एफआइआर भी शामिल है। इन तीनों की सीबीआइ जांच समानांतर चली है। जांच एजेंसी केस की चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। ऐसी स्थिति में बीच का रास्ता खोजने के लिए महापंचायत ने एक कमेटी का गठन किया है जो लीगल राय लेगी।

बीरेंद्र को याद आया आरक्षण : अपने आइएएस बेटे बृजेंद्र सिंह का राजनीतिक करियर बनाने के लिए राज्यसभा से इस्तीफा देने वाले भाजपा के कद्दावर जाट नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह ने एक बार फिर जाटों को आरक्षण देने की खुलकर वकालत की है। उनका कहना है कि हरियाणा में गुर्जर और अहीर बिरादरी जैसी ही स्थिति जाट, जट सिख, मुल्ला जाट, बिश्नोई और त्यागी की है। ऐसे में जाट आरक्षण की मांग को गलत नहीं ठहराया जा सकता। वे आरक्षण को लेकर पार्टी के भीतर और बाहर अपनी बात कहते रहेंगे। दरअसल प्रदेश में जाटों को साधने के लिए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और बीरेंद्र सिंह जुटे हुए हैं। तीनों नेताओं का प्रदेश के जाटों पर एकछत्र राज नहीं है। इसका प्रमाण हरियाणा के विगत विधानसभा चुनाव में देखने को भी मिला था जब कांग्रेस रोहतक, सोनीपत और झज्जर बेल्ट में सिमट कर रह गई थी। दुष्यंत भी एक सीमित इलाके के जाटों को ही लुभा पाए थे। ऐसी स्थिति में सर छोटूराम के नाती बीरेंद्र जाट नेता के तौर पर अपना कद बड़ा करना चाहते हैं।

पारदर्शिता का पहलू

भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत

अनुपमा झा
पूर्व कार्यकारी निदेशक, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल

यदि सभी लोग यह निश्चय करें कि हम नियमों का पालन करेंगे और अपने विवेक से निर्देशित होंगे, तो देश में व्याप्त भ्रष्टाचार में व्यापक कमी आ सकती है

प्रतीकात्मक फोटो।

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत 80वें स्थान पर आया है। भारत इस स्थिति को चीन, घाना, मोरक्को और बेनिन के साथ साझा करता है। इस रिपोर्ट के साथ सरकार ने अपने प्रयासों और उपायों के माध्यम से भ्रष्टाचार को कम करने के दावों को हवा दी है। इसका स्कोर और रैंक 13 विभिन्न डाटा स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है जो सार्वजनिक क्षेत्र में कई भ्रष्ट व्यवहारों का आकलन करता है। इसमें निजी लाभ के लिए सार्वजनिक कार्यालय में दिए जाने वाले रिश्वत और सार्वजनिक धन तक का आकलन किया गया है।

अपारदर्शी राजनीतिक फंडिंग और राजनीतिक हितों की पैरवी व कम हाथों में धन तथा शक्ति का केंद्रित होना आमतौर पर उच्च भ्रष्टाचार वाले देशों की कुछ विशेषताएं हैं। भारत इससे अलग नहीं है। महज कुछ वर्ष पहले जब भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन हुआ था, तब यह महसूस किया गया था कि यह सही दिशा में एक कदम है। तब यह महसूस किया गया कि देश में भ्रष्टाचार में कमी आएगी और सरकार अधिक पारदर्शी व जवाबदेह होगी। लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। भ्रष्टाचार कायम है। थानों में रिश्वत के बिना एफआइआर अभी भी दर्ज नहीं हो पाती है। आरटीओ में भी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कमोबेश यही दशा कायम है। इसके अलावा भी रोजमर्रा की जिंदगी में आम लोगों को अब भी भ्रष्टाचार से दोचार होना पड़ रहा है।

भ्रष्टाचार और रिश्वत भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग बन गए हैं। जब तक कोई बड़ा घोटाला सामने नहीं आता है, वे सुर्खियां नहीं बनते हैं। नीरव मोदी के फर्मों और मेहुल चोकसी के कारोबार से जुड़े 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक के वित्तीय घोटाले का असर इस कदर होता है कि भ्रष्टाचार पर सार्वजनिक विमर्श शुरू हो जाता है। यह भी कुछ दिनों तक ही रहता है, क्योंकि लोग अपने रोजाना के अस्तित्व और बुनियादी सामाजिक आर्थिक जरूरतों के साथ जुड़ जाते हैं।

एक राष्ट्र के रूप में हम इतने भ्रष्ट क्यों हैं? पिछले 20-30 वर्षों पर ही नजर डालें तो घोटालों की सूची अंतहीन है। आम नागरिक अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सरकारी अधिकारियों के साथ काम करते हुए भ्रष्टाचार की समस्या का सामना करता है, लेकिन अपने जीवन को संवारता है। बेशक सरकार द्वारा कुछ बेबी स्टेप्स उठाए गए हैं जो रिश्वतखोरी की जांच करेंगे, जैसाकि भारतीय रेलवे द्वारा हाल ही में शुरू किया गया है जिसमें आरक्षित टिकटों को ऑनलाइन प्रदर्शित करता है ताकि यात्री अपनी टिकट बुक करते समय सीटों की स्थिति देख सकें। परिणामस्वरूप ट्रेन में खाली सीट पर पहुंचने के लिए यात्रियों को अब टीटीई के पीछे नहीं भागना पड़ेगा।

हालांकि देश में भ्रष्टाचार की समस्या इतनी विकट है कि इससे निपटने के लिए एक बहुस्तरीय प्रयास की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में उच्च और निम्न रैंक वाले देशों में क्या अंतर है? कम भ्रष्टाचार वाले देशों में लोग अधिक शिक्षित और जागरूक हैं। उन देशों में राजनीतिक फंडिंग अपेक्षाकृत पारदर्शी है, जबकि कॉरपोरेट हित समूह राजनीतिक दलों को हर जगह प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह भ्रष्ट देशों की तुलना में कम है। उन देशों में जो कानून पारदर्शिता को बढ़ाते हैं और भ्रष्टाचार के अवसरों को कम करते हैं, उन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। भ्रष्ट देशों में कानून इस तरह से बनाए जाते हैं कि भ्रष्टाचार के लिए या कानून तोड़ने वालों के लिए कानून को एक तरह से मोड़ने के लिए पर्याप्त जगह हो।

कानून प्रवर्तन एजेंसियां 'क्लीनर' देशों में स्वतंत्र हैं और लोकपाल की भूमिका भ्रष्टाचार से परे है, जो अक्षमता, पूर्वाग्रह या उदासीनता के कारण प्रथाओं को कवर करती है। यह भ्रष्टाचार का पता लगाने और इस तरह के मामले को भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी या अभियोजक को आगे की कार्रवाई के लिए संदर्भित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या इसकी तुलना भारत की स्थिति से की जा सकती है? लोकपाल अधिनियम 2013 में पारित किया गया था। अधिनियम पारित होने के छह वर्ष बाद पिछले साल लोकपाल नियुक्त किया गया था, और वह भी तब जब एक गैर सरकारी संगठन ने देरी के खिलाफ याचिका दायर की थी। ज्यादातर राज्यों में अभी भी लोकायुक्तों की नियुक्ति नहीं की गई है। उन देशों में आम नागरिक कानून का सम्मान करते हैं।

एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या हम भ्रष्टाचार के डीएनए को बदल सकते हैं जो लंबे समय तक और एक भ्रष्ट समाज के लगातार संपर्क में रहने के कारण हमारे अंदर समा गया है? आण्विक जीवविज्ञान में हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि जीन को हमारी विश्वास प्रणाली में परिवर्तन द्वारा सक्रिय और निष्क्रिय किया जा सकता है।

इसी तरह अगर भ्रष्टाचार की बीमारी को कम करना है, तो हमें पैसा बनाने और समृद्धि हासिल करने के छोटे-छोटे तरीकों का मूल्य कम रखकर अपनी सोच बदलनी होगी। यदि समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपनी सोच बदलता है और यह मानता है कि रिश्वत देना और लेना दोनों ही गलत है, तो भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है।

एक ही समय में विभिन्न संस्थानों, राजनेताओं, सरकारी अधिकारियों और न्यायपालिका को निजी क्षेत्र, मीडिया और नागरिक समाज संगठनों के साथ मिलकर काम करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि भ्रष्टाचार से निबटने के लिए अधिक से अधिक पारदर्शिता लाई जाए और जवाबदेही तय की जाए।

2011 की जनगणना बताती है कि किसानों की संख्या में 86 लाख की गिरावट आई है। दूसरी ओर कृषि मजदूरों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
मंगलवार 28 जनवरी 2020

हिमाचल प्रदेश

निजी स्कूलों पर सख्ती की दरकार

अच्छी शिक्षा का महत्व किसी से छिपा नहीं है। सुनहरे भविष्य की राह इसी से निकलती है। यही वजह है कि आज के प्रतियोगी युग में देश के हर अभिभावक की चाहत होती है कि उनका बच्चा बेहतर से बेहतर शिक्षा हासिल करे। इसी के चलते वे अच्छे से अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला कराते हैं। वे चाहते हैं कि शिक्षण संस्थानों में उसे हर तरह की सुविधा मिले और बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। अधिकांश निजी स्कूल इस दिशा में बेहतर कार्य कर भी रहे हैं। इन स्कूलों में बच्चों को हर तरह की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इन स्कूलों में शिक्षकों को पढ़ाई के अलावा अन्य कार्यों में भी नहीं लगाया जाता है। यहां पर बच्चों के लिए कई तरह की गतिविधियां भी करवाई जाती हैं। जिससे उनका सभी क्षेत्रों में विकास होता है। निजी स्कूलों की मांग बढ़ने की यह भी एक वजह है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी अच्छी शिक्षा के लिए लोग सरकारी स्कूलों को छोड़ निजी स्कूलों की तरफ आकर्षित हुए हैं। यही कारण है कि गांव-गांव तक निजी स्कूलों की भरमार हो गई है। इसी बीच कई स्कूल प्रबंधकों ने मनमाने तरीके से फीस बढ़ानी शुरू कर दी, जिससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ने लगा। वर्दी, किताबें, स्टेशनरी समेत अन्य तरह के खर्च भी साल दर साल बढ़ाए जाने लगे। इससे आम लोगों के लिए निजी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो रहा है।

निजी स्कूलों की मनमानी को रोकने के लिए सरकार की पहल सराहनीय है। जरूरत इस बात की है कि इसकी लगातार निगरानी भी की जाए

इसी के रोषस्वरूप लोग विरोध भी करते रहे हैं। राजधानी शिमला में तो लोगों ने एकजुट होकर प्रदर्शन तक भी किए थे। राज्य के अन्य शहरों में भी कुछ निजी स्कूलों में फीस बढ़ाए जाने पर विरोध तो परिजन करते रहे हैं, लेकिन बच्चे के भविष्य को देखकर खुलकर सामने नहीं आए हैं। इन लोगों का कहना है अगर वे विरोध करते हैं तो स्कूल प्रबंधक उन्हें साफ कह देते हैं कि अगर किसी तरह की दिक्कत है तो बच्चों को किसी अन्य स्कूल में दाखिल करवा लें। इसी कारण लोग ऐसे निजी स्कूलों के खिलाफ बोलने से डरते हैं और शोषण सहते हैं। अब राज्य के उच्चतर शिक्षा निदेशक ने अधिसूचना जारी कर निर्देश दिए हैं कि फीस बढ़ाए जाने, कब से इसे बढ़ाया जाना है, कहां से किताबें एवं वर्दी खरीदनी है, के बारे में शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में अभिभावकों की आम सभा बुलाई जाएगी। इसमें सभी बातें तय की जाएंगी। अभिभावकों की राय के बाद फीस बढ़ाने का फैसला लिया जाएगा। इस संबंध में सभी जिलों के शिक्षा उपनिदेशकों को स्कूलों पर नजर रखने के निर्देश जारी किए गए हैं।

उच्चतर शिक्षा निदेशक का फैसला सराहनीय है। इस फैसले से उन निजी शिक्षण संस्थानों के प्रबंधकों की मनमानी पर रोक लगेगी, जिन्होंने शिक्षण संस्थानों को कमाई का साधन बना रखा है। अब जरूरत है कि इस फैसले की कड़ी निगरानी भी की जाए, ताकि स्कूलों को मनमानी का मौका न मिले। निजी स्कूलों की फीस तार्किक होनी ही चाहिए, ताकि अभिभावकों पर बहुत ज्यादा बोझ भी नहीं पड़े और स्कूलों को घाटा भी नहीं उठाना पड़े।

झारखंड

मंत्रिमंडल की कशमकश

झारखंड में नई सरकार बनने के एक महीने बाद भी मंत्रिमंडल के पूरी तरह से आकार नहीं ले पाने के कारण विकास की गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री अपने स्तर से लगातार लोगों की शिकायतों का निपटारा करते हुए अबतक जनता का भरोसा कायम रखने में सफल साबित हुए हैं। ब्यूरोक्रेसी को भी उन्होंने सक्रिय किया है। मौजूदा हालात में नई सरकार में शामिल दलों को यह बात समझने की जरूरत है कि झारखंड की जनता ने उन्हें ढेर सारी उम्मीदों के साथ स्पष्ट जनादेश दिया है। ऐसे में जनता की कसौटी पर कसे और परखे जाने के शुरुआती और अहम वक्त का यूं आपसी खींचतान में गुजर जाना अच्छा तो नहीं माना जा सकता। झारखंड में गठबंधन की सरकारों की आपसी खींचतान का हश्र यहां की जनता ने कई बार देखा है। अपने गठन के बाद वर्षों तक झारखंड ने राजनीतिक अस्थिरता का दंश झेला है। अपने साथ गठित उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुकाबले इसके विकास में पिछड़ने की एक वजह यह भी रही है। लोगों ने इससे सबक भी लिया है। यही कारण है कि पिछले दो चुनावों से जनता ने राज्य में बहुमत की सरकार बनाने को तरजीह दी है।

गठबंधन समन्वय के साथ-साथ समय-समय पर त्याग की भी मांग करते हैं। इसके लिए आपसी हितों से ऊपर उठने की जरूरत भी होती है। फिलहाल महागठबंधन में शामिल दलों के सामने सरकार के

प्रतीकात्मक फोटो

नई सरकार के साथ जनता की काफी उम्मीदें जुड़ी हैं। ऐसे में सरकार में शामिल दलों को जल्द से जल्द आपसी पेच सुलझाकर राज्य के विकास को तेज रफ्तार देनी होगी

सफलतापूर्वक संचालन के साथ-साथ दलों के बीच आपसी समझ बढ़ाने और संतुलन साधने की चुनौती है। सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन ने अबतक कांग्रेस से समन्वय बनाने में काफी सूझबूझ का परिचय दिया है। कांग्रेस के दो मंत्री मुख्यमंत्री के साथ ही शपथ ले चुके हैं। अब इसके बाद उसके कोटे में और दो मंत्री पद आएंगे या तीन, इस बात को लेकर जिच है। उधर झाविमो से दो निष्कासित विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने की उम्मीद को देखते हुए कांग्रेस तीन और मंत्रियों पर अपनी दावेदारी की बात और भी मजबूती से करती दिख रही है।

मंत्रिमंडल का स्वरूप चाहे जैसा भी हो, यह सरकार में शामिल दलों को समझना होगा कि पदों को लेकर लंबे समय तक चलने वाले मोल-तोल का संदेश जनता के बीच अच्छा नहीं जाता। साथ में यह भी, कि बदलाव की बयार वाले दौर में नई सरकार को तेजी से कई बड़े फैसले लेने हैं और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाना है।

सियासी दलों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जमीनी बदलाव राजनीति के जरिये ही आती है। इसके लिए प्रदेश में राजनीतिक स्थिरता पहली शर्त होती है। अर्थात एक चुनी हुई सरकार बिना किसी बाधा के पांच साल चलनी चाहिए और जनता के हित में फैसले लेने वाली होनी चाहिए। यह तभी संभव होगा जब गठबंधन में शामिल दलों के नेता पद पाने के लिए जोड़तोड़ नहीं करेंगे और जनता की सेवा को अपनी पहली प्राथमिकता बनाएंगे। सरकार में शामिल घटक दलों में कुर्सी की लड़ाई होने से सरकार अस्थिर हो सकती है और फिर राज्य में राजनीतिक रूप से अस्थिर हो सकता है। यह स्थिति झारखंड के लिए घातक होगी।

उत्तराखंड

सिस्टम की संवेदनहीनता

लंबे संघर्ष के बाद अस्तित्व में आए उत्तराखंड में उम्मीद थी कि अपनों का राज होगा तो उपेक्षा की पीड़ा से निजात मिलेगी। तब सोचा जा रहा था कि सहोदर उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद विकास की किरण प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंच जाएगी। अब बीस साल बाद मानो ये उम्मीदें धूमिल होती नजर आ रही हैं।

हालात को चमोली जिले में जोशीमठ विकासखंड के सुभाई गांव से समझा जा सकता है। भारी बर्फबारी से सुभाई गांव में बिजली गुल हो गई। पता चला कि ट्रांसफार्मर खराब हो गया है। ऐसे में ट्रांसफार्मर बदलने का निर्णय लिया गया। संवेदनहीनता की इंतेहा देखिए ऊर्जा निगम का ठेकेदार ट्रांसफार्मर को सड़क पर छोड़ गया। कई दिन तक गांव में इसलिए बिजली बहाल नहीं हो पाई कि ट्रांसफार्मर गांव तक नहीं पहुंचा। आखिरकार ग्रामीणों ने स्वयं ट्रांसफार्मर को गांव पहुंचाने की ठानी। वे खुद बर्फ में छह किलोमीटर पैदल चलकर ट्रांसफार्मर को कंधे पर उठा गांव ले गए। यह अकेला मामला नहीं है, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य

जैसी सुविधाओं को गांवों तक पहुंचाने के दावों के बीच यह हकीकत आईना दिखाने वाली है। यह सिस्टम की खामी ही है कि उत्तरकाशी के मोरी क्षेत्र के गांवों में डायरिया का मरीज इसलिए दम तोड़ गया कि गांव की सड़क से दूरी आठ से दस किलोमीटर है। उसे सड़क तक ले जाना आसान नहीं था। पौड़ी से लेकर पिथौरागढ़ तक ऐसे एक नहीं तमाम उदाहरण मिल जाएंगे। सरकार पलायन पर अंकुश को लेकर बेहद गंभीर है और इसके लिए तमाम योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, लेकिन सिस्टम की संवेदनहीनता ही ऐसी योजनाओं पर पलीता लगाती प्रतीत हो रही है। प्रदेश में 1700 से ज्यादा गांव जनशून्य हो चुके हैं और ऐसी गांवों की संख्या भी सैकड़ों में है, जहां मुट्ठीभर लोग ही रह गए हैं। सरकार रिवर्स पलायन के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन सवाल वही है कि यदि खामियों को दुरुस्त न किया गया तो कोई वापस लौटने के बारे में कैस सोचेगा।

एक और उदाहरण से इसे समझा जा सकता है, पिछले साल चमोली जिले में ही बरसात के दौरान बरसाती नदी पर बना पुल बह गया। सिस्टम के भरोसे बैठे ग्रामीणों को जब यह अहसास हुआ कि ऐसे तो उनके नौनिहालों की जिंदगी खतरे में बनी रहेगी, उन्होंने खुद ही पुल बना डाला। यही सब पिछले दिनों पिथौरागढ़ के गांव में देखने को मिला। महिलाओं ने खुद ही कोसी नदी पर लकड़ी का पुल बना डाला। दरअसल पहाड़ पर गांवों को आबाद करने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले अधिकारी संवेदनशील बनें। यह कहने में गुरेज नहीं कि सिस्टम की संवेदनहीनता पहाड़ की सबसे बड़ी पीड़ा है।

बंगाल

सियासी लाभ के लिए संविधान की अनदेखी

तमाम विधिक औपचारिकताओं के बाद नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) लागू हो गया है, लेकिन देश के कई राज्य इसे मानने से इन्कार कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस के ठीक दूसरे दिन पश्चिम बंगाल विधानसभा में भी सत्तारुढ़ तृणमूल कांग्रेस ने सीएए के विरोध में प्रस्ताव पेश कर संविधान की अनदेखी की है। इसके पहले केरल, पंजाब और राजस्थान में भी इसके विरोध में प्रस्ताव पारित किए जा चुके हैं। भले इस मामले में पश्चिम बंगाल चौथे नंबर पर है, लेकिन हल्ला-हंगामा करने में यह सबसे अव्वल रहा है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसके विरोध में सड़कों पर उतर कर लगातार रैली और जुलूस में शामिल होती रही हैं। उनकी पार्टी की युवा, महिला और छात्र शाखाओं ने सीएए, एनआरसी और एनआरपी के विरोध में लगातार धरना-प्रदर्शन किया। वामो-कांग्रेस ने भी विरोध प्रदर्शन जारी रखा। फर्क बस इतना रहा कि वामो-कांग्रेस ने अलग राह बनाई और तृणमूल प्रमुख के विरोध का सुर अलग गूंजता रहा। पर यह सवाल उठना तो स्वाभाविक है कि आखिर संविधान का सम्मान कैसे हो? क्या राजनीतिक विरोध में संविधान की अनदेखी नहीं की जा रही है? क्या सियासी मुद्दों को हवा देने के लिए तर्कों को दरकिनार किया जा रहा है? आखिर विरोधी दल संविधान सम्मत आचरण क्यों नहीं कर रहे हैं। सीएए को लेकर दुष्प्रचार भी हो रहा है और आखिरी कोशिश यही है कि इसे चुनावी मुद्दा बनाया जाए। फिर चुनावी मुद्दे के लिए सच की अनदेखी भी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह हर मंच से कह रहे हैं कि नागरिकता संशोधन कानून से देश के लोगों को कोई लेना देना नहीं है। यह नागरिकता देने का कानून है, न कि लेने का। ऐसे में इससे देश के किसी नागरिक को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन वोट बैंक के चलते कुछ दल मुसलमानों में भ्रम फैलाकर उन्हें डरा रहे हैं।

गणतंत्र दिवस के ठीक दूसरे दिन तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में सीएए के विरोध में प्रस्ताव पेश कर संविधान की अनदेखी की है

यह भी विडंबना है कि इस मुद्दे को हवा देने के लिए हिंसक वारदातें हो रही हैं। सीएए का समर्थन कर रहे भाजपाइयों के घर में घुस कर मारपीट की गई है। उत्तर दिनाजपुर के चोपड़ा थाना क्षेत्र के धूमडांगी में सीएए के समर्थन में घर-घर संपर्क करने वाले कार्यकर्ताओं को जमकर मारा पीटा गया। धमकी भी दी गई कि अगर सीएए का समर्थन किया तो उन्हें गांव से निकाल दिया जाएगा। इतना दुस्साहस करने वाले कौन हैं? पीड़ित कार्यकर्ताओं ने तो तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों पर मुकदमा दर्ज कराया है। आखिर कानून की अनदेखी करने वालों पर कानूनी शिकंजा कैसे कसेगा? वह भी तब जब राज्य की सत्ताधारी पार्टी खुद ही सीएए के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए है।

केंद्र की बंगाल राज्य इकाई के भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष लगातार अभिनंदन यात्रा निकाल रहे हैं और वह अपनी रैलियों के जरिये भी सीएए का समर्थन कर रहे हैं। मालदा में उन्होंने जनसमर्थन रैली निकालने का एलान भी किया है, लेकिन पुलिस ने उन्हें अनुमति नहीं दी है। इससे भी तनाव बढ़ना तय है।

19 साल बाद भी बिहार-झारखंड के बीच नहीं सुलझा पेंशन विवाद

दिलीप कुमार, रांची

- दोनों राज्यों में से किसी ने भी ऐसे कर्मियों का पता लगाने में नहीं पाई सफलता
- 31 जनवरी को भुवनेश्वर में पूर्वी जोन की बैठक में बिहार-झारखंड के अधिकारी रखेंगे अपने विचार

झारखंड अलग राज्य बने हुए 19 साल हो गए, लेकिन अब तक बिहार-झारखंड के बीच कर्मियों का पेंशन विवाद नहीं सुलझ सका है। यह विवाद एक बार फिर एक मंच पर रखने की तैयारी है। आगामी 31 जनवरी को भुवनेश्वर में होने वाले पूर्वी जोन काउंसिल की बैठक में इस समस्या के समाधान की कोशिश होगी। इस बैठक में बिहार, ओडिशा, झारखंड व बंगाल के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव व अन्य अधिकारी शामिल होंगे।

अलग राज्य गठन के बाद से ही पेंशन विवाद को सुलझाने की कोशिश होती रही है, लेकिन अब तक यह अनसुलझी है। 15 नवंबर, 2000 के बाद दोनों राज्य कर्मियों की संख्या का पता लगाने में अब तक सफल नहीं हुए हैं। यह तय हुआ है कि अगर बिहार 15 नवंबर 2000 तक के कर्मचारियों (तब संयुक्त बिहार) की संख्या का प्रमाणित डाटा देगा तो झारखंड सरकार उसके अनुसार आगे कदम उठा सकती है।

दोनों राज्यों के महालेखाकार के दावे अलग-अलग : महालेखाकार बिहार की गणना के अनुसार, झारखंड सरकार से बिहार सरकार

प्रतीकात्मक

को 310.52 करोड़ का भुगतान किया जाना है, जबकि झारखंड के महालेखाकार की रिपोर्ट इसे केवल 95.47 करोड़ रुपये बताती है। झारखंड के महालेखाकार की रिपोर्ट की मानें तो बैंकों से जो रिपोर्ट मिली है, उसमें वित्तीय वर्ष 2016-17 में झारखंड से दी जाने वाली पेंशन राशि 15 नवंबर 2000 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों से अधिक थी। इसलिए बिहार को किया गया अतिरिक्त भुगतान वापस करना चाहिए।

एमएसपी पर पुनर्विचार की सिफारिश पर पंजाब सरकार ने जताई आपत्ति

इन्द्रप्रीत सिंह, चंडीगढ़

- खेती लागत एवं मूल्य आयोग की ओर से की गई है सिफारिश
- सीएमओ ने सभी सिफारिशों का अध्ययन कर रिपोर्ट बनाने को कहा

खेती लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीबी) द्वारा रबी की फसलों के लिए हाल में की गई सिफारिशों पर पंजाब सरकार ने ऐतराज जताया है। आयोग ने धान और गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की नीति पर फिर से विचार करने को कहा है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके अपना पक्ष रखेंगे।

मुख्यमंत्री कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने खेती विभाग के अधिकारियों को पंजाब के हितों को ध्यान में रखते हुए आयोग की सभी सिफारिशों का अध्ययन कर रिपोर्ट बनाने को कहा है। मुख्यमंत्री इस रिपोर्ट के आधार पर ही प्रधानमंत्री के पास यह मामला उठाएंगे। सीएमओ के अधिकारी ने बताया कि एमएसपी पर पुनर्विचार करने की सिफारिशें करने का काम आयोग का है ही नहीं। उसका काम फसल की लागत के अनुसार किसानों के लिए उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना है।

भारतीय किसान यूनियन के प्रधान बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि धीरे-धीरे

कैप्टन अमरिंदर सिंह फाइल

एमएसपी को तोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। पंजाब, हरियाणा में ही मंडीकरण सिस्टम बना हुआ है जहां पर एमएसपी पर पूरी फसल खरीदी जा रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार व अन्य प्रदेशों जहां पर मंडीकरण सिस्टम नहीं है, वहां एमएसपी से आधी कीमत भी फसलों की नहीं मिलती।

आयोग अपनी सीमा से बाहर जा रहा : राजेवाल : राजेवाल ने कहा कि आयोग अपनी सीमा से बाहर जाकर सिफारिशें कर रहा है। उन्होंने सवाल किया कि एमएसपी सिस्टम को तोड़कर सरकार यदि इसमें प्राइवेट सेक्टर को लाती है तो इतना ज्यादा अनाज कौन सी प्राइवेट फर्म खरीदेगी? यह कौन तय करेगा कि संबंधित फसलें सही कीमत पर बिकी हैं? केंद्र सरकार सभी फसलों का समर्थन मूल्य तय करती है, लेकिन क्या गेहूं और धान के अलावा कोई फसल आज तक एमएसपी पर खरीदी गई है? यह किसानों को बर्बाद करने वाली नीति है, जिसका पंजाब व हरियाणा सरकारों को विरोध करना चाहिए।

आयोग की सिफारिशें

खेती लागत एवं मूल्य आयोग ने अपनी सिफारिशों में कहा है कि चावल और गेहूं की पूरी फसल खरीदने की नीति के कारण अन्न भंडारण ज्यादा हो गया है। अनाज की अधिकता के कारण जहां भंडारण की समस्या खड़ी हो गई है वहीं, इस अनाज को सब्सिडी पर देने से बड़ी राशि खर्च हो रही है। फसली विविधता भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। इसलिए धान व गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फिर से विचार किया जाए।

आज मध्य क्षेत्र के राज्यों की बैठक लेंगे अमित शाह

नईदुनिया, रायपुर

- करीब सात घंटे रायपुर में रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री, योगी आदित्यनाथ, कमलनाथ, त्रिवेंद्र रावत व भूपेश मौजूद रहेंगे बैठक में

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 22वीं बैठक मंगलवार को रायपुर में होगी। इसमें छत्तीसगढ़ समेत चार राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे।

अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ मंगलवार को सुबह साढ़े दस बजे रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। वे नया रायपुर अटल नगर स्थित एक होटल में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री टीएस रावत सोमवार शाम को ही रायपुर पहुंच गए। शाह करीब चार घंटे मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में अंतरराज्यीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद दोपहर तीन बजे से ढाई घंटे तक भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में सीधा संवाद करेंगे।

नक्सल सहित 30 बिंदुओं के एजेंडे पर होगी चर्चा : बैठक में अंतरराज्यीय 30 बिंदुओं को एजेंडे में शामिल किया गया है। इसमें नक्सलवाद के साथ आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर मंथन किया जाएगा। इसके साथ

अमित शाह फाइल

खाद्यान्न सुरक्षा, सड़क कनेक्टिविटी, कृषि के क्षेत्र में राज्यों से समन्वय और आइटी सेक्टर को लेकर विचार-विमर्श किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को बैठक की तैयारियों की समीक्षा की। इसमें आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए सड़क और मोबाइल कनेक्टिविटी का प्रस्ताव भी सौंपा जाएगा। मुख्यमंत्री बघेल परिषद के उपाध्यक्ष हैं।

कुत्तों की आबादी से केंद्र सरकार भी चिंतित, राज्यों से मांगा प्लान

नईदुनिया, रायपुर

सरकारी आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में रैबीज की वजह से प्रतिवर्ष करीब 20 हजार लोगों की मौत हो जाती है। इसमें 90 फीसद से अधिक मामले कुत्तों के काटने के होते हैं। स्ट्रीट डॉग अकेले छत्तीसगढ़ ही नहीं सभी राज्यों के लिए बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं। यही वजह है इस मामले में सीधे केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा है।

- प्रतिवर्ष न्यूनतम 70 फीसद कुत्तों को एंटी रैबीज वैक्सीन देने के निर्देश

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि केंद्र ने रैबीज की रोकथाम के लिए व्यापक स्तर पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसमें स्ट्रीट डॉग्स का बधियाकरण भी शामिल है। राज्यों को हर वर्ष कुत्तों की कुल आबादी के न्यूनतम 70 फीसद को एंटी रैबीज वैक्सीन देने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए सभी राज्यों से प्लान भी मांगा है।

केंद्र सरकार ने राज्यों को भेजे गए पत्र में रैबीज के सभी प्रकरणों की नियमित जानकारी देने के लिए कहा है। इसमें रैबीज पीड़ित के साथ ही रैबीज के संदिग्ध मरीजों की भी रिपोर्ट अनिवार्य रूप से केंद्र को भेजने के लिए कहा गया है।

हर राज्य में न्यूनतम एक लैब बनाने के निर्देश : रैबीज की जांच के लिए हर राज्य में कम से कम एक डायग्नोसिस्ट लैब बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इस लैब में फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी परीक्षण की सुविधा अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।

छग में रैबीज से हर वर्ष 20 हजार लोगों की जाती है जान। प्रतीकात्मक

हरकत में आए तीन विभाग

केंद्र सरकार के इस पत्र के बाद राज्य के तीन विभाग हरकत में आए गए हैं। इनमें पशु चिकित्सा सेवा, पशुधन विकास विभाग और नगरीय प्रशासन विभाग हरकत में आ गए हैं। तीनों विभाग मिलकर संयुक्त कार्ययोजना तैयार कर रहे हैं।

सर्विलांस के लिए संयुक्त टीम का गठन

विभागीय अधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार ने राज्यों को कुत्तों के सर्विलांस के लिए स्वास्थ्य एवं पशुधन विकास विभाग की संयुक्त टीम बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही लोगों में रैबीज से बचाव व नियंत्रण के लिए जागरूकता के प्रयास करने को भी कहा है।

श्रीलंका में सीता माता का भव्य मंदिर बनवाएगी मप्र सरकार

नईदुनिया, भोपाल

- मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दिए मंदिर की योजना बनाने के निर्देश
- मध्य प्रदेश और श्रीलंका के अधिकारियों की बनाएंगे समिति

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने श्रीलंका में सीता माता के भव्य मंदिर के निर्माण की योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए मध्य प्रदेश और श्रीलंका के अधिकारियों की समिति भी बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंदिर निर्माण और सांची में अंतरराष्ट्रीय स्तर का बौद्ध संग्रहालय, अध्ययन एवं प्रशिक्षण केंद्र बनाने के लिए शीघ्र ही योजना बनाएं और उसका क्रियान्वयन करें।

मुख्यमंत्री सोमवार को मंत्रालय में जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा कर रहे थे। बैठक में महाबोधि सोसायटी के अध्यक्ष बनागला उपतिसा भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीलंका में सीता माता मंदिर के भव्य निर्माण के लिए शीघ्र ही एक समिति बनाई जाए, जिसमें मध्य प्रदेश एवं श्रीलंका सरकार के अधिकारियों के साथ महाबोधि सोसायटी के सदस्य भी शामिल हों। यह समिति मंदिर निर्माण कार्यों की निगरानी करेगी, जिससे समयसीमा में मंदिर का निर्माण हो सके। उन्होंने कहा कि मंदिर के डिजाइन को अंतिम रूप दिया जाए और इसी वित्तीय वर्ष में आवश्यक धन राशि भी उपलब्ध करवाई जाए, जिससे मंदिर का निर्माण शीघ्र हो सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि जापान की कई कंपनियों और संस्थाओं ने सांची में विभिन्न संरचनाओं के निर्माण

कमलनाथ फाइल

के लिए वित्तीय सहायता देने की पेशकश की है।

जनसंपर्क मंत्री ने हाल ही में श्रीलंका यात्रा के दौरान मंदिर के निर्माण को लेकर में वहां की सरकार से हुई चर्चा की जानकारी दी। शर्मा ने कहा कि अगर बेहतर वायु सेवाएं उपलब्ध हों तो श्रीलंका सहित बौद्ध धर्म को मानने वाले अन्य देशों के श्रद्धालुओं को सांची आने में सुविधा होगी। इसी तरह मध्य प्रदेश के लोगों को भी सीता मंदिर के दर्शन करने में आसानी होगी। इस मौके पर महाबोधि सोसायटी श्रीलंका के अध्यक्ष बनागला उपतिसा ने बौद्ध प्रतिमा, बौद्ध ग्रंथ एवं स्वयं की लिखित पुस्तक भेंट की। जनसंपर्क मंत्री ने भी श्रीलंका यात्रा के दौरान वहां से लाए उपहार मुख्यमंत्री को भेंट किए।

पर्यटन और गोशाला पर भी खर्च होगी खनिज निधि

नईदुनिया, भोपाल

- मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला

मध्य प्रदेश में खनिज निधि की राशि अब पर्यटन क्षेत्रों के विकास और गोशाला के निर्माण पर भी खर्च होगी। इसके लिए खनिज प्रतिष्ठान नियम 2016 में संशोधन होगा।

यह बात मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोमवार को मंत्रालय में राज्य खनिज निधि को लेकर आयोजित बैठक में कही। उन्होंने खनिज विभाग के अधिकारियों को 10 दिन के भीतर खनिज निधि के बेहतर उपयोग की कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि खनिज निधि का उपयोग उन क्षेत्रों में अधिक होना चाहिए, जो खनन से प्रभावित होते हैं। इसके साथ ही प्रभावित क्षेत्र से संबंधित पर्यटन स्थलों के विकास में भी निधि खर्च की जानी चाहिए। गोशाला के निर्माण में भी निधि का उपयोग हो सके, इसके प्रावधान भी किए जाएं।

उन्होंने खनिज विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि खनिज निधि का अधिक से अधिक इस्तेमाल हो सके, इसके लिए नई कार्ययोजना बनाई जाए। साथ ही मध्यप्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम 2016 में भी परिवर्तन करके उसे व्यावहारिक बनाया जाए।

30 फीसद राशि से जिला खनिज निधि बनाई गई

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि मुख्य खनिजों से मिलने वाली रॉयल्टी के अतिरिक्त 30 प्रतिशत राशि से जिला खनिज निधि बनाई गई है। लीज होल्डरों से निधि ली जाती है। इसमें 60 प्रतिशत राशि पेयजल, स्वास्थ्य एवं शिक्षा और 40 प्रतिशत राशि अधोसंरचना पर खर्च करने का प्रावधान है।

2030 तक भारत दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा और आबादी का बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहेगा।

कितनी तेजी से ब्रह्मांड को निगल रहा ब्लैक होल, बताएगा भारत

जागरण विशेष ▸ ब्लैक होल बाइनरी सिस्टम के गुरुत्व बल का आंकड़ा जुटाने के लिए कानपुर आइआइटी बना रहा मैथमेटिकल मॉडल

आंतरिक अभिवृद्धि की त्रिज्या व अभिवृद्धि की दर से करेंगे ब्लैक होल में प्रति सेकेंड समा रहे द्रव्यमान की गणना

विक्सन सिक्रोड़िया, कानपुर

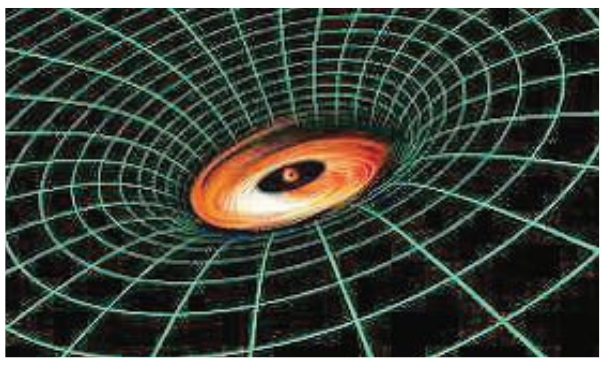

प्रतिनिधि चित्र

प्रो. रंजीव मिश्र, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनामी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, पुणे

दिव्या रावत, शोध छात्रा, आइआइटी कानपुर

प्रो. पंकज जैन, भौतिक विभाग, आइआइटी कानपुर

प्रो. जेएस यादव, भौतिक विभाग, आइआइटी कानपुर

सभी तस्वीरें, सौ.-प्रो. पंकज जैन

कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल के राज अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश में आगे बढ़ चुका भारत जल्द ही दुनिया को यह भी बताएगा कि ब्लैक होल कितनी तेजी से ब्रह्मांड को निगल रहा है। ब्लैक होल के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र (इंडियन स्पेस रिसर्च आर्गेनाइजेशन, इसरो) की तरफ से पांच साल पहले भेजे गए एस्ट्रोसेट उपग्रह (सेटेलाइट) के जरिये यह उपलब्धि हासिल होगी। कानपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आइआइटी) सेटेलाइट से प्राप्त आंकड़ों का अध्ययन करने में जुटा है।

इसरो से इस प्रोजेक्ट में कानपुर आइआइटी के साथ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (टीआइएफआर) और इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनामी एंड एस्ट्रोफिजिक्स की टीम एक साथ काम कर रही है। रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए आइआइटी कानपुर के एस्ट्रोफिजिक्स विभाग की टीम एक और उन्नत गणितीय मॉडल तैयार कर रही है। इसरो ने वर्ष 2015 में एस्ट्रोसेट सेटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा था। इस सेटेलाइट के साथ कानपुर आइआइटी के प्रोफेसर जेएस यादव का बनाया हुआ और टीआइएफआर में विकसित एक्स-रे डिटेक्टर सॉफ्ट एक्स-रे टेलीस्कोप व लार्ज एरिया एक्स-रे प्रोपर्शनल काउंटर भी भेजा गया है। यह दोनों उपकरण वहां से ब्लैक होल संबंधी डाटा भेज रहे हैं।

ब्लैक होल से निकलने वाली ऊर्जा से उत्सर्जित पराबैंगनी किरण, एक्स किरण और गामा किरण संबंधी आंकड़े भी इनमें शामिल हैं। इसरो ने आंकड़ों के अध्ययन की जिम्मेदारी आइआइटी कानपुर के एस्ट्रोफिजिक्स विभाग के प्रो. पंकज जैन को दी है। इन आंकड़ों के अध्ययन से पता चला है कि ब्लैक होल में तेजी से समा रहे द्रव्यमान के कारण बनी डिस्क से निकलने वाली ऊर्जा एक्स किरण की प्रकृति बदलने की कारक है। इसके पीछे ब्लैक होल में द्रव्यमान के समाने से हो रही आंतरिक अभिवृद्धि की त्रिज्या और अभिवृद्धि की दर का संबंध प्रमुख कारण है।

प्रो. जैन ने बताया कि सेटेलाइट से इस संबंध में प्राप्त तमाम सूचनाओं-आंकड़ों की गणना अब तक सामान्य गणितीय मॉडल से की जा रही थी, लेकिन अब सटीक गणना के लिए एक अन्य उन्नत गणितीय मॉडल तैयार किया जा रहा है। जुटाए जा रहे डाटा से आइंस्टीन के सापेक्षिता के सिद्धांत के साथ तुलना की जाएगी। यह भी देखा जाएगा कि क्या किसी अन्य थ्योरी पर भी काम किया जा सकता है। डाटा विश्लेषण से बन रहे इस मॉडल के जरिए भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों को समझाने में आसानी होगी। छात्र ब्लैक होल के बारे में और करीब से जान सकेंगे। ब्लैक होल के क्षेत्र में वर्षों से अध्ययन करने वाले द इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे के प्रो. रंजीव मिश्रा व पीएचडी स्कॉलर दिव्या रावत ने भी इस अध्ययन में अहम योगदान दिया है।

> ब्रह्मांड में घूम रहे सूर्य से दस गुना बड़े ब्लैक होल जीआरएस1915+105 से उत्सर्जित एक्स किरणों के अध्ययन से पता चला है कि वह ब्लैक होल के इर्द-गिर्द बनी डिस्क के आंतरिक क्षेत्र से उत्पन्न हो रही हैं। एक निश्चित समय अंतराल में इसके उत्सर्जन, तीव्रता और व्यवहार में बदलाव हो रहा है। इस बदलाव की गति द्रव्यमान के ब्लैक होल में समा जाने की गति के सापेक्ष है। हम इसकी सटीक गणना करने में जुटे हैं। प्राथमिक रिपोर्ट इसरो को भेजी जा रही है।
> – प्रो. पंकज जैन, आइआइटी कानपुर

यह भी जानें

- **2015** में इसरो ने भेजा एस्ट्रोसेट सेटेलाइट
- **2016** में एस्ट्रोसेट ने ब्लैक होल बाइनरी सिस्टम की पहली जानकारी दी
- **2018,** अक्टूबर 28 को प्रधान अन्वेषक और टीआइएफआर के प्रो. सुदीप भट्टाचार्य ने कहा- एस्ट्रोसेट से ब्लैक होल के बनने, उसके द्रव्यमान और स्पिन का आसानी से पता चलेगा
- **2018,** नवंबर दो को एस्ट्रोसेट ने एक और ब्लैक होल बाइनरी सिस्टम की दी जानकारी
- **2019** में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जारी की थी ब्लैक होल की फोटो, नासा भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें www.jagran.com/topics/jagran-special

हाई कोर्ट की शर्त, पेड़ सूखे तो फिर जाओगे जेल

भलाई की सीख ▸ मुरैना के जंगल में हैं जमानत के पेड़, निगरानी करती है पुलिस

शिवप्रताप सिंह जादौन, मुरैना

▸ अपराध की प्रवृत्ति को नेकी व जिम्मेदारी में बदलने का अदालत का प्रयास

▸ देवरी पंचायत में बने इस पितृवन में लगे हैं 200 से ज्यादा पेड़

मप्र के मुरैना जिले में एक ऐसा जंगल भी है, जहां लगे पेड़ों को देखने पुलिस भी पहुंचती है। ऐसा नहीं है कि यह पुलिस का पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़-पौधों के लिए प्रेम हो, बल्कि ड्यूटी के लिए ये पुलिस की मजबूरी है। दरअसल, ये पेड़ हैं जमानत के, जिन्हें आपराधिक मामलों में आरोपितों ने हाई कोर्ट के आदेश पर लगाया है। यदि इन पेड़ों के रख रखाव में लापरवाही बरती जाती है तो आरोपितों की जमानत निरस्त हो सकती है, यह कोर्ट की शर्त है, जिसके आधार पर जमानत दी गई है।

इसलिए आरोपित भी हर हफ्ते इन पेड़-पौधों को सुरक्षित रखने के लिए न सिर्फ पैसे खर्च करते हैं बल्कि समय-समय पर खुद निताई-गुढ़ाई के साथ खाद पानी भी देते हैं। मुरैना की देवरी पंचायत के अंतर्गत बने पितृवन में जमानत के रूप में ऐसे लगभग 200 पेड़ लगाए जा चुके हैं। मुरैना जिले से करीब 5 किमी दूर क्वारी नदी के किनारे देवरी पंचायत के बीहड़ हैं। बीहड़ में करीब 4 साल पहले प्रशासन और शहर के समाजसेवियों की पहल पर एक ऐसा जंगल तैयार किया गया है, जहां लोग अपने पूर्वजों और जीवन के यादगार दिनों की स्मृति में पौधे लगाते हैं। इन पौधों की देखरेख कल्पवृक्ष सेवा समिति द्वारा की जाती है। पितृवन नाम से संरक्षित किए गए इस स्थान पर अब तक 2 हजार पौधे लगाए जा चुके हैं। 2 हजार पौधों में 200 पौधे ऐसे हैं, जिन्हें दुष्कर्म, जालसाजी, मारपीट और दहेज प्रताड़ना के मामलों में आरोपितों ने लगाया है। यह पेड़ असल में इन लोगों की कोर्ट में जमानत के रूप में हैं।

पर्यावरण संरक्षण

आरोपित उठा रहे हैं खर्च: ग्वालियर हाई कोर्ट (खंडपीठ) ने बीते पांच माह में एक दर्जन के करीब आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत देवरी पंचायत में 200 के करीब पेड़ लगे हैं। यह पेड़ पितृवन में कल्पवृक्ष सेवा समिति द्वारा पाले पोसे जा रहे हैं। इसका खर्च इन पेड़ों को लगाने वाले आरोपित उठा रहे हैं। हर हफ्ते इनकी देख-रेख की चिंता आरोपितों को यहां खींच लाती है । पेड़ खराब न हो जाएं या सूख न जाएं, इसकी चिंता भी आरोपित करते हैं और हर हफ्ते यहां आते हैं। पूरी तन्मयता से इनकी देखभाल करते हैं। खुद खुरपी और दूसरे औजार लेकर इन पौधों की निताई-गुढ़ाई करते हैं और साथ ही खाद पानी देते हैं। स्थिति यह है कि आरोपितों ने अपने पौधों की पहचान के लिए इनके चारों ओर अलग से जाली लगाकर अपने नाम की प्लेट भी लगाई हैं।

अदालत को सूचित करने का जिम्मा पुलिस : मजेदार बात यह कि पितृवन में लगाए गए पौधों में से किसी आरोपित के पौधे खराब तो नहीं हो गए, नियमित अंतराल पर इसकी जांच रिपोर्ट तैयार कर अदालत को सूचित करने का जिम्मा पुलिस को सौंपा गया है। हर माह स्थानीय सिविल लाइंस थाने के बीट इंचार्ज यहां आते हैं और पेड़ों को दखेते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं। पितृ वन की संचालनकर्ता कल्प वृक्ष सेवा समिति भी आरोपितों को समय-समय पर सर्टिफिकेट देती है, जिसे आरोपित कोर्ट में पेश कर बताते हैं कि उनकी जमानत के पेड़ सही सलामत हैं।

जंगल का एक हिस्सा जहां लगे हैं जमानत के पेड़। नईदुनिया

जंगल में पौधे देखने पहुंचे बीट इंचार्ज (दाएं)। नईदुनिया

> पितृ वन में जमानत के तौर पर न्यायालय के आदेशों पर पौधे लगाए गए हैं। पौधे ठीक से लगे हैं, इस बात का सर्टिफिकेट समिति जारी करती है। पुलिस भी आकर पौधों को देखती है। पौधे खराब होने पर जमानत निरस्त मानी जाए, इस तरह की शर्त है। इसलिए आरोपित भी यहां हफ्ते दो हफ्ते में आकर श्रमदान करते हैं।
> – अतुल माहेश्वरी, अध्यक्ष कल्पवृक्ष सेवा समिति

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें www.jagran.com/topics/positive-news

ऋषिकेश रेलवे स्टेशन के बाहर लगी काउंटडाउन घड़ी

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश : ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना का पहले स्टेशन 'योग नगरी ऋषिकेश' पर निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। चार फरवरी को कमिश्नर रेलवे सेफ्टी इसका निरीक्षण करेंगे। यदि उन्होंने हरी झंडी दे दी तो यहां रेल गाड़ियों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए स्टेशन के बाहर काउंटडाउन घड़ी भी लगाई गई है।

रेल विकास निगम ने योग नगरी ऋषिकेश स्टेशन को तैयार करने के लिए चार फरवरी तक का लक्ष्य तय किया है। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन पर ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक कुल 12 स्टेशन बनाए जाने हैं। इनमें योग नगरी ऋषिकेश स्टेशन पहला स्टेशन है। रेल विकास निगम ने करीब दो वर्ष पूर्व इस स्टेशन के निर्माण पर काम शुरू किया था। परियोजना प्रबंधक ओमप्रकाश मालगुड़ी ने बताया कि अलग-अलग स्तर पर स्टेशन की जांच की जा रही है। चार फरवरी को कमिश्नर रेलवे सेफ्टी स्टेशन व रेल लाइन का अंतिम निरीक्षण करेंगे। उन्होंने बताया कि 90 फीसद काम पूरा हो चुका है, शेष 10 फीसद काम अगले एक सप्ताह में पूर्ण कर दिया जाएगा।

स्टेशन पर बनाए गए दो अंडर पास : रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म तक जाने के लिए फुटओवर ब्रिज नहीं, बल्कि दो अंडर पास बनाए गए हैं। इनमें से एक अंडर पास पर दो लिफ्ट होंगी,।

राजकोट राजपरिवार में चार दिवसीय राजतिलक समारोह की हुई शुरुआत

शत्रुघ्न शर्मा, अहमदाबाद

▸ मां आसापुरा की पूजा के साथ शुरू किया गया समारोह

▸ देशभर के 100 राजवाड़े और खास मेहमान आमंत्रित

राजकोट राजपरिवार में चार दिवसीय राजतिलक समारोह की शुरुआत सोमवार को आसापूरा माता के दर्शन व पूजा से हुई। 30 जनवरी को राजपरिवार के सदस्य मांधाता सिंह जाडेजा का पारंपरिक रूप से राज्याभिषेक होगा। शहर के रणजीत विलास पैलेस में आयोजित समारोह में देश के करीब सौ राजपरिवार व नामी हस्तियों को आमंत्रित किया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी आमंत्रितों में शामिल हैं।

30 जनवरी तक चलने वाले इस समारोह में राजपूत समाज के करीब 3000 युवक-युवती तलवार रास का प्रदर्शन करेंगे। यह अपने आप में रिकार्ड होगा। सोमवार को रामकथा वाचक मोरारी बापू रणजीत विलास पहुंचे और मांधाता सिंह जाडेजा को बधाई दी। द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती, दंडी स्वामी सहित देश-प्रदेश के करीब 50 संत-महात्मा भी इस समारोह में शामिल होंगे। 51 ब्राह्मण वैदिक मंत्रोच्चार के साथ राज्याभिषेक कराकर समारोह को संपन्न कराएंगे।

समारोह में करीब डेढ़ हजार विशिष्ट मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। 28 जनवरी को बैंड बाजे के साथ हाथी पर सवारी निकलेगी और राजपरिवार के पास जमा हैरीटेज कारों की एक रैली भी निकाली जाएगी। मीडिया में इस राजपरिवार के समारोह की खासी चर्चा है। राजकोट को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। रणजीत विलास पैलेस को राजपरिवार के ध्वज व राज चिह्न से सजाया गया है। मेहमानों के बैठने, जलपान सहित समारोह की विविध तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 400 साल पुराने इस राजपरिवार में यह राजतिलक का 17वां समारोह है।

राजकोट निवासी हिमांशु बायानी बताते हैं कि इससे पहले उनके पिता मनहर सिंह जी जाडेजा का राज्याभिषेक हुआ था। मनहर सिंह गुजरात विधानसभा के सदस्य चुने गए थे तथा स्वास्थ्य, वित्त, पोर्ट सहित आधा दर्जन से अधिक मंत्रालयों को संभाला था।

रणजीत विलास पैलेस में राजतिलक समारोह के दौरान राजकोट राजपरिवार के सदस्य मांधाता सिंह जाडेजा पुत्र जयदीप सिंह जाडेजा के साथ। सौ. राजपरिवार

दुर्लभ प्रजाति के लकड़बग्घों के संरक्षण पर राजाजी पार्क प्रशासन ढुलमुल

अनूप कुमार, हरिद्वार

▸ शेड्यूल-वन के प्राणी लकड़बग्घे के संरक्षण को राजाजी प्रशासन के पास नहीं है कोई ठोस योजना

▸ वर्ष 2013 की आपदा के बाद राजाजी के जंगलों में मिले थे लकड़बग्घे की मौजूदगी के प्रमाण

जंगल के प्राकृतिक सफाई कर्मी कहे जाने वाले दुर्लभ प्रजाति के लकड़बग्घों (हायना) के संरक्षण को राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन गंभीर नजर नहीं आ रहा। वर्ष 2013 में उत्तराखंड में आई आपदा के बाद राजाजी के जंगलों में लकड़बग्घों की मौजूदगी के प्रमाण मिले थे। तब लकड़बग्घा न सिर्फ कैमरा ट्रैप में कैद हुआ था, बल्कि कुछ पर्यटकों और पार्क कर्मियों को भी दिखाई दिया था। बाद में लकड़बग्घों की तादाद बढ़ने की जानकारी सामने आने पर राजाजी टाइगर रिजर्व के तत्कालीन निदेशक सनातन सोनकर ने इसे संरक्षित किए जाने की बात भी कही थी, लेकिन जमीनी स्तर पर आज तक इस दिशा में कोई पहल नहीं हुई।

शेड्यूल-वन के प्राणियों में शामिल लकड़बग्घा की पार्क में मौजूदगी के बावजूद इसके संरक्षण को लेकर राजाजी पार्क प्रशासन का रवैया नकारात्मक ही रहा। पार्क के वर्तमान निदेशक पीके पात्रो तो यह जानकारी होने से भी साफ इन्कार करते हैं कि पूर्व निदेशक सनातन सोनकर की ओर से लकड़बग्घा के संरक्षण की बात कही गई थी, जबकि प्रभागीय वनाधिकारी आकाश वर्मा इस वर्ष बाघों के साथ लकड़बग्घों की भी गिनती किए जाने की बात कह रहे हैं। वास्तविकता यह है कि राजाजी पार्क प्रशासन का सारा ध्यान बाघ व गुलदार पर केंद्रित होने के कारण लकड़बग्घा उसकी प्राथमिकता में नहीं है। हालांकि, विभागीय कर्मी लकड़बग्घा के संरक्षण में हो रही हीला-हवाली को जंगल के ईको सिस्टम के लिए खतरा मानते हैं। वह कहते हैं कि वर्षों पहले पार्क में लकड़बग्घों की अच्छी-खासी मौजूदगी रही है, लेकिन अनदेखी के चलते वर्तमान में इनकी संख्या ना के बराबर रह गई है।

राजाजी टाइगर रिजर्व की चीला रेंज को छोड़ दें तो पार्क की बाकी अन्य आठ रेंजों में लकड़बग्घा की मौजूदगी के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। इससे साफ है कि बीते छह वर्षों के दौरान इन रेंजों में लकड़बग्घा की आमद दर्ज कराने के कोई प्रयास नहीं हुए, जबकि दावा किया गया था कि हर रेंज में लकड़बग्घा के संरक्षण को वृहद योजना तैयार की जाएगी।

जमीनी स्तर पर लकड़बग्घों के संरक्षण के लिए नहीं की गई पहल। फाइल

जनजातीय समुदाय के मेले में हुनर के दर्शन

जागरण संवाददाता, प्रयागराज : दैनिक उपयोग की सामग्रियां बनाने में देश के जनजातीय समुदाय के लोगों की हस्तकला बेमिसाल है। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र (एनसीजेडसीसी) में लगे 'आदि महोत्सव' में 20 राज्यों के करीब 200 जनजातीय कलाकारों का संगम हुआ है, जो उनकी कलाकारी से रोशन है। चित्रकला, ज्वैलरी, साड़ियां, गर्म कपड़े, पश्मीना शॉल के साथ-साथ खाद्य सामग्रियां भी लुभा रही हैं। इनमें हैदराबादी कद्दू की खीर और लद्दाख की सीबक थॉर्न चाय के दीवाने भी खूब हैं।

▸ एनसीजेडसीसी में आयोजित आदि महोत्सव में हस्तकला एवं संस्कृति की झलक

▸ देशभर के 20 राज्यों से आए कारीगरों के हस्तशिल्प उत्पाद बने हर किसी की पसंद

आदि महोत्सव में पहाड़ी राज्यों जैसे सिक्किम, उत्तराखंड, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के अलावा ओडिशा, तेलंगाना, मणिपुर और नगालैंड जैसे राज्यों के हस्तकला के कुशल कारीगर प्रतिभाग कर रहे हैं। लद्दाख से आए एस कर्मा की सीबक थॉर्न चाय लोगों को शुगर फ्री होने के साथ ही हृदय को दुरुस्त रखने, मधुमेह के मरीजों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, कैंसर के कीटाणुओं से लड़ने में भी लाभदायक होती है। लद्दाख से ही गर्म कपड़े लेकर आईं श्रीन छोटन कहती हैं कि पश्मीना शॉल कॉमन भाषा में ताना-बाना है। इसे हथकरघा मशीन से बनाया जाता है। स्टॉल, मफलर, ऊन भी प्रयागराज को नया उत्पाद दे रहे हैं।

बंगाल के वर्धमान जिले से आए प्रोले मंडल ने हाथ से बनी साड़ियां, दुपट्टा, सूट पीस और कुर्ती आदि का प्रदर्शन कर महिला ग्राहकों को आकर्षित कर रखा है तो राजस्थान के जयपुर से घासीराम मीणा के स्टॉल में लगे प्लास्टिक के नेकलेस टोकरी आदि खूबसूरती बिखेर रहे हैं। खाद्य सामग्री में हैदराबादी चिकन बिरयानी, कद्दू की खीर ने जायके का नया अंदाज पेश किया है।

कारीगरों की प्रतिभा लाजवाब : ट्राइफेड देहरादून के प्रयागराज क्षेत्रीय प्रबंधक अल्ताफ अंसारी का कहना है कि जनजातीय समुदाय के कलाकारों और कारीगरों की प्रतिभा लाजवाब है। उनका उत्साहवर्धन करने के लिए यह महोत्सव आयोजित किया गया है जो तीन फरवरी तक चलेगा।

आया सामने

खोदाई में शाही ताबूत, दो ताबूतों के साथ रथ, धनुष-बाण, तलवार आदि मिले थे, एक हौद भी मिला था, संभवत : इसका उपयोग शवों पर लेप लगाने जैसी क्रियाओं में किया जाता था

3800 साल पुराने हैं सिनौली में मिले साक्ष्य

वी.के. शुक्ला, नई दिल्ली

महाभारत काल की खोज को ध्यान में रखकर उत्तर प्रदेश के बागपत के सिनौली में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) को बड़ी सफलता मिली है। वहां से खोदाई में मिले जले अवशेषों की कार्बन डेटिंग (काल निर्धारण की विधि) जांच में इनके 3800 साल पुराने होने की पुष्टि हुई है। वहां से मिले एक हौद के सीक्रेट चैंबर होने का पता चला है। संभवतः इसका उपयोग अंतिम संस्कार में शवों पर लेप आदि लगाने के लिए किया जाता था। इसके बाद शव को ताबूत में रख कर जमीन में गाड़ दिया जाता था। इस चैंबर में दक्षिण दिशा से प्रवेश के संकेत मिले हैं।

सिनौली में दो साल तक लगातार खोदाई हुई है। इसमें शाही ताबूत, दो ताबूतों के साथ रथ, धनुष-बाण, तलवार, युद्ध में पहने जाने वाले हेलमेट आदि चीजें मिली हैं जो ताबूतों में रखे शवों के योद्धा के होने की ओर इशारा करती हैं। इन ताबूतों के साथ मिट्टी के बर्तनों में जले हुए कुछ अवशेष मिले थे। ये कितने पुराने हैं इनकी जांच के लिए एएसआइ ने इनके तीन सैंपल लखनऊ स्थित बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान को भेजे थे। जिनकी रिपोर्ट करीब एक माह पहले एएसआइ के पास आ गई है, जिसमें इन अवशेषों के 3800 साल पुराने होने की पुष्टि की है।

एएसआइ के अनुसार, यह काल उत्तर वैदिक था। उस समय हिंदू रीति-रिवाजों में तीन तरह से शव का अंतिम संस्कार किया जाता था। पहले शव को खुले में छोड़ दिया जाता था। जानवरों के खा लेने के बाद बची हुई हड्डियों को नदी में बहाया या जला दिया जाता था। दूसरे में शव को जला दिया जाता था। तीसरे में शव को ताबूत में रखकर जमीन में गाड़ दिया जाता था। ताबूत में रखकर जमीन में गाड़ने की परंपरा राजा महाराजाओं में ही होती थी।

जांच में हम महाभारत काल की ओर बढ़ रहे हैं : भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अतिरिक्त महानिदेशक डॉ. संजय मंजुल का कहना है कि हम यह दावा नहीं कर सकते कि सिनौली में मिले साक्ष्य महाभारत के योद्धाओं के हैं, मगर हम यह जरूर कह रहे हैं जो साक्ष्य मिल रहे हैं वे उसी काल से संबंधित हैं जो हम महाभारत का आंकते हैं। अब कार्बन डेटिंग में भी इस बात की पुष्टि हुई है। हम खोदाई में मिले साक्ष्यों की जांच को आगे बढ़ा रहे हैं। सिनौली में जो साक्ष्य मिले हैं इस तरह के साक्ष्य देश में आज तक किसी खोदाई में नही मिले हैं। खोदाई स्थल के आसपास के क्षेत्र की कराई गई जांच में अभी वहां जमीन में और भी तमाम ताबूत आदि के बारे में पता चला है। भविष्य में इस पर आगे काम किया जाएगा।

बागपत के सिनौली में मिले सीक्रेट चैंबर में ताबूत रखकर एरिया की जांच कराते भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी। फाइल

बागपत के सिनौली में मिला सीक्रेट चैंबर। फाइल

सियाम ने की प्रोत्साहन आधारित स्क्रैप पॉलिसी की मांग

नई दिल्ली, प्रेट्र : वाहन कंपनियों के संगठन सियाम ने सोमवार को सरकार से बजट से पहले प्रोत्साहन आधारित कबाड़ नीति लाने और बीएस-6 मानक वाले वाहनों पर जीएसटी घटाने का आग्रह किया है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्यूफैक्चरर्स (सियाम) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को राज्यों द्वारा खरीदी जाने वाली पेट्रोल-डीजल बसों के लिए बजट आवंटन बढ़ाने का भी सुझाव दिया।

यदि कारोबारी स्वदेशी अपनाएं, स्वदेशी बेचें और स्वदेशी को प्रोत्साहित करें तो विकास दर दहाई अंक तक जा सकती है।
— पीयूष गोयल
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

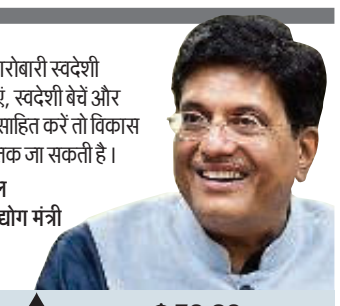

सेंसेक्स	41,155.12	458.07	निफ्टी	12,119	129.25	सोना प्रति दस ग्राम	₹ 41,292	₹133	चांदी प्रति किलोग्राम	₹ 47,277	₹238
$ डॉलर	₹ 71.43	₹0.10	क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल	$ 59.29							

'महाराजा' के कंगाल होने की कहानी

महाराजा के नाम से मशहूर एयर इंडिया में सरकार ने सौ प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की तैयारी की है। सरकार एयर इंडिया एक्सप्रेस में अपनी सौ प्रतिशत और संयुक्त उपक्रम कंपनी एयर इंडिया सैट्स में पचास प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी। बोली लगाने की अंतिम तिथि 17 मार्च है। बोली के लिए सरकार ने सब्सिडियरी कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयरपोर्ट सर्विस कंपनी को भी आमंत्रित किया है।

ऋण और देनदारियों का भी स्थानांतरण: एयर इंडिया के लिए चुने गए खरीदार को 32,447 करोड़ रुपये का ऋण व देनदारियां भी स्थानांतरित की जाएंगी, जबकि 56,334 करोड़ रुपये का ऋण, देनदारियां और कॉरपोरेट गांरटी विशेष उद्देश्य से बनाई गई कंपनी एयर इंडिया असेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआइएएचएल) को स्थानांतरित की जाएंगी। विनिवेश प्रक्रिया पूरी होने तक यदि एयर इंडिया पर ऋण या देनदारी बढ़ती है तो अतिरिक्त बोझ एआइएएचएल को वहन करना होगा।

...तो अंतर के बराबर राशि सरकार देगी

दिल्ली और मुंबई में एयर इंडिया की जमीन और इमारतें एआइएएचएल को स्थानांतरित की जाएंगी जिसे बेचकर वह ऋण तथा देनदारियों की पूर्ति करेगी। यदि फिर भी भरपाई नहीं हो सकेगी तो अंतर के बराबर राशि सरकार द्वारा दी जाएगी।

कर्मचारियों का पूरा ध्यान

नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अनुसार कर्मचारी पूरी प्रक्रिया से प्रभावित नहीं होंगे। स्थायी कर्मचारियों को तीन प्रतिशत हिस्सेदारी दी जाएगी। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के 17 हजार कर्मचारी हैं जिनमें नौ हजार से अधिक स्थायी हैं। कर्मचारियों के मद में एयरलाइन की देनदारी 1,300 करोड़ रुपये से कुछ अधिक है। मुख्य देनदारी सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को देय राशि की है। यह राशि सरकार द्वारा दी जाएगी। स्थायी कर्मचारियों में 36 प्रतिशत अगले पांच साल में सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

घाटे का बड़ा कारण यह भी

अधिकारियों की मानें तो पाकिस्तान द्वारा हवाई रूट बंद कर दिए जाने के बाद एयरलाइन को हर दिन तीन से चार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। जेआरडी टाटा द्वारा लांच की गई और आजादी के कुछ ही वर्षों बाद सरकार के नियंत्रण में आने वाली एयर इंडिया की कहानी अगले लगभग पांच दशकों तक खुशियों से भरी रही। लेकिन वर्ष 2005 में 111 नए प्लेन खरीदने का इसका फैसला ठीक नहीं रहा। इस डील के कारण कंपनी पर 70 हजार करोड़ रुपए का बड़ा खर्च आया था।

मिलेगा बना-बनाया बाजार

अगर कोई निवेशक इस कंपनी को खरीदता है तो उसे बना बनाया बाजार मिलेगा। कंपनी के पास कई लाभकारी रूट हैं। साथ ही उसे घरेलू स्तर पर उड़ान के लिए जरूरतों की पूर्ति भी आसानी से हो जाएगी। 118 एयरक्राफ्ट के साथ एयर इंडिया का बेड़ा इंडिगो के बाद दूसरे नंबर पर है।

अब शर्तें की आसान

वर्ष 2018	वर्ष 2020
51 हजार करोड़ का कर्ज था, खरीदार को 33,392 करोड़ का भार उठाना था	60 हजार करोड़ रुपये का कर्ज, खरीदार को 23,286 करोड़ की जिम्मेदारी लेनी है
76% शेयर बेचना चाहती थी	100% हिस्सेदारी बेची जाएगी
नेटवर्थ 5,000 करोड़ रुपये होना जरूरी	नेटवर्थ 3,500 करोड़ रुपये होने चाहिए
कंसोर्टियम के प्रमुख सदस्य की हिस्सेदारी 51 प्रतिशत, अन्य सदस्यों की 20 प्रतिशत आवश्यक	प्रमुख सदस्य की हिस्सेदारी 26 प्रतिशत, जबकि अन्य सदस्यों की 10 प्रतिशत जरूरी होगी
बोली लगाने वाले को बीते पांच में से तीन वर्ष फायदे में होना आवश्यक	किसी खास अवधि के लिए फायदे के मामले में अब ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गई है

नीति आयोग ने दिया था प्रस्ताव

बीते साल भी सरकार एयर इंडिया को बेचना चाहती थी, लेकिन कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता के कारण सरकार ने इसे रोक दिया था। अब सरकार इसे बेचने के लिए एक बार फिर सक्रिय हुई है।

ये भी जानें

- टाटा एयरलाइन ने 1932 में यह सर्विस शुरू की थी। 15 अक्टूबर 1932 को जेआरडी टाटा ने कराची से मुंबई की फ्लाइट खुद उड़ाई थी। वह देश के पहले लाइसेंसी पायलट थे। 1946 में इसका नाम बदलकर एयर इंडिया किया गया। 1953 में सरकार ने इसे खरीद लिया था।
- वर्ष 2000 तक यह मुनाफे में चलती रही। 2001 में कंपनी को 57 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। 2007 में केंद्र सरकार ने एयर इंडिया में इंडियन एयरलाइंस का विलय किया।
- दोनों कंपनियों का विलय के वक्त संयुक्त घाटा 770 करोड़ रुपये था, जो बाद में बढ़कर के 7,200 करोड़ रुपये हो गया।
- एयर इंडिया ने घाटे की भरपाई के लिए अपने तीन एयरबस 300 और एक बोइंग 747-300 को 2009 में बेच दिया था।
- मार्च, 2011 में कंपनी का कर्ज बढ़कर 42600 करोड़ रुपये और परिचालन घाटा 22000 करोड़ रुपये का हुआ।
- इस समय करीब 58 हजार करोड़ के कर्ज में दबी एयर इंडिया को वित्त वर्ष 2018-19 में 8,400 करोड़ रुपये का घाटा हुआ।
- इस वित्त वर्ष में एयर इंडिया 9,000 करोड़ के कर्ज का भुगतान करने पर काम कर रही है। इसके लिए कंपनी ने सरकार से मदद मांगी है।
- एयर इंडिया को ज्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट और विदेशी मुद्रा में घाटे के चलते भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है।
- एयर इंडिया तेल कंपनियों को ईंधन का बकाया नहीं दे पा रही है।

कर्मियों का बकाया भुगतान पहले : हरदीप पुरी

केंद्रीय मंत्री ने कहा ▶ 2018 के मुकाबले मौजूदा समय में काफी अलग हो चुकी है एयर इंडिया की स्थिति

एयर इंडिया असेट होल्डिंग कंपनी करेगी भुगतान

नई दिल्ली, आइएएनएस: नागरिक विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को कहा कि एयर इंडिया के प्रस्तावित विनिवेश से पहले कंपनी के कर्मचारियों का बकाया चुका दिया जाएगा। एरियर के साथ बकाया भुगतान प्रस्तावित एयर इंडिया असेट होल्डिंग कंपनी द्वारा किया जाएगा।

इससे पहले दो जनवरी को कंपनी के विभिन्न कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधियों ने मंत्री से मुलाकात कर निजीकरण की चिंताओं से अवगत कराया था। तब सरकार ने कहा था कि कर्ज में डूबी एयरलाइंस का निजीकरण उसके लिए मजबूरी बन गया है, क्योंकि कंपनी कर्ज के जाल में फंस चुकी है। पुरी ने कहा कि विनिवेश की वर्तमान प्रक्रिया वर्ष 2018 के मुकाबले गुणात्मक रूप से भिन्न है। इस बार हमारा दृष्टिकोण पूरी तरह स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि विमानन क्षेत्र न सिर्फ बेहद स्पर्धी है, बल्कि इसमें पूंजी की भी अत्यधिक जरूरत होती है। इस क्षेत्र में जो लोग विमान बनाते हैं वे लाभ कमाते हैं, जो एयरपोर्ट का रखरखाव करते हैं वह भी लाभ में रहते हैं, लेकिन जो लोग एयरलाइंस चलाते हैं, वह हमेशा घाटे में रहते हैं। इसे बदलने की जरूरत है।

हरदीप सिंह पुरी। फाइल

प्रतिष्ठित ब्रांड है एयर इंडिया

हरदीप पुरी ने एयर इंडिया और उसकी दो सहयोगी कंपनियों को अमूल्य संपत्ति बताते हुए कहा कि जो भी इसे खरीदेगा वह इस प्रतिष्ठित ब्रांड का उपयोग कर सकेगा। कंपनी की भूमि, भवन, पेंटिंग और कलाकृतियां लेनदेन का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पर स्थित कुछ ऑफिस और कॉरपोरेट कार्यालय का उपयोग सफल बोलीकर्ता कंपनी कुछ समय कर सकेगी। इस विनिवेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कहने वाले भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी के बयान पर पुरी ने कहा कि उनका बयान सरकार का दृष्टिकोण नहीं है। भाजपा एक लोकतांत्रिक पार्टी है और नेता अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र हैं।

खरीदारों को शुरुआती चरण में ही मिलेंगे कंपनी के रिकॉर्ड्स

नई दिल्ली, प्रेट्र : एयर इंडिया के संभावित खरीदारों को विनिवेश प्रक्रिया के शुरुआती चरण में ही कंपनी से जुड़े सभी दस्तावेज और शेयर खरीद समझौते के मसौदे तक पहुंच उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार के निविदा पत्र के अनुसार संभावित खरीदारों को इसके अलावा एयर इंडिया की खरीद के लिए प्रस्ताव पत्र भेजने के चरण से पहले कंपनी के लेखा-जोखा की विस्तृत शोध रपट भी उपलब्ध कराई जाएगी। आमतौर पर प्राथमिक सूचना ज्ञापन (पीआइएम) रखे जाने के बाद बोली लगाने वालों के रुचि दिखाने पर उन्हें सभी दस्तावेज और शेयर खरीद समझौते का मसौदा उपलब्ध कराया जाता है। एक अधिकारी ने बताया कि विस्तृत रपट बनाते वक्त कंपनी के विभिन्न समझौतों के विधिक और प्रौद्योगिकी पक्षों के लिए बहुत जल्द प्रौद्योगिकी और कानूनी सलाहकार की नियुक्ति करेगी। बोली लगाने वालों में जिन्हें कंपनी के दस्तावेजों और शेयर खरीद समझौते के मसौदे का अध्ययन करना है, उन्हें एक करोड़ रुपये जमा कराने होंगे।

कर्मचारियों को ईसॉप के तहत मिलेंगे शेयर

प्रथम पृष्ठ से आगे

विमानन मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक विनिवेश प्रक्रिया के अंतर्गत एयर इंडिया के कर्मचारियों को एंप्लाईज स्टॉक ऑप्शन प्रोग्राम (ईसॉप) के तहत एयर इंडिया के कुल शेयरों में से तीन फीसद शेयर प्रदान करने का प्रस्ताव है। इसके लिए लगभग 98 करोड़ शेयर अलग रखे जाएंगे।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव तुहिन कांत पांडेय ने कहा कि इस बार का प्रस्तावित विनिवेश मॉडल बहुत सोच-समझकर तैयार किया गया है। आठ अंतरराष्ट्रीय रोड शो के अनुभवों के आधार पर इसमें पिछली बार की गलतियों से सबक लिया गया है। पिछली बार केवल 76 फीसद विनिवेश का प्रस्ताव था। जबकि इस बार 100 प्रतिशत विनिवेश का फैसला किया गया है।

ऐसी है नई विनिवेश योजना

- एयर इंडिया व एयर इंडिया एक्सप्रेस में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी बिकेगी, सरकार प्रबंधन छोड़ेगी
- एआइसैट्स में भी कंपनी अपनी पूरी 50 प्रतिशत हिस्सेदारी बेच लेगी
- एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज, एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, एयर इंडिया अलाइड सर्विसेज तथा होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को एयर इंडिया असेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआइएएचएल) में हस्तांतरित किया जाएगा।
- कुल 56,334 करोड़ रुपये की देनदारियों में से संभावित खरीदार को सिर्फ 23,286 करोड़ रुपये का बोझ वहन करना होगा।
- शेष लगभग 33,048 करोड़ रुपये का कर्ज एआइएएचएल वहन करेगी, कर्मियों के करीब 1,384 करोड़ का भुगतान सरकार करेगी।
- विनिवेश योजना के तहत स्थायी कर्मचारियों को ईसॉप के तहत कंपनी के तीन प्रतिशत शेयर दिए जाएंगे।

बजट में होगी डिस्कॉम को सुधारने की एक और कोशिश

- बिजली क्षेत्र की सभी स्कीमों को एक स्कीम के तहत लाने की तैयारी
- उदय विफल नहीं लेकिन और बेहतर स्कीम की जरूरत : आरके सिंह

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

पिछले कार्यकाल में राजग सरकार की ओर से शुरू की गई उदय स्कीम के बाद भी राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की हालत बहुत नहीं सुधरी है। ऐसे में आगामी बजट में इन कंपनियों के लिए एक नई स्कीम लाने की तैयारी है। इस बारे में बिजली मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच कई दौर की बातचीत हुई है। बिजली मंत्री आरके सिंह ने उम्मीद जताई है कि आगामी बजट में इस नई स्कीम का एलान होगा। बिजली मंत्री वैसे उदय स्कीम को एक विफल योजना नहीं मानते हैं।

सोमवार को पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) की तरफ से 75 करोड़ डॉलर के अंतरराष्ट्रीय बांड निर्गम के सूचीबद्ध होने के अवसर पर बिजली मंत्री ने संकेत दिया कि सरकार बिजली क्षेत्र की विभिन्न स्कीमों को मिलाकर एक शीर्ष स्कीम बनाने पर विचार कर रही है। अभी उदय के साथ ही दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम अलग-अलग चलाई जा रही हैं। नई स्कीम के तहत डिस्कॉम को ट्रांसमिशन एवं वितरण (टीएंडडी) से होने वाली हानि को मौजूदा स्तर 19 फीसद से घटाकर अगले दो साल में 15 फीसद पर लाना होगा। उदय के तहत भी यही लक्ष्य था। कुछ राज्यों में इसमें प्रगति हुई है लेकिन कई राज्यों की प्रगति बहुत सुस्त है। बिजली मंत्रालय ने नई स्कीम का जो प्रस्ताव तैयार किया है वह राज्यों की बिजली कंपनियों पर कई तरह से अंकुश भी लगाएगा। इसमें यह प्रस्ताव किया जा रहा है कि जो राज्य विभिन्न लक्ष्यों को हासिल करेंगे उन्हें ही सरकारी फंड दिया जाएगा। जैसे-जैसे डिस्कॉम के नुकसान में कमी आएगी, वैसे-वैसे उन्हें केंद्र से मिलने वाली राशि की अदायगी होगी। बिजली सब्सिडी का वित्त पोषण राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होगी।

कार्यक्रम में पीएफसी के सीएमडी राजीव शर्मा ने कहा कि कंपनी के बांड निर्गम में जिस तरह से विदेशी निवेशकों ने रुचि दिखाई है वह उत्साहवर्द्धक है। कंपनी को चार गुना ज्यादा निवेश के प्रस्ताव आए। पीएफसी ने अपने एनपीए को घटाने में भी सफलता पाई है। कुछ महीनों में एनपीए में और कमी की उम्मीद है, क्योंकि तीन-चार लंबित मामलों पर जल्द फैसला आने वाला है।

अर्बन को-ऑपरेटिव बैंकों में 220 करोड़ की धोखाधड़ी

- आरटीआइ के जवाब में आरबीआइ ने दी जानकारी
- पिछले पांच वर्षों में इन बैंकों में धोखाधड़ी के आए करीब 1,000 मामले

नई दिल्ली, प्रेट्र: पिछले पांच वर्षों के दौरान अर्बन को-ऑपरेटिव बैंकों (यूसीबी) में 220 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं। सूचना का अधिकार (आरटीआइ) के तहत पूछे गए सवाल पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने यह जानकारी दी है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि पिछले पांच वर्षों के दौरान देशभर में अर्बन को-ऑपरेटिव बैंकों में धोखाधड़ी के लगभग 1,000 मामले सामने आए हैं। वर्तमान में देशभर में 1,544 अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक हैं और 31 मार्च, 2019 तक इसमें 4.84 लाख करोड़ रुपये जमा थे। अकेले महाराष्ट्र के 496 यूसीबी में सबसे अधिक तीन लाख करोड़ रुपये जमा हैं।

आरबीआइ के मुताबिक 2018-19 के दौरान 127.7 करोड़ रुपये के कुल 181 धोखाधड़ी मामले सामने आए। उससे पिछले वित्त वर्ष यानी 2017-18 में 46.9 करोड़ रुपये के कुल 99 मामले सामने आए थे। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान धोखाधड़ी के 27 मामले सामने आए थे, जिनके माध्यम से इन बैंकों को 9.3 करोड़ रुपये की चपत लगाई गई थी।

आरबीआइ के मुताबिक वित्त वर्ष 2015-16 में 17.3 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के 187 मामले दर्ज किए गए जबकि 2014-15 के दौरान 19.8 करोड़ रुपये के 478 ऐसे मामले दर्ज किए। आरबीआइ ने कहा कि बैंकों को धोखाधड़ी के मामलों को प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर आपराधिक शिकायतों के रूप में दर्ज कराना होता है। बैंक को कर्मचारियों की जवाबदेही तय करनी होती है और उन्हें आंतरिक कार्रवाई के माध्यम से दंडित भी किया जाता है। हालांकि अभी तक धोखाधड़ी के मामलों में कितने कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, इस बारे में आरबीआइ ने जानकारी उपलब्ध नहीं होने की बात कही है।

एलएनजी की कीमत कम करने पर भारत और कतर में नहीं बनी बात

- भारत चाहता है कि लंबी अवधि के पुराने करारों की समीक्षा करे कतर
- कतर ने कहा - अनुबंधों की समीक्षा करना कारोबार के लिहाज से सही नहीं

नई दिल्ली, प्रेट्र : मौजूदा करारों की समीक्षा करते हुए लिक्विफाइड नेचुरल गैस (एलएनजी) की कीमत करने के मसले पर भारत और कतर के बीच सहमति नहीं बन पाई है। भारत का कहना है कि ईंधन के मामले में वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए पुराने अनुबंधों की समीक्षा होनी चाहिए। वहीं कतर का तर्क है कि वह कम कीमत पर नए अनुबंध करने को तैयार है, लेकिन कारोबारी मूल्यों को ध्यान में रखते हुए पुराने अनुबंधों की समीक्षा नहीं होगी।

कतर भारत का सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकर्ता है। लंबी अवधि के दो पुराने अनुबंधों के तहत भारत सालाना 85 लाख टन एलएनजी का आयात कतर से करता है। इन अनुबंधों में गैस की कीमत को क्रूड की कीमत से लिंक किया गया है। मौजूदा दौर में इसकी कीमत नौ से 10 डॉलर (करीब 700 रुपये) प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट पड़ती है। वहीं अभी स्पॉट और करेंट मार्केट में इसकी कीमत आधी पड़ रही है। इस लिहाज से कतर के साथ किए गए अनुबंध भारत के लिए सबसे महंगे हैं। ऑस्ट्रेलिया, रूस और अमेरिका से किए गए अनुबंधों में काफी सस्ती कीमत पर गैस की आपूर्ति होती है।

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कतर के ऊर्जा मंत्री साद शेरिदा अल काबी से मुलाकात कर उनसे पुराने अनुबंधों की समीक्षा को कहा। उन्होंने कहा कि कीमत बाजार के मौजूदा हालात के अनुसार होनी चाहिए। इससे अंतिम उपभोक्ता को भी लाभ होगा। प्रधान ने कहा कि तेल की कीमतों के हिसाब से गैस की कीमतें तय करने से इस स्वच्छ ईंधन की कीमत ज्यादा हो जाती है। इससे इस दिशा में कई लक्ष्य हासिल करने में भी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। क्रूड से लिंक होने का मतलब है कि जब भी क्रूड महंगा होता है, गैस की कीमत बढ़ जाती है। अमेरिका और रूस से आने वाली गैस का क्रूड से कोई लिंक नहीं है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'सभी ईंधन उत्पादकों को इस पुरानी प्रक्रिया की समीक्षा करनी चाहिए और मांग व आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए कीमतें तय करने का नया तरीका निर्धारित करना चाहिए। हम चाहते हैं कि कतर भी लंबी अवधि के समझौतों में कीमतों की समीक्षा करे।'

कतर के ऊर्जा मंत्री साद शेरिदा अल काबी ने फिलहाल ऐसी किसी संभावना से इन्कार किया है। उन्होंने कहा, 'हम मौजूदा अनुबंधों की समीक्षा नहीं कर सकते। अनुबंधों पर एक तय समय के लिए हस्ताक्षर किया जाता है। एक कारोबारी के तौर पर हमारा मानना है कि दोनों पक्षों के लिए अनुबंध की अपनी महत्ता होती है। दोनों ही पक्षों को इसका सम्मान करना चाहिए। हम नई कीमत पर अतिरिक्त अनुबंध करने को तैयार हैं।' उन्होंने कहा कि भारत में गैस की बड़ी मांग है और कतर इसे पूरा करने का इच्छुक है।

प्रॉपर्टी और इक्विटी पर कैपिटल गेन टैक्स में मिल सकती है राहत

नई दिल्ली, आइएएनएस : आगामी बजट को अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिहाज से अहम माना जा रहा है। कई ऐसे सेक्टर जहां बीते दिनों मंदी की आहट दिखी है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उनके लिए बड़ी घोषणाएं कर सकती हैं। प्रॉपर्टी और इक्विटी भी ऐसे ही सेक्टर में शुमार हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, आगामी बजट में प्रॉपर्टी और इक्विटी बिक्री पर कैपिटल गेन टैक्स में राहत मिल सकती है।

उद्योग जगत काफी समय से लांग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (एलटीसीजी) में राहत की मांग कर रहा है। उम्मीद है कि इस बजट में प्रॉपर्टी की बिक्री पर इस टैक्स को खत्म किया जा सकता है। वहीं इक्विटी बिक्री के मामले में एलटीसीजी के लिए समयसीमा को एक साल से बढ़ाकर दो साल किए जाने की उम्मीद है। वर्तमान में यदि प्रॉपर्टी 24 महीने के भीतर बेची जाती है, तो उस व्यक्ति को अपनी आयकर स्लैब के अनुसार लाभ पर शॉट टर्म कैपिटल गेन (एसटीसीजी) टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। 24 महीने के बाद बिक्री पर एलटीसीजी टैक्स देना होता है, जो इंडेक्सेशन बेनिफिट्स के साथ 20 फीसद की दर से वसूला जाता है। अभी कुछ मामलों में इससे सशर्त छूट मिलती है। फिलहाल सरकार प्रॉपर्टी बिक्री से इस टैक्स को हटाने का कदम उठा सकती है। ऐसा हुआ तो सुस्त पड़े रियल एस्टेट सेक्टर को गति मिलेगी।

इसी तरह डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स (डीडीटी) के मामले में सरकार इसकी देनदारी को डिविडेंड जारी करने वाले या कंपनी से हटाकर डिविडेंड प्राप्त करने वाले पर कर सकती है।

हालात

सोमवार को इंट्रा-डे में सेंसेक्स करीब 500 अंक टूटा, पिछले चार महीने में यह सेंसेक्स की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट

कोरोना के खौफ में सेंसेक्स ने लगाया 458 अंकों का गोता

मुंबई, प्रेट्र : कोरोना वायरस के चलते कई देशों की अर्थव्यवस्था पर प्रत्यक्ष-परोक्ष असर पड़ने की आशंका के चलते सोमवार को दुनियाभर के प्रमुख बाजारों में हलचल देखी गई। ऐसी स्थिति में घरेलू शेयर बाजार को भी निवेशकों की चिंताओं का शिकार होना पड़ा बीएसई का 30-शेयरों वाला सेंसेक्स पिछले चार महीनों की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट का शिकार हुआ। इंट्रा-डे में करीब 500 अंक टूटने वाला सेंसेक्स कारोबार के आखिर में 458.07 अंकों यानी 1.10 प्रतिशत की गिरावट के साथ 41,155.12 अंक पर स्थिर हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50-शेयरों वाला प्रमुख सूचकांक निफ्टी भी सोमवार को 129.25 अंक यानी 1.06 प्रतिशत फिसलकर 12,119 पर बंद हुआ।

सेंसेक्स पैक में सोमवार को सबसे ज्यादा 4.31 प्रतिशत की गिरावट टाटा स्टील के शेयरों में दर्ज की गई। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ), इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक, पावरग्रिड और एचडीएफसी के शेयर भी टूट गए। हालांकि महिंद्रा एंड महिंद्रा (एमएंडएम), अल्ट्राटेक सीमेंट, टेक महिंद्रा, आइसीआइसीआइ बैंक और एक्सिस बैंक के शेयरों में 1.63 प्रतिशत का उछाल दर्ज किया गया। सेंसेक्स के 30 में से 21 स्टॉक्स लाल निशान पर और नौ हरे निशान पर बंद हुए। सेक्टोरल इंडेक्स के मामले में बीएसई मेटल 3.25 प्रतिशत टूट गया। टेलीकॉम, पावर, फाइनेंस, बैंकेक्स व एफएमसीजी इंडेक्स में भी गिरावट दर्ज की गई। बीएसई मिडकैप 0.40 प्रतिशत टूट गया। हालांकि बीएसई स्मॉलकैप थोड़ा चढ़कर बंद हुआ।

वायरस के डर से दुनियाभर के बाजारों में अफरातफरी का माहौल। प्रतीकात्मक फोटो

जानकारों का कहना था कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप से इकोनॉमी पर इसके संभावित असर को देखते हुए दुनियाभर के शेयर बाजारों में अफरातफरी दिखी। चीन में इस वायरस से 80 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 2,700 से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हैं। अब तक यह वायरस दर्जनभर से ज्यादा देशों में फैल चुका है। दिन के कारोबार के बारे में एलकेपी सिक्युरिटीज के रिसर्च प्रमुख एस. रंगनाथन ने कहा कि कोरोना वायरस के फैसले से दुनियाभर के शेयर बाजार सतर्क हो गए हैं। फाइनेंशियल और मेटल स्टॉक्स पर इसकी सबसे ज्यादा मार दिखी, क्योंकि निवेशकों को अंदेशा है कि अभी कुछ समय तक खदानों की गतिविधियां प्रभावित रह सकती हैं। हालांकि फार्मास्युटिकल्स सेक्टर के कुछ शेयरों में मजबूती दिखी है।

इनमें गहमागहमी

महिंद्रा लाइफस्पेस : चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में कमजोर कमाई के चलते इस कंपनी के शेयर सोमवार को बीएसई में 3.04 प्रतिशत और एनएसई में 3.51 प्रतिशत टूट गए। महिंद्रा लाइफस्पेस डेवलपर्स लिमिटेड ने इससे पहले बताया था कि चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर, 2019) में उसका शुद्ध मुनाफा 91 प्रतिशत गिरकर 1.81 करोड़ रुपये रह गया।

बीओबी : सरकारी क्षेत्र के अग्रणी कर्जदाता बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) के शेयरों में सोमवार को तीन प्रतिशत से अधिक गिरावट आई। इसकी मुख्य वजह यह रही कि चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में कंपनी को 1,407 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ है। बीएसई में सोमवार को कंपनी के शेयर 3.40 प्रतिशत और एनएसई में 3.13 प्रतिशत टूट गए। बीएसई में कंपनी के 14.50 लाख शेयरों की खरीद-फरोख्त हुई।

आइसीआइसीआइ बैंक : चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के बेहतरीन प्रदर्शन का फायदा सोमवार को बैंक के शेयरों पर दिखा। बीएसई में बैंक के शेयर 0.45 प्रतिशत और एनएसई पर 0.38 प्रतिशत उछले। बीएसई पर बैंक के 20.98 लाख शेयरों की खरीद-फरोख्त हुई। बीती तिमाही में बैंक का शुद्ध लाभ करीब डेढ़ गुना बढ़कर 4,670 करोड़ पर जा पहुंचा।

हर साल एक नई कार लांच करेगी निसान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : जापान की कार कंपनी निसान ने भारतीय बाजार में हर वर्ष एक नई कार लांच करने की योजना बनाई है। इसकी शुरुआत इसी वर्ष एक कंपैक्ट एसयूवी से होगी। कंपनी मानती है कि उसकी नई रणनीति अगले चार से पांच वर्षों में असर दिखाएगी। कंपनी हर वर्ग में उत्पाद लांच करेगी और सारे मॉडल सिर्फ निसान ब्रांड के तहत उतारे जाएंगे। कंपनी अभी तक दात्सुन ब्रांड के तहत भी वाहन लांच करती रही है। कंपनी के एमडी राकेश श्रीवास्तव ने बताया कि अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में ही कंपनी की नई एसयूवी लांच कर दी जाएगी। कंपनी का दावा है कि इस कार की माइलेज 31.59 किलोमीटर की है।

मारुति सुजुकी की कारें होंगी महंगी : कच्चे माल की बढ़ी लागत का हवाला देते हुए मारुति सुजुकी ने दिल्ली में अपने वाहनों की कीमतों में 4.7 फीसद तक का इजाफा किया गया है। यह वृद्धि 27 जनवरी से ही लागू हो गई है। कंपनी ने ऑल्टो का सीएनजी वर्जन बीएस-6 मानकों के साथ लांच करने का भी एलान किया है।

30 की मौत हो गई है दक्षिणपूर्वी ब्राजील में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ और भूस्खलन से। जबकि 17 लोग लापता बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव कार्य में जुटी टीम के मुताबिक, मिनास गैरेस राज्य में भारी बारिश के बाद साढ़े तीन हजार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।

न्यूज गैलरी

अमेरिका में लापता भारतवंशी छात्रा का शव झील में मिला

वाशिंगटन : अमेरिका में 21 जनवरी से लापता भारतवंशी छात्रा का शव इंडियाना प्रांत की एक झील में मिला है। स्थानीय मीडिया के अनुसार, केरल के एर्नाकुलम में जन्मी 21 वर्षीय एनरोज जेरी नोट्रे डेम यूनिवर्सिटी से स्नातक कर रही थीं। करीब 20 साल पहले उनका परिवार अमेरिका जाकर बस गया था। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार को सेंट मैरी झील से एनरोज के शव को बाहर निकाला गया। शरीर पर किसी प्रकार की चोट के निशान नहीं थे। एनरोज के परिवार से जुड़े लोगों के मुताबिक जब झील से शव निकाला गया तो एनरोज का मोबाइल फोन और ईयरबड्स जस के तस थे। उन लोगों ने आशंका जताई है कि टहलते या जॉगिंग करते समय वह गलती से झील में गिर गई होगी। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद वह डेंटल स्कूल में प्रवेश लेने की तैयारी कर रही थी। एनरोज के पिता जेरी जेम्स एक आइटी कंपनी में काम करते हैं जबकि उनकी मां रेनी डेंटिस्ट हैं। विश्वविद्यालय ने एनरोज के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। (आइएएनएस)

केक खाने की प्रतियोगिता में ऑस्ट्रेलियाई महिला की मौत

कैनबरा : ऑस्ट्रेलिया में रविवार को खान-पान की एक प्रतियोगिता के दौरान केक खाते वक्त बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। ऑस्ट्रेलिया दिवस के उपलक्ष्य में क्वींसलैंड के तटीय शहर हार्वी वे के एक होटल में केक खाने की प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। स्पंज केक खाते वक्त 60 वर्षीय महिला की सांस उस वक्त अटक गई, जब उन्होंने पुरस्कार जीतने के चक्कर में एक बड़ा टुकड़ा निगलने की कोशिश की। गले में केक फंसते ही महिला को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और उनकी तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल पहुंचने से पहले ही महिला ने दम तोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया दिवस के मौके पर हर साल देशभर में कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। खान-पान की प्रतियोगिताओं में निश्चित समय में ज्यादा से ज्यादा केक, पाई, हॉट डॉग या अन्य खाद्य पदार्थ खाने वालों को पुरस्कृत किया जाता है। यह दिवस यूरोपीय लोगों के ऑस्ट्रेलिया आगमन की खुशी में मनाया जाता है। (एएफपी)

स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री ने की इस्तीफे की घोषणा

लुबलियाना : स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री मरियन सारेज ने सोमवार को घोषणा की कि वह इस्तीफा दे रहे हैं। इस दौरान उन्होंने ताजा चुनाव कराए जाने की बात भी कही। इससे पहले उनके वित्त मंत्री ने भी इस्तीफ दे दिया था। सारेज ने पत्रकारों से कहा, 'संसद के सदस्यों और इस गठबंधन के साथ मैं लोगों की उम्मीदों को पूरा नहीं कर सकता हूं।' उन्होंने कहा कि इस स्थिति में सबसे ईमानदार चीज ताजा चुनाव ही हो सकता है। (एएफपी)

कोरोना वायरस के प्रकोप से चीन में और बिगड़े हालात

महामारी ▶ बढ़ाई गईं नए साल की छुट्टियां, कंपनियों ने बंद किए दफ्तर

हालात बिगड़ते देख वुहान पहुंचे चीनी पीएम ली कछ्यांग

बीजिंग, एजेंसियां : चीन में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। वायरस के प्रसार पर अंकुश लगाने के प्रयास में सरकार ने नए साल (लूनर ईयर) की छुट्टियां दो फरवरी तक बढ़ा दी हैं। कई बड़ी कंपनियों ने अपने दफ्तर बंद कर दिए या स्टाफ को घर से ही काम करने को कह दिया है। वायरस की चपेट में आकर जान गंवाने वालों की संख्या सोमवार को बढ़कर 81 हो गई। जबकि संक्रमित लोगों का आंकड़ा 2700 के पार पहुंच गया है। हालात बिगड़ते देख प्रधानमंत्री ली कछ्यांग सोमवार को यह संदेश देने के लिए महामारी का केंद्र बताए जा रहे वुहान शहर पहुंचे कि सरकार मामले से गंभीरता से निपट रही है। मास्क और सुरक्षात्मक सूट पहने कछ्यांग ने वायरस के प्रकोप से निपटने के उपायों का जायजा लिया।

स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, रहस्यमय कोरोना वायरस के संक्रमण के करीब आधे मामले मध्य चीन के हुबेई प्रांत में सामने आए हैं। इसी प्रांत की राजधानी वुहान से संक्रमण की शुरुआत हुई थी। अकेले हुबेई में 76 मौतें हुई हैं। उन्होंने आगाह किया कि वायरस के चलते संक्रमण बढ़ता जा रहा है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि संक्रमित लोगों की संख्या सरकार द्वारा बताए जा रहे आंकड़े से ज्यादा हो सकती है। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए एक कराड़ से ज्यादा आबादी वाले वुहान समेत लगभग पूरे प्रांत में आवाजाही रोक दी गई है। चीन नियंत्रित हांगकांग में भी आठ मामले पाए गए हैं। हांगकांग ने हुबेई से लोगों के आने पर 14 दिन के लिए रोक लगा दी है। मकाउ ने भी इसी तरह का प्रतिबंध लगा दिया है।

न्यूमोनिया का बन सकता है कारण : कोरोना वायरस का अभी कोई ज्ञात उपचार नहीं है। सांस संबंधी दूसरी बीमारियों की तरह ही बुखार, खांसी और सांस लेने में दिक्कत इस संक्रमण के लक्षण हैं। यह न्यूमोनिया का कारण भी बन सकता है।

वुहान से ही दुनिया में फैल रहा वायरस : कोरोना वायरस वुहान से दुनिया के कई देशों में पहुंच चुका है। इस शहर की यात्रा से अपने देशों में पहुंचने वाले कई लोगों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। यह वायरस थाइलैंड, फ्रांस, जापान, अमेरिका, ताइवान, नेपाल, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, पाक और ब्रिटेन में दस्तक दे चुका है। चीन के अलावा अभी किसी देश में इस वायरस से मौत की खबर नहीं है।

कई देश अपने नागरिकों को निकालने में जुटे : अमेरिका समेत कई देश वुहान में फंसे अपने नागरिकों को निकालने में जुट गए हैं। शहर से ऑस्ट्रेलिया के करीब 100 बच्चों और वयस्कों को निकालने की तैयारी चल रही है।

चीन में सोमवार को 'कोरोना' से पीड़ित मरीज को अस्पताल ले जाता मेडिकल स्टाफ। एएफपी

चीन ने खोला खजाने का मुंह

चीन ने वायरस के प्रकोप पर अंकुश लगाने के लिए खजाने का मुंह खोल दिया है। वित्त मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार, वायरस से निपटने के लिए 60.33 अरब युआन (करीब 62 हजार करोड़ रुपये) आवंटित किए गए हैं।

वुहान में फंसे भारतीयों को निकालने की तैयारी

नई दिल्ली, एजेंसियां : नोवेल कोरोना वायरस से प्रभावित चीन के हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान में फंसे भारतीयों को निकालने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए एयर इंडिया का एक विमान तैयार रखा गया है।

एयर इंडिया के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया, 'कोरोना वायरस की आशंका के कारण वुहान से भारतीयों को निकालने के लिए एयर इंडिया का बोइंग-747 तैयार रखा गया है। एयर इंडिया इस संबंध में सरकार के फैसले का इंतजार कर रही है।' इस सिलसिले में सोमवार को कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें इस दिशा में कदम उठाने का फैसला लिया गया। इसके लिए भारतीय विदेश मंत्रालय चीनी अधिकारियों से अनुरोध करेगा। वुहान में फंसे भारतीयों में गुजरात के जूनागढ़, जामनगर, वडोदरा, गोधरा, अहमदाबाद, सूरत सहित देश के विभिन्न शहरों के 300 से अधिक मेडिकल छात्र भी हैं। अभिभावकों का कहना है कि उन्हें यूनिवर्सिटी के बाहर भी नहीं निकलने दिया जा रहा है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने केंद्र से अपने-अपने राज्यों के छात्रों को वापस लाने के कदम उठाने का आग्रह किया है।

देश में कोरोना वायरस को कोई मरीज नहीं : 27 जनवरी, 2020 तक देश में 155 उड़ानों के जरिये चीन से आए 33,552 यात्रियों में नोवेल कोरोना वायरस के लक्षणों की जांच की गई है। अभी तक देश में कोई भी व्यक्ति इस वायरस से संक्रमित नहीं मिला है। सोमवार को चीन से आए 4,359 यात्री की जांच की गई।

▶ एयर इंडिया का बोइंग-747 तैयार, सरकार से हरी झंडी का इंतजार

चीन से लौटी छात्रा को सोमवार को पटना मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। एएनआइ

450 से ज्यादा लोग निगरानी में : कोरोना वायरस से संक्रमण की आशंका में करीब 450 लोगों को निगरानी में रखा गया है इनमें से अधिकांश केरल में हैं। इस बीच, पिछले कुछ हफ्तों में चीन से लौटे कुछ लोगों ने एहतियातन चिकित्सा अधिकारियों से संपर्क किया है।

चीनी पर्यटक कोलकाता के अस्पताल में भर्ती : पर्यटक वीजा पर भारत आई एक चीनी नागरिक को हलके बुखार और पेट में दर्द की शिकायत पर कोलकाता के बेलाघाट आइडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें एक अलग वार्ड में रखा गया है। राज्य में स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव विवेक कुमार ने बताया कि वह कुछ समय से यात्रा कर रही हैं और कुछ महीने पहले मेडागास्कर से भारत आईं थीं। उनकी मेडिकल रिपोर्ट अभी नहीं आई है।

पटना के अस्पताल में महिला भर्ती : पिछले हफ्ते चीन से लौटी एक महिला को सोमवार को पटना के अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह महिला 22 जनवरी को चीन से अपने घर छपरा लौटी थीं।

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने की तैयारियों की समीक्षा

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने सोमवार को नेपाल से लगते पांच राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और सिक्किम के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये एक बैठक की और कोरोना वायरस की रोकथाम व उससे निपटने के उपायों की समीक्षा की। प्रमुख सचिव (स्वास्थ्य) ने अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ इसी तरह की बैठक की।

एम्स और आरएमएल में अलग वार्ड

राजधानी दिल्ली में केंद्र सरकार के एम्स और राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल में कोरोना वायरस के संभावित पीड़ितों के इलाज के लिए अलग वार्ड बनाए गए हैं। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) के विशेषज्ञों ने सोमवार को आरएमएल में इस वार्ड का निरीक्षण किया और तैयारियों को परखा।

मध्य-पूर्व को लेकर ट्रंप आज घोषित करेंगे शांति योजना

वाशिंगटन, रायटर : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल और फलस्तीन से संबंधित अपना मध्य-पूर्व शांति योजना तैयार कर ली है, मंगलवार को वह इसे सार्वजनिक करेंगे। ट्रंप की घोषणा के मौके पर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और वहां के विपक्ष के नेता बेनी गेंट्ज मौजूद रहेंगे। फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने दुनिया के शक्तिशाली देशों से ट्रंप की पहल को खारिज करने की अपील की है। अब्बास को आशंका है कि शांति योजना के नाम पर ट्रंप इजरायल को फलस्तीनी इलाकों पर कब्जे के और अधिकार दे देंगे जिससे स्वतंत्र फलस्तीन की स्थापना का सपना बहुत दूर हो जाएगा।

सोमवार को इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ अपने ओवल ऑफिस में बैठे ट्रंप ने कहा, उनकी योजना सभी लोगों के लिए अच्छी होगी और उससे संभावनाओं ने नए द्वार खुलेंगे। ट्रंप ने योजना से फलस्तीनियों को होने वाले फायदे के बारे में बताने से इन्कार कर दिया लेकिन कहा कि इसमें वह भी होगा, जो वे (फलस्तीनी) चाहते हैं।

▶ आशंकित महमूद अब्बास की विश्व समुदाय से खारिज करने की अपील

फलस्तीनी नेताओं ने ट्रंप प्रशासन से शांति योजना के बारे में बात करने से इन्कार कर दिया है। उन्हें अमेरिकी दूतावास यरुशलम स्थानांतरित करने के ट्रंप के फैसले से घोर आपत्ति है। इसलिए अब वे ट्रंप की शांति योजना से भी सशंकित हैं। फलस्तीनियों को आशंका है कि शांति योजना से स्वतंत्र फलस्तीन राष्ट्र बनने का सपना और दूर हो जाएगा।

आइएस की अब इजरायल पर हमले की धमकी

बेरूत, एएफपी : आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (आइएस) अब इजरायल की ओर रुख करेगा और उस पर हमलों को अंजाम देगा। आइएस की ओर से उसके प्रवक्ता ने ऑडियो मैसेज जारी कर यह बात कही है। अबू हमजा अल-कुरैशी ने कहा है- आइएस नेता अबू इब्राहीम अल-हाशिमी अल-कुरैशी ने लड़ाकों को अब नया मोर्चा खोलने के लिए कहा है।

37 मिनट के टेप में प्रवक्ता ने कहा है कि खिलाफत के सिपाहियों की आंखों में यरुशलम पर कब्जे का सपना है। अल्लाह ने चाहा तो जल्द ही हम वह सपना साकार करने में कामयाब होंगे। इसके लिए इतनी भीषण लड़ाई लड़ी जाएगी कि लोग अभी तक हुए युद्धों की बर्बादी को भूल जाएंगे। खुफिया सूत्रों ने इस संदेश की विश्वसनीयता को लेकर भी शक जताया है। वैसे अमेरिका के नेतृत्व में लड़ी गई लड़ाई में आइएस लड़ाकों के पैर उखड़ चुके हैं।

ईरान में रनवे से मुख्य मार्ग पर पहुंचा विमान

दक्षिण-पश्चिम ईरान के माहशहर में सोमवार को एयरपोर्ट पर उतरते वक्त विमान रनवे से फिसलता हुआ पास के राजमार्ग पर जा पहुंचा। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नही हुआ, परंतु अचानक सड़क पर विमान पहुंचने से अफरा-तफरी का आलम जरूर रहा। विमानन प्राधिकरण के प्रमुख के अनुसार, लैंडिंग गीयर में खराबी आने की वजह से यह हादसा हुआ। उस वक्त विमान में 150 यात्री सवार थे। कैस्पियन एयरलाइन्स के मैकडॉनल्ड डगलस के इस विमान ने तेहरान के मेहराबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। एपी

'ईरान की जनता को भड़का रहे हैं ट्रंप'

दुबई, रायटर : ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने देश की जनता से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने वाले प्रयासों को सफल नहीं होने देने की अपील की है। संसदीय चुनावों से पहले की गई इस अपील के साथ ही वह प्रत्याशियों को अयोग्य ठहराए जाने के मुद्दे को लेकर कट्टरपंथियों पर भी बरसे। अमेरिका द्वारा लगाए गए कड़े प्रतिबंधों के कारण ईरान को अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। परमाणु करार से अमेरिका के बाहर निकलने के बाद ईरान के तेल निर्यात पर भी अंकुश लगाया गया है।

आधिकारिक वेबसाइट पर लाइव प्रसारण के दौरान रूहानी ने कहा, 'हमें ट्रंप को किसी भी कीमत पर जनता और सरकार के बीच दूरियां पैदा करने में सफल नहीं होने देना है। हमें हरहाल में एकजुट रहना होगा। 21 फरवरी को होने वाले संसदीय चुनावों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें। हमें ट्रंप और व्हाइट हाउस में बैठे आतंकियों को ईरान को अलग-थलग करने के प्रयासों को कामयाब नहीं होने देना है।' ईरान की कट्टरपंथी गार्डियन काउंसिल ने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। उदारवादियों से संबंध रखने वाले 14 हजार में से करीब नौ हजार प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया गया है। उदारवादियों का कहना है कि ज्यादातर शहरों में उनके पास कोई उम्मीदवार ही नहीं है।

▶ राष्ट्रपति ने जनता से की ट्रंप के प्रयासों को विफल करने की अपील

▶ कहा- हरहाल में रहें एकजुट संसदीय चुनावों में बढ़-चढ़कर लें हिस्सा

ईरान के राष्ट्रपति हसन रुहानी। फाइल

सरकार से शिकायतों के बावजूद वोट डालिए: ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा, यह संसदीय चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराए जाने के मुद्दे पर संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखा है। कट्टरपंथियों का दावा है कि चुनाव में जीत उन्हीं की होगी। अगर वह चुनाव जीतते हैं तो इससे किसी को कोई एतराज नहीं, लेकिन चुनाव को प्रतिस्पर्धी होने से नहीं रोका जाना चाहिए। सभी नागरिकों से अपील है कि उन्हें सरकार से कई शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद वह मतदान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें।

विमान हादसे के बाद और बिगड़े हालात : वर्ष 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद से मुल्क की सत्ता पर कट्टरपंथियों की पकड़ रही है। लेकिन पिछले साल आम जनता और शासकों के बीच उस समय दूरियां बढ़ गईं जब सरकार विरोधी प्रदर्शनों में सैकड़ों युवाओं को मौत के घाट उतार दिया गया। यूक्रेनी विमान को मार गिराए जाने की घटना ने इस आग में घी का काम किया।

फरवरी से वैज्ञानिकों को फास्ट ट्रैक वीजा देगा ब्रिटेन

लंदन, आइएएनएस : ब्रिटेन अगले माह से वैज्ञानिकों, गणितज्ञों और शोधकर्ताओं के लिए फास्ट ट्रैक वीजा प्रणाली की शुरुआत करने जा रहा है। दुनियाभर से प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित करने वाली इस पहल की घोषणा पीएम बोरिस जॉनसन ने की।

बीबीसी के मुताबिक, 20 फरवरी से शुरू होने वाली ग्लोबल टैलेंट वीजा प्रणाली के तहत ऐसे सभी लोग आवेदन कर सकेंगे जो विशेषज्ञता वाले क्षेत्र में काम करते हैं और जिन्हें सरकारी ब्रिटिश संस्था अनुमोदन करेगी। सरकार के अनुसंधान कार्यों को धन मुहैया कराने वाली यूके रिसर्च एंड इनोवेशन एजेंसी (यूकेआरआइ) इस नई वीजा प्रणाली का प्रबंधन करेगी।

रविवार को इसकी घोषणा करते हुए जॉनसन ने कहा, 'वैज्ञानिक खोजों में ब्रिटेन का गौरवशाली इतिहास रहा है। लेकिन भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए प्रतिभाशाली लोगों और नए तरह के अनुसंधान पर निवेश करना होगा। इन्हीं कारणों के चलते हम यूरोपीय यूनियन से अलग हो रहे हैं।'

पाकिस्तान में मंदिर पर हमला मूर्तियां तोड़ीं, मामला दर्ज

कराची, एजेंसियां : पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और उनके धार्मिक स्थलों पर हमलों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। गुरुद्वारा ननकाना साहिब पर पथराव का जख्म अभी भरा नहीं था कि सिंध प्रांत स्थित एक गांव के मंदिर पर शनिवार की रात कुछ अज्ञात लोगों ने हमला बोल दिया। मंदिर को नुकसान पहुंचाने और मूर्तियों को क्षतिग्रस्त करने के बाद आरोपित फरार हो गए। पुलिस ने चार अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, थार के छाचरो शहर स्थित माता देवल भिटानी मंदिर में शनिवार को तड़के चार लोगों ने तोड़फोड़ की। एक्सप्रेस ट्रीब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपितों ने मूर्तियां तोड़ दीं और पवित्र ग्रंथ को आग के हवाले कर दिया। स्थानीय निवासी प्रेम कुमार की तरफ से दर्ज कराई गई एफआइआर के मुताबिक मूर्तियों के हाथ तोड़ दिए गए थे और उनके चेहरे पर पेंट पोत दिया गया था।

छाचरो थाना प्रभारी हुसैन बक्स राजर ने बताया कि पुलिस आरोपितों की तलाश कर रही है। चार आरोपितों के पदचिह्न पाए गए हैं। इस इलाके में किसी मंदिर पर हमले का यह पहला मामला है। मीरपुरखास के डीआइजी ने मीडिया को बताया कि इलाके में शांति व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मुख्यमंत्री के विशेष सहयोगी (मानवाधिकार मामले) व वकील वीरजी कोल्ही ने कहा कि शरारती तत्व प्रदेश की शांति और सौहार्द को भंग करना चाहते हैं।

▶ सिंध प्रांत में स्थित है माता देवल भिटानी मंदिर, गुरुद्वारा ननकाना साहिब पर भी हो चुका है हमला

पाकिस्तान में हिंदू सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है। सरकार का मानना है कि वहां 75 लाख हिंदू रहते हैं, जबकि समुदाय के लोगों का कहना है कि उनकी आबादी 90 लाख से ज्यादा है। ज्यादातर हिंदू आबादी सिंध प्रांत में रहती है। उल्लेखनीय है कि पकिस्तान में स्थित सिखों के पवित्र तीर्थस्थल गुरुद्वारा ननकाना साहिब पर भीड़ ने हमला बोल दिया था।

पाक सेना की आलोचना पर पश्तून नेता गिरफ्तार

पेशावर, प्रेट्र : पाकिस्तान की सेना के दमनात्मक रवैये के खिलाफ आवाज उठाने वाले पश्तून नेता मंजूर पश्तीन (27) को सोमवार को पेशावर में गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान के अल्पसंख्यक पश्तून समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ने वाली संस्था पश्तून तहाफुज मूवमेंट (पीटीएम) के प्रमुख मंजूर पर पुलिस ने देशद्रोह का मामला दर्ज किया है। युवा नेता पर गत 18 जनवरी को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान शहर में सभा आयोजित कर देश के संविधान का अपमान करने का आरोप है।

मंजर पर देशद्रोह के अलावा धमकी देने, दुश्मनी फैलाने, आपराधिक षड्यंत्र रचने और देश की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने का मामला भी दर्ज किया गया है। मंजूर के साथ पुलिस ने पीटीएम के नौ अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार किया है। देश के उत्तर पश्चिमी इलाके में रहने वाले पश्तूनों पर सेना की कठोर कार्रवाई सवालों के घेरे में रही है। पीटीएम ने इसका विरोध करती रही है। गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मंजूर को तुरंत रिहा करने की मांग की है।

बड़ा मामला

बोल्टन का दावा बिडेन के खिलाफ जांच तक अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेन की सुरक्षा सहायता रोकने की कही थी बात

ट्रंप की मुश्किल बढ़ाएगा पूर्व एनएसए बोल्टन का रहस्योद्घाटन

न्यूयॉर्क टाइम्स से

वाशिंगटन : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त, 2019 में तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) जॉन बोल्टन से कहा था कि वह चाहते हैं कि यूक्रेन को दी जाने वाली 39.1 करोड़ डॉलर (करीब 2800 करोड़ रुपये) की सुरक्षा सहायता तब तक रोक दी जाए, जब तक कि उसके अधिकारी जो बिडेन समेत डेमोक्रेट्स नेताओं की जांच में मदद नहीं करते। बोल्टन ने यह सनसनीखेज दावा अपनी एक किताब में किया है। यह किताब अभी प्रकाशित नहीं हुई है, लेकिन उनके इस रहस्योद्घाटन से महाभियोग का सामना कर रहे ट्रंप की मुसीबत बढ़ सकती है। ट्रंप ने बोल्टन को पिछले साल सितंबर में एनएसए पद से बर्खास्त कर दिया था।

ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने पिछले साल 25 जुलाई को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से फोन पर बात के दौरान राष्ट्रपति चुनाव में अपने संभावित डेमोक्रेट प्रतिद्वंद्वी बिडेन के खिलाफ जांच शुरू करने का दबाव बनाया था। इसी मामले को लेकर इस समय अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सीनेट में ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की सुनवाई चल रही है। अमेरिका के इतिहास में ट्रंप ऐसे तीसरे राष्ट्रपति बन गए हैं, जिन पर महाभियोग चलाया जा रहा है। बोल्टन के इस दावे से ट्रंप की कई दलीलें कमजोर पड़ सकती हैं। महाभियोग सुनवाई में उनकी ओर से यह दलील दी गई है कि सुरक्षा सहायता रोकने और जांच के लिए मदद का आग्रह करने में कोई संबंध नहीं है। इस अप्रकाशित किताब की प्रतियां ह्वाइट हाउस और ट्रंप के सहयोगियों के पास भी भेजी गई थीं। इस पर ह्वाइट हाउस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

बोल्टन ने जताई है गवाही की इच्छा : 71 वर्षीय बोल्टन ने इस माह के प्रारंभ में यह इच्छा जताई थी कि वह सीनेट में होने वाली महाभियोग की सुनवाई में गवाही देना चाहते हैं। उनके इस बयान के बाद से ही विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद नए गवाहों को शामिल करने की मांग कर रहे हैं। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के ज्यादातर सांसद चुप्पी साधे हुए हैं। सीनेट में ट्रंप की पार्टी बहुमत में है। जबकि ट्रंप ने पिछले हफ्ते पत्रकारों से कहा था कि वह नहीं चाहते कि बोल्टन की गवाही हो। अगर वह सार्वजनिक तौर पर कुछ बोलते हैं तो वह राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

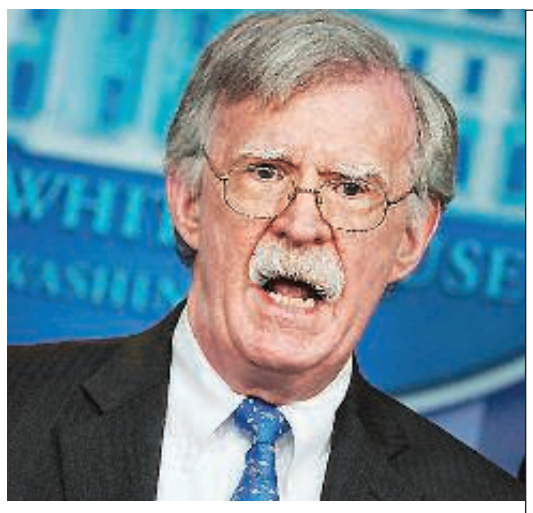

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सलाहकार जॉन बोल्टन। फाइल/एएफपी

ट्रंप ने बोल्टन के दावे को किया खारिज

समाचार एजेंसी एपी के अनुसार, ट्रंप ने बोल्टन के दावे को खारिज किया है। उन्होंने सोमवार को ट्वीट के जरिये कहा, 'मैंने जॉन बोल्टन से यह कभी नहीं कहा था कि यूक्रेन की सहायता को जांच से जोड़ा जाए। अगर वह ऐसा कह रहे हैं तो सिर्फ किताब बेचने के लिए बोल रहे हैं।'

पाकिस्तान में अमेरिकी दूतावास की कार से टक्कर में एक की मौत

इस्लामाबाद, प्रेट्र : पाकिस्तान में अमेरिकी दूतावास की एक कार ने दूसरी कार में टक्कर मार दी। इस हादसे में कार सवार एक महिला की मौत हो गई और उसके परिवार के पांच सदस्य घायल हो गए। पाकिस्तान में अमेरिकी दूतावास के वाहनों से पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। जिसको लेकर दोनों देशों में कूटनीतिक तनातनी देखने को मिली थी।

एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार के अनुसार, यह दुर्घटना रविवार को इस्लामाबाद की मार्गला सड़क पर हुई। अमेरिकी दूतावास की टोयोटा लैंड क्रूजर ने सुजुकी खैबर कार में पीछे से टक्कर मार दी। कार सवार नादिया नामक महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घायलों को पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है।

पुलिस ने कहा, शुरुआती जांच के बाद ऐसा लगता है कि दुर्घटना में शामिल कारों में से एक ने रेड लाइट जंप की थी। दूतावास की कार के पाकिस्तानी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है।

▶ पाकिस्तानी ड्राइवर गिरफ्तार, कार सवार पांच अन्य घायल

▶ दोनों देशों में फिर देखने को मिल सकती है कूटनीतिक तनातनी

पहले भी हुए हैं कई हादसे : फरवरी, 2013 में अमेरिकी दूतावास की एसयूवी कार ने एक बाइक में टक्कर मार दी थी। इसमें बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और दूसरा घायल हो गया था। यह कार दूतावास का एक प्रशासनिक अधिकारी चला रहा था। इसी तरह का एक हादसा अप्रैल, 2018 में हुआ था। तब अमेरिकी दूतावास की कार ने मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी थी। इस हादसे में बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई थी। कार चला रहे अमेरिकी राजनयिक को हिरासत में ले लिया गया था।

मुझे लगता है कि हमारी टीम के प्रदर्शन में सुधार हुआ है और टीम की ताकत पेनाल्टी कॉर्नर पर गोल करने की है।
— मनप्रीत सिंह, हॉकी खिलाड़ी, भारत

बलवंत ने गोलकर एटीके को शीर्ष पर पहुंचाया

कोलकाता : आखिरी पांच मिनट के खेल के लिए मैदान पर उतरे स्थानापन्न खिलाड़ी बलवंत सिंह के गोल की मदद से दो बार की चैंपियन एटीके ने इंडियन सुपर लीग (आइएसएल) के मुकाबले में नॉर्थईस्ट युनाइटेड एफसी को 1-0 से हराया। दोनों टीमों ने निर्धारित 90 मिनट तक प्रयास किए लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली लेकिन 90+4 मिनट में बलवंत ने हेडर से गोलकर टीम की जीत पक्की कर दी।

तेरा जाना...

अमेरिकी बास्केटबॉल दिग्गज कोबे ब्रायंट और उनकी बेटी गियाना की मौत से दुनिया सन्न

ऑस्ट्रेलियन ओपन में नडाल के खिलाफ ब्रायंट की आठ नंबर जर्सी पहनकर उतरे निक किर्गियोस

गियाना के अलावा कोबे की तीन और बेटियां नतालिया (17), बियांका (3) और कैपरी (छह महीने) हैं

कोबे ब्रायंट 1978-2020

लास एंजिलिस, एएफपी: द ब्लैक मांबा के नाम से पहचाने जाने वाले अमेरिका की नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन (एनबीए) लीग के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी कोबे ब्रायंट और उनकी 13 वर्षीय बेटी गियाना सहित नौ लोगों की मौत से पूरा विश्व शोकग्रस्त है। दुनियाभर में अगर बास्केटबॉल के कुल पांच महानतम खिलाड़ियों का नाम लिया जाए तो उसमे कोबे का नाम प्रमुख है। कोबे की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनकी मृत्यु के बाद ट्विटर से लेकर फेसबुक के टॉप ट्रेंड्स में यह दुर्घटना थी। ब्रायंट अपने 20 साल लंबे करियर में हमेशा लास एंजिलिस लेकर्स के साथ खेले। ब्रायंट ने कहा था, 'मैं इस खेल की हर चीज को पसंद करता हूं। मेरे लिए, यह जीवन का हिस्सा नहीं है, यह जीवन है, और यह मेरा एक हिस्सा है।'

लोकप्रियता अपरंपार: कोबे के खेल की खासियत इसी बात से समझी जा सकती है कि 1996 में उन्हें हाईस्कूल से सीधे एनबीए के लिए ड्राफ्ट किया गया। लास एंजिलिस लेकर्स को दिए 20 सालों में से 18 साल वह ऑल स्टार टीम का हिस्सा रहे। ऑल स्टार टीम में हर साल वे सात खिलाड़ी चुने जाते हैं, जो टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ रहते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ब्रायन ने अपना जलवा कायम रखा और अमेरिकी टीम को 2008 बीजिंग ओलिंपिक और 2012 लंदन ओलिंपिक में स्वर्ण पदक दिलाया। 2016 में चोट के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और अपने आखिरी गेम में लेकर्स के लिए 60 अंक हासिल किए। साल 2016 के अप्रैल महीने में रिटायर होने वाले कोबे ने साल 2008 में एनबीए के सबसे अहम खिलाड़ी का खिताब हासिल किया था।

बास्केटबॉल से ऑस्कर तक: कोबे ने साल 2015 में बास्केटबॉल को एक प्रेम पत्र लिखा था। जब इस प्रेम पत्र पर डियर बास्केटबॉल नाम से एक शॉर्ट एनिमेटेड फिल्म बनाई गई तो इसे ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

कोबे के मृत्यु की भविष्यवाणी हुई सच: ट्विटर पर सोमवार को वर्ष 2012 का एक ट्वीट वायरल हुआ जिसमें यह दावा किया गया कि ब्रायंट की मृत्यु हेलीकॉप्टर के कारण होगी। डॉटनोसो के नाम से एक यूजर ने 13 नवंबर 2012 को एक ट्वीट किया था जिसमें उसने लिखा था कि कोबे हेलीकॉप्टर हादसे में मरेंगे।

कैलाबसास में दुर्घटनाग्रस्त हुआ हेलीकॉप्टर ● एपी

थम गया गियाना का सफर

नई दिल्ली: पांच फुट 10 इंच की गियान अपने पिता के नक्शेकदम पर चलना चाहती थीं और उनकी तरह शानदार बास्केटबॉल खिलाड़ी बनने की राह पर चल रही थीं। जब यह हादसा हुआ था तो वह मुंबा अकादमी जा रही थी जहां वह अपने पिता के मार्गदर्शन में इस खेल को सीखती हैं। ब्रायंट ने कहा था कि बेटी की इच्छा के कारण ही वह उन्हें इस खेल में लेकर आए थे। मैंने उसके कई मैच देखे थे और वह अच्छी तरह से गेंद को बास्केट में डालती थी। गियाना ने पिता कोब का निक नेम द ब्लैक मांबा को अपनी जर्सी में पर लिखवाया था। कोबे ने कहा था कि जब मैंने उसको पहला मैच खेलते हुए देखा था तो मुझे बहुत मजा आया था। कोबे ने पिछले सप्ताह गियाना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था जिसमें वह गेंद को बास्केट में डाल रही थीं और इसको देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि कोबे ने ही मानो यह गेंद बास्केट में डाली हो।

धुंध के कारण उड़ान नहीं भर सके पुलिस के हेलीकॉप्टर

वॉशिंगटन: लॉस एंजिलिस काउंटी के अधिकारी ने मीडिया को बताया कि अग्निशमन दल को सुबह नौ बजकर 47 मिनट पर (अमेरिकी समयानुसार) दुर्घटना की सूचना मिली। अधिक धुंध होने के कारण पुलिस के हेलीकॉप्टर दोपहर बाद तक उड़ान नहीं भर सके थे। स्थानीय मीडिया के अनुसार, मृतकों में एक अन्य खिलाड़ी और उसके माता-पिता भी शामिल हैं। ऑरेंज कोस्ट कॉलेज ने पुष्टि की है कि मृतकों में 56 वर्षीय बेसबॉल कोच जॉन एल्टोबेली भी शामिल हैं। एल्टोबेली की पत्नी केरी और उनकी एक बेटी एलिसा भी हेलीकॉप्टर में सवार थी। अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (एफएए) और राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड (एनटीएसबी) ने कहा है कि वे इस हादसे की जांच करेंगे।

लिमोजिन जैसा मजबूत था हेलिकॉप्टर

नई दिल्ली: ब्रायंट और गियाना की मृत्यु जिस हेलीकॉप्टर में हुई, वह लिमोजिन कार जैसा मजबूत था। इस सिकोर्सकी एस-76 चॉपर की कीमत 13 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 93 करोड़ रुपये) है। यह हेलीकॉप्टर 1991 में तैयार हुआ था। 2014 से 2016 तक ब्रायंट का हेलीकॉप्टर उड़ाने वाले पायलट कुर्ट डीट्ज ने इस हेलीकॉप्टर को 10 में से नौ अंक दिए हैं। जिस तरह लिमोजिन कार में सुविधाएं होती हैं उसी तरह यह हेलीकॉप्टर भी सुविधाओं से लैस था। अनुमान लगाया जा रहा है कि खराब मौसम के बाद इंजन में खराबी के कारण यह हादसा हुआ होगा। रविवार को बहुत ज्यादा धुंध के कारण दृश्यता कम थी।

महिला ने लगाए थे आरोप

नई दिल्ली: कोबे ब्रायंट पर 2003 में कोलोराडो के एक होटल में काम करने वाली एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया था, जिससे उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई और इस मामले को लेकर मीडिया में भी बहुत तूल दी गई थी। ब्रायंट ने आरोपों से इन्कार कर दिया था लेकिन गवाहों ने अपने बयान नहीं दर्ज कराए जिसके बाद उन पर लगे आरोप हटा दिए गए और यह मामला खत्म हो गया।

टूटने से बची थी शादी

नई दिल्ली: 10 साल की शादी के बाद कोबे ब्रायंट और उनकी पत्नी वेनेसा लेन ब्रायंट ने एक समय अलग होने का फैसला किया था और लग रहा था कि यह शादी टूट जाएगी। कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दाखिल की गई थी लेकिन 2013 में फिर दोनों ने साथ रहने का फिर से फैसला किया।

ब्रायंट के लिए आंखें नम

- भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने इंस्टाग्राम पर ब्रायंट के साथ एक फोटो शेयर की और लिखा कि जब वह 13 साल की थीं तो उनसे मिली थी
- न्यूयॉर्क में मेडिसन स्क्वॉयर गार्डन में कोबे ब्रायंट की फोटो लगाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई
- रविवार को हुए एनबीए के मैचों में हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी
- सोशल मीडिया पर प्रशंसकों ने लास एंजिलिस लेकर्स को सलाह दी है कि ब्रायंट की आठ और 24 नंबर की जर्सी को रिटायर्ड कर दें
- ग्रैमी अवॉर्ड्स कार्यक्रम के दौरान भी ब्रायंट को याद किया गया
- दुनिया भर में लोगों ने ब्रायंट को अलग-अलग तरह से श्रद्धांजलि दी। किसी ने उनकी फोटो के आगे बैंगनी रंग के फूल चढ़ाए तो किसी ने बास्केटबॉल रखी। बैंगनी रंग उनकी टीम लेकर्स का प्रतीक है

श्रद्धांजलि

वे कोर्ट पर एक दिग्गज थे, वे अपनी दूसरी पारी शुरू ही कर रहे थे, जो कि काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। माता-पिता के तौर पर गियाना को खोना अधिक दुख देने वाला है। मिशेल और मेरी तरफ से ब्रायन के परिवार, उनकी पत्नी वेनेसा के लिए प्रार्थना और संवेदनाएं।
बराक ओबामा, पूर्व राष्ट्रपति, अमेरिका

इस खबर को सुनकर बहुत दुखी हूं। बचपन की कई यादें जुड़ी हैं। सुबह जल्दी उठकर कोर्ट पर उनकी जादूगरी देखना, जिससे मैं मंत्रमुग्ध हो जाता था। जीवन कितना अप्रत्याशित और अस्थिर है। दुर्घटना में उनकी बेटी की भी मौत हो गई। मैं इससे बहुत आहत हूं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। परिवार के प्रति संवेदना। ईश्वर उन्हें मजबूती प्रदान करे। **विराट कोहली**, , भारतीय क्रिकेट कप्तान

खेल जगत का वास्तविक दिग्गज। प्रिय कोबे और उनकी बेटी की आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे। ईश्वर उनके परिवार को इस दुखद समय से उबरने के लिए शक्ति दे।
विवियन रिचर्ड्स, दिग्गज क्रिकेटर, वेस्टइंडीज

हर किसी की तरह मैं भी कोबे ब्रायंट और उनकी बेटी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत से स्तब्ध और दुखी हूं। उनके परिवार और परिजनों के प्रति संवेदनाएं।
शेन वार्न, पूर्व स्पिनर, ऑस्ट्रेलिया

मेरे पास कोई शब्द नहीं हैं। कोबे के परिवार और दोस्तों के लिए मेरा प्यार। आपसे मिलकर अच्छा समय साझा करना खुशी की बात थी। **लियोन मेसी**, फुटबॉलर, बार्सिलोना

दिल दहला देने वाली खबर सुनकर दुख हुआ। कोबे एक सच्चे दिग्गज और प्रेरणास्रोत थे। उनके परिवार, दोस्तों और दुर्घटना में जान गंवाने वाले सभी लोगों के परिवारों के प्रति मेरी संवेदना भेजना।
क्रिस्टियानो रोनाल्डो, फुटबॉलर, जुवेंटस

मुझे मैच के बाद पता चला है कि ब्रायंट का निधन हो गया। विश्व खेल जगत और हमारे लिए दुखद खबर है। मैं उन्हें जानता था। **नेमार**, फुटबॉलर, पेरिस सेंट जर्मेन

यह खबर सुनकर सच में मेरा दिल शोक मना रहा है। कोबे मेरे लिए एक महान गुरु और मित्र थे। आप और आपकी बेटी हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे। ब्रायंट और इस त्रासदी से पीड़ित हर परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं।
नोवाक जोकोविक, टेनिस खिलाड़ी, सर्बिया

दुनिया के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक ब्रायंट की मौत की दुखद खबर सुनकर मैं सुबह जग गया। **राफेल नडाल**, टेनिस खिलाड़ी, स्पेन

मेरा दिल टूट गया। मैं आपकी उदारता और वो समय कभी नहीं भूलूंगी जब आपने मेरे कठिन समय में साथ दिया। मेरा दिल आपके परिवार के साथ है। **मारिया शारोपावा**, टेनिस खिलाड़ी

खेल जगत की एक बड़ी हस्ती ने इस दुनिया को बहुत जल्दी अलविदा कह दिया। रेस्ट इन पीस कोबे ब्रायंट, गियाना और हादसे के शिकार अन्य लोग। **रोहित शर्मा**, बल्लेबाज, भारत

इस दुखद अंत से हम सभी अकल्पनीय शोक में हैं। 20 सालों तक कोबे ने हमें दिखाया कि जब बेहतरीन प्रतिभाएं जीत के लिए पूरे समर्पण लिए एक साथ आती हैं तो क्या संभव है। **एनबीए**

निशब्द... दुनिया ने एक महान एथलीट खो दिया है। बहुत सारे बच्चों और मेरी भतीजी को कोबे ने बास्केटबॉल खेलने के लिए प्रेरित किया। **अक्षय कुमार**, अभिनेता, बॉलीवुड

ब्रायंट हमेशा से जीत के लिए प्रतिबद्ध थे। वह दिग्गज खिलाड़ियों में से एक थे और हमने दिग्गज खिलाड़ी को खो दिया। **टाइगर वुड्स**

भारत व ऑस्ट्रेलिया के युवाओं के बीच आज होगी क्वार्टर फाइनल की जंग

पोचेस्फ्रस्ट्रूम (दक्षिण अफ्रीका), प्रेट्र: भारत और ऑस्ट्रेलिया की जूनियर टीमें आइसीसी अंडर-19 विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में मंगलवार को यहां जब आमने-सामने होंगी तो न सिर्फ रोमांचक मुकाबले की संभावना बनेगी, बल्कि कलाई के स्पिनरों रवि बिश्नोई और तनवीर सांघा के बीच भी रोचक जंग देखने को मिलेगी।

सफेद गेंद की क्रिकेट में हाल के दिनों में कलाई के स्पिनरों ने अहम भूमिका निभाई है और जूनियर क्रिकेट भी इससे अछूता नहीं है, जहां बिश्नोई टूर्नामेंट के सबसे प्रभावशाली गेंदबाज साबित हुए हैं और वह ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ अपनी टीम का पलड़ा भारी रखने की कोशिश करेंगे। बिश्नोई ने अब तक तीन मैचों में 10 विकेट लिए हैं। इनमें न्यूजीलैंड के खिलाफ 30 रन देकर चार विकेट लेने का शानदार प्रदर्शन भी शामिल है। इससे बिश्नोई ने साबित कर दिया कि आखिर आइपीएल नीलामी के दौरान किंग्स इलेवन पंजाब ने उन पर दो करोड़ रुपये क्यों खर्च किए थे।

आंकड़ों पर गौर करें तो सांघा भी बिश्नोई से पीछे नहीं हैं और उन्होंने भी अब तक 10 विकेट लिए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 14 रन देकर पांच विकेट है, जो उन्होंने नाईजीरिया के खिलाफ किया था। भारतीय मूल के इस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने वेस्टइंडीज के खिलाफ भी चार विकेट लिए थे और इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने एक विकेट हासिल किया था। मंगलवार को होने वाले मैच में कलाई के दोनों स्पिनर अपनी टीमों के लिए काफी अहम साबित होंगे।

इस मैच में ऑस्ट्रेलिया जूनियर स्तर पर भारत के खिलाफ अपने खराब रिकॉर्ड में सुधार करना चाहेगा। वर्ष 2013 के बाद अंडर-19 स्तर पर इन दोनों टीमों के बीच जो पांच मैच खेले गए, उनमें से चार मैच भारत ने जीते, जबकि एक मैच बारिश के कारण रद कर दिया गया था। दोनों टीमों की तुलना की जाए तो भारतीय टीम अपने प्रतिद्वंद्वी से काफी आगे नजर आती है। उसके पास यशस्वी जायसवाल, उनके सलामी जोड़ीदार दिव्यांश सक्सेना और कप्तान प्रियम गर्ग के रूप में उपयोगी बल्लेबाज हैं जिन्होंने अब तक अपने कौशल की अच्छी छाप छोड़ी है। गेंदबाजी विभाग में उत्तर प्रदेश के कार्तिक त्यागी और बायें हाथ के तेज गेंदबाज आकाश सिंह ने उपयोगी जोड़ी बनाई है। बायें हाथ के स्पिनर अथर्व अंकोलेकर ने भी न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार वापसी करके अपनी काबिलियत साबित की थी। क्षेत्ररक्षण के दौरान उनके दायें हाथ की अंगुली चोटिल हो गई थी, जो उनकी राह में रोड़ा बन सकती है।

ऑस्ट्रेलिया के पास कप्तान मैकेंजी हार्वे (ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर इयान हार्वे के भतीजे) अच्छे बल्लेबाज हैं। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अंतिम लीग मैच में 65 रन की शानदार पारी खेली थी। गेंदबाजी में कोनोर सुली हैं जो एक उपयोगी गेंदबाज होने के साथ बल्लेबाजी में भी योगदान देते हैं।

अंडर-19 विश्व कप

- कलाई के स्पिनरों रवि व तनवीर पर रहेंगी नजरें
- जूनियर स्तर पर 2013 से भारी रहा है भारत का पलड़ा

न्यूजीलैंड के विकेटकीपर बोले, बुमराह को खेलना मुश्किल

हैमिल्टन, प्रेट्र: न्यूजीलैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज टिम सेफर्ट ने कहा कि भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की विविधतापूर्ण गेंदबाजी को समझना मुश्किल है और उनकी टीम को अगर टी-20 सीरीज में वापसी करनी है तो उसे भारत से सीखना होगा कि परिस्थितियों से कैसे सामंजस्य बिठाया जाता है। भारत ने रविवार को ऑकलैंड में दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय में न्यूजीलैंड को सात विकेट से हराकर पांच मैचों की सीरीज में 2-0 से बढ़त बनाई। बुमराह ने चार ओवर में 21 रन देकर एक विकेट लिया।

सेफर्ट ने कहा, 'यहां तक कि पहले मैच में भी बुमराह ने धीमी गेंदें कीं। अमूमन डेथ ओवरों में यह गेंदबाज सीधी लाइन पर गेंद करता है। इसके अलावा यॉर्कर करता है। वह अपनी गेंदों में काफी बदलाव करते हैं और उन्हें खेलना मुश्किल है। गेंद काफी रुककर आ रही थी जिससे मुश्किलें बढ़ीं। इसलिए एक बल्लेबाज के रूप में आपको कुछ अवसरों पर विकेटों से हटकर यह देखना होता कि क्या गेंद सीधी लाइन पर आ रही है। मैं विकेटों पर खड़ा रहने के बजाय कुछ अलग करने में विश्वास करता हूं।'

सेफर्ट ने कहा कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को भारतीय बल्लेबाजों से सीखना चाहिए। उन्होंने कहा, 'भारतीय बल्लेबाजों ने दिखाया कि कैसे गेंद की लाइन में आकर सही टाइमिंग से उसे खेलना है। धीमे विकेट पर आपको इस तरह का खेल दिखाना होता है। उनकी (गेंदबाजों की) लाइन बिगाड़ने की कोशिश करो, अच्छी गेंद पर भी शॉट लगाने के लिए सही स्थिति में आओ। टी-20 क्रिकेट में यह महत्वपूर्ण होता है। भारतीय बल्लेबाजों ने ऐसा अच्छी तरह से किया।'

सेफर्ट ने कहा कि न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने पहले दो मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन भारतीय बल्लेबाज उन पर पूरी तरह हावी रहे। उन्होंने कहा, 'ईमानदारी से कहूं तो पहले मैच में उनका स्कोर एक विकेट पर 110 था और उनके पास विकेट बचे थे। हमने पहले मैच में खराब गेंदबाजी नहीं की थी। दूसरे मैच में हम केवल 130 रन ही बना पाए और ईडन पार्क पर इस स्कोर का बचाव करना मुश्किल था।' न्यूजीलैंड की टीम अब भी सीरीज में वापसी करने के प्रति आश्वस्त है। तीसरा मैच बुधवार को यहां खेला जाएगा, जबकि अगले दो मैच वेलिंगटन और माउंट मौंगानुई में होंगे। उन्होंने कहा, 'हमने दो मैच गंवा दिए, लेकिन हम बुरा नहीं खेले। हमने निश्चित तौर पर अपना सर्वश्रेष्ठ खेल नहीं दिखाया, लेकिन भारत बहुत अच्छा खेला। अगर हम बुधवार को सीरीज गंवा देते हैं तो यहीं सब कुछ समाप्त नहीं हो जाएगा। लेकिन, अगर हम वहां जीत दर्ज करते हैं तो फिर चीजों को आगे लेकर जा सकते हैं। हमने पिछली बार (2019 में) 2-1 से सीरीज जीती थी, इसलिए हमें इसे तीन मैचों की सीरीज की तरह लेना होगा, लेकिन हमें पहले दो मैच जीतने हैं।'

पोंटिंग बोले, पंत जल्द ही भारतीय एकादश में वापसी करेंगे: रिकी पोंटिंग को रिषभ पंत की मैच जिताने वाली क्षमताओं पर पूरा भरोसा है और उन्हें उम्मीद है कि यह प्रतिभाशाली विकेटकीपर बल्लेबाज न्यूजीलैंड के खिलाफ मौजूदा सीरीज में जल्द ही भारतीय एकादश में वापसी करेगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुंबई में पहले वनडे मैच में पंत के सिर में चोट लग गई थी, लेकिन अब वह फिट हैं। इस बीच उनके स्थान पर विकेटकीपर की जिम्मेदारी निभाने वाले केएल राहुल ने वनडे और टी-20 दोनों में विकेट के आगे और विकेट के पीछे अच्छा प्रदर्शन किया। दिल्ली कैपिटल्स के कोच पोंटिंग ने ट्विटर पर अपने 'फॉलोअर्स' के साथ सवाल-जवाब के सत्र में कहा, 'रिषभ पंत प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वह जल्द ही भारतीय टीम की अंतिम एकादश में वापसी करेंगे।'

रवींद्र जडेजा और संजय मांजरेकर के बीच ट्विटर पर हुई मजाकिया भिड़ंत

ऑकलैंड, आइएएनएस: न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की मौजूदा सीरीज के रविवार को यहां हुए दूसरे टी-20 मैच में भारत को मिली बेहतरीन जीत के बाद ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा और क्रिकेटर से कमेंटेटर बने संजय मांजरेकर के बीच ट्विटर पर मजाकिया बातचीत शुरू हो गई। इस मैच में जडेजा ने प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए 18 रन देकर दो विकेट लिए थे, जिसकी मदद से भारत ने न्यूजीलैंड को 20 ओवर में पांच विकेट पर 132 रन पर रोक दिया था। इस दौरान तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने भी प्रभावी गेंदबाजी करते हुए 21 रन देकर एक विकेट झटका था। उन्होंने कीवी बल्लेबाजों को डेथ ओवरों में रन नहीं बनाने दिए थे। जवाब में भारतीय टीम ने 15 गेंद बाकी रहते हुए सात विकेट से जीत हासिल की थी, जिसमें केएल राहुल ने नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली थी, जबकि श्रेयस अय्यर ने शानदार 44 रन बनाए थे। राहुल को उनके नाबाद 57 रन के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया था। हालांकि, मांजरेकर इस फैसले से नाराज नजर आए और उन्होंने ट्वीट किया, 'मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार किसी गेंदबाज को मिलना चाहिए था।' इस पर जडेजा ने अपनी प्रतिक्रिया दी और मांजरेकर से गेंदबाज का नाम बताने को कहा। उन्होंने पूछा, 'उस गेंदबाज का नाम क्या है? कृपया बताएं।' इस पर पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने जडेजा को जवाब दिया और कहा, 'हा...हा... या तो आप या फिर बुमराह। बुमराह, क्योंकि जब उन्होंने ओवर नंबर तीन, 10, 18 और 20 में बेहद किफायती गेंदबाजी की।' मांजरेकर इससे पहले 2019 विश्व कप में जडेजा के साथ एक विवाद में उलझ गए थे। जुलाई में न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच से पहले मांजरेकर ने जडेजा को 'टुकड़ो में प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी' बताया था और उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले के लिए अपनी अंतिम एकादश से बाहर रखा था। इस पर वह काफी ट्रोल हुए थे। सोशल मीडिया पर मांजरेकर के बयान पर काफी प्रतिक्रियाएं आई थीं। जडेजा ने भी वापस ट्वीट करते हुए लिखा था, 'जितने आपने मैच खेले हैं, मैं उससे दोगुने मैच खेल चुका हूं और अभी भी खेल रहा हूं। उन लोगों का सम्मान करना सीखिए, जिन्होंने कुछ हासिल किया है। मैंने आपके मुंह से काफी गंदगी उगलने (वर्बल डायरिया) के बारे में सुना है संजय मांजरेकर।'

न्यूजीलैंड दौरा

- कहा, भारतीय टीम से सीखना होगा हालात से सामंजस्य बिठाना
- हमने निश्चित तौर पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं किया

टेनिस विश्व के नंबर एक खिलाड़ी ने किर्गियोस को चार सेटों में हराया, ज्वेरेव और थिएम ने भी जीते अपने-अपने मैच

नडाल ने 12वीं बार बनाई क्वार्टर फाइनल में जगह

मेलबर्न, एएफपी: विश्व रैंकिंग में पहले स्थान पर काबिज राफेल नडाल, जर्मनी के एलेक्जेंडर ज्वेरेव, ऑस्ट्रिया के पांचवीं वरीयता प्राप्त डोमिनिक थिएम और दो बार की ग्रैंडस्लैम चैंपियन सिमोना हालेप ने सोमवार को यहां अपने-अपने मुकाबलों में जीत के साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।

स्पेन के शीर्ष वरीय खिलाड़ी को स्थानीय दावेदार निक किर्गियोस ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन वह इससे पार पाने में सफल रहे। नडाल ने रॉड लावेर परिसर में खेले गए इस मुकाबले को 6-3, 3-6, 7-6, 7-6 से अपने नाम किया। नडाल का अंतिम आठ में डोमिनिक थीम से सामना होगा जिन्होंने फ्रांस के 10वीं वरीयता प्राप्त गेल मोनफिल्स को 6-2, 6-4, 6-4 से पराजित किया। नडाल इस टूर्नामेंट में 12वीं बार क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। नडाल ने किर्गियोस के खिलाफ पहला सेट जीतने के बाद दूसरा सेट गंवा दिया था, लेकिन फिर अगले दोनों सेट जीतकर अगले दौर में अपनी जगह पक्की की। नडाल ने यह मुकाबला तीन घंटे 38 मिनट में जीता। वहीं, सातवीं वरीयता प्राप्त ज्वेरेव ने अपने करीबी दोस्त और शानदार लय में चल रहे रूस के आंद्रेय रूब्लेव को सीधे सेटों में हराया। ज्वेरेव ने एक घंटे 37 मिनट तक चले इस मुकाबले को 6-4, 6-4, 6-4 से अपने नाम किया। ज्वेरेव की इस खिलाड़ी के खिलाफ यह 15 मैच में 15वीं जीत थी। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए उन्हें स्टेन वावरिंका की चुनौती से पार पाना होगा। वावरिंका ने एक अन्य मुकाबले में रूस के डेनिल मेदवेदेव को पराजित किया। वावरिंका ने चौथी वरीयता प्राप्त मेदवेदेव को 6-2, 2-6, 4-6, 7-6, 6-2 से शिकस्त देकर टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखाया।

महिलाओं के वर्ग में चौथी वरीयता प्राप्त रोमानियाई खिलाड़ी हालेप ने बेल्जियम की 16वीं वरीय एलिस मार्टेंस को 6-4, 6-4 से हराकर अंतिम-आठ में जगह बनाईं। विश्व की पूर्व नंबर एक खिलाड़ी और 2018 के फाइनल में कैरोलिन वोजनियाकी से हारने वाली हालेप ने मेलबर्न में इस साल अब तक एक भी सेट नहीं गंवाया है। इस जीत से वह विश्व रैंकिंग में तीसरे से दूसरे स्थान पर भी पहुंच जाएंगी।

समलैंगिकों के खिलाफ बयान देने पर मार्गरेट कोर्ट की आलोचना

मेलबर्न: मार्टिना नवरातिलोवा और जॉन मैकेनरो जैसे दिग्गज टेनिस खिलाड़ियों ने दिग्गज महिला टेनिस खिलाड़ी मार्गरेट कोर्ट के उस बयान की आलोचना कि जिसमें उन्होंने समलैंगिकता के खिलाफ विचार व्यक्त किए थे। कोर्ट ने 1970 में कैलेंडर वर्ष में चारों ग्रैंडस्लैम खिताब अपने नाम किए थे जिसके 50 साल पूरे होने के मौके पर उन्हें सम्मानित करने के लिए 'मार्गरेट कोर्ट परिसर' में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सबसे अधिक 24 ग्रैंडस्लैम जीतने वाली महिला खिलाड़ी मार्गरेट को इस दौरान ऑस्ट्रेलियन ओपन की प्रतिकृति भेंट की गई। इस दौरान 77 साल की कोर्ट ने कहा, 'मेरे में आप जैसा देखेंगे वैसा वापस पाएंगे।' चर्च की पादरी बन चुकीं कोर्ट इससे पहले दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति का समर्थन कर चुकी हैं और टेनिस समलैंगिकों से भरा है जैसे बयान देने के साथ उन्होंने ट्रांसजेंडर के बच्चों को 'शैतान की देन' करार दिया। नवरातिलोवा ने कहा कि उनकी इस तरह के विचारों से लोगों को दुख हुआ जबकि अमेरिकी दिग्गज मैकेनरो ने उनके लिए पागल औरत जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। मैकेनरो ने कहा, 'मार्गरेट कोर्ट की उपलब्धियों की सूची से सिर्फ एक चीज लंबी है और वह है समलैंगिकता के खिलाफ उनके बयान।' सात बार के ग्रैंड स्लैम विजेता ने कहा, 'मार्गरेट कोर्ट बाइबिल का गलत इस्तेमाल कर चीजों की अपने तरीके से पेश करती हैं।' डब्ल्यूटीए के संस्थापक बिली जीन किंग ने कोर्ट के नाम में मेलबर्न में बने मार्गरेट कोर्ट परिसर का नाम बदलने की मांग की। चेक गणराज्य की पूर्व टेनिस खिलाड़ी नवरातिलोवा ने कहा, 'यह काफी दुर्भाग्यशाली है कि कोर्ट को इस बात का अंदेशा नहीं है कि वह अपने बयानों से कितने लोगों को दुख पहुंचा रही हैं।'

जीत का जश्न मनाते हुए राफेल नडाल ● एएफपी

बुमराह और कोहली सर्वश्रेष्ठ : मैक्ग्रा

दावोस, प्रेट्र : ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर ग्लेन मैक्ग्रा ने भारत के जसप्रीत बुमराह और दक्षिण अफ्रीका के कैगिसो रबादा को वर्तमान समय में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज, जबकि विराट कोहली और स्टीव स्मिथ को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज करार दिया।

मैक्ग्रा ने विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के दौरान विशेष कार्यक्रम में वर्तमान समय के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज और बल्लेबाजों के बारे में पूछे जाने पर यह जवाब दिया। उन्होंने कहा, 'बुमराह खास तरह के गेंदबाज हैं। उनका कई तेज गेंदबाजों की तरह लंबा रनअप नहीं है, लेकिन वह अच्छी तेजी से गेंदबाजी करते हैं। उनका अपनी गेंदों पर अविश्वसनीय नियंत्रण है और उनका रवैया सकारात्मक है।' रबादा के बारे में उन्होंने कहा, 'दक्षिण अफ्रीका के रबादा बेहतरीन गेंदबाज हैं। मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। मैं इस सूची में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को नहीं रख रहा हूं क्योंकि मेरा मानना है कि वे सभी शानदार हैं।'

अनिल एशियाई टेनिस महासंघ के आजीवन अध्यक्ष नामित

नई दिल्ली, प्रेट्र : वरिष्ठ खेल प्रशासक अनिल खन्ना को एशियाई टेनिस महासंघ (एटीएफ) ने आजीवन अध्यक्ष नामित करने की घोषणा की। खन्ना 2005 से 2019 तक तक एटीफ के अध्यक्ष और वह 2015 से 2019 तक आइटीएफ के उपाध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने एटीफ अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की थी। एटीफ हुई निदेशक मंडल की बैठक में सर्वसम्मति से खन्ना को आजीवन अध्यक्ष नामित किया।

टीम के प्रदर्शन में सुधार की जरूरत है और मेरी कोशिश अगले मैच में गोल करने की रहेगी।
– ग्रेबियल जीसस, स्ट्राइकर, मैनचेस्टर सिटी

न्यूज गैलरी

प्रागननंधा ने पूर्व विश्व चैंपियन टोपोलोव को हराया

जिब्राल्टर : भारत के युवा ग्रैंडमास्टर आर प्रागननंधा ने छठे दौर में पूर्व विश्व चैंपियन वेसलिन टोपालोव को उलटफेर का शिकार बनाकर 18वें जिब्राल्टर शतरंज महोत्सव में अपनी लगातार पांचवीं जीत दर्ज की। चेन्नई के 14 वर्षीय खिलाड़ी ने बुल्गारियाई दिग्गज को केवल 33 चाल में हरा दिया। प्रागननंधा ने हमवतन पी वी नंदिता के खिलाफ हार से शुरुआत की थी लेकिन इसके बाद उन्होंने अपनी पांचों बाजियां जीती हैं। हाल में विश्व अंडर-18 का खिताब जीतने वाले प्रागननंधा छह अन्य खिलाड़ियों के साथ संयुक्त दूसरे स्थान पर हैं। सातवें दौर में उनका सामना चीन के ग्रैंडमास्टर वांग हाओ से होगा। रूस के 17 वर्षीय ग्रैंडमास्टर आंद्रे एस्पिंको ने काले मोहरों से खेलते हुए जॉर्जिया के इवान चेपरिनोव पर जीत दर्ज की जिससे वह 5 .5 अंक लेकर शीर्ष पर पहुंच गए। भारत के बी अधिबान, के शशिकिरण, शार्दुल गागरे, कार्तिकेयन मुरली और एस एल नारायणन के समान 4 .5 अंक हैं। (प्रेट्र)

पदक विजेताओं को एक-एक लाख रुपये

नागपुर : महाराष्ट्र सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को एक-एक लाख रुपये देने का एलान किया। महाराष्ट्र के खेल मंत्री सुनील केदार ने यह घोषणा की। खेलों में रजत पदक जीतने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को 75000 रुपये और कांस्य पदक विजेताओं को 50000 रुपये दिए जाएंगे। महाराष्ट्र 78 स्वर्ण, 77 रजत व 101 कांस्य समेत 256 पदक जीतकर चैंपियन रहा था। (प्रेट्र)

घोषाल पिट्सबर्ग ओपन के फाइनल में हारे

पिट्सबर्ग (अमेरिका) : भारतीय स्क्वॉश खिलाड़ी सौरव घोषाल पीएसए विश्व टूर स्पर्धा में अपना पहला खिताब जीतने से चूक गए जिन्हें पिट्सबर्ग ओपन के फाइनल में मिस्र के शीर्ष वरीय फारेस डेस्सोउकी ने सीधे सेटों में हराया। रविवार रात को खेले गए फाइनल में घोषाल को 7-11, 4-11, 9-11 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। इससे पहले उन्होंने सेमीफाइनल के मुश्किल मुकाबले में मिस्र के ही ओमर मोस्साद को हराया था। घोषाल ने मैच 11-6, 16-18, 11-7, 12-10 से जीता था। (प्रेट्र)

रवि ने करियर के पहले ओवर में ही ली हैट्रिक

रणजी ट्रॉफी ▶ पदार्पण मैच के पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले देश के पहले गेंदबाज बने

उप्र के निवासी यादव को उसी राज्य की टीम के खिलाफ मिली सफलता

इंदौर, नईदुनिया : मध्य प्रदेश (मप्र) के तेज गेंदबाज रवि यादव ने भारत के घरेलू क्रिकेट में कीर्तिमान रचते हुए करियर के पहले ही रणजी ट्रॉफी मैच में हैट्रिक हासिल की। उत्तर प्रदेश (उप्र) के खिलाफ सोमवार से शुरू हुए रणजी ट्रॉफी एलीट समूह-बी मैच के पहले दिन रवि ने यह उपलब्धि हासिल की। वह प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पदार्पण करते हुए पहले ही ओवर में हैट्रिक लेने वाले भारत के पहले गेंदबाज बने हैं।

रवि ने सातवें ओवर की तीसरी गेंद पर आर्यन जुयाल (13) को विकेटकीपर अजय रोहेरा के हाथों कैच कराया। उन्होंने अगली दो गेंदों पर कप्तान अंकित राजपूत और समीर रिजवी को बोल्ड किया। इसके चलते होलकर स्टेडियम में पहले दिन का खेल समाप्त होने तक उप्र ने आठ ओवर में तीन विकेट पर 22 रन बना लिए हैं। दिन का खेल खत्म होने तक अल्मास शौकत (नाबाद 02) के साथ अक्सदीप नाथ (नाबाद 06) क्रीज पर मौजूद हैं।

किस्मत से मिला था मौका : रवि को मप्र टीम में मौका किस्मत से मिला था। तेज गेंदबाज आवेश खान का चयन भारतीय-ए टीम में होने से उनकी जगह रवि को चुना गया था। इस मौके का रवि ने बखूबी फायदा उठाया। रवि ने बताया कि मैं मूलतः उप्र के फिरोजाबाद के रहने वाला हूं। आगरा के विविधा क्रिकेट क्लब में कोच सर्वेश भटनागर से इस खेल की बारीकियां सीखीं। फिर मौके की तलाश में 2016 में मप्र का रुख किया। यहां चंबल के लिए क्लब और संभागीय मैचों में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद तीन साल से मप्र रणजी टीम के नेट गेंदबाज बने। संयोग से पदार्पण का मौका उप्र के ही खिलाफ मिला।

दिन का खेल खत्म होने के बाद पवेलियन लौटते मप्र के तेज गेंदबाज रवि यादव (मध्य)। साथ में हैं साथी गेंदबाज ईश्वर पांडे व कप्तान नमन ओझा। राजू पवार

अनुस्तूप-श्रीवत्स ने बंगाल को संकट से उबारा : अनुस्तूप मजुमदार (नाबाद 94) और श्रीवत्स गोस्वामी (59) की शानदार पारियों की बदौलत बंगाल ने सोमवार को दिल्ली के खिलाफ ईडन गार्डेंस स्टेडियम में रणजी मैच के पहले दिन पांच विकेट खोकर 286 रन बना लिए हैं। युवा कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन की गैरमौजूदगी में एक बार फिर अनुभवी मनोज तिवारी की कप्तानी में खेलने उतरी बंगाल के एक समय 100 रन पर चार विकेट गिर गए थे। अनुस्तूप ने श्रीवत्स के साथ मिलकर वहां से पारी को संभाला। अनुस्तूप की पारी में 14 चौके शामिल हैं जबकि श्रीवत्स ने 10 चौके लगाए। हैदराबाद के खिलाफ पिछले मैच में 303 रन की जबरदस्त पारी खेलने वाले मनोज तिवारी (07) का बल्ला हालांकि पहली पारी में खामोश रहा। दिल्ली की तरप से विकास मिश्रा ने 78 रन देकर तीन विकेट चटकाए।

फोटोग्राफर बने स्टीव वॉ : पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव वॉ सोमवार को ईडन गार्डेंस स्टेडियम में बंगाल-दिल्ली के बीच रणजी मैच के पहले दिन फोटोग्राफर के रूप में नजर आए। स्टीव ने मैच की कई तस्वीरें अपने कैमरे में कैद कीं। वह बिलकुल मंझे हुए फोटोग्राफर की तरह तस्वीरें खींच रहे थे। स्टीव अपनी नई पुस्तक के सिलसिले में कोलकाता के दो दिवसीय दौरे पर हैं।

बादल गरजे, सरफराज बरसे : धौलाधार की गोद में स्थित धर्मशाला के खूबसूरत अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पर सोमवार को मुंबई के बल्लेबाज सरफराज ने जबरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहिरा पेश करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया। हालांकि दोपहर तक काले घने बादलों ने गर्जना के साथ आसमान पर डेरा जमा लिया था लेकिन इस बीच स्टेडियम पर सरफराज के बल्ले से ऐसी रनवर्षा हुई कि मेजबान हिमाचल की रणजी टीम के सारे मंसूबे धरे के धरे रह गए। सरफराज 226 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। सरफराज हाल ही में उत्तर प्रदेश के खिलाफ मुकाबले में तिहरा शतक भी लगा चुके हैं। हिमाचल व मुंबई के बीच एलीट ग्रुप का रणजी मुकाबला सोमवार को शुरू हुआ। हिमाचल की टीम ने मुंबई के तीन बल्लेबाजों को 20 रनों से पहले ही पवेलियन लौटा दिया।

इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका से 3-1 से जीती सीरीज

जोहानिसबर्ग, एएफपी : रेसे वेन डेर डुसेन (98) की संघर्षपूर्ण पारी भी दक्षिण अफ्रीका को इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच में सोमवार को यहां हार से नहीं बचा सकी। जीत के लिए मिले 466 रन का लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम 274 रन पर आउट हो गई।

इंग्लैंड ने इस मैच को 191 रन से जीत कर सीरीज 3-1 से अपने नाम की। इंग्लैंड के पहली पारी में 400 रन के जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 183 रन बनाए थे। इंग्लैंड की दूसरी पारी 248 रन पर सिमटी थी। चौथी पारी में जीत के लिए रिकॉर्ड 466 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए डुसेन ने कप्तान फाफ डुप्लेसिस (35) के साथ 30 ओवर से अधिक की साझेदारी में तीसरे विकेट के लिए 92 रन जोड़े। बेन स्टोक्स (2/47) ने डुप्लेसिस को बोल्ड कर इस साझेदारी को तोड़ा, जबकि अगले ओवर में मैन ऑफ द मैच मार्क वुड ने डुसेन को पवेलियन का रास्ता दिखाया। डुसेन दो रन से अपना पहला शतक बनाने से चूक गए, लेकिन उन्होंने 138 गेंद की पारी में 15 चौके और दो छक्के लगाए। पहली पारी में पांच विकेट लेने वाले मैन ऑफ द मैच वुड ने दूसरी पारी में 54 रन देकर चार विकेट लिए। दो ओवर में दो विकेट गंवाने के बाद लय में चल रहे डिकॉक (39) और तेंबा बावुमा (27) अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल सके। पांचवें विकेट के लिए 48 रन की साझेदारी को स्टुअर्ट ब्रॉड (2/26) ने बावुमा को आउट कर तोड़ा।

भारतीय महिला हॉकी टीम को मिली मात

ऑकलैंड, प्रेट्र : भारतीय महिला हॉकी टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे मैच में सोमवार को यहां 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय टीम ने दौरे के पहले मैच में 4-0 से जीत दर्ज की थी। न्यूजीलैंड ने आक्रामक शुरुआत की और पहले क्वार्टर के शुरू में ही पेनाल्टी कॉर्नर हासिल किया जिसे मेगान हल ने तीसरे मिनट में गोल में बदला। युवा सलीमा टेटे ने पहले क्वार्टर के आखिरी क्षणों में पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर भारत को बराबरी दिलाई। दूसरे और तीसरे क्वार्टर में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिला लेकिन कोई भी टीम इस दौरान गोल नहीं कर पाई। आखिरी 15 मिनट में रक्षापंक्ति की ढिलाई भारत को भारी पड़ी।

मुंबई में होगा आइपीएल फाइनल, नहीं बदलेगा मैचों का समय

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

बीसीसीआइ अध्यक्ष सौरव गांगुली ने सोमवार को साफ किया कि इंडियन प्रीमियर लीग (आइपीएल) की गवर्निंग काउंसिल ने तय किया है कि आइपीएल का खिताबी मुकाबला 24 मई को मुंबई में खेला जाएगा और रात के मैच सामान्य तौर की तरह ही रात आठ बजे से शुरू होंगे।

आइपीएल की गवर्निंग काउंसिल की बैठक के बाद गांगुली ने कहा, 'आइपीएल के रात के मैचों के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले के वर्षों की तरह ही इस बार भी मैच रात आठ बजे शुरू होंगे। इस बार सिर्फ पांच डबल हेडर (दिन में दो मैच, शाम चार बजे और रात आठ बजे) होंगे। हमने डबल हेडर मैचों की संख्या कम करने का फैसला किया है। फाइनल मुकाबला मुंबई में खेला जाएगा।'

इस पूर्व भारतीय कप्तान ने जानकारी दी कि इस लोकप्रिय टी-20 लीग के आगामी संस्करण में पहली बार 'कंकशन स्थानापन्न' और 'थर्ड अंपायर नो बॉल' को प्रयोग में लाया जाएगा। बल्लेबाजी करते हुए खिलाड़ियों के सिर पर चोट लगने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए कंकशन का नया नियम पिछले साल टेस्ट प्रारूप में प्रयोग में लाया गया था। तब लॉर्ड्स के मैदान में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट के दौरान ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज स्टीव स्मिथ के हेलमेट में गेंद लगी थी। नए नियम के कारण स्मिथ की जगह 12वें खिलाड़ी मानर्स लाबुशाने पांचवें दिन बल्लेबाजी करने उतरे थे। अब मैदानी अंपायर के बजाय तीसरा अंपायर ही नोबॉल देगा। हाल में घर में हुई भारत-वेस्टइंडीज वनडे सीरीज के दौरान इसका प्रयोग भी किया गया था।

एनबीए की तर्ज पर होगा ऑल स्टार गेम : आइपीएल शुरू होने से पहले 29 मार्च को बीसीसीआइ द्वारा चैरिटी के मकसद से ऑल स्टार गेम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी शीर्ष अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी खेलेंगे। हालांकि, इसके लिए स्थल अभी तय नहीं हुआ है। गांगुली ने कहा, 'आइपीएल से तीन दिन पहले ऑल स्टार गेम का आयोजन होगा। इसका स्थल अहमदाबाद नहीं होगा क्योंकि वह स्टेडियम अभी मैच के लिए तैयार नहीं है। हमने अभी तक तय नहीं किया है कि हम कहां राशि दान करेंगे।' ऑल स्टार गेम की अवधारणा एनबीए से ली गई है, जो प्रदर्शनी मैच होता है। इसके तहत आइपीएल की आठों फ्रेंचाइजियों में से बेहतरीन खिलाड़ियों को छांटकर उनसे दो टीमें बनाई जाएंगी और फिर उन टीमों के बीच प्रदर्शनी मैच खेला जाएगा। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख राहुल द्रविड़ के साथ बैठक के बारे में पूछे जाने पर गांगुली ने कहा कि वहां सुविधा को लेकर व्यापक चर्चा की गई है। जैसा कि पहले ही बताया गया है, हमारे पास एनसीए में एक न्यूट्रीशनिस्ट और बायोमैकेनिक्स गेंदबाजी कोच होगा।'

वर्मा ने गांगुली को दिए सुझाव : बिहार क्रिकेट संघ के सचिव आदित्य वर्मा ने बीसीसीआइ अध्यक्ष सौरव गांगुली को पत्र लिखकर आइपीएल को लेकर कुछ सुझाव दिए हैं। वर्मा ने लिखा कि न्यूयॉर्क की स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी आइएमजी को आइपीएल आयोजन के लिए प्रति वर्ष 35 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाता है। बीसीसीआइ सीधे भारतीय संसाधनों का प्रयोग करके आइपीएल क्यों नहीं आयोजित करा सकता है। यह इंडियन प्रीमियर लीग है और इसमें विदेशी कंपनियों की जगह भारतीयों को रोजगार मिलना चाहिए। उन्होंने साथ ही लिखा कि निलंबित आइपीएल टीम कोच्चि टस्कर्स के मामले का जल्द से जल्द निराकरण करना चाहिए। शहरों में कुछ मैचों का आयोजन करना चाहिए।

विविध

बच्ची से दुष्कर्म व हत्या के दोषी को फांसी की सजा

जासं, पलवल : हरियाणा की पलवल जिला अदालत ने सोमवार को पांच वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म व हत्या के दोषी 28 वर्षीय वीरेंद्र उर्फ भोला को फांसी की सजा सुनाई है। दोषी की मां को साजिश रचने और शव को खुर्दबुर्द करने के लिए सात वर्ष की कैद और 10 हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक माह की सजा बढ़ जाएगी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश व महिला विरुद्ध अपराधों की अदालत की प्रभारी न्यायाधीश करुणा शर्मा ने शुक्रवार को जमानत पर चल रही दोषी की मां कमला को भी हिरासत में लेने के आदेश दिए थे। अभियोग के मुताबिक गदपुरी थाना क्षेत्र के एक गांव में 31 मई 2018 को पांच वर्षीय बच्ची अचानक लापता हो गई थी। एक टेंट हाउस के बाहर सीसीटीवी की फुटेज जांची गई तो उसमें भोला बच्ची को साथ ले जाता दिखा। ग्रामीणों के साथ पुलिस ने दोषी के घर से बच्ची का शव आटे के ड्रम से बरामद किया, जिसकी चाकू से गोदकर हत्या की गई थी।

दो अंतरराज्यीय इनामी बदमाश दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- दोनों बदमाश मकोका के तहत हैं आरोपित, दो वर्ष से चल रहे थे फरार
- हत्या, हत्या के प्रयास और लूट के मामलों में दिल्ली, हरियाणा पुलिस को थी तलाश
- एक पर दो लाख और दूसरे पर एक लाख का इनाम घोषित

मकोका के आरोपित दो अंतरराज्यीय इनामी बदमाशों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दबोचा है। एक पर दो लाख और दूसरे पर एक लाख का इनाम घोषित है। हत्या, हत्या के प्रयास और लूट के आधा दर्जन मामलों में दिल्ली और हरियाणा पुलिस को दोनों की दो वर्ष से तलाश थी। पकड़ा गया आरोपित अमित उर्फ दबंग उर्फ सोनू टिल्लू तेजपुर कलां गांव का रहने वाला है। वह तेजपुरिया गिरोह का शार्प शूटर है और इस पर दो लाख का इनाम था। दूसरा बदमाश हरियाणा के सोनीपत के बरोना गांव निवासी रवि उर्फ मुनिया है। इस पर दिल्ली और हरियाणा पुलिस की तरफ से 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित था। वह सुनील राठी, नीरज बवानिया गिरोह का बदमाश है।

डीसीपी स्पेशल सेल, मनीषी चंद्रा ने बताया कि 24 जनवरी को स्पेशल सेल को दो बदमाशों के बारे में सूचना मिली। इंस्पेक्टर विक्रम दहिया के नेतृत्व में दोनों को अलग-अलग स्थानों से दबोच लिया गया। उन्होंने बताया कि दोनों बदमाश काफी शातिर हैं।

दोनों ने खूब मचाया आतंक : 2012 से अमित उर्फ दबंग और टिल्लू ताजपुरिया का जितेन्द्र उर्फ गोगी से टकराव चल रहा था। 2014 में अमित उर्फ दबंग ने जितेन्द्र उर्फ गोगी के ऊपर रोहिणी जेल के पास गोलियां चलाई थी। लेकिन, वह बच निकला था। 2015 में अमित ने जितेंद्र के करीबी अरुण उर्फ कमांडो को मार डाला था। इस मामले में अमित को गिरफ्तार किया गया था। 2015 में अमित ने जितेंद्र को फिर से निशाने पर लिया, पर वह बचता रहा और उसने अमित को खत्म करके टिल्लू ताजपुरिया गिरोह को नुकसान पहुंचाना चाहता था। गिरफ्तार आरोपित रवि उर्फ मुनिया ने पुलिस से बचने के दौरान सुनील राठी, नीरज बवाना गिरोह में शामिल होकर अमित से हाथ मिला लिया। गैंगस्टर राजेश बवानिया ने रवि उर्फ मुनिया पर हमले करके नीरज बवाना और सुनील राठी गिरोह को कमजोर करने की साजिश रची थी। लेकिन, हमले में मुनिया की जगह उसका भाई मारा गया। दिसंबर 2018 में उसने अमित उर्फ दबंग के साथ मिलकर जोगिंदर की हत्या कर दी। वह रवि उर्फ लांबा का भाई था। रवि राजेश बवानिया गिरोह का बदमाश था और उसने मुनिया के भाई को मारा था। पुलिस के लिए मुसीबत बनते जा रहे टिल्लू ताजपुरिया गिरोह के जितने भी बदमाशों को पुलिस जानती थी, सभी पर मकोका के तहत स्पेशल सेल थाने में मामला दर्ज किया गया।

सड़क हादसे में दारोगा की मौत, भाई समेत तीन घायल

जासं, ग्रेटर नोएडा : सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र में दादरी-ग्रेटर नोएडा बाइपास के समीप तेज रफ्तार में दारोगा की कार पीछे से ट्रक से टकरा गई। ट्रक चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए थे जो कि हादसे का कारण बना। हादसे में यूपी पुलिस के दारोगा सौदान सिंह की मौत हो गई और उनके भाई समेत दो लोग घायल हो गए। घायलों का उपचार निजी अस्पताल में चल रहा है।

मूलरूप से मथुरा के भूड़ा गांव निवासी सौदान सिंह कासना कोतवाली में बतौर उप निरीक्षक तैनात थे। रविवार देर शाम वह सेंट्रों कार में सवार होकर भाई महेंद्र के साथ रूपबास गांव में एक परिचित के यहां कार्यक्रम में गए थे। देर रात कार्यक्रम से लौटते दौरान दादरी-ग्रेटर नोएडा बाइपास के समीप कंटेनर डिपो के सामने उनकी कार के आगे चल रहे ट्रक के चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए। कार आगे चल रहे सरिया से लदे हुए ट्रक से टकरा गई। हादसे में कार सवार तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार के दौरान चिकित्सकों ने सौदान सिंह (51) को मृत घोषित कर दिया।

कड़ी सुरक्षा में कुख्यात उमेश की कोर्ट में पेशी, भेजा जेल

जागरण संवाददाता, हापुड़

गौरव चंदेल हत्याकांड

- मिर्ची गैंग के सरगना आशू जाट की पत्नी को भी किया गया पेश

नोएडा के गौरव चंदेल हत्याकांड में शामिल मिर्ची गैंग के बदमाश उमेश और कुख्यात आशू की पत्नी को पुलिस ने कड़ी सुरक्षा में सोमवार को कोर्ट में पेश किया। अदालत ने दोनों को जेल भेज दिया है। एसओजी और हापुड़ की धौलाना थाना पुलिस ने रविवार रात मुठभेड़ के बाद उमेश को गिरफ्तार किया था। आरोपित के पैर में दो गोली लगी थीं। एसपी ने आरोपित को पकड़ने वाली टीम को 25 हजार का इनाम देने की घोषणा की है।

एसओजी टीम के प्रभारी धर्मेंद्र सिंह, थाना प्रभारी धौलाना रविरतन सिंह, नोएडा के फेस तृतीय के प्रभारी देवेंद्र सिंह ने टीम के साथ शनिवार रात गौरव चंदेल हत्याकांड में शामिल आरोपित बुलंदशहर के रायपुर गांव निवासी उमेश, कुख्यात आशू की पत्नी पूनम को एनटीपीसी रोड पर देहरा झाल के पास से गिरफ्तार किया था। आरोपितों से चोरी की बाइक, गौरव की हत्या में प्रयुक्त पिस्टल, कारतूस, कार की चाभी बरामद हुई थी। पुलिस आरोपित उमेश को गौरव से लूटे गए लैपटॉप की बरामदगी के लिए पारपा नहर की ओर ले जा रही थी। इसी बीच उमेश ने एसएसआइ राजीव शर्मा का सर्विस पिस्टल छीन ली और पुलिस पर फायरिंग कर भागने लगा। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो उसके दोनों पैरों में गोली लग गई। एसएसआइ ने आरोपित से लूटी गई पिस्टल बरामद कर दोबारा गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ने सोमवार सुबह कड़ी सुरक्षा में आरोपित उमेश और आशू की पत्नी को न्यायालय में पेश किया।

ढाई माह की नवजात को दादी को किया सुपुर्द : पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन ने बताया कि आशू की पत्नी पूनम की ढाई माह की बच्ची को मेरठ जिले के मुंडाली थाना क्षेत्र के लोटी गांव निवासी दादी ओमवीरी के सुपुर्द कर दिया है। ओमवीरी करीब पंद्रह दिन पहले ही जमानत पर जेल से छूटकर आई है।

क्या है मामला

हरियाणा के गुरुग्राम स्थित सर्जिकल इक्विपमेंट बनाने वाली एक कंपनी के रीजनल मैनेजर गौरव चंदेल की करीब बीस दिन पहले बदमाशों ने हत्या कर कार व अन्य सामान लूट लिया था। गौरव का शव सात जनवरी को हरनंदी के किनारे स्थित स्टेडियम के पास सर्विस रोड पर मिला था। मूलरूप से कानपुर के अशोकनगर निवासी गौरव चंदेल ग्रेटर नोएडा स्थित गौर सिटी के पांच एवेन्यू में रहते थे। परिवार में पत्नी प्रीति चंदेल व दस वर्षीय पुत्र आदित्य है।

छह महीने में एक बार बनेगी ओपीडी की पर्ची

चंद्रशेखर वर्मा, ग्रेटर नोएडा

- जिम्स में जल्द मिलेगी पेशेंट बुक की सुविधा, सामान्य ओपीडी की सुविधा रहेगी बरकरार

राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान (जिम्स) में मरीजों को जल्द पेशेंट बुक' की सुविधा मिलेगी। इसे ओपीडी के पर्ची के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसकी कीमत 50 रुपये रखी गई है। खास बात यह है कि इसकी वैधता छह महीने की होगी। इसमें मरीजों के इलाज से संबंधित पूरा ब्योरा अंकित होगा। वहीं, अस्पताल में मिल रही एक रुपये के सामान्य ओपीडी की पर्ची की वैधता महज 15 दिन होती है।

जिम्स के प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि मरीजों को गुणवत्तापूर्वक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए संस्थान हमेशा तत्पर है। इसी कड़ी में यह कवायद की गई है। इसको लेकर पिछले दिनों गवर्निंग बॉडी की बैठक हुई थी। इसमें पुस्तिका को शुरू करने के लिए अनुमोदन मिल चुका है। अब मरीजों को जल्द पेशेंट बुक की सुविधा मिलने लगेगी। उन्होंने बताया कि इसका मकसद मरीजों को बार-बार पर्ची लेने की दिक्कतों से निजात दिलाना है। हालांकि ओपीडी में एक रुपये में मिलने वाली पर्ची की सुविधा बरकरार रहेगी। मरीज अपनी सुविधा के अनुसार पेशेंट बुक ले सकते हैं। इस पुस्तिका में 12 पेज दिए गए हैं। इनमें मरीज की बीमारी, इलाज आदि का ब्योरा अंकित रहेगा। इसके साथ ही पुस्तिका में अस्पताल के जरूरी फोन नंबर और डॉक्टरों के नाम भी दिए जाएंगे। लोगों को आपातकालीन स्थिति में नंबर आदि के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। डॉ. अनुराग ने बताया कि पेशेंट बुक तैयार की जा चुकी है। फरवरी में इसे लागू कर दिया जाएगा।

जिम्स के प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव। जागरण आर्काइव

रीढ़ विशेषज्ञ की भी मिलेगी सुविधा : अस्पताल में जल्द रीढ़ रोग विशेषज्ञ की सुविधा भी मिलने वाली है। यह सुविधा हड्डी रोग विभाग के तहत मिलेगी। इसमें रीढ़ रोग में महारत हासिल विशेषज्ञों को बाहर से बुलाया जाएगा। मरीजों की जांच मुफ्त में होगी।

डॉक्टरों को किसी तरह की फीस नहीं देनी होगी। अगर मरीज को ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी तो इसे अस्पताल में सब्सिडी दरों पर किया जाएगा। इसके साथ जल्द ही गेस्टो, न्यूरो, कार्डियो आदि की सुपर स्पेशलिटी सुविधा अस्पताल परिसर में मिलने वाली है।

192 छात्राओं ने खुद को कमरे में किया बंद, ताला तोड़कर निकाला

नईदुनिया, नागदा

मध्य प्रदेश में उज्जैन जिले के नागदा में जवाहर नवोदय विद्यालय की छात्राओं ने रविवार शाम हड़ताल कर दी। उन्होंने प्राचार्य पर सख्ती करने का आरोप लगाते हुए खुद को कमरे में बंद कर लिया। 23 घंटे बाद सोमवार शाम इन्हें दरवाजा तोड़कर निकाला गया। भूखे रहने से एक छात्रा की तबीयत भी बिगड़ गई।

शहर से लगभग 10 किमी दूर गांव बुरानाबाद में मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा संचालित जवाहर नवोदय विद्यालय है। इसमें दो माह पूर्व प्राचार्य मंजू चौधरी की नियुक्ति हुई थी। छात्राओं का आरोप है कि प्राचार्य चौधरी द्वारा उन पर सख्ती की जा रही है। वे छात्राओं की आजादी पर प्रतिबंध लगा रही हैं। आवश्यक कार्य होने पर भी अवकाश नहीं दिया जा रहा है। परिजन से मिलने भी नहीं दिया जाता है। इसके विरोध में कक्षा छठी से 12वीं तक की 192 छात्राओं ने रविवार शाम चार बजे हड़ताल कर दी। विद्यालय में छात्राओं को अलग-अलग कमरे में रखा जाता है, लेकिन आंदोलन के चलते सभी छात्राएं एक ही कमरे में आ गईं और अंदर से ताला लगा लिया। रविवार रात वरिष्ठ अधिकारी विद्यालय पहुंचे, लेकिन छात्राओं ने किसी की नहीं सुनी। सोमवार शाम तक छात्राओं ने ताला नहीं खोला तो विद्यालय प्रबंधन ने दरवाजा तोड़कर इन्हें बाहर निकाला।

किसी प्रकार की सख्ती नहीं की जा रही है। छात्राओं को किसी के द्वारा उकसाया जा रहा है। मेरे साथ राजनीति की जा रही है।
– मंजू चौधरी, प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय

भूख से आने लगे थे चक्कर : छात्राओं ने हड़ताल के दौरान 23 घंटे तक कुछ भी नहीं खाया। इतने समय तक उन्होंने बस पानी ही पीया। इस कारण कुछ छात्राओं को भूख से चक्कर आने लगे थे।

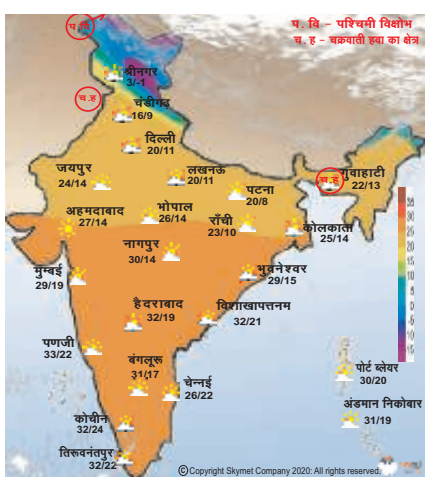

मौसम विशेष

जम्मू-कश्मीर, लद्दाख व हिमाचल प्रदेश में घने बादलों के साथ दिन के तापमान में गिरावट आएगी। अनेक स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा व बर्फबारी होगी। दिल्ली सहित मैदानी भागों में अनेक स्थानों पर गरज व तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी वर्षा होगी। एक-दो स्थानों पर ओलावृष्टि होगी।

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	28/17/व	अहमदाबाद	28/07/व
कोलकाता	25/12/आंबा	बड़ौदा	30/09/सा
चेन्नई	30/22/आंबा	नागपुर	29/12/व
हैदराबाद	31/18/आंबा	इन्दौर	23/13/व
बंगलूरू	31/17/व	रांची	25/12/आंबा
त्रिवेन्द्रम	32/22/आंबा	पटना	20/10/व
गुवाहाटी	22/14/आंबा	जमशेदपुर	26/11/आंबा
जंगटोक	16/07/आंबा	पुणे	29/19/व

टेलीफोन पर पहली बार की गई कॉल

1878 में आज के दिन व्यापारिक स्तर पर पहला टेलीफोन एक्सचेंज अमेरिका के न्यू हैवन शहर में शुरू हुआ और ग्राहम बेल व सहयोगी वाटसन के बीच में न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के बीच पहली कॉल की गई। 10 मार्च 1876 को बेल ने सबसे पहले फोन पर कुछ बोला था।

राजीव गांधी के हत्यारों को सुनाई गई मौत की सजा

आज ही के दिन 1998 में देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में ट्रायल कोर्ट ने दोषियों को मौत की सजा सुनाई, पर तमिलनाडु के राज्यपाल ने 24 अप्रैल, 2000 को दोषियों मुरुगन, सांतन और पेरारिवलन समेत नलिनी की सजा उम्रकैद में बदल दी। इस फैसले को केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

आजादी के साथ कुरीतियों के खिलाफ लड़ी जंग

गरम दल के तीन प्रमुख नेताओं लाल-बाल-पाल में से एक लाला लाजपत राय आज ही के दिन 1865 में पंजाब के मोगा जिले के ढुधिके गांव में जन्मे थे। शुरुआती पढ़ाई हरियाणा के रेवाड़ी और एलएलबी लाहौर के राजकीय कॉलेज से की। छुआछूत के खिलाफ लंबी जंग लड़ी और हिंदू अनाथ राहत आंदोलन की नींव रखी। पंजाब केसरी के नाम से मशहूर लाला जी ने 15 अक्टूबर, 1916 को अमेरिका में होम रूल लीग की स्थापना की। 1921 में जेल गए। 30 अक्टूबर, 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करने के दौरान गंभीर रूप से घायल हुए और 17 नवंबर, 1928 को उनका निधन हो गया।

इधर-उधर की

... और बाल काटने के लिए लगा दी आग

नई दिल्ली, जेएनएन : टिकटॉक पर वायरल होने के लिए लोग क्या कुछ नहीं कर रहे, खतरा मोल ले रहे तो चुनौतियों का सामना करने के लिए मौत से भी खेल जा रहे। इस समय ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। हेयर ड्रेसर का बाल काटने का एक रोचक अंदाज दर्शकों को बड़ा पसंद आया है। इस वीडियो को अभी तक चार करोड़ बार देखा गया है। सबसे पहले उसने लड़के के कंधे पर तौलिया डाला, बालों में जेल लगाया और लाइटर से उसमें आग लगा दी। फिर दो कंघियां लेकर उसके बाल पीछे से सेट करना शुरू कर दिया। धीरे-धीरे आग बुझ गई और बाल अपने आप कम हो गए। जिस वक्त आग लगी उस वक्त लड़का बिलकुल शांत होकर देख रहा था। वीडियो कब और कहां का है, इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि लोग इस वीडियो को भारत का बता रहे हैं।

18 साल की नवोदित गायिका बिली एलिश ने जीते पांच ग्रैमी अवार्ड

लॉस एंजिलिस, रायटर : अमेरिका के लॉस एंजिलिस शहर में रविवार देर रात दिए गए 62वें ग्रैमी अवार्ड्स में 18 साल की नवोदित गायिका बिली एलिश ने पांच पुरस्कार जीते। उन्हें छह श्रेणियों में नामांकन मिला था। बिली इस बार अवार्ड जीतने वाली सबसे युवा गायिका हैं। सबसे ज्यादा आठ श्रेणियों में नामांकित लिज्जो को ट्रूथ हर्ट्स के लिए बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस सहित तीन अवार्ड मिले। अमेरिका में हर साल दिए जाने वाले ग्रैमी अवार्ड्स मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा में संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं।

- **शीर्ष श्रेणी के चार अवार्ड जीतने वाली दूसरी और सबसे युवा कलाकार**
- **लिज्जो को ट्रूथ हर्ट्स के लिए बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस सहित तीन अवार्ड**
- **संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है यह अवार्ड**

अमेरिका के लॉस एंजिलिस शहर में आयोजित वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स समारोह के दौरान नवोदित गायिका बिली एलिश। एएफपी

हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले महान बास्केटबॉल खिलाड़ी कोबे ब्रायंट को श्रद्धांजलि देने के साथ ग्रैमी 2020 अवार्ड्स समारोह की शुरुआत हुई। 15 बार ग्रैमी जीतने वाली एलिशिया कीज ने समारोह का संचालन किया। कोबे को श्रद्धांजलि देते हुए कीज ने कहा, मैंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी इस तरह समारोह की शुरुआत करनी पड़ेगी। बिली को चार शीर्ष श्रेणियों बेस्ट न्यू आर्टिस्ट, सांग ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर और एलबम ऑफ द ईयर में अवार्ड मिले। हरे बाल और बैगी कपड़ों से पहचानी जाने वाली बिली ने अपने भाई फिनीज के साथ मिलकर लॉस एंजिलिस स्थित अपने घर के बेडरूम में एलबम - व्हेन वी ऑल फाल अस्लीप, व्हेयर डू वी गो - की रिकॉर्डिंग की थी। दिवंगत रैपर निप्सी हसल ने भी दो ग्रैमी जीते। उनकी पिछले साल लॉस एंजिलिस के नजदीक गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

चार साल की उम्र में लिखा था पहला गाना : 18 दिसंबर 2001 को लॉस एंजिलिस में जन्मीं बिली अभिनेत्री और गीतकार मैगी बेअर्ड और अभिनेता पैट्रिक ओकॉनेल की बेटी हैं। बिली को संगीत और गाने लिखना उनकी मां ने सिखाया। महज चाल साल की उम्र में उन्होंने पहला गाना लिखा था और आठ साल से उन्होंने म्यूजिक शो में भाग लेना शुरू किया।

बिकमिंग ऑडियो बुक के लिए मिशेल ओबामा को ग्रैमी

लॉस एंजिलिस, प्रेट्र : अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल को उनकी ऑडियो बुक 'बिकमिंग' के लिए प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार से नवाजा गया है। अपनी बेस्टसेलिंग आत्मकथा बिकमिंग की ऑडियो बुक में मिशेल ने ही आवाज दी है। मिशेल को बेहतरीन शब्दों वाले ऑडियो एलबम की श्रेणी में यह पुरस्कार मिला। उन्होंने इस श्रेणी में बीस्टी ब्वॉज, एरिक एलेक्जेंड्राकिज और जॉन वाटर्स जैसे प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ा। बिकमिंग में मिशेल के बचपन से लेकर अमेरिका की प्रथम महिला बनने तक के सफर को दर्शाया गया है। ग्रैमी पुरस्कार पाने वाली मिशेल अपने परिवार की पहली सदस्य नहीं हैं। इससे पहले बराक ओबामा को भी इसी श्रेणी में 'ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर' (2006) और 'द ऑडेसिटी ऑफ होप' (2008) के लिए दो ग्रैमी अवार्ड मिल चुके हैं।

अमेरिका के लॉस एंजिलिस के स्टेप्लस सेंटर में आयोजित म्यूजिक के सबसे प्रतिष्ठित गैमी अवार्ड्स समारोह में शामिल होने पहुंचे निक जोनास और बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा। इस दौरान प्रियंका ने अनोखे अंदाज में दिवंगत बास्केटबॉल खिलाड़ी कोबी ब्रायन को श्रद्धांजलि दी। प्रियंका ने अपने दाहिने हाथ की तर्जनी के नाखून में कोबी का जर्सी नंबर '24' लिखवाया था। एपी

बिना छुए चीजों को उठा सकता है यह रोबोट

तकनीक ▸ स्विटजरलैंड की ईटीएच ज्यूरिक के शोधकर्ताओं ने विकसित किया रोबोटिक ग्रिपर

ध्वनि तरंगों का मदद से वस्तुओं को रख सकता है एक जगह से दूसरी जगह

जेनेवा, प्रेट्र : क्या आपने कभी कल्पना की है चीजों को बिना छुए उसे उसकी मूल जगह से हटाकर दूसरी जगह कैसे रखा जाता है। फिल्मों में अक्सर हम ऐसा होते देखते हैं लेकिन वास्तविकता में यह मुश्किल लगता है। लेकिन अब यह संभव है। दरअसल, वैज्ञानिकों ने एक ऐसा रोबोटिक ग्रिपर किया है, जो छोटी और नाजुक चीजों को बिना छुए ध्वनि तरंगों का मदद से एक जगह से दूसरी जगह रख सकता है।

इस प्रोटोटाइप रोबोट को स्विटजरलैंड की ईटीएच ज्यूरिक यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है। इसमें दो अर्द्ध-गोलीय वस्तुएं और एक ही तरह के दो हेडफोन लगे होते हैं। ये गोलीय वस्तु माइक्रोचिप से लैस एक सर्किट बोर्ड से जुड़ी होती हैं। एक छोटी गोलीय वस्तु इन दोनों अर्द्ध-गोलीय वस्तु के ऊपर होती है, जिसे अल्ट्रासाउंड वाली तरंगें नियंत्रित करती हैं। ज्यूरिक ईटीएच के फेलो मार्सल शुक का कहना है, 'इस परिघटना को ध्वनि उत्तोलन कहा जाता है।' वह एक ऐसी पद्धति विकसित कर रहे हैं, जो इसे छोटी वस्तुओं को बिना छुए पूरी तरह उठाने में सक्षम बना सके।

रोबोटिक ग्रिपर की जांच करते शोधकर्ता। साभार : ईटीएच ज्यूरिक

शोधकर्ताओं का कहना है कि यह उन परिस्थितियों में काफी कारगर साबित हो सकता है, जब छोटी चीजों के नुकसान का असर हमारी जेब पर पड़ता है। उदाहरण के तौर पर, घड़ी बनाने के काम या फिर सेमीकंडक्टर उद्योग में। उनका कहना है कि पारंपरिक रोबोटिक ग्रिपर से नाजुक वस्तुओं के नुकसान का खतरा होता है। इससे बचने के लिए मुलायम और रबड़ जैसे ग्रिपर का प्रयोग किया जा सकता है। हालांकि, इन मुलायम रोबोटिक ग्रिपर से चीजों को स्थानांतरित करने की सीमा भी है।

ऐसे काम करती है नई तकनीक : शोधकर्ताओं ने बताया कि नई तकनीक एक ऐसे प्रभाव पर आधारित है, जिसका प्रयोग 80 वर्षों से होता आ रहा है और पहली बार अंतरिक्ष अन्वेषण में इस्तेमाल किया गया। अल्ट्रासाउंड वेव एक दबाव क्षेत्र पैदा करती है, जिसे मनुष्य देख या सुन नहीं सकता है। दबाव बिंदुओं को ध्वनि तरंगों के रूप में एक-दूसरे के ऊपर बनाया जाता है और छोटी वस्तुओं को इन बिंदुओं के भीतर फंसाया जा सकता है। नतीजतन, वे एक ध्वनि जाल में हवा में स्वतंत्र रूप से तैरने लगती हैं। शोधकर्ताओं ने थ्री-डी प्रिंटर का उपयोग करके कई छोटे-छोटे लाउडस्पीकर को दोनों अर्द्ध-गोलों में फिट किया। संबंधित सॉफ्टवेयर शोधकर्ताओं को लाउडस्पीकर इस तरह नियंत्रित करने में सक्षम बनाता है कि दबाओ बिंदुओं को चारों तरफ घुमाया जा सके। शोधकर्ताओं का कहना है कि रोबोटिक्स के क्षेत्र में यह ग्रिफर बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है।

आकार के मुताबिक खुद को समायोजित करता है ग्रिपर

शुक ने बताया कि हमारा लक्ष्य वस्तुओं को जमीन पर गिरे बिना उनकी जगह को वास्तविक समय में बदलने की है। इस तकनीक का प्रयोग करके वैज्ञानिक अंतरिक्ष में कई छोटी-छोटी वस्तुओं को स्थानांतरित करने में सक्षम थे। शोधकर्ताओं ने बताया कि वस्तु के आकार के हिसाब से सॉफ्टवेयर ग्रिपर को समायोजित किया जाता है और रोबोट का बाजु फिर उसे लक्षित जगह तक पहुंचाता है। उनका कहना है कि बिना छुए वस्तुओं को पकड़ने का आर्थिक लाभ भी है। जब हम पारंपरिक रोबोट से काम करते हैं, तो लगभग सभी नए आकार के लिए अलग-अलग ग्रिपर की जरूरत पड़ती है। वहीं, ध्वनि तरंगों के आधार पर काम करने वाला ग्रिपर महंगे ग्रिपर की जरूरत खत्म कर देगा।

सुपरबग जीन भी फैला सकते हैं धूल में रहने वाले बैक्टीरिया

लॉस एंजिलिस, प्रेट्र : एक नए अध्ययन में दावा किया गया है कि धूल में रहने वाले बैक्टीरिया ऐसे जीन फैला सकते हैं जो रोगाणुओं को एंटीबायोटिक्स का मुकाबला करने की क्षमता प्रदान करते हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि इस अध्ययन की मदद से माइक्रोब्स यानी रोगाणुओं से बचने के लिए नई प्रतिरोधी दवाएं विकसित कर सकते हैं।

पीएलओएस पैथोजंस नामक जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है कि हालांकि ज्यादातर बैक्टीरिया हानिकारक नहीं होते, फिर भी बीमारी होने पर ये जीन्स को फैलाते हैं और इनका संक्रमण इतना खतरनाक होता है कि इलाज करना मुश्किल हो जाता है।

अमेरिका की नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता और इस अध्ययन के सह-लेखक इरिका हार्टमन ने कहा, ' इसका मतलब यह नहीं है कि एंटीबायोटिक प्रतिरोधी दवाएं असर नहीं कर रही है। यह सिर्फ एक जोखिम वाला कारक है और इसके बारे में हमें सावधान रहने की जरूरत है।'

ऐसे फैलते हैं जीन : अध्ययन के मुताबिक, बैक्टीरिया अपने जीन को विभाजित करके या क्षैतिज जीन स्थानांतरण (होरिजेंटल जीन ट्रांसफर) के माध्यम से फैला सकते हैं, जिसमें एक रोगाणु अपने जीन की एक प्रति बनाता है और अपने पड़ोसी जीन के साथ उसकी अदला-बदली कर लेता है। शोधकर्ताओं ने कहा कि एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन्स को जीवों में प्रसारित करने का यह प्राथमिक और सबसे खतरनाक तरीका है। उन्होंने कहा कि इस विधि के जरिये बैक्टीरिया अलग-अलग तरीके के जीन्स को प्रसारित करते रहते हैं।

प्रतीकात्मक

खतरनाक है धूल के माइक्रोब्स : इरिका हार्टमैन और उनकी टीम ने पहली बार पाया है कि धूल के माइक्रोब्स (रोगाणुओं) में खतरनाक जीन्स को फैलाने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। उन्होंने कहा कि अध्ययन के दौरान हमने पाया कि बैक्टीरिया एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन को आसानी से प्रसारित करते हैं।

फोटो न्यूज

तिरंगे से जगमगाया बुर्ज खलीफा

संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी दुबई स्थित विश्व की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा भारत के 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर तिरंगे के रंग में रंग गई। रविवार की रात विशेष लाइटों के जरिये इमारत पर तिरंगे झंडे का प्रतिरूप बनाया गया था। दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास के अनुसार, हजारों प्रवासी भारतीय यह नजारा देखने पहुंचे। ट्विटर

डेंगू से बचाव कर सकती है स्किन क्रीम

शोध अनुसंधान

एक नए अध्ययन में दावा किया गया है कि मस्से और त्वचा कैंसर के उपचार में काम आने वाली एक स्किन क्रीम डेंगू और जीका जैसी बीमारियों से बचाव में भी मददगार हो सकती है। इमिकुमोड या एल्डरा नामक यह स्किन क्रीम मस्से और कुछ प्रकार के त्वचा कैंसर के उपचार में आमतौर पर इस्तेमाल होती है। शोधकर्ताओं के अनुसार, यह निष्कर्ष मच्छर द्वारा संचारित चार प्रकार के वायरस पर किए गए अध्ययन के आधार पर निकाला गया है। इसमें पाया गया कि मच्छर के काटने के महज एक घंटे के अंदर यह क्रीम लगाने से संक्रमण को रोका जा सकता है। ब्रिटेन की लीड्स यूनिवर्सिटी के प्रमुख शोधकर्ता क्लाइव मैककिमी ने कहा, 'इस अध्ययन से जाहिर होता है कि चिकित्सकीय तौर पर स्वीकृत और व्यापक तौर पर इस्तेमाल होने वाली स्किन क्रीम कीट जनित बीमारियों से बचाव में भी कारगर हो सकती है।' -आइएएनएस

स्तन कैंसर की पहचान में एमआरआइ स्कैन मददगार

शोधकर्ताओं को स्तन कैंसर की जल्द पहचान करने की दिशा में बड़ी कामयाबी मिली है। एक नए अध्ययन में पाया गया है कि स्तन कैंसर के बायोमार्कर की पहचान करने में मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग (एमआरआइ) स्कैन मददगार हो सकता है। इसकी मदद से इस घातक बीमारी की प्रारंभिक अवस्था में ही पहचान हो सकती है। अमेरिका के स्लोगन केटरिंग कैंसर सेंटर के शोधकर्ताओं के अनुसार, कैंसर रोगियों के स्वस्थ ब्रेस्ट टिश्यू के विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है। यह बीमारी धीरे-धीरे पूरे शरीर में फैल सकती है। उन्होंने पाया कि पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी (पीईटी) या एमआरआइ स्कैन के उपयोग से बायोमार्कर्स में कई अंतर खोजे जा सकते हैं। इससे खतरे का आकलन करने और इससे बचाव की रणनीति अपनाने में मदद मिल सकती है। स्तन कैंसर की प्रारंभिक अवस्था में पहचान पीड़ितों को बचाने के लिहाज से बेहद अहम मानी जाती है। -प्रेट्र

स्क्रीन शॉट

ऋषि कपूर के साथ कॉमेडी फिल्म में नजर आएंगी दीपिका पादुकोण

'छपाक' के बाद दीपिका पादुकोण कौन-सी फिल्म करेंगी, इसका उन्होंने खुद सोमवार को एलान कर दिया। 'पद्मावत' व 'छपाक' में गंभीर किरदार निभाने के बाद वह कोई हल्का-फुल्का किरदार निभाना चाहती थीं। अब वह कॉमेडी फिल्म करेंगी, जिसमें उनके साथ ऋषि कपूर भी मुख्य भूमिका में होंगे। यह फिल्म साल 2015 में बनी हॉलीवुड कॉमेडी फिल्म 'द इंटर्न' का भारतीय रूपांतरण होगी। फिल्म की घोषणा करते हुए दीपिका ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'अपनी अगली फिल्म 'द इंटर्न' के भारतीय रूपांतरण को प्रस्तुत करते हुए काफी रोमांचित हूं।' दीपिका ने ऋषि कपूर को टैग करते हुए लिखा कि आपसे फिल्म में मुलाकात होगी। दीपिका इस फिल्म से बतौर निर्माता भी जुड़ेंगी। नैन्सी मेयर्स के निर्देशन में बनी 'द इंटर्न' में हॉलीवुड एक्टर रॉबर्ट डी नीरो, एनी हाथवे और रेने रूसो मुख्य भूमिका में थे। फिल्म की कहानी एक 70 वर्षीय विधुर व्यक्ति के इर्द-गिर्द घूमती है।

अनिल कपूर नहीं कर रहे हैं 'इंडियन 2'

बीते दिनों आई खबरों में कहा गया था कि अनिल कपूर 'इंडियन 2' में खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं। यह फिल्म वर्ष 1996 में आई 'इंडियन' का सीक्वल है। हालांकि अनिल कपूर ने 'इंडियन 2' में होने से इन्कार किया है। अनिल के मुताबिक, वह फिल्म के सेट पर निर्देशक शंकर से मिलने गए थे। वहां पर दोनों की साथ की तस्वीरें वायरल हो गईं। लोगों को लगा कि हम फिल्म साथ में कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। दरअसल, इस फिल्म में पहले अजय देवगन खलनायक की भूमिका निभाने वाले थे। यह उनकी पहली तमिल फिल्म भी होती, लेकिन अपनी व्यस्तताओं के चलते उन्होंने फिल्म से किनारा कर लिया।

'इंडियन 2 में कमल हासन, काजल अग्रवाल, विद्युत जामवाल प्रमुख भूमिका में हैं। अनिल कपूर सात फरवरी को रिलीज होने वाली 'मलंग' में पुलिस अधिकारी के किरदार में नजर आएंगे।

कश्मीर में फिल्म स्कूल खोलना चाहते हैं विधु विनोद चोपड़ा

जिहादी इस्लामिक ताकतों ने कश्मीरी पंडितों पर ऐसा कहर ढाया कि 19 जनवरी 1990 को लाखों कश्मीरी पंडितों को रातोंरात अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था। कश्मीरी पंडितों की इसी दर्द भरी दास्तान को करीब तीन दशक बाद विधु विनोद चोपड़ा ने अपनी फिल्म 'शिकारा' में दिखाया है। विधु खुद भी कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। 'परिंदा', 'मिशन कश्मीर', '1942 : ए लवस्टोरी' जैसी फिल्मों का निर्देशन करने वाले विधु विनोद की इच्छा कश्मीर में एक फिल्म स्कूल स्थापित करने की है। उनका कहना है कि उनके पिता की कमाई खास नहीं थी। लिहाजा वह किसी फिल्म इंस्टीट्यूट नहीं जा सके थे। उन्होंने काफी संघर्ष के बाद अपना मुकाम बनाया है। उनका कहना है कि उन्होंने अपने भाई से 200 रुपये लिए, जब उन्होंने नौकरी ज्वाइन की थी। वह आर्थिक स्तर पर संघर्षरत थे। जब वह भूख से तड़प रहे होते थे तो दो केले खा लिया करते थे। इस तरह के संघर्षों से उबरकर वह इस मुकाम तक पहुंचे हैं। इसलिए वह अपने जैसे संघर्षरत लोगों के लिए कश्मीर में स्कूल खोलना चाहते हैं। 'शिकारा' के जरिए विधु विनोद चोपड़ा अपनी दिवंगत मां को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उन्होंने 'शिकारा' की शूटिंग वास्तविक शरणार्थी शिविर के निवासियों और अन्य शिविरों के लोगों के साथ की है। फिल्म सात फरवरी को रिलीज होगी।

बेटे संग बॉबी ने मनाया अपना जन्मदिन

सोमवार को अभिनेता बॉबी देयोल ने अपना 51वां जन्मदिन अपने बेटे के साथ मनाया। इस मौके पर उन्होंने सोशल मीडिया पर बेटे आर्यमान के साथ एक तस्वीर साझा की। बॉबी फिलहाल परिवार के साथ अपना जन्मदिन मनाने अमेरिका गए हैं। उनका बेटा न्यूयॉर्क में बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा है। तस्वीर साझा करते हुए उन्होंने लिखा, 'अपना 51वां जन्मदिन मनाने के लिए आप सब की शुभकामनाओं से अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। मैं अपने परिवार के प्रति आपके निस्वार्थ प्रेम के लिए आभारी हूं।' ट्विंकल खन्ना, रितेश देशमुख समेत कई हस्तियों ने उन्हें बधाई दी। बॉबी देयोल पिछले साल रिलीज फिल्म 'हाउसफुल 4' में नजर आए थे। फिलहाल वह अपनी आगामी फिल्म 'क्लास ऑफ 83' पर काम कर रहे हैं।

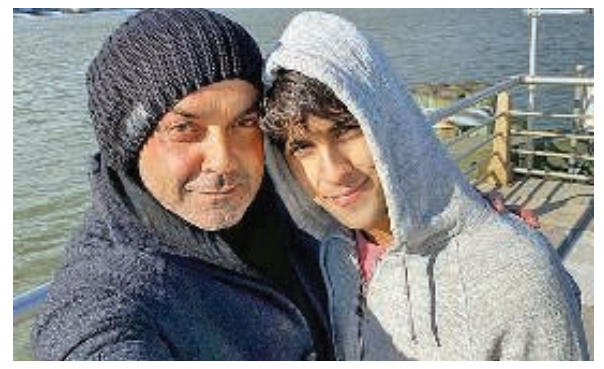

'शुभ मंगल ज्यादा सावधान' करने से पहले आयुष्मान को पुनर्विचार करने को कहा गया था

अपने अनूठे किरदारों के साथ अपनी पहचान बनाने वाले आयुष्मान फिल्म 'शुभ मंगल ज्यादा सावधान' में समलैंगिक व्यक्ति की भूमिका निभा रहे हैं। अभी तक किसी लीडिंग स्टार ने ऐसा किरदार नहीं निभाया है। आयुष्मान अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ फिल्म देखने के लिए तैयार हैं। दरअसल, उनका परिवार उनका सपोर्ट सिस्टम रहा है। आयुष्मान का कहना है, 'मैं आज जिस मुकाम पर हूं, उसकी वजह मेरा परिवार है। जब मैंने सिनेमा में करियर बनाने का फैसला किया, तो वे चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े रहे। मेरी फिल्मों का विषय और किरदार वर्जित विषयों पर रहे हैं। 'विकी डोनर' में एक स्पर्म डोनर, 'शुभ मंगल सावधान' में स्तंभन दोष से परेशान व्यक्ति और 'बाला' में समय से पहले गंजेपन का सामना करने वाले वाले शख्स का किरदार निभाने के बाद 'शुभ मंगल ज्यादा सावधान' में एक समलैंगिक की भूमिका निभा रहा हूं। उन्होंने मुझे हमेशा अपनी सहज प्रवृत्ति के साथ रहने और लोग क्या कहते हैं, इसके बारे में न सोचने को कहा।' आयुष्मान कहते हैं कि इंडस्ट्री के कई लोगों ने उन्हें स्क्रीन पर समलैंगिक व्यक्ति की भूमिका निभाने के फैसले पर दोबारा सोचने को कहा था। वह कहते हैं, 'किसी भी लीडिंग हीरो ने अब तक स्क्रीन पर समलैंगिक व्यक्ति का किरदार नहीं निभाया है। मुझे पता था, इस स्टीरियोटाइप को तोड़ने की जरूरत है और अब इसे बदलने का समय आ गया है। मेरे परिवार ने मेरे फैसले का पूरी तरह से समर्थन किया। मैं अपने माता-पिता और अपने सभी रिश्तेदारों के साथ इस फिल्म को देखना चाहता हूं।'

आमिर के कहने पर अक्षय ने बदली फिल्म की तारीख

फिल्मों की बढ़ती संख्या के कारण अब एक ही तारीख पर दो बड़े सितारों की फिल्में रिलीज होने लगी हैं। उसके बावजूद ज्यादातर निर्माताओं की कोशिश रहती है कि उनकी फिल्म किसी बड़े स्टार की फिल्म के साथ न टकराए। आमिर खान अभिनीत फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। यह फिल्म इस साल 25 दिसंबर को क्रिसमस पर रिलीज होगी। अक्षय कुमार की फिल्म 'बच्चन पांडे' भी क्रिसमस के आसपास ही रिलीज होने वाली थी। दोनों फिल्मों में टकराव टालने के लिए आमिर खान के निवेदन पर फिल्म निर्माता साजिद नाडियाडवाला और अक्षय कुमार ने 'बच्चन पांडे' की रिलीज तारीख बदल दी है। सोमवार को सोशल मीडिया पर यह जानकारी देते हुए आमिर ने दोनों का धन्यवाद किया। उन्होंने लिखा, 'कई बार ऐसा सिर्फ एक ही बातचीत में हो जाता है। मेरे निवेदन पर 'बच्चन पांडे' की रिलीज डेट आगे बढ़ाने के लिए अक्षय कुमार और साजिद नाडियाडवाला को धन्यवाद। फिल्म के लिए मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं।' कुछ देर बाद ही अक्षय ने सोशल मीडिया पर 'बच्चन पांडे' के दूसरे पोस्टर के साथ फिल्म की नई रिलीज तारीख की घोषणा की। अब यह फिल्म अगले साल 22 जनवरी को रिलीज होगी।